बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 93

कारोबार के स्वर्णिम मानक

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने इस सप्ताह कहा कि वह इस बात को लेकर 'बहुत आशान्वित' हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौते पर शीघ्र ही सहमति बन सकती है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क के स्थगन की जुलाई में 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले भी पूरा हो सकता है। यह बहुत अच्छी खबर प्रतीत होती है लेकिन इसकी सराहना के साथ थोड़ी शंका भी बनती है। भारत के वार्ताकारों की मानें तो वे इस बातको लेकर बहुत निश्चिंत नहीं हैं कि कोई भी आरंभिक समझौता क्या इतना व्यापक होगा कि दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सके। यह समझौता कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह सकता है जो राजनीतिक दृष्टि से मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बहरहाल, इसमें चुनिंदा कृषि क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जो भारत की ओर से एक बड़ी रियायत होगी।

यह आवश्यक है कि सरकार उच्च शुल्क दर से बचने का हरसंभव प्रयास करे लेकिन उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका के साथ कोई भी समझौता उसके नेतृत्व की अनिश्चितताओं और राजनीतिक तथा कानूनी माहौल में बदलाव से प्रभावित होगा। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए शुल्क संबंधी निर्णयों को न्यायिक चुनौती पहले ही दी जा चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस में भले ही ट्रंप के दल का दबदबा है लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह ट्रंप के अंतिम निर्णय का समर्थन करेगी या नहीं। तकनीकी तौर पर देखें तो व्यापार समझौते विधायिका का मसला हैं, न कि कार्यपालिका का। विधायिका किसी भी समय स्वीकृति देने की शक्ति पुनः हासिल कर सकती है। और यकीनन ट्रंप के आवेश में आकर निर्णय लेने को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के साथ कोई भी समझौता जो उनके समर्थकों के मन मुताबिक नहीं हुआ, उसे किसी भी समय एकतरफा ढंग से रद्द किया जा सकता है। भले ही इसके लिए जरूरी कानूनी आधार हो अथवा नहीं।

चूंकि अमेरिका एक तरह के राजनीतिक उथलपुथल से गुजर रहा है इसलिए वह विश्वसनीय सहयोगी नहीं रह गया है। व्यापार के मामले में भारत सारा दांव अमेरिका पर नहीं लगा सकता। सच तो यह है कि दुनिया के तमाम अन्य देशों की तरह भारत के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वह अन्य कारोबारी साझेदार तलाश करे जिनके साथ वह नियम आधारित विश्वसनीय समझौते कर सके। अमेरिका के वर्तमान हालात जैसे अस्थिर माहौल के बीच टिकाऊ कारोबारी संपर्क नहीं कायम किया जा सकता है। नियम और विश्वसनीयता की बदौलत ही पूंजी और समय का निवेश करके मजबूत कारोबारी संपर्क कायम किए जा सकते हैं। भारत को अमेरिका के साथ वार्ता में कुछ ठोस रेखाएं खींचनी होंगी लेकिन इसके साथ ही उसे उन देशों के साथ अपनी मांगें कम करनी चाहिए जो नियमों का पालन करने के इच्छुक हैं।

कई संभावनाएं हैं, जिनमें से कुछ के लिए अवधि बहुत कम है। उदाहरण के लिए भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी वादा किया है कि वर्ष के अंत तक समझौता हो जाएगा। चूंकि यह नियम आधारित और विश्वसनीय होगा इसलिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और भारत को इसे पूरा करने में पूरी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। परंतु यहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न बहुपक्षीय ब्लॉक पर नजर डालते हुए व्यापार के नए युग में उनकी उपयोगिता पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से इस डर से बाहर हो गया कि उसमें चीन भी है, लेकिन तब से समय बदल चुका है और चीन की वस्तुओं या उसके निवेश को मूल्य श्रृंखला से पूरी तरह बाहर करना असंभव है। उच्च गुणवत्ता वाले समझौते मसलन प्रशांत पार व्यापक एवं प्रगतिशील समझौता यानी सीपीटीपीपी आदि पर एक बार फिर नजर डालनी चाहिए और ऐसे नियामकीय बदलाव किए जाने चाहिए जो भारत को सदस्य बनने का अवसर दें। नियम आधारित व्यवस्थाएं अभी भी कारोबार के लिए सबसे अच्छे मानक हैं।

अजय मोहंती

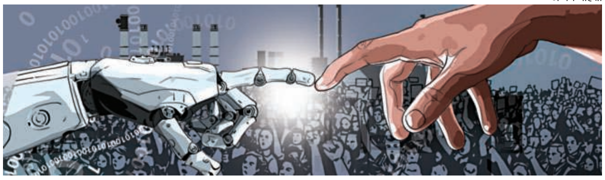

तकनीकी क्रांतियों के पीछे की सच्चाई

औद्योगिक-तकनीकी क्रांतियों के महिमामंडन में तमाम कठोर सच्चाइयों को छिपा लिया गया। बता रहे हैं अजित बालाकृष्णन

मेरे जीवन में निरंतर चले आ रहे रहस्यों में से एक यह समझने की कोशिश भी रही है कि आखिर इंगलैंड में 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति, जिसने कताई और बुनाई की मशीनों की शुरुआत की, वह पहले भारत में क्यों नहीं घटित हुई। आखिर भारत उस समय दुनिया में सबसे अधिक कपास के धागे और कपड़े तैयार कर रहा था। मैं जब भी यह सवाल करता हूं तो मुझे उत्तर मिलता है, 'भारत में श्रम की लागत इतनी कम थी कि किसी ने कताई या बुनाई के लिए मशीनों का अविष्कार करने के बारे में सोचा ही नहीं।'

औद्योगिक क्रांति शब्द को ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1882 में ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में इस्तेमाल किया था और यह बताया था कि कैसे कताई और बुनाई की मशीनों ने इंगलैंड को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी बदौलत घरेलू स्तर पर होने वाले उत्पादन में भारी बदलाव आया। घरों और छोटी वर्कशॉप में होने वाला काम अब कारखानों में होने लगा जहां मशीनों के जरिये व्यवस्थित ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। उन्होंने 'क्रांति' शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे बहुत तेज और भारी बदलाव आया था जिसने समाज को उसी तरह बदल दिया जैसे कि कोई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति करती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि केवल मशीनों के इस्तेमाल ने ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय रिश्तों के बुनियादी पुनर्गठन ने इसे एक 'क्रांति' में बदल दिया।

काश मैं उस समय श्रोताओं के बीच होता तो खड़ा होकर कहता, 'आप ब्रिटेन की बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं श्रीमान टॉयनबी।' प्रिय पाठको, इससे पहले कि आप सोचें कि मैं इतना बगावती क्यों हूं, कुछ तथ्यों पर ध्यान दीजिए।

यह एक व्यापक मान्यता है कि ब्रिटेन के सूती कपड़ा विनिर्माता इन मशीनों का इस्तेमाल किए जाने से इतना किफायती कपड़ा तैयार करने लगे जिसके चलते न केवल वे भारत से सूती वस्त्र का आयात पूरी तरह रोक सके बल्कि वे भारत के कताई-बुनाई उद्योग को पूरी तरह नष्ट करने में भी कामयाब रहे।

बहरहाल एक सच जिसका जिक्र इस कहानी में नहीं किया जाता वह यह है कि मैनचेस्टर के कताई-बुनाई कारोबार को फलने-फूलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1700 में कानून पारित किए और आयात शुल्क को बेतहाशा बढ़ा दिया। भारत से आने वाले सूती वस्त्र पर उनके प्रकार के हिसाब से 15 से लेकर 75 फीसदी तक आयात कर लगाया गया। इस कपड़े को वहां कैलिको कहा जाता था क्योंकि उसे केरल के कालीकट बंदरगाह से ब्रिटेन भेजा जाता था। चूंकि इससे मांग कम करने को लेकर वांछित असर नहीं पड़ा तो 1720 में दूसरा कानून पारित किया गया ताकि भारत सूती वस्त्र आयात पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सके।

इस कानून में यह प्रावधान भी था कि आयातित सूती कपड़े पहनने वाले लोगों पर 15 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और ऐसे कपड़े रखने अथवा बेचने वालों पर 200 पाउंड तक के जुर्माने का प्रावधान था। जब ये प्रावधान भी नाकाम रहे तब ब्रिटिश बुनकरों ने कैलिको पहनने वाली महिलाओं पर हमले करके विरोध जताया, उन्होंने उनके कपड़े फाड़े और यहां तक कि उन पर तेजाब भी फेंका गया।

शायद औद्योगिक क्रांति की कहानी के पीछे का सबसे सावधानी से छिपाया गया तथ्य यह है कि आखिर किस बात ने ब्रिटिश सूती वस्त्र निर्माताओं को भारतीय हथकरघा बुनकरों पर अंतिम बढ़त प्रदान की। सन 1800 के आसपास ब्रिटेन अपना अधिकांश कपास अमेरिका के दक्षिण से आयात करता था जिसे हजारों दास अफ्रीकियों की बदौलत एक विशाल बंधुआ मजदूर शिविर में बदल दिया गया था। ये दास अकल्पनीय रूप से कम कीमत पर कच्चा कपास बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध कराते थे।

एक बार जब मुझे ये तथ्य पता चल गए तो मैं गहरे अवसाद का शिकार हो गया: क्या यह संभव है कि मानवता ऐसे तथ्यों की अनदेखी करती रहे और पिछले 200 से अधिक वर्षों से यह मानती आ रही हो कि 'औद्योगिक क्रांति' जैसे जुमले का इस्तेमाल उन कार्यों को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है जो वास्तव में 'औपनिवेशिक शोषण' था? 'तकनीक आधारित विकास' या 'तकनीकी क्रांति' जैसे जुमले तो और भी चिंतित करने वाले हैं। इनका इस्तेमाल उन कदमों के लिए किया गया जो वास्तव में विभिन्न पहलों का मिश्रण थे और जिनमें तकनीक की हिस्सेदारी बेहद कम थी। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमें उन कई 'तकनीकी क्रांतियों' के पुनर्परीक्षण की जरूरत है जिन्हें हम अब तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नज़रिये से देखते आए थे? कहने का तात्पर्य यह है कि हमें केवल इंजीनियरिंग के लिहाज से ही नहीं, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के नज़रिये से अलग साधनों और तरीकों का इस्तेमाल कर उन तमाम तकनीकी क्रांतियों का पुनर्परीक्षण करना होगा, जिनके बारे में हम सभी मानते हैं कि वे घटित हुई हैं।

पहली औद्योगिक क्रांति (18वीं-19वीं सदी) ने भाप से चलने वाली मशीनें दीं जिन्होंने हाथ से होने वाले उत्पादन की जगह ली। दूसरी औद्योगिक क्रांति (19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी) ने बिजली और व्यापक उत्पादन की तकनीक मसलन असेंबली लाइन आदि तैयार कीं। तीसरी औद्योगिक क्रांति जिसे डिजिटल क्रांति कहा जाता है उसने कारखानों में स्वचालन और एकीकृत व्यवस्था के लिए उन्हें कंप्यूटरों और इंटरनेट से जोड़ा। चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) का संबंध आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से है। ये एक साथ मिलकर साझा संपर्क और मेधा के क्षेत्र में काम करते हैं। अब पांचवीं औद्योगिक क्रांति उभर रही है।

शायद अब वक्त आ गया है कि महात्मा गांधी की ओर लौटें और उस बात पर ध्यान दें जो उन्होंने स्वराज आंदोलन के समय कही थी, 'उनका जोर श्रम की बचत करने वाली मशीनरी पर है। लोग तब तक श्रम की बचत करेंगे जब तक कि हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते और सड़कों पर भूख से मरने के लिए नहीं फेंक दिए जाते। मैं समय और श्रम बचाना चाहता हूं, मानव जाति के कुछ हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। मैं चाहता हूं कि धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में न हो बल्कि सभी के पास धन हो। आज मशीनरी केवल कुछ लोगों की सहायता करती है ताकि वे लाखों लोगों पर शासन कर सकें लेकिन इसके पीछे की प्रेरणा परोपकार नहीं बल्कि लालच है। ऐसा नहीं है कि हमें मशीनरी नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे इसके उचित स्थान पर चाहते हैं। जब तक इसे सरल नहीं बनाया जाता है और सभी के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक यह हमारे पास नहीं होगी।'

क्या यही वह अगला आंदोलन है जिसे हमें अपनाना चाहिए और जो शायद आज के दिनों में उतना ही अहम हो सकता है जितना कि गांधी के दौर में स्वराज आंदोलन था।

(लेखक तकनीक और समाज के बीच संपर्कों के बारे में अध्ययन को समर्पित हैं)

बिहार में शराबबंदी फिर बन रहा चुनावी मुद्दा

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

कुछ लोग इसे कभी भरपाई न होने वाली आपदा बताते हैं। कुछ लोग इसकी समीक्षा और इसमें सुधार चाहते हैं। कम संख्या में ही सही, कुछ लोगों का मानना है कि इसे पूरी तरह हटा लेना चाहिए क्योंकि यह कारगर नहीं है। मगर सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) का कहना है कि राज्य में चुनाव हो या नहीं हो, शराबबंदी नीति वापस नहीं ली जाएगी। इस साल अक्टूबर और नवंबर में राज्य में चुनाव होने हैं।

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य सभा सदस्य संजय झा ने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के सोल से फोन पर बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें पता है कि इससे किस तरह बिहार की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। इसका असर भले ही पटना अथवा दिल्ली में नहीं दिखता हो मगर बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं पर होने वाली हिंसा में भारी कमी आई है। हां, इस नीति के कारण राजस्व को भले झटका लगा है, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या सरकार जनता का जीवन बेहतर बनाने के लिए नहीं होती है।' संजय झा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए सोल में थे। उन्होंने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान नीतीश ने बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की है। हम उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे।

हालांकि, प्रदेश सरकार के घटक दल उतने आशावादी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के आरा से सांसद रहे आरके सिंह ने कुछ हफ्ते पहले भोजपुर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान पार्टी लाइन से अलग हटकर शराबबंदी के नीतीश के फैसले की गहन समीक्षा करने का आह्वान किया था। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद 2,000 लोगों की मौत का इसे ही प्रमुख कारण माना जा रहा है।

सिंह ने कहा, 'बिहार में शराबबंदी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी। इसलिए इसे सही तरीके से खत्म करना ही सही रहेगा।' उन्होंने कहा, 'सच्चाई यही है कि शराबबंदी महज कागजों पर है। अगर अच्छा प्रबंधन किया जाता तो बिहार में शराबबंदी सफल होती। अवैध शराब की बिक्री में लोगों का एक बड़ा वर्ग संलिप्त है।'

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रह चुके सिंह ने स्पष्ट रूप से यह कहने से गुरेज किया कि बिहार में शराबबंदी लागू करने की प्रशासनिक क्षमता का अभाव है। उनकी पार्टी ने प्रत्यक्ष तौर पर उनका विरोध नहीं किया, इसकी जगह उसने शराबबंदी नीति की समीक्षा की मांग कर रहे विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं पर पहले शराब के व्यापार में निवेश की ओर इशारा करते हुए निशाना साधा। साल 2016 में लागू की गई शराबबंदी नीति को तब बिहार में दोनों दलों का समर्थन मिला था। उस वक्त, जदयू-राजद की गठबंधन सरकार थी और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था। वह इस बात पर सहमत हुए थे कि शराबबंदी लागू होने से राज्य की महिलाओं की घरेलू आय बढ़ेगी और शराब के कारण होने वाली घरेलू हिंसा को भी कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, तब विपक्ष में रही भाजपा के पास इसका विरोध करने का कोई खास कारण नहीं था, जब तक कि अवैध शराब के कारण राज्य भर में सैकड़ों लोगों की मौत होने की खबरें सामने नहीं आई थीं।

सबसे भयानक घटना साल 2022 में छपरा (सारण) में हुई थी, जब 80 फीसदी मिथाइल अल्कोहल और उद्योग में उपयोग होने वाली स्पिरिट से बनी शराब पीने से 65 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के गवाह रहे एक आईएएस अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने के लिए जगह नहीं थी। अस्पताल परिसर में केवल पीड़ित परिवारों की चीख-पुकार गूंज रही थी। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ लोग तो अस्पताल तक नहीं पहुंच सके और गांव में ही दम तोड़ दिया। तब भाजपा ने तथाकथित शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी।'

हालांकि, तब से जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों की खबरें बीच-बीच में आती रही हैं। पिछले साल अक्टूबर में दीवाली के आसपास सिवान और सारण जिले में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है शराबबंदी पर राजनीतिक दलों का रुख बदल रहा है। पिछले हफ्ते बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने पर्यटन और राज्य के होटल उद्योग में जान फूंकने के लिए शराबबंदी नीति में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कोई भी फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में ही लिया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर चुनाव के बाद राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वह ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटा देंगे और इसे का उद्योग का दर्जा देंगे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) ने भी इसका समर्थन किया है।

इन परिवर्तनों का कारण भी पूरी तरह साफ है। पासी और मुसहर जैसे दलित समुदायों के लिए महुआ के फूलों से देसी शराब बनाना और ताड़ी निकालना लंबे अरसे से आजीविका का स्रोत रहा है। मगर यह बात भी पूरी तरह साफ है कि अवैध शराब जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा शराबबंदी से बिहार के राजस्व को काफी नुकसान हुआ है, इससे भी कोई आनाकानी नहीं कर सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने साल 2018 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साल 2016-17 में मुख्य तौर पर शराबबंदी से राज्य के राजस्व में 1,490 करोड़ रुपये की गिरावट आई। इस बीच, इस नीति को लागू करने की लागत के कारण राज्य के आबकारी विभाग का खर्च उस साल करीब दोगुना हो गया था। यह साल 2015-16 के 49 करोड़ रुपये से बढ़कर 91 करोड़ रुपये हो गया।

शराबबंदी के कारण बिहार में प्रत्यक्ष निवेश पर भी असर पड़ा है। साल 2005 में सत्तासीन होने वाले नीतीश ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के वास्ते शराब व्यापार को उदार बनाने का वादा किया था। नतीजतन, आबकारी प्राप्तियों में आठ गुना वृद्धि हुई और यह 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये हो गया। ब्रिटेन के उद्योगपति और कोबरा बियर के मालिक करण बिलिमोरिया ने बिहटा में एक डिस्टिलरी स्थापित की और राज्य में जौ उत्पादन को सहारा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय बियर ब्रांड मोल्सन कूर्स के साथ साझेदारी में बिहार में 10 और इकाइयां स्थापित करने की योजना का भी ऐलान किया था। उनके करीबी सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि साल 2016 के बाद राज्य सरकार ने उनके बिहटा संयंत्र को फलों के रस का उत्पादन करने की भी मंजूरी नहीं दी।

सासाराम के पास कोनार में, जहां 2013 में शराबबंदी की मुहिम ने सबसे पहले जोर पकड़ा था, बहुत कम बदलाव हुआ है। गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक, शराब की लत एक गंभीर चिंता बनी हुई है, खासकर महिलाओं के लिए। प्रशांत किशोर जैसी राजनीतिक हस्तियों ने कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आ जाती है तो शराबबंदी को एक घंटे के भीतर खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इसे लागू करना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

बिहार में शराबबंदी कानून काफी सख्त है। इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर पूरे परिवार को जेल जाना पड़ सकता है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2016 से अगस्त 2024 के दौरान इससे जुड़े 8.43 लाख मामले दर्ज किए गए और 12.79 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया।

हालांकि, इन अपुष्ट खबरों के बीच कि शराब की कुछ श्रेणियों के लिए नीति की समीक्षा की जा सकती है संजय झा ने जोर देकर कहा कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। फिर भी चुनाव अभियान के दौरान शराबबंदी एक बार फिर प्रमुख मुद्दे के तौर पर उभर सकती है।

आपका पक्ष

जलवायु परिवर्तन: अगले पांच वर्षों में बढ़ती चुनौती

हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर हम यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि धरती और पर्यावरण की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 से 2029 के बीच पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक युग (1850-1900) से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की 70 फीसदी संभावना है। यह सीमा इसलिए महत्त्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते में तय किया गया था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को इसी स्तर तक सीमित रखा जाए। 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल माना गया है और अगले पांच वर्षों में किसी एक साल का तापमान इससे भी अधिक होने की 80 फीसदी संभावना है। इन पांच वर्षों में औसत तापमान 1.2 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की आशंका है, जिससे बाढ़, सूखा और जंगलों में आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं और भी अधिक गंभीर होंगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना होगा। सौर और पवन ऊर्जा को प्राथमिकता देनी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना होगा। वनों की रक्षा करने के साथ पेड़ भी लगाने होंगे। कम कार्बन उत्सर्जन वाली नीतियां बनानी होंगी।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना होगा

आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की जरूरत

1990 के दशक में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं लगभग समान आकार की थीं, यहां तक कि चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम थी। दोनों देश वैश्विक रैंकिंग में 140वें से 145वें स्थान के बीच थे। चीन ने 1978 में आर्थिक सुधार शुरू किए, लेकिन 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों के बाद ही उनकी गति तेज हुई। आज ये दोनों एशियाई दिग्गज वैश्विक अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर खड़े हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका आकार 19 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत हाल ही में 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले तीन दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था 11.5 गुना बढ़ी है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 51 गुना बढ़ी है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर आया है। 1990 में समान प्रति व्यक्ति आय (360 डॉलर) की तुलना में, 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,700 डॉलर है, जबकि चीन की 13,000 डॉलर है। यह अंतर चीन की लगातार कई साल तक 10 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर का परिणाम है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत अब 'मध्यम आय वर्ग' में है, जबकि चीन 'उच्च आय देश' बनने के करीब है। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित देश बनना है जिसके लिए अगले दो दशकों तक करीब 7.8 फीसदी की निरंतर डॉलर-आधारित वृद्धि आवश्यक होगी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के 40 फीसदी तक निवेश बढ़ाना, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ना और अनुसंधान व विकास में निवेश महत्त्वपूर्ण होगा। छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने से रोजगार, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

राजूराम प्रजापत, नागौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

मणिपुर के इंफाल में बुधवार को बाढ़ के कारण लोग अपने घरों से सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर आए। राज्य में विगत दिनों भारी बारिश के कारण 56,000 लोग प्रभावित हुए और करीब 174 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय संस्करण, गुरुवार, 5 जून, 2025 dainikbhaskar.com 8

पर्यावरण प्रदूषण का असर धरती सहित हमारे शरीर और मन पर भी दिखने लगा है। हम नहीं संभले, तो जद्दोजहद बढ़ती जाएगी... पढ़िए खास रिपोर्ट

क्लाइमेट चेंज ऐसे प्रभावित कर रहा है

2050 : शहरों के 2.4 अरब लोग जल संकट झेलेंगे, एक अरब पलायन को मजबूर होंगे

बीमारी, कुपोषण और मानसिक तनाव जैसे कई रूपों में जलवायु परिवर्तन का संकट हमारे सामने आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य रिपोर्ट के तथ्य और उपाय भविष्य की तस्वीर भी दिखाते हैं और उसे बेहतर बनाने का रास्ता भी।

2040 तक हर चार में से एक बच्चे पर जल संकट

2040 तक हर चार में से एक बच्चा जल संकट वाले क्षेत्र में रहेगा। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बल्कि पोषण और शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों से भी बच्चे वंचित रह सकते हैं। 2050 तक 2.4 करोड़ और बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने जैसे कारणों से दुनिया में 1.2 अरब लोग 2050 तक पलायन को मजबूर हो सकते हैं।

भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.9 टन है। शहरों में यह तेजी से बढ़ रहा है। एसी का तापमान 24-26° रखें तो 20% ऊर्जा की बचत होगी, जो उत्सर्जन कम करने में सहायक होगा।

नीलगिरि, नष्ट हो रहा है पर्यावरण

समय रहते अलर्ट नहीं हुए तो धरती के रंग ऐसे ही फीके पड़ने लगेंगे...

दक्षिण भारत के नीलगिरि क्षेत्र में चाय की औद्योगिक खेती ने 70% मूल घासभूमियों, वनों को नष्ट कर दिया है। इससे जैव विविधता में गिरावट आई है। इससे वन्यजीवों के साथ टकराव बढ़ा है। प्राकृतिक आवास सिमट रहे हैं। भूस्खलन, सूखा क्षेत्र को और संवेदनशील बना रहे हैं। समय रहते हम पर्यावरण के प्रति अलर्ट नहीं हुए तो धरती के रंग इस तस्वीर की तरह फीके पड़ने लगेंगे।

2050 तक देश के 30 शहरों पर गंभीर समस्या

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि भारत जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित होगा। दुनिया में 2050 तक शहरी जल संकट झेलने वाली जनसंख्या 93.3 करोड़ से बढ़कर 170-240 करोड़ तक जा सकती है। भारत के 30 शहर 2050 तक 'गंभीर जल संकट' श्रेणी में आ जाएंगे। शहरीकरण व जल स्रोतों के अति-दोहन ने संकट को और गहरा कर दिया है।

पेड़ लगाइए। क्योंकि एक परिपक्व पेड़ सालाना 15-30 हजार ली. पानी जमीन में पहुंचाता है। अगर घर में नल से पानी टपकता है तो उसे रोकें। एक टपकता नल रोज 20-30 लीटर पानी बहाता है।

2040 तक मलेरिया की चपेट में होंगे 5 अरब लोग

जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छरजनित रोग पहाड़ों और ठंडे इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। बाढ़ जैसी आपदाएं पानी से होने वाली बीमारियों को फैलने का मौका दे रही हैं। डेंगू, चिकनगुनिया के मामलों में 20% वृद्धि की आशंका है। 2040 तक मलेरिया 5 अरब लोगों तक पहुंच सकता है। जंगलों की कटाई और मानव-वन्यजीव संपर्क बढ़ने से खतरा बढ़ रहा है।

पर्यावरण को बचाने के लिए छत-बालकनी में गमले लगाएं। 10 छोटे पौधे भी घर के अंदर की हवा को साफ कर सकते हैं। पक्षियों के लिए पानी, दाना रखें -स्थानीय पारिस्थितिकी को बचाएं।

'क्लाइमेट एंग्जायटी' पर खर्च होंगे 4 लाख करोड़

बाढ़, आग, तूफान मन पर गहरा असर डाल रहे हैं। लोग अपने घर, रोजगार और पहचान खो रहे हैं, जिससे डिप्रेशन और एंग्जायटी बढ़ रही हैं। खासकर युवा और किशोर पीढ़ी 'क्लाइमेट एंग्जायटी' से जूझ रही है- भविष्य को लेकर डर, बेचैनी और असहायता की भावना। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक जलवायु से जुड़ी मानसिक बीमारियों पर सालाना 3.9 लाख करोड़ खर्च हो सकते हैं।

एक अध्ययन के अनुसार 59% युवा मानते हैं कि भविष्य के प्रति उनका डर जलवायु परिवर्तन के कारण है। हफ्ते में 2 घंटे हरे वातावरण में बिताएं। तनाव 30% तक कम होता है।

सब्जियों में घट गई है पोषक तत्वों की मात्रा

बदलते पर्यावरण और खेती के तरीकों से खाद्य पदार्थ कम पौष्टिक हो रहे हैं। शोध में पाया गया है कि 43 सब्जियों में पोषक तत्वों की मात्रा घट गई है- जैसे हरी फलियों में कैल्शियम 65 से 37mg रह गया है। 2018 के अध्ययन में पाया गया कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ने से चावल में प्रोटीन, आयरन व जिंक की कमी पाई गई। इस तरह सब्जियां अब पहले से कम पौष्टिक रह गई हैं।

देश में हर साल 7.7 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है। ये यूके की सालाना खपत के बराबर है। बायोफोर्टिफाइड अनाज, आयरनयुक्त बाजरा या जिंक युक्त चावल और स्थानीय भोजन चुनें।

जंगल बचाएं

देश में 18 हजार हेक्टेयर जंगल नष्ट हुआ पिछले वर्ष

पढ़िए, जंगलों को कितना नुकसान हुआ है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है?

2.31 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण नष्ट हुआ है 2001-24 के बीच देशभर में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार।

▪ **2024 में ही 18 हजार हेक्टेयर जंगल कम हुआ है देशभर में। जंगल कम होने के कारणों में कटाई के साथ ही आग का भी खासा योगदान है।**

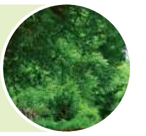

25 फीसदी भू-भाग पर जंगल या ट्री कवर है देश में यानी करीब 8 लाख वर्ग किमी क्षेत्र। देश में 2021 के बाद से अब तक 150 वर्ग किमी जंगल बढ़ा है।

नई पद्धतियों से लगाएं पौधे

ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वॉटर के मुताबिक 2050 तक जंगलों की कटाई व जलवायु परिवर्तन से भारत की जीडीपी को नुकसान की आशंका है। देश में 25 करोड़ लोग जीविका के लिए जंगलों पर आश्रित हैं। जंगल घटने से तापमान बढ़ रहा है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है। जंगल बढ़ाने के लिए मियावाकी जैसी पद्धतियों से पौधे लगाएं। इस पद्धति से एक वर्ग मीटर में 4-5 स्थानीय पौधे लगाए जाते हैं। ये कम समय में जंगल का रूप ले लेते हैं।

जल सहेजें

2030 में आपूर्ति से 40% ज्यादा रहेगी पानी की मांग

ग्लोबल वॉर्मिंग व प्रदूषण से 1900 से अब तक दुनियाभर के 20% जल स्रोत सूख गए हैं।

70 फीसदी सतही जल इंसानी उपयोग के लायक नहीं बचा है भारत की नदियों व झीलों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक।

▪ **40 फीसदी ज्यादा हो जाएगी दुनिया में ताजे पानी की मांग आपूर्ति की तुलना में 2030 तक। 40% ताजे जल के स्रोत गंभीर रूप से प्रदूषित हैं।**

470 से 600 करोड़ रुपए देश में जलजनित स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च होते हैं हर साल। पानी, स्वच्छता की कमी से हर साल 4 लाख लोगों की जान जाती हैं।

ग्रे वॉटर से बचाएं रोज 90 ली. पानी

भारत में पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की बड़ी संभावना है, खासकर ग्रे वॉटर यानी रसोई, बाथरूम और वॉशिंग मशीन से निकलने वाले हल्के गंदे पानी के जरिए। चार लोगों का एक परिवार रोज प्रति व्यक्ति करीब 90 लीटर ऐसा पानी नष्ट करता है, जिसे अगर शौचालय फ्लश जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाए, तो ताजे पानी की जरूरत 10 से 20% तक कम हो सकती है। भारत में हर साल करीब 47.67 अरब घन मीटर गंदा पानी बनता है, लेकिन बहुत थोड़ा हिस्सा दोबारा उपयोग में लिया जाता है।

हवा स्वच्छ बनाएं

हर साल 21 लाख मौतें वायु प्रदूषण से हो रहीं

देश की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। 2024 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के थे। वायु प्रदूषण से लोगों को कई गंभीर बीमारियां तक हो रही हैं। मेघालय का बायरनिहाट सर्वाधिक प्रभावित है।

21 लाख लोगों की मौत हो जाती है भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल। वायु प्रदूषण के मामले में भारत दुनिया में पांचवें नंबर पर है। पाकिस्तान तीसरे और चीन 13वें नंबर पर है।

2024 में दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 13 भारत के शहर थे। इन शहरों में दिल्ली, नोएडा, बायरनिहाट, गंगानगर, गुरुग्राम आदि शामिल थे।

▪ **जहरीली हवा से देश को हर साल करीब 95 अरब डॉलर का नुकसान होता है। इससे स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहा है।**

ये छोटे उपाय खतरे को 30% तक कम कर सकते हैं

2030 तक देश के 67 करोड़ लोग उच्च वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों के संपर्क में रहेंगे। अगर हम घरों में चिमनी का इस्तेमाल करते हैं तो फिल्टर जरूर लगाएं। बिजली बचाएं। वाहनों की नियमित सर्विस कराते रहें। घर से निकलने वाले कचरे को जलाएं नहीं। इन उपायों से आप वायु प्रदूषण के खतरों को 20 से 30 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं।

कंटेंट एक्सपर्ट- **डॉ. अनिल प्रकाश जोशी** पद्मभूषण से सम्मानित पर्यावरणविद् **सीमा जावेद,** पर्यावरणविद्

अभिव्यक्ति

प्रेरणा

हम बड़ी बातों और बड़े कामों से ही इस संसार में श्रेष्ठ बन सकते हैं। **-कन्फ्यूशियस,** दार्शनिक

संपादकीय

हमारे युवा फैनहुड और उन्माद में अंतर को समझें

आरसीबी की आईपीएल में जीत के जश्न के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में आए दर्शकों की भीड़ में भगदड़ के कारण अनेक लोग मारे गए और कई घायल हैं। इसके तत्काल बाद भाजपा का कांग्रेस सरकार पर आरोप शुरू हो गया, कुछ वैसे ही जैसे प्रयागराज कुम्भ की भगदड़ की खबरों के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार को लेकर किया था। तर्क वही थे। तर्क परोसने वाले बदल गए। भारत में आयोजनों में ज्यादा भीड़ आना सम्बंधित व्यक्ति या समारोह की सफलता मानी जाती है। कुम्भ में कितने लोग रोज नहाए, इसका एआई डेटा रिलीज किया जाता था यह बताते हुए कि सरकार कितनी सफल आयोजक है। जाहिर है इसी पैरामीटर पर बेंगलुरु हादसे के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे उन्माद के लिए उन लोगों की निंदा क्यों नहीं की जानी चाहिए, जो पेड़ों पर चढ़कर भी अपने आइकॉन को देखना चाहते थे और पुलिस की उतरने की अपील पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे? फिर सरकार और आईपीएल क्यों न इस उन्माद का अपने-अपने हिसाब से लाभ लें? लिहाजा समारोह में नेता चेहरा दिखाना चाहते थे और आईपीएल की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते था। युवाओं को सोचना होगा कि फैनहुड और उन्माद में अंतर होता है। इसे जान का जोखिम न बनाएं। जीवन देना है तो देशहित और समाज-कल्याण के लिए दें।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

मन पर कई आक्रमण हो रहे हैं, इनमें नया है नशे का

हमारे मन पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। विचारों का आक्रमण हो रहा है, कहीं क्रोध प्रहार कर रहा है, कहीं वासनाओं ने घेर रखा है। इन सबके साथ एक नया आक्रमण चला है और वो है नशे का। खासतौर पर शराब के नशे के दुष्परिणाम आ रहे हैं। मध्यप्रदेश में खंडवा के पास एक गांव में दुष्कर्म हुआ और अपराधियों ने इतना घृणित कुकृत्य किया कि उस नारी की आंतें तक निकाल लीं। दृश्य देखकर डॉक्टर भी व्यथित हो गए। बात ये सामने आई कि अपराधी शराब पीए हुए थे। अब तो चिंता पालनी चाहिए। भारत में शराब की खपत तीन गुना बढ़ गई है और हर साल बढ़ेगी। जानकार लोग कहते हैं आने वाले तीन साल में शराब की खपत 4% बढ़ने वाली है। चिंता इसलिए पालें कि हमारा देश युवा आबादी का देश है। विश्व में अनेक देश अपने लोगों को शराब से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जहां रज-रज, कण-कण में धर्म-संस्कृति बसी है, वहां वो ही लोग शराब को प्रश्रय दे रहे हैं, जिनके कंधे पर धर्म-अध्यात्म की डोली हमने छोड़ रखी है। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का परिदृश्य

विदेश में एकता लेकिन देश में मतभेदों का दृश्य क्यों है?

सियासत

राजदीप सरदेसाई

वरिष्ठ पत्रकार

rajdeepsardesai52@gmail.com

असदुद्दीन ओवैसी को 'राष्ट्रवादी' होने का प्रमाण-पत्र देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 87 घंटे लंबे सैन्य-अभियान की जरूरत पड़ी। इससे पहले कई सालों से उनकी राजनीति को 'राष्ट्र-विरोधी' बताकर बदनाम किया जा रहा था। अपनी अलग धार्मिक पहचान को शेरवानी की तरह पहनने के चलते वे उन लोगों की आंख में खटकते थे, जिनकी राजनीति भारतीय मुसलमानों के 'अन्यीकरण' के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन आज वही ओवैसी वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद पर भारत के स्टैंड को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए 'देशभक्त' के रूप में सम्मानित हो रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हैदराबाद के इस मुखर-सांसद की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान और उसके 'दो राष्ट्र' के सिद्धांत का विरोध किया है।

पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री शाह की हालिया टिप्पणियों को भी देखें, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 'वोट बैंक की राजनीति' करने का आरोप लगाया। जबकि अधिकांश विपक्षी दलों की तरह टीएमसी भी पाकिस्तान से युद्ध में सरकार का समर्थन करती रही है। जब शाह कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पूर्वी एशिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में पाकिस्तान के मिलिट्री-स्टेट के खिलाफ प्रखर भाषण दे रहे थे। लेकिन बंगाल में चुनाव होने में एक साल से भी कम समय है और यह भाषण चुनावी बिगुल बजाने के लिए था।

भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बदहाली पर भी नजर डालें। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पार्टी ने घोषणा की थी कि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करेगी। और इसके बावजूद जब शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हैं तो केरल के स्थानीय कांग्रेस नेता उन्हें भाजपा के 'सुपर-प्रवक्ता' के रूप में ब्रांड कर देते हैं। वाशिंगटन डीसी में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए थरूर ने इस आरोप का भी खंडन किया कि ट्रम्प ने भारत को युद्ध विराम के लिए सहमत होने पर मजबूर किया था। जबकि भोपाल में पार्टी की एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर व्हाइट हाउस के सामने 'सरेंडर' करने का आरोप लगा दिया। इस सबसे कांग्रेस की आतंरिक विचार-प्रक्रिया में निहित भ्रम ही खुलकर उजागर हुआ है।

ऐसे अंतर्विरोधों से भरे राजनीतिक माहौल को कैसे समझें, जो विदेशी धरती पर तो भारत के लिए मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन घर में एक-दूसरे पर बिना किसी सामंजस्य या शिष्टाचार के हमले करता है? ऐसी संस्थागत कमजोरी से लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल होता जा रहा है। संसद की संस्था का ही उदाहरण लें, जिसे पिछले एक दशक में सत्ताधारी पार्टी ने नोटिस-बोर्ड तक सीमित कर दिया है। सरकार के कानून निर्माताओं ने विपक्ष के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बातचीत करने की बहुत कम या बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। विधेयकों को जबरन पास कर किया जाता है, चर्चाओं को बीच में ही रोक दिया जाता है, विवादास्पद मुद्दों को खारिज कर दिया जाता है। जब चीनी घुसपैठ पर बहस की मांग की जाती है, तो उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तो प्रधानमंत्री उसमें शामिल ही नहीं होते। जब पहलगाम के बाद विशेष सत्र की मांग की जाती है, तो सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर देती है। इन तमाम बातों से लोकतंत्र ही कमजोर होता है।

ऐसे अंतर्विरोधों से भरे राजनीतिक माहौल को हम कैसे समझें, जो विदेशी धरती पर तो भारत के हितों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अपने ही घर में एक-दूसरे पर बिना किसी सामंजस्य या शिष्टाचार के हमले करता है?

इसमें मीडिया की भूमिका पर भी नजर रखी जानी चाहिए। जब मीडिया सरकार का प्रवक्ता बन जाता है, तो लोक-विमर्श समानतापूर्ण नहीं रह जाता। ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार से असुविधाजनक सवाल उठाने की बहुत कम या बिलकुल भी कोशिश नहीं की गई, जबकि नियमित रूप से राज्यसत्ता के प्रचार को बढ़ावा दिया गया। क्या यह आश्चर्य की बात है कि सीडीएस की स्वीकारोक्ति भी सिंगापुर में विदेशी मीडिया नेटवर्क के समक्ष थी, न कि घरेलू दर्शकों के सामने? आखिर जनता को जानने का अधिकार है, गलत सूचनाओं की अंधेरी सुरंग में रखे जाने का नहीं।

पुनश्च : सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक विपक्षी सांसद ने मुझसे चर्चा में बताया कि उन्हें अपनी साथी भाजपा सांसद 'अच्छी व्यक्ति' लगीं। उन्होंने कहा, 'संसद में तो वे द्वेषपूर्ण व्यवहार करती हैं, लेकिन फ्लाइट में उनसे बातें करके काफी अच्छा लगा!' शायद इस तरह की कुछ और सर्वदलीय-मुलाकातें पक्ष-विपक्ष के बीच जमी बर्फ को पिघलाने में मदद कर सकती हैं!

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

मुद्दा • तिब्बत में मानवाधिकारों और पर्यावरण का हनन

'दुनिया की छत' पर चीन की हरकतें सबके लिए खतरनाक

विस्तारवाद

ब्रह्मा चेलानी

पॉलिसी फॉर सेंटर रिसर्च के प्रोफेसर एमेरिटस

तिब्बत के पठार पर विशाल ग्लेशियल-रिजर्व्स हैं, जो दुनिया में ताजे पानी के सबसे बड़े भंडारों में से एक हैं। यह दस प्रमुख एशियाई नदी-प्रणालियों का उद्गम भी है- जिनमें चीन की येलो और यांग्त्से, दक्षिण-पूर्व एशिया की मेकांग, साल्विन और इरावदी और भारत की सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल हैं। ये वैश्विक आबादी के लगभग 20% हिस्से को पानी की आपूर्ति करती हैं। लेकिन आज यही पठार एक आसन्न पर्यावरणीय संकट का साक्षी बन रहा है, जो पूरे एशियाई महाद्वीप की जल सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन और भू-राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

पिछले दो दशकों से चीन तिब्बती पठार पर केंद्रित एक आक्रामक बांध निर्माण अभियान में लगा हुआ है। चीन की सरकार ने इसके निचले हिस्से के किसी भी देश के साथ जल-साझाकरण संधि पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इससे इन देशों को चीन की सनक के परिणाम भुगतने होंगे। पठार की सीमा के पास चीन द्वारा निर्मित भीमकाय-बांधों ने पहले ही मेकांग नदी में पानी के स्तर को अभूतपूर्व रूप से कम कर दिया है, जिसका कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में मत्स्य-पालन और आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। जैसे-जैसे दक्षिणी वियतनाम में मेकांग डेल्टा पीछे हट रहा है, चावल के किसानों को पारंपरिक आजीविका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

फिर भी चीन की बांध बनाने की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। यांग्त्से नदी पर बना थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। लेकिन वह भी चीन द्वारा तिब्बती पठार के भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी (उसे वहां यारलुंग जंगबो कहा जाता है) पर बनाए जा रहे बांध के सामने बौना साबित होगा। अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है, तो इससे भारत और बांग्लादेश में पानी के प्रवाह में भारी बदलाव आएगा, क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को खतरा होगा और निचले इलाकों के देशों पर चीन का भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। पानी के हथियारीकरण का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, पानी तेजी से नया तेल बनता जा रहा है- यानी ऐसा रणनीतिक संसाधन, जो संघर्षों को बढ़ावा दे सकता है। देशों के भीतर और उनके बीच पानी के विवाद पहले ही तेज होते जा रहे हैं।

चीन की नजर तिब्बत की खनिज-समृद्ध भूमि- जिसमें लीथियम, सोना, तांबा जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं- पर भी है। वह वहां पर जंगलों की कटाई कर रहा है और विषाक्त उत्सर्जन में योगदान दे रहा है। उसकी ये तमाम गतिविधियां तिब्बती पठार के सैन्यीकरण के लिए कवर प्रदान कर रही हैं। चीन वहां पर जो विनाश-लीला कर रहा है, उसके पूरे ब्योरे जानना असंभव है। यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की नजरों से बहुत दूर है, और स्थानीय तिब्बती समुदायों की आवाजों को दबा दिया जाता है। इस सबसे वहां का पारिस्थितिक तंत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है। तिब्बती पठार वैश्विक औसत से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है और उसकी बर्फ ध्रुवों की तुलना में तेजी से पिघल रही है।

इसके दूरगामी निहितार्थ हैं। तिब्बती पठार एशियाई जलवायु, मौसम और मानसून के पैटर्न को गहराई से प्रभावित करता है। इसका क्षरण सूखे और बाढ़ को बढ़ाएगा, जैव विविधता के नुकसान को बढ़ाएगा, कृषि के पतन में योगदान देगा और एशिया और उसके बाहर बड़े पैमाने पर पलायन को बढ़ावा देगा।

इन तमाम जोखिमों के बावजूद वैश्विक जलवायु मंचों से लेकर संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं तक- अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत को लेकर पूरी तरह से चुप है। इसका कारण अज्ञानता नहीं, बल्कि डर है। क्योंकि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल 'दुनिया की छत' पर अपनी गतिविधियों की सार्थक आलोचना को दबाने के लिए करता है। जबकि दुनिया के देशों को तिब्बती पठार पर चीन की गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता के लिए लगातार दबाव डालना चाहिए। विशेष रूप से, चीन को अपने रियल-टाइम हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए और उसे अपनी परियोजनाओं को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। स्वतंत्र पर्यावरण शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए पठार तक बेरोकटोक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

तिब्बत एशिया की पारिस्थितिक जीवनरेखा है। चीन को इसका ऐसे तरीके से दोहन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे पूरे महाद्वीप के लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए। चीन की मनमानी पर रोक लगानी जरूरी है।

चीन को तिब्बतियों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 2000 से लगभग दस लाख तिब्बतियों को अपनी पैतृक भूमि से जबरन विस्थापित किया गया है। पश्चिमी सरकारें और बहुपक्षीय संस्थाएं यहां अपना प्रभाव डाल सकती हैं।

(© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

https://t.me/AllNewsPapersPaid

कम पड़ना

भारत को ईवी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए

2 जून को भारत ने बेहतरी की ओर कदम बढ़ाया अपने परिष्कृत विद्युतीकरण ... में रियायती आयात शुल्क की पेशकश पूरी तरह से निर्मित इकाइयों पर 15%। यह ईवी निर्माता द्वारा भारत में स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए तीन वर्षों में कम से कम ₹4,150 करोड़ का निवेश करने पर निर्भर है, जिसमें तीन वर्षों में 25% का आधार घरेलू मूल्य वर्धन होगा, जो अन्य दो वर्षों में 50% तक बढ़ जाएगा। मार्च 2024 में घोषित भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) के तहत अधिसूचना, पांच वर्षों के लिए प्रत्येक निर्माता के लिए सालाना अधिकतम 8,000 पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के आयात की अनुमति देती है। एसपीएमईपी-सीआई उन नीतियों के गुलदस्ते में जुड़ती है जो ईवी अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। हालांकि, ये नीतियां एक साथ मिलकर भारत की गतिशीलता को कार्बन मुक्त करने और बदलने की यात्रा में एक दबाव वाले मुद्दे को संबोधित करने में कम पड़ती हैं भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और बनाने (FAME) योजना के लिए पांच वर्षों तक 895 करोड़ रुपये का परिव्यय 2019 में बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गया। चीन ने 2009 में अपने महत्वाकांक्षी न्यू एनर्जी व्हीकल सब्सिडी कार्यक्रम की घोषणा की, जिसने 2022 तक ईवी के अनिवार्य संयुक्त उद्यम निर्माण के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम किया। इसके अलावा, ईवी पर कम आयात शुल्क (2010 में 25% से 2018 में 15%), और पिछले 15 वर्षों में लगभग 230 बिलियन डॉलर का संचयी प्रोत्साहन - किसी भी देश द्वारा सबसे अधिक - ने चीन को उच्चतम वैश्विक ईवी अपनाने की दर हासिल करने में सक्षम बनाया।

अमेरिका ने 2010 में अपने उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन विनिर्माण ऋण कार्यक्रम के लिए 25 बिलियन डॉलर के प्रारंभिक परिव्यय के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी।

बिडेन प्रशासन के उत्सर्जन न्यूनीकरण अधिनियम के तहत इसे काफी हद तक बढ़ाया गया था। लेकिन इसकी ईवी अपनाने की दर चीन की तुलना में बहुत कम है। 2024 में, 17 मिलियन वैश्विक ईवी कार की बिक्री में से, अकेले चीन में 11.3 मिलियन की हिस्सेदारी होगी, इसके बाद यूरोप में 3.2 मिलियन, अमेरिका में 1.5 मिलियन और शेष दुनिया में शेष की हिस्सेदारी होगी। खनन, प्रसंस्करण से लेकर संयोजन तक बैटरी निर्माण के चीन के ऊर्ध्वाधर एकीकरण ने पारंपरिक ICE वाहनों के मुकाबले EV के प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में सहायता की है। अभी के लिए, भारत जिस 25% DVA को अभी घोषित योजना के तहत लक्ष्य कर सकता है, वह ICE वाहनों के लिए स्थानीय रूप से निर्मित ऑटो घटकों को EV में बदलना और इसे सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस के साथ जोड़ना होगा। लेकिन ई.वी. के हृदय-स्थल - इसकी बैटरी - के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए भारत को स्थानीय स्तर पर आई.सी.ई. विनिर्माण के लिए अपना दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसके तहत स्थानीय आई.सी.ई. या ई.वी. निर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना अनिवार्य किया जाएगा, तथा धीरे-धीरे पूर्ण रूप से खुले बाजार की अनुमति दी जाएगी।

आखिर कार

आईपीएल जीत में आरसीबी ने पुराने भूतों और हालिया मीम्स को शांत कर दिया

आरआईपीएल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेला इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के उद्घाटन 18 अप्रैल 2008 को यूरल गेम। यह एक ऐसी रात थी, जो हालांकि, प्रतिद्वंद्वी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए थी, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम के नाबाद 158 रन ने मैच को मेजबान के पीछे एम। चिन्नास्वामी स्टेडियम में काफी दूर तक पहुंचा दिया था। बाद के संस्करणों में, एक बहुत ही वफादार प्रशंसक आधार वाली फ्रैंचाइज़ी ने बहुत कुछ वादा किया, बहुत कम दिया और दिखाने के लिए तीन रनर-अप फिनिश थे। अंत में, अतीत के भूतों को आराम दिया गया जब रजत पाटीदार के लोगों ने मंगलवार रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स पर छह रन की जीत के साथ खिताब पर कब्जा कर लिया। आईपीएल के 18 वें संस्करण में आरसीबी की जीत भी विराट कोहली की दीर्घायु का एक श्रद्धांजलि थी। वह 2008 में टीम के पहले मैच से ही टीम के साथ हैं। अतीत में राहुल द्रविड़, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और रॉस टेलर जैसे सितारों वाली टीम में कोहली हमेशा से ही टीम की रीढ़ रहे हैं। युवा खिलाड़ी एक पितामह बन गए हैं और उन्होंने भारतीय टीम के साथ खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी न जीत पाना हमेशा उन्हें परेशान करता रहा। आखिरकार वह कमी दूर हो गई और जून की एक अवास्तविक रात में उनके अंदर जो राहत और खुशी थी, उसे देखकर कोई भी हैरान नहीं हुआ।

पाटीदार का भरोसा, कोहली का अनुभव, स्पिनर क्रुणाल पांड्या के दमदार स्पेल और जोश हेजलवुड की तेज गति, सभी ने अच्छा संयोजन किया, जबकि कई अन्य ने आरसीबी को नवीनतम आईपीएल के माध्यम से दौड़ में बनाए रखने के लिए कैमियो किया। भले ही कप मायावी साबित हुआ, पंजाब किंग्स ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, विशेष रूप से इसके कप्तान श्रेयस अय्यर; रोहित शर्मा और कोहली के उस प्रारूप को अलविदा कहने के बाद भारतीय वनडे टीम में उनकी बड़ी भूमिका होगी। बाकी में, मुंबई इंडियंस ने ठंडी शुरुआत के बाद वापसी की और प्ले-ऑफ में जगह बनाई, जिसमें गुजरात टाइटन्स भी शामिल थे। यदि आईपीएल आरसीबी के मोचन गीत और पंजाब किंग्स के चुटकुलों के बारे में था, तो समान रूप से, इसने एक पुरानी टीम, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पतन को भी प्रतिबिंबित किया, 22 मार्च को शुरू होने के बाद, आईपीएल काफ़ी लंबा खिंच गया और पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के कारण ब्रेक के कारण कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। आईपीएल ने युवा वैभव सूर्यवंशी और साई सुदर्शन जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी उजागर किया। एक खेल ब्रांड के रूप में, लीग दुर्जेय है, लेकिन जैसा कि कोहली ने कहा, टेस्ट गुणवत्ता में पाँच स्तर ऊपर हैं और उम्मीद है कि आधुनिक खिलाड़ी इस वास्तविकता का सम्मान करेंगे।

बेहतर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक्सपोसोमिक्स

Dr. Kalpana Balakrishnan

डीन (अनुसंधान) हैं, श्री रामचन्द्र उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षा और अनुसंधान (एसआरआईएचईआर), चेन्नई

टी 2025 (5 जून) में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। माइक्रो-प्लास्टिक उन हज़ारों रासायनिक, भौतिक और जैविक खतरों में से एक है जो हवा, पानी और रहने की जगहों में छिपे हुए हैं, जिनके लिए हमारे पास न तो संवेदी क्षमताएँ हैं और न ही जोखिम को मापने और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए संवेदन तकनीकें हैं। इस प्रकार, पर्यावरणीय रोग के बोझ को कम करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक कठिन चुनौती बनी हुई है।

भारत में, तेज़ आर्थिक विकास पर्यावरणीय जोखिमों के पैमाने और जटिलता को बढ़ा रहा है और रहने के वातावरण और जीवन शैली के बीच अंतर-निर्भरता को बढ़ा रहा है। भारत में पहले से ही वैश्विक पर्यावरणीय रोग भार का लगभग 25% हिस्सा है, इसलिए पर्यावरण प्रबंधन के लिए नए प्रतिमान विकसित करने की आवश्यकता है जो एकीकृत स्वास्थ्य जोखिम आकलन पर आधारित हों।

इनमें सभी पर्यावरणीय कारक शामिल होने चाहिए रोग विकास के अध्ययन में। पर्यावरण या स्वास्थ्य संकेतकों पर हमारे वर्तमान ढाँचे को परिभाषित करने वाले टुकड़ों-टुकड़ों के दृष्टिकोण पर्यावरणीय स्वास्थ्य असमानताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और स्वास्थ्य लागतों में वृद्धि करने की संभावना रखते हैं। हमें जीवन भर बीमारी के कारणों की पूरी तस्वीर प्राप्त करने और समग्र रोकथाम रणनीतियों को विकसित करने के लिए "एक्सपोज़ोमिक्स" के क्षेत्र में नए और अत्याधुनिक वैज्ञानिक विकास को अपनाना चाहिए। दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य निगरानी में रणनीतिक निवेश जो डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान प्लेटफ़ॉर्म के साथ नए पर्यावरणीय और जैव निगरानी प्रयासों को एकीकृत करता है, महत्वपूर्ण है।

पर्यावरणीय रोग भार विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2000 में पर्यावरणीय रोग भार का अनुमान लगाना शुरू किया, जो वैश्विक रोग, चोटों और जोखिम कारक (GBD) अध्ययन में अपनाए जा रहे आधुनिक अनुमान दृष्टिकोण का आधार है। GBD का प्रत्येक चक्र सबसे अधिक जिम्मेदार स्वास्थ्य भार वाले जोखिम कारकों की पहचान करता है। नवीनतम चक्र (2021) में जिसमें 88 जोखिम कारक शामिल थे, GBD में पर्यावरणीय और व्यावसायिक (OEH) जोखिम कारक वैश्विक मृत्यु के 18.9% (12.8 मिलियन) और सभी विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (DALYs) के 14.4% के लिए जिम्मेदार थे, जिसका नेतृत्व परिवेशी PM2.5 वायु प्रदूषण (4.2% DALYs, 4.7 मिलियन मृत्यु) और खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के उपयोग से घरेलू वायु प्रदूषण (3.9% DALYs, 3.1 मिलियन मृत्यु) ने किया।

भारत में, लगभग तीन मिलियन मौतें और 100 मिलियन मौतें व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य (OEH) जोखिमों के कारण होती हैं। भारत में OEH जोखिम कारकों का अनुमान है कि वे गैर-संचारी रोगों के लिए जिम्मेदार बोझ के 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें इस्केमिक हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज, लंग कैंसर, अस्थमा और हाल ही में, मधुमेह और क्रॉनिक किडनी रोग शामिल हैं। सीसा जोखिम जैसे जोखिम कारक वी.ई. से कम उम्र के बच्चों के लिए गंभीर विकासात्मक स्वास्थ्य प्रभाव डाल सकते हैं, भारत में वी.ई. से कम उम्र के बच्चों में वैश्विक स्तर पर खोए गए कुल अनुमानित IQ अंकों का 154 मिलियन या 20% हिस्सा है।

हम क्या चूक रहे हैं? जी.बी.डी. के परिणाम बताते हैं

स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और बेहतर स्वच्छता के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए सबूतों का एक मजबूत और ठोस निकाय। हालाँकि, बीमारी का वर्तमान पर्यावरणीय बोझ पर्यावरणीय जोखिम कारकों की केवल सीमित संख्या (लगभग 11) श्रेणियों को संबोधित करता है क्योंकि मानव जोखिम डेटा की कमी है। कई पर्यावरणीय जोखिम कारक जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बोझ में योगदान कर सकते हैं, वर्तमान में जीबीडी में शामिल नहीं हैं।

इनमें विभिन्न रासायनिक जोखिम, सूक्ष्म प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट जैसे जटिल मिश्रणों से होने वाले जोखिम तथा पर्यावरणीय शोर जैसे भौतिक खतरे शामिल हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरणीय जोखिम कारक चयापचय (उच्च रक्तचाप या उपवास के दौरान उच्च प्लाज्मा ग्लूकोज) और व्यवहारिक जोखिम कारकों (धूम्रपान और अस्वास्थ्यकर आहार) के साथ-साथ अंतर्निहित आनुवंशिक संवेदनशीलता और स्वास्थ्य निर्धारकों (जैसे सामाजिक-आर्थिक स्थिति) के साथ जटिल तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, जिससे आबादी के भीतर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

जोखिम अनुमान अक्सर एकल जोखिम कारकों के लिए निकाले जाते हैं; जबकि दीर्घकालिक कोहोर्ट अध्ययनों में अक्सर भ्रम को अच्छी तरह से समायोजित किया जाता है, लेकिन जीवन काल में जटिल मिश्रण और अंतःक्रियाओं का पर्याप्त रूप से अन्वेषण नहीं किया गया है।

अंत में, जलवायु परिवर्तन कई पर्यावरणीय जोखिम कारकों, जैसे गर्मी, वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित रोग, तूफान और बाढ़, और जंगलों द्वारा उत्पन्न खतरों को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन फसल की पैदावार को कम कर सकता है, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता को कम कर सकता है, खाद्य सुरक्षा को बाधित कर सकता है और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है।

अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य परिणाम, जो पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं और जलवायु-संवेदनशील पर्यावरणीय जोखिम कारकों जैसे कि सूक्ष्म कण पदार्थ के प्रत्यक्ष स्वास्थ्य प्रभावों दोनों से प्रेरित हैं, पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। इनमें से कई जोखिम कारक एक साथ हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मिश्रित घटनाएँ और सहक्रियात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ये खतरे स्वास्थ्य प्रणालियों या स्वस्थ खाद्य प्रणालियों तक अपर्याप्त पहुँच वाली आबादी के बीच स्वास्थ्य प्रभावों को और बढ़ा सकते हैं। वैश्विक रोग मूल्यांकन में इन महत्वपूर्ण जोखिम कारकों को शामिल करने के लिए अभी तक तरीके और डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

इस प्रकार, रोगों के पर्यावरणीय बोझ के वर्तमान अनुमान न केवल रूढ़िवादी रूप से कम आंके गए हैं, बल्कि समग्र, मापनीय निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों को विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धी जोखिम कारकों के विरुद्ध प्राथमिकता देने का पर्याप्त साधन भी प्रदान नहीं करते हैं।

मानव एक्सपोज़ोम वैश्विक मानव जीनोम परियोजना (1990-2003) ने रोग की आनुवंशिक उत्पत्ति का पता लगाने की हमारी क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव किया। हालाँकि, इसने कई सामान्य बीमारियों के लिए व्यक्तिगत आनुवंशिक भिन्नता की सीमित भविष्यवाणी शक्ति को भी उजागर किया। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक कारक हृदय रोग के जोखिम के आधे से भी कम में योगदान करते हैं, जो मृत्यु दर का एक प्रमुख स्रोत है।

मानव जीनोम के मानचित्रण में सफलता ने "एक्सपोज़ोम" की पूरक अवधारणा को बढ़ावा दिया है। एक्सपोज़ोम को किसी व्यक्ति के सभी एक्सपोज़र के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है।

जीवन भर में जोखिम कितना होता है और उन जोखिमों का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। पारंपरिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य अध्ययनों में परिकल्पना-संचालित विधियाँ शामिल हैं, जो कुछ समय बिंदुओं पर एक या एक वर्ग के पर्यावरणीय जोखिमों पर केंद्रित हैं। ये मानव स्वास्थ्य पर जीवन भर के जोखिमों के जटिल प्रभावों को समझने में विफल रहते हैं।

एक्सपोसोमिक्स का उद्देश्य यह समझकर इस अंतर को पाटना है कि भौतिक, रासायनिक, जैविक और मनो-सामाजिक वातावरण से बाहरी जोखिम किस तरह आहार और जीवनशैली तथा आनुवंशिकी, शरीर विज्ञान और एपिजेनेटिक्स जैसी आंतरिक व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य या बीमारी पैदा करते हैं। इससे एक्सपोज़र वाइड एसोसिएशन (EWAS) का एटलस तैयार करने की अनुमति मिलेगी जो जीनोम-वाइड एसोसिएशन (GWAS) को पूरक बनाएगा और स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभावों के खोज-आधारित विश्लेषण को सक्षम करेगा।

एक्सपोज़ोम के लिए कई अंतःविषयी प्रौद्योगिकियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसमें पहनने योग्य उपकरणों के साथ वास्तविक समय सेंसर आधारित व्यक्तिगत एक्सपोजर निगरानी; मानव जैव-निगरानी नमूनों पर अलक्षित रासायनिक विश्लेषण; मानव-प्रासंगिक सूक्ष्म-शारीरिक प्रणालियों (जिन्हें ऑर्गन्स-ऑन-ए-चिप के रूप में भी जाना जाता है) पर परीक्षण, जिसमें जैविक प्रतिक्रिया के यांत्रिक आधार को समझने के लिए इन विट्रो मॉडल मानव अंगों या ऊतकों की संरचना और कार्य को दोहराते हैं; और डेटा का विश्लेषण करने और साक्ष्य के एकीकृत टुकड़े उत्पन्न करने के लिए बड़ा डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शामिल हैं।

यह देखते हुए कि उत्पादन की क्षमता और संसाधन एक्सपोज़ोमिक डेटा व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, एक्सपोज़ोमिक ढांचे को वास्तविकता बनाने के लिए एक तत्काल आवश्यकता एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी है जिसमें सुसंगत डेटा पाया जा सकता है, उस तक पहुँचा जा सकता है, और निरंतर और अंतर-संचालन योग्य डेटा भंडारों के माध्यम से साझा किया जा सकता है।

स्वास्थ्य के भीतर मुख्यधारा का पर्यावरण एक्सपोसोम ढांचा भारत में अविश्वसनीय या अप्रासंगिक लग सकता है, जहाँ पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन, प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित दृष्टिकोणों की ओर छलांग लगाना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई नई बात नहीं है। एक्सपोसोमिक्स कई पुरानी बीमारियों के लिए अधिक सटीक पूर्वानुमान मॉडल तैयार करके और सटीक चिकित्सा को सक्षम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के भीतर मुख्यधारा के पर्यावरणीय जोखिमों के लिए अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करता है।

क्षमता निर्माण में बेलगाम निवेश और उपलब्ध विश्लेषणात्मक, पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को समन्वयित करने से हमारी आबादी की चिंताओं को अभूतपूर्व लागत-प्रभावशीलता के साथ संबोधित करने का वादा किया जाता है। भारतीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक्सपोज़ॉमिक्स के विज्ञान पर वैश्विक गति में शामिल होने और योगदान देने का समय आ गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस के भावी समारोह जल्द ही इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है कि क्यों मानव एक्सपोज़ोम परियोजना समग्र रोकथाम प्रयासों के लिए सबसे अच्छा नुस्खा हो सकती है जो स्वास्थ्य समानता को संरक्षित और बढ़ावा देती है।

> एक्सपोसोमिक्स के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास से रोग के कारणों की बेहतर तस्वीर प्राप्त करने और समग्र रोकथाम रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी

भारत में 'बायोहैप्पीनेस' के युग का लक्ष्य

डॉ. सौम्या स्वामीनाथन

एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं

डॉ. ई.डी. इज़राइल ओलिवर किंग

एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में जैव विविधता के निदेशक हैं

आर हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर, हम इसकी विविधता से आश्चर्यचकित थे आहार में हरी सब्जियाँ शामिल करें - सभी ताज़ी तोड़ी हुई जंगल और खेतों से। इसी तरह, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, बाजरा, सेम, फलियां, कंद, जंगली फल और हरी पत्तेदार सब्जियों की कई किस्में मिल सकती हैं, जिनके बारे में शहरी भारतीयों को शायद ही पता हो। राज्य में न्यिशी और अपातानी आदिवासी समुदाय इनमें से कई स्थानीय पौधों के पोषण और औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं।

हालांकि एक वरिष्ठ सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है पूर्वोत्तर भारत में कृषि जैव विविधता जिस तीव्र गति से लुप्त हो रही है, वह प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में वैश्विक वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है।

इन खाद्य पदार्थों के औषधीय और पोषण संबंधी गुणों के बारे में पारंपरिक ज्ञान, साथ ही आदिवासी समुदायों की पाक-पद्धतियां भी संभवतः उसी गति से विलुप्त हो रही हैं।

भारत की जैव विविधता भारत वैश्विक भूमि क्षेत्र का लगभग 2% कवर करता है, लेकिन वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा इसमें समाहित है। इसे दुनिया के 17 'मेगाडायवर्स' देशों में से एक माना जाता है; इसमें 36 वैश्विक जैव विविधता 'हॉटस्पॉट' में से चार खंड शामिल हैं; और यह वैश्विक खाद्य-फसल विविधता के केवल आठ केंद्रों में से एक है। भारत के विविध वनों से मिलने वाली प्राकृतिक सेवाओं का मूल्य प्रति वर्ष ₹130 ट्रिलियन से अधिक है, और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ ग्रामीण आबादी के विशाल बहुमत की आजीविका को बनाए रखती हैं।

हालाँकि, हमारी प्राकृतिक संपदा में निरंतर गिरावट आ रही है जैव विविधता और मानव कल्याण को बढ़ाने की इसकी क्षमता अभी भी काफी हद तक अज्ञात है।

वैश्विक खाद्य प्रणालियों में तीन फसलों का वर्चस्व है - चावल, गेहूं और मक्का - जो दुनिया की 50% से अधिक वनस्पति आधारित कैलोरी प्रदान करते हैं। जैव विविधता का यह संकेन्द्रण और नुकसान भारी कीमत पर आता है, जिससे पोषण असंतुलन और जलवायु झटकों के प्रति संवेदनशीलता पैदा होती है।

मधुमेह और मोटापे जैसी गैर-संचारी बीमारियाँ विश्व स्तर पर बढ़ रही हैं, और कृषि में तकनीकी प्रगति के बावजूद, जिससे उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी खाद्य प्रणालियों की लचीलापन खतरे में है।

लंबे समय से हम स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों की अनदेखी करते आए हैं। जैसे कि छोटे बाजरा, कुट्टू, ऐमारैंथ, कटहल, रतालू और कंद, तथा देशी फलियाँ जो लोकप्रिय व्यावसायिक फसलों के पक्ष में उपेक्षित और कम उपयोग वाली प्रजातियाँ (एनयूएस) के रूप में वर्गीकृत हैं। अनाथ फसलों के रूप में भी जानी जाने वाली एनयूएस को अब अवसर फसलों के रूप में संदर्भित किया जा रहा है क्योंकि वे पोषण से भरपूर, जलवायु-लचीली और स्थानीय वातावरण के अनुकूल हैं।

फसलें और समुदाय अनाथ (या अवसर) फसलें हमेशा स्थानीय पाक परंपराओं में अंतर्निहित रही हैं, जिन्हें अक्सर सांस्कृतिक पहचान और पारिस्थितिक ज्ञान से जोड़ा जाता है। कोल्ली हिल्स (तमिलनाडु के पूर्वी घाट) के समुदाय ने स्थानीय रूप से अनुकूलित बाजरा उगाना पसंद किया। तीन दशकों में, किसान नकदी फसलों जैसे कसावा, कोइ और काली मिर्च की खेती करने लगे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि जैव विविधता में गिरावट आई है। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) 20 से अधिक वर्षों से यहां कृषि समुदायों के साथ काम कर रहा है, ताकि भागीदारी अनुसंधान और किसान समूहों को सशक्त बनाने के माध्यम से क्षेत्र में बाजरा फसल विविधता के क्षरण को रोका जा सके। इन हस्तक्षेपों ने किसानों के एक समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं को पारंपरिक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने में सक्षम बनाया है

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित भारत की कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय बाजरा एवं श्री अन्न वर्ष योजना का ध्यान बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित था

उत्पादन और उत्पादकता, खपत, निर्यात, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, ब्रांडिंग, स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता पैदा करना आदि।

कई राज्यों के पास अपने स्वयं के बाजरा मिशन हैं। ओडिशा के कोरापुट जिले में, हमने बीज से लेकर उपभोग तक समुदाय-नेतृत्व वाले बाजरा पुनरुद्धार का समर्थन करने में ओडिशा बाजरा मिशन के साथ मिलकर काम किया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रागी, ज्वार और बाजरा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अगला कदम राज्य मिशनों का विस्तार करना होना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार के छोटे बाजरे को कवर किया जा सके और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया जा सके।

पाँच दशक से भी अधिक समय पहले, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक सदाबहार क्रांति की कल्पना की थी - जो रासायनिक तीव्रता में नहीं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन और पोषण सुरक्षा को बहाल करने में निहित है। भोजन का भविष्य विविधतापूर्ण और पौष्टिक है। इन भूले हुए खाद्य पदार्थों को वापस मेज पर लाना हमारी सांस्कृतिक पहचान और पारिस्थितिक ज्ञान को जलवायु संकट के मामले में सबसे आगे रखना है - लोगों, ग्रह और उसकी भावी पीढ़ी के लिए।

आज, विश्व भर में एक नया जैवविविधता विज्ञान उभर रहा है, जिसका भारत अपने मानव संसाधनों और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे के बल पर लाभ उठा सकता है ।

इसके अलावा, यह अंतःविषय विज्ञान हमें भारत की अद्वितीय जैव विविधता के सतत उपयोग, कृषि और खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य और पोषण, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन, जैव-अर्थव्यवस्था, तथा 1.4 बिलियन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की नौकरियां प्रदान करने में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा।

भारत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग में वैश्विक नेता बन सकता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य और मानव कल्याण हो सकता है। क्या हम “बायोहैप्पीनेस” के युग का लक्ष्य रख सकते हैं, जैसा कि एमएस ने दूरदर्शी रूप से कल्पना की थी

स्वामीनाथन?

> प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग
>
> संसाधनों का उपयोग - जिसमें
>
> भूले हुए खाद्य पदार्थों को वापस मेज पर
>
> लाना शामिल है -
>
> बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा

द टेटर्सटूदएडिटर

दृढ़ता का फल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की लंबे समय से प्रतीक्षित आईपीएल जीत सिर्फ़ क्रिकेट की जीत से कहीं बढ़कर है। यह दृढ़ता की एक सम्मोहक कहानी है, विश्वास और लचीलापन। डेढ़ दशक से भी ज़्यादा समय तक, आरसीबी ने उम्मीदों का बोझ उठाया, अक्सर अपने अभियान का अंत दिल टूटने और नज़दीकी हार के साथ किया। फिर भी, इसके बजाय आलोचना या संदेह के आगे झुकने के बावजूद, टीम ने संघर्ष जारी रखा। इसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता अक्सर समय लेती है, और यह उन लोगों को मिलती है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तत्काल परिणामों से ग्रस्त दुनिया में, आरसीबी की जीत हमें धैर्य, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास की शक्ति का मूल्य सिखाती है।

प्रशंसकों की ओर से भी उत्साह यह दर्शाता है कि खेल किस तरह लोगों को एकजुट कर सकते हैं, उन्हें उम्मीद और साझा खुशी दे सकते हैं, खासकर इन कठिन समय के दौरान। उम्मीद है कि यह जीत दृढ़ता की लड़ाई लड़ रहे सभी लोगों को प्रेरित करेगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद प्रशंसकों के लिए प्रार्थना।

पवित्रा एम., तिरुचि, तमिलनाडु

letters@thehindu.co.in पर ईमेल किए गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

संसद का विशेष सत्र क्यों ?

भारत के 16 विरोधी राजनैतिक दलों ने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को खत लिखकर पहलगाम जनसंहार की आतंकवादी घटना के बाद पैदा देश की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्षी दलों की इस मांग के पीछे जो मंशा है वह पहलगाम घटना के बाद भारत द्वारा चलाये गये सैनिक 'ऑपरेशन सिन्दूर' पर चर्चा करने की है। विपक्ष इस मामले में सरकार से कई तरह के सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के कितने लड़ाकू विमान गिरे। इसके साथ ही विगत छह मई को शुरू हुआ यह ऑपरेशन अचानक 10 मई को क्यों मुल्तवी कर दिया गया? इस सन्दर्भ में विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उस घोषणा को भी सवालिया घेरे में ले रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत व पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में अमेरिका की प्रमुख भूमिका रही है और उसी ने मध्यस्थता कराकर संघर्ष विराम कराया। हालांकि विदेश मन्त्रालय की तरफ से इसका जवाब दिया जा चुका है, जिसमें उसने कहा था कि ऑपरेशन को मुल्तवी करने या संघर्ष विराम में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही है और दोनों देशों के सैनिक कमांडरों के बीच हुई बातचीत के बाद संघर्ष विराम किया गया। ऐसा लगता है कि विपक्ष सरकार के इस मत से सहमत नहीं है क्योंकि विदेश मन्त्रालय के बयान के बाद भी कई बार श्री ट्रम्प ने अपने कथन को दोहराया है।

दूसरी तरफ प्रधानमन्त्री से लेकर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह घोषणा कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिन्दूर खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ स्थगित हुआ है और यह जारी है। इन हालात में अगर विपक्षी दल संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं तो इसमें राजनैतिक बढ़त प्राप्त करने की इच्छा छिपी हुई लगती है। स्वतन्त्र भारत में अभी तक सिर्फ एक बार 1962 में ही विपक्ष की मांग पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था जब चीन से भारत युद्ध हार गया था। इस सत्र को बुलाने की मांग तत्कालीन विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. जवाहर लाल नेहरू से मिलकर की थी। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तब जनसंघ के नेता स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसके अलावा अभी तक भारत की संसद के जितने भी कुल 13 विशेष सत्र बुलाये गये वे सरकारों के कहने पर ही बुलाये गये। असल में संसद का विशेष एक दिवसीय सत्र तो 14 व 15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को ही बुलाया गया था जिसमें अंग्रेजों के स्थान पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। उस समय विद्यमान संविधान सभा को ही अस्थायी लोकसभा में परिवर्तित कर दिया गया था। अत: स्वतन्त्र भारत की शुरूआत ही संसद के एक दिवसीय विशेष सत्र से हुई थी। परन्तु इसके बाद 1972, 77, 91, 92, 97, 2008, 12,15,17 व 2023 के विशेष सत्र सरकारों की तरफ से ही बुलाये गये।

> **इन हालात में अगर विपक्षी दल संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं तो इसमें राजनैतिक बढ़त प्राप्त करने की इच्छा छिपी हुई लगती है। स्वतन्त्र भारत में अभी तक सिर्फ एक बार 1962 में ही विपक्ष की मांग पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था जब चीन से भारत युद्ध हार गया था। इस सत्र को बुलाने की मांग तत्कालीन विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. जवाहर लाल नेहरू से मिलकर की थी। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तब जनसंघ के नेता स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।**

पिछले विशेष सत्रों में सबसे ताजा 2023 का पांच दिवसीय विशेष सत्र मोदी सरकार ने तब बुलाया था जब संसद के नये भवन का श्रीगणेश किया जाना था। इसी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था। 1962 को छोड़ कर जितने भी विशेष सत्र बुलाये गये वे सभी सत्ता पर काबिज सरकारों की तरफ से ही बुलाये गये। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 2008 का लोकसभा का जुलाई महीने में बुलाया गया दो दिवसीय सत्र था जिसमें अमेरिका से परमाणु करार के मुद्दे पर तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सदन का विश्वास मत प्राप्त किया था। इससे पूर्व 2017 में मोदी सरकार ने माल व वस्तु कर (जीएसटी) से सम्बन्धित विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया था। इससे पूर्व 2015 में मोदी सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती के अवसर पर दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। जबकि 2012 में मनमोहन सरकार ने भारतीय संसद के 60 साल पूरे होने पर रविवार को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। प्राय: ये विशेष सत्र सरकारों द्वारा भारतीय गणतन्त्र के उज्ज्वल पक्षों को लेकर ही बुलाये गये। अत: विपक्ष की मांग की तुलना 1962 के विशेष सत्र से नहीं की जा सकती क्योंकि उस समय भारत-चीन के युद्ध में भारत की पराजय हो रही थी और चीनी सेनाएं उस युद्ध के दौरान भारत के असम राज्य के तेजपुर शहर तक आ गई थीं।

जबकि वर्तमान में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिये हैं और वहां स्थित नौ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला है और 11 पाकिस्तानी सैनिक हवाई अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत इस ऑपरेशन सिन्दूर की मार्फत विजयी रहा है। इसी वजह से मोदी सरकार इस सत्र को बुलाये जाने पर सहमत नहीं दिखती है। पाकिस्तान के होश ठिकाने लाने के लिए उसने इस देश के साथ हुए सिन्धु नदी जल समझौते को भी ताक पर रख दिया है और चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान की ओर से अब भविष्य में भारत की भूमि पर कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होती है तो उसे लड़ाई का कृत्य समझा जायेगा। इसी से मोदी सरकार के पाकिस्तान के प्रति कड़े रुख को समझा जा सकता है। वैसे जिन 16 विपक्षी दलों ने सत्र बुलाये जाने की मांग पर हस्ताक्षर किये हैं उनमें देश के सबसे अनुभवी नेता व राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शरद पवार के दस्तखत नहीं हैं। श्री पवार नरसिम्हाराव सरकार के दौरान देश के रक्षामन्त्री भी रह चुके हैं और सैनिक मामलों पर उनकी पैनी पकड़ को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तो आगे बढ़कर यह तक कह दिया कि विशेष सत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।

भारतीय एकता का परचम

"सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पूरे विश्व में
भारतीय एकता का परचम फहराया है,
और आतंक के विरुद्ध पड़ोसी देश के रवैए से
विश्व के बाकी मूल्कों को अवगत कराया है,,
राजनीतिक मतभेद जहां कभी मनभेद नहीं बन पाया है,
भारतीय लोकतंत्र की इस अनुपम खूबसूरती से विश्व ने खुद को अचंभित पाया है...।।"

-गीता पाढा

शशि थरूर : इधर या उधर

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

ऑपरेशन सिंदूर अभी निलम्बित किया गया है पर उसे लेकर एक साइड स्टोरी शुरू हो गई है। अपना पक्ष रखने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए हैं। उनको लेकर राजनीतिक तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गई है। विशेष तौर पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर को एक महत्वपूर्ण डेलिगेशन का लीडर बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी सरकार और थरूर दोनों से खूब नाराज़ है। 1994 में पी. वी. नरसिम्हा राव ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मनावाधिकार सम्मेलन में भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा था ताकि यह संदेश जा सके कि सारा देश एकजुट है। इस बार वह समन्वय नहीं है। पर यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया हमें और पाकिस्तान को बराबर रख रही है। विदेशों में लिबरल वर्ग, सरकारों में, मीडिया में, थिंक टैंक में, उच्च शिक्षा संस्थानों में, जो कभी हमारे पक्ष में था,वह अब अलग भाषा बोल रहा है क्योंकि हमें अब अनुदार लोकतंत्र समझा जा रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प का अजब नकारात्मक रवैये परेशानी खड़ी कर रहा है।

जहां तक प्रतिनिधिमंडल का सवाल है, सरकार ने कांग्रेस पार्टी को तीन चार नामों का सुझाव दिया था। मंत्री किरण रिजीजू ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी पर कांग्रेस ने अपने चार अलग नाम भेज दिए अगर वह दुनिया को संदेश देना चाहती थी कि इस नाज़ुक घड़ी में सभी दल इकट्ठे हैं तो सरकार को कांग्रेस के नाम स्वीकार कर लेने चाहिए था, पर सरकार ने केवल आनंद शर्मा का नाम स्वीकार किया और अपनी तरफ़ से शशि थरूर, सलमान ख़ुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह को शामिल कर लिया। यह सभी कांग्रेस के नेता अनुभवी हैं और सही चुनाव है पर बेहतर होता कि पार्टी की अनुमति ली जाती। सरकार ने गलती की पर कांग्रेस को इस समय ख़ामोश रहना चाहिए था। वह श्रेय ले सकती थी कि अनुभवी और प्रतिभाशाली लोग उसी के पास हैं जबकि भाजपा में कमी है। आख़िर विदेश में जिन नेताओं ने अच्छी तरह से पक्ष रखा वह सब विपक्ष से हैं। पर जिस समय यह प्रतिनिधिमंडल विदेशी धरती पर थे कांग्रेस ने अपने ही लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कांग्रेस कुछ समय के लिए ख़ामोश रह सकती थी। पर राहुल गांधी की कांग्रेस तो बेधड़क आगे बढ़ जाती है। इतनी पुरानी पार्टी में परिपक्वता नहीं रही। इस बार नाराज़गी विशेष तौर पर एक नाम को लेकर अधिक लगती है, शशि थरूर।

देश में गांधी परिवार को छोड़ कर शशि थरूर कांग्रेस का सबसे अधिक जाना पहचाना नाम है। इन प्रतिनिधिमंडल को भेजने का कोई फ़ायदा हुआ भी या नहीं यह अलग बात है, क्योंकि किसी को भी कहीं कोई वरिष्ठ नेता नहीं मिला, पर यह मानना पड़ेगा कि आपरेशन सिंदूर पर देश का पक्ष शशि थरूर ने किसी भी भाजपा प्रवक्ता से बेहतर रखा। उनके सामने विदेश मंत्री एस.जयशंकर एक सख्त स्कूल टीचर नज़र आते हैं। और यही थरूर की समस्या है, उनका व्यक्तित्व। वह पढ़े-लिखें हैं, शायद अधिक पढ़े-लिखे हैं। अंग्रेज़ी पर उनकी विशेष महारत है, जो चर्चा का विषय रहता है। उनकी शैली बहुत नफ़ीस है, वह चार्मिंग है, अगर देखा जाए कि वह चार बार सांसद चुने जा चुके हैं तो उन्हें केवल कॉकटेल सर्कल का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। अपनी बात कहने की वह खूब क्षमता रखते हैं। कई किताबें लिख चुके हैं। युवाओं में लोकप्रिय हैं। उन्हें लेडीज मैन भी कहा जाता है पर इसमें उनका भी क़सूर नहीं अगर दूसरों को वह आकर्षक लगते हैं। महिलाओं से घिरे उनकी तस्वीरें अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं क्योंकि व्यक्तित्व आकर्षक है। आख़िर जीन्स का मामला है।

पर आज की राजनीति में ज़्यादा प्रतिभा कमजोरी भी हो सकती है क्योंकि कई लोग आपको अपने लिए ख़तरा समझने लगते हैं। यह बीमारी हर पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी के साथ शशि थरूर की दूरी का कारण भी यही है। वह अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं। उनकी लोकप्रियता अपनी पार्टी के कारण नहीं है। देश में उनकी अलग जगह है। कांग्रेस पर सत्तारूढ़ लोगों के साथ उनका झगड़ा तब शुरू हुआ जब अक्तूबर, 2022 में उन्होंने हाईकमान के नुमाइंदे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रधान पद का चुनाव लड़ा। खड़गे अच्छी तरह 7800 वोट लेकर जीत गए पर शशि थरूर को मिले 1000 वोट से हाईकमान चौकन्ना हो गया कि इस शक्स में चुनौती देने का दम है। उन्हें एक तरफ़ तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि तिरूवनंतपुर से लोकसभा चुनाव जीतना था पर शशि थरूर को उनके स्तर के बराबर भाव नहीं दिया गया। वह शिकायत करते हैं कि राहुल गांधी उनसे मिलते नहीं। यह शिकायत करने वाले वह अकेले नहीं हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा ने बताया था कि जब वह कांग्रेस में थे तो एक दिन राहुल गांधी को मिलने गए। उनसे बात करने की जगह राहुल अपने कुते को बिस्कुट खिलाते रहे। नाराज़ विस्वा सरमा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और अब उत्तर पूर्व में कांग्रेस की नाक में दम किया हुआ है। क्या शशि थरूर का भी रुख उधर की तरफ़ है?

विदेश की धरती पर शशि थरूर का बयान कि आपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लांघ गई 'जो पहले कभी नहीं हुआ था", विवाद का विषय रहा है। यह अनावश्यक टिप्पणी थी। मोदी सरकार को श्रेय देने के लिए पिछली सरकारों को लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह तथ्यात्मक भी ग़लत है। यह सही है कि मोदी सरकार वहां तक गई जहां पहले कोई सरकार नहीं गई थी पर यह ग़लत है कि पहली सरकारों ने नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। रिटायर्ड लै. जनरल डी.एस. हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि कम-से कम छह बार पहले पाकिस्तान के अंदर तक स्ट्राइक हो चुकी है। विशेषज्ञ अजय साहनी ने कहा है कि, "क्रास बार्डर पहले भी हुए हैं। कई बार हुए हैं। जब भी उस तरफ़ से हमला होता तो सेना टार्गेट हमला कर जवाब देती। केवल इसका प्रचार नहीं किया गया"। सैनिक अभियान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हैरानी है कि थरूर जैसा समझदार व्यक्ति ग़लत बह गया। जयराम रमेश की टिप्पणी, 'कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में ज़मीन आसमान का अंतर है', बता गई कि पार्टी के नेतृत्व की उनके बारे राय क्या है?

क्या शशि थरूर चाहते हैं कि पार्टी ही उन्हें निकाल दें ताकि विश्वासघात या अकृतज्ञता का आरोप न लगे? यह तो लगता ही है कि शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी सारी किश्तियां जला दी हैं। विदेश में मोदी सरकार की नीति का समर्थन और पिछली सरकारों, जिनमें वह खुद भी मंत्री रहे हैं, की परोक्ष निन्दा तो लक्ष्मण रेखा पार करने के बराबर है। आख़िर वह 69 वर्ष के हैं और कांग्रेस से उन्हें कुछ मिलने की कोई सम्भावना नहीं। तो क्या वह भी अगले ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने जा रहे हैं ? अगले साल केरल विधानसभा के चुनाव हैं। शशि थरूर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे पर इसकी कोई सम्भावना नहीं कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा का वहां सत्ता में आने का सवाल ही नहीं और थरूर लेफ्ट के साथ नहीं जाएंगे। अर्थात् उनके विकल्प भी सीमित हैं पर कांग्रेस के लिए भी समस्या है। वह केरल में सत्ता में आना चाहती है पर अगर शशि थरूर छोड़ जाते हैं तो बड़ा धक्का लगेगा। यह प्रभाव भी फैलेगा कि कांग्रेस प्रतिभाशाली लोगों को सम्भाल नहीं सकती, क्योंकि वह राहुल गांधी को चुनौती दे सकते हैं।

> **शशि थरूर को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी रही है। अपने राजनीतिक करियर को 69 की उम्र में शशि थरूर कहां लेकर जाएंगे यह जवाब वक्त देगा**

शशि थरूर का अतीत भाजपा और संघ विरोधी रहा है। वह कट्टर उदारवादी हैं और भाजपा तथा संघ की तीखी निन्दा कर चुके, अगर कांग्रेस में स्वतन्त्र सोच की इजाज़त नहीं तो भाजपा में तो यह और भी कम है, अगर कांग्रेस उनके व्यक्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो भाजपा द्वारा तो बर्दाश्त किए जाने की और भी कम सम्भावना है। दिलचस्प है कि अपनी किताब द पैराडाक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में वह लिखते हैं, " 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का शर्मनाक दोहन...जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, जबकि ऐसी कई स्ट्राइक पहले कर चुके हैं "। यही थरूर अब कह रहे हैं कि पहले ऐसी स्ट्राइक नहीं हुई। शशि थरूर का भाजपा विरोध केवल राजनीतिक ही नहीं वैचारिक और सैद्धांतिक भी रहा है। अपनी किताब वाईआईएमए हिंदू में वह अपनी विचारधारा स्पष्ट करते हैं कि वह हिन्दुत्व के विरोधी क्यों हैं? वह लिखते हैं, "जिसे स्वामी विवेकानंद हिन्दू धर्म की शक्ति देखते थे, इसकी असाधारण विविधता... इसे ही आरएसएस के विचारक कमजोरी समझते हैं...राजनीतिक ज़रूरत के लिए हिन्दुत्व का लक्ष्य सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता पैदा करना है...इसलिए हिन्दुत्व मेरे हिन्दू धर्म के सिद्धांतों से बेमेल है...मेरा हिन्दू धर्म नेहरूवादी भारतीयता की अवधारणा से मेल खाता है... हिन्दुत्व की संकीर्ण विचारधारा हिन्दू धर्म जो वास्तव में है, का उपहास है"। इस अध्याय जिसका शीर्षक उन्होंने हिन्दू धर्म एंड पोलिटिक्स ऑफ हिन्दुत्व, दिया है का अंत वह इस पंक्ति से करतें हैं, "संघ मेरे जैसे हिन्दुओं का प्रवक्ता नहीं है"। जिसके ऐसे विचार हों, जो 'नेहरूवादी भारतीयता' का समर्थक हो, उसे मैं 'उधर' जाते नहीं देखता। पर यह राजनीति है और कहा जाता है कि यहां कुछ भी असम्भव नहीं है।

जत्थेदार अकाल तख्त के प्रति सिख पंथ में विवाद बरकरार

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

श्री अकाल तख्त साहिब के मौजूदा जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ताजपोशी से लेकर आज तक निरन्तर विवादों में घिरे दिखाई दे रहे हैं।ज्यादातर सिख समाज के लोग तो उन्हें जत्थेदार के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। तख्त पटना साहिब के मामले में हस्तक्षेप करके उन्होंने नए विवाद को जन्म दे दिया जिसके बाद संसार भर में सन्देश अच्छा नहीं गया। आज तक कभी भी तख्तों के बीच टकराव नहीं हुआ ऐसा शायद पहली बार ही देखने को मिल रहा है। सिख बुद्धिजीवि और राजनीति के जानकार मानते हैं कि जत्थेदार गरगज के द्वारा अपने आका के इशारों पर ऐसा किया गया। तख्त पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार रणजीत सिंह गौहर जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे, मर्यादा के उलंघन के चलते तख्त पटना साहिब के पांच सिंह साहिबान के द्वारा उन्हें ना सिर्फ तनखाईया बल्कि पंथ से निष्कासित भी किया था पर जत्थेदार अकाल तख्त के द्वारा उन्हें बिना पेश हुए ही माफ कर अपनी सेवाएं जारी रखने का आदेश जारी कर दिया जिसके बाद तख्त पटना साहिब पर विवाद पैदा हो गया और वहां के पांच सिंह साहिबान के द्वारा जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज, जत्थेदार टेक सिंह को तनखाईया करार दिया और इस सारी साजिश के पीछे सुखबीर सिंह बादल के शामिल होने के चलते उन्हें पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया गया।

दमदमी टकसाल के द्वारा भी जत्थेदार गरगज को 6 तारीख को होने वाले शहीदी समागमों में सन्देश न देने की बात कही गई है, वहीं जरनैल सिंह भिन्डरावाले के बेटों ने भी जत्थेदार गरगज से सम्मान लेने से इन्कार कर दिया है असल में हर साल शहीदी समागम पर शहीद परिवारों को जत्थेदार अकाल तख्त सम्मानिन्त करते हैं। अब तो आवाज यह भी उठने लगी है कि जो व्यक्ति किसी भी तख्त से तनखाईया हो वह किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। ऐसे में अगर जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज आपरेशन ब्ल्यू स्टार की याद में होने वाले शहीदी समागम में हिस्सा लेने पहुंचते हैं तो वहां बड़ा टकराव भी हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज की मुश्किलों में निरन्तर बढ़ौतरी ही देखने को मिल रही है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन : इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुगल काल के दौरान हिंदू लड़कियों का जबरन अपहरण किया जाता था। ऐसे में सिख योद्धा मुगलों का सामना करते, लड़कियों को उनकी कैद से मुक्त कराते और उन्हें सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाते थे। 1947 में भारत के बंटवारे के समय भी, पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों के साथ मुगलों के वंशजों द्वारा अत्याचार किए गए। उन्हें जबरन उनके परिवारों से अलग किया गया और उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। पाकिस्तान से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार वहां हिंदू और सिख अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार, 1,000 से अधिक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है। इनमें गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंहों, सेवादारों और यहां तक कि सिख नेताओं की बेटियां भी शामिल हैं। कई मामलों की जानकारी सामने नहीं आ पाती क्योंकि परिवार शर्म या डर के कारण चुप्पी साधे रहते हैं। ऐसे मामलों के बारे में सुनना बेहद पीड़ादायक है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि सदियों बाद भी मुगल मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। यह भी संभव है कि आज जो लोग यह कुकृत्य कर रहे हैं, वे उन्हीं मुगलों के वंशज हों जिन्होंने कभी सिख गुरुओं पर अत्याचार किए थे और कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन थोपा था। इस पूरे संदर्भ में उन लोगों को दोबारा सोचने की ज़रूरत है जो आज भी कहते हैं कि ''हमें पाकिस्तान की निंदा नहीं करनी चाहिए'' एक पंजाबी गायक ने भी इस भावना को लेकर एक गीत लिखा है। हम इस भावना का सम्मान करते हैं क्योंकि यह उस आस्था से उत्पन्न होती है कि जिस धरती पर गुरु नानक साहिब ने जन्म लिया, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए, तो ननकाना साहिब जहाँ गुरु साहिब का जन्म हुआ पहले भारत का ही हिस्सा था, जिसे ब्रिटिश हुकूमत और मुस्लिम समुदाय की अलग देश की माँग के कारण भारत से अलग कर पाकिस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान ने भारत से लड़ी हर लड़ाई हारी है, फिर भी वह अपनी नकारात्मक गतिविधियों से बाज नहीं आता। भारत सरकार को चाहिए कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जोरशोर से उठाए।

पंथक सेवाओं के लिए सेवा रत्न अवार्ड : गुरुद्वारा राजौरी गार्डन भले ही सिंह सभा हो मगर सेवाओं के मामले में देखा जाए तो वह किसी बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब की कमेटी से कम नहीं है। धार्मिक कार्यों से लेकर मिनी अस्पताल रुपक विशाल डिस्पैंसरी, कीमोथैरेपी, दांत इंपलांट, डायलेसिस आदि के साथ ही समय -समय पर गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी,

जरुरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने जैसे अनेक कार्य इस कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी के चलते सर्व सेवा संस्थान द्वारा गुरुद्वारा राजौरी गार्डन के प्रधान हरमनजीत सिंह को सेवा रतन अवार्ड से सम्मानित किया। इसी प्रकार सतनाम सिंह बजाज और तराशा कौर को भी उनके द्वारा की जा रही समाज सेवा के लिए सेवा रत्न अवार्ड पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और संस्था की मुखी डा. सीमा सूरी के द्वारा दिया गया।

न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद काजीरंगा के पास अवैध खनन बढ़ा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि शीर्ष अदालत द्वारा 2019 में रोक लगाने के बावजूद असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास पार्कुप पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन जारी है तथा और तेज हो गया है।

न्यायालय ने 2019 में उद्यान के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में और उसके आसपास खनन और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा में दुनिया में लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडों की लगभग 65 प्रतिशत आबादी निवास करती है। यह ब्रह्मपुत्र बाढ़ क्षेत्र और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने सीईसी के पूर्व निष्कर्षों पर कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों और वन्य परिदृश्यों के क्षरण को रोकने के लिए इस क्षेत्र में खनन और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। असम में एक अज्ञात सरकारी कर्मचारी की शिकायत और फील्ड स्तरीय सत्यापन के आधार पर,

सीईसी ने 30 मई को उच्चतम न्यायालय को एक नई रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि चार अप्रैल 2019 को उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के आदेश के बावजूद क्षेत्र में खनन गतिविधियां जारी हैं तथा और तेज हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, बड़े पैमाने पर खनन जारी है, विशेष रूप से पार्कुप पहाड़ रेंज में, जो एक घोषित वन्यजीव अभयारण्य है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा बनाता है। दिसंबर 2024 में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त शिकायत में 2019 से 2023 तक की 'गूगल अर्थ इमेजरी' और स्थल-विशिष्ट डेटा शामिल थे। कथित तस्वीरों से पता चलता है कि खनन उच्चतम न्यायालय के 2019 के प्रतिबंध आदेश के बाद बंद हो गया था लेकिन 2021 के बाद फिर से शुरू हुआ तथा तेज हो गया। असम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पांच फरवरी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें खनन पट्टों के निलंबन सहित की गई कार्रवाई की रूपरेखा दी गई। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पत्थर खनन बोर्जुरी झरने और उसके आसपास की धाराओं के पास हो रहा है, जो काजीरंगा की ओर बहती हैं। सीईसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) ने वन क्षेत्रों और प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में "दर्जनों" खदानों के लिए नई अनुमति दी, जो उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध का उल्लंघन है और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति और केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमोदन के बिना यह अनुमति दी गई है। समिति ने कहा कि केएएसी को ऐसी अनुमति जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि पार्कुप पहाड़ क्षेत्र और वन्य जलग्रहण क्षेत्रों में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को तत्काल रोक दिया जाए तथा कोई नया पट्टा न दिया जाए। इसने केएएसी को असम के मुख्य सचिव के माध्यम से तिमाही स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

हिसार में पकड़ा गया बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री प्रसारित करने का आरोपी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बच्चों से बलात्कार और उनके यौन शोषण से संबंधित सामग्री इंटरनेट पर प्रसारित करने के आरोप में हरियाणा के हिसार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण (आईसीएसई) डेटाबेस और गूगल द्वारा तैयार तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को प्रस्तुत साइबर टिपलाइन रिपोर्ट का उपयोग करते हुए सीबीआई ने सामग्री का पता लगाया तथा पीड़ितों और अपराधी की पहचान की। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा संबंधित सामग्री और कथित अपराधी की भूमिका का पता लगाए जाने से पहले किसी भी पीड़ित या उनके परिवार ने शिकायत लेकर पुलिस से संपर्क नहीं किया था। एजेंसी ने कई बच्चों से बलात्कार और उनके यौन उत्पीड़न के आरोप में 29 मई को हिसार निवासी सोमनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के आवासीय परिसरों की तलाशी के बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री थी। उन्होंने कहा कि इससे कई पीड़ित बच्चों की पहचान करने में मदद मिली, जिनका पिछले कुछ वर्षों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया तथा धमकी देकर अश्लील उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल किया गया।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विश्व पर्यावरण दिवस आज | प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना है
#BEATPLASTICPOLLUTION

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

प्रकृति की आराधना की राह पर चलने से ही मंगल

पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज का दिन खासा महत्त्व रखता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस बार की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें' (बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन) है। दुनिया में इस समय सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण संतुलन और पृथ्वी के तापमान को लेकर है। अब यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि प्लास्टिक आज पर्यावरण प्रदूषण का आम और सबसे बड़ा कारक है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर वर्ष दुनियाभर में 500 अरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है, जो सभी प्रकार के अपशिष्टों का करीब 10 फीसदी है। पृथ्वी पर इतना प्लास्टिक मौजूद है कि इससे पूरी पृथ्वी को पांच बार लपेटा जा सकता है। यह स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि प्लास्टिक को खत्म होने में 450 से 1000 साल लगते हैं।

दुनिया में प्लास्टिक के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकारों की ओर से इस पर प्रतिबंध लगाने के आश्वासन दिए जाते रहे हैं लेकिन हकीकत में किसी भी प्रयास का असर जमीन पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसका उपयोग लगातार बढ़ता गया। हमारे देश में ही करीब 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिदिन निकलता है और यह मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर प्लास्टिक प्रदूषण इसलिए भी खतरनाक है कि इससे जलवायु परिवर्तन का संकट, प्रकृति, भूमि और जैव विविधता को नुकसान तथा कचरे की परेशानी बढ़ जाती है। यही माइक्रोप्लास्टिक खेतों में जमा होकर जमीन को भी बंजर बना रहा है। इसके साथ ही हर साल करीब 1 करोड़ 10 लाख टन प्लास्टिक कचरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच जाता है। यह समुद्र में कचरा बढ़ा ही रहा है वहीं मछलियों के शरीर में पहुंचकर खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है और मानव शरीर में पहुंचकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पृथ्वी मानव जीवन के साथ-साथ लाखों-लाख वनस्पतियों, जीव-जंतुओं की आश्रय स्थली भी है और हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए।

ऐसे में प्लास्टिक की प्रलय को रोकने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। प्लास्टिक की खपत कम करने से ही माइक्रोप्लास्टिक को कम किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, उद्योग और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर पहल करनी होगी, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, बोतलबंद पानी और प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग बंद करना होगा। जरूरी होने पर रिसाइकिल किए जाने वाले प्लास्टिक को प्राथमिकता देनी होगी। केन्या की पर्यावरणविद् और नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई ने एक समय कहा था कि सभ्य होना है, तो जंगलों के साथी बनो, प्रकृति से जुड़ो, उससे प्रेम करो। हमें हमारे पूर्वज भी प्रतिदिन प्रकृति और पृथ्वी की आराधना की राह बताकर गए हैं। ऐसे में उसी राह पर चलने में मंगल होगा।

कर्पूर चन्द्र कुलिश
जन्म शताब्दी वर्ष
भाग - 11

यह वह सभ्यता व संस्कृति है जो बिना पानी के ही बालू रेत में पैदा हुई। देवताओं ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया था लेकिन यहां तो...

गांव-गांव में पानी के गीत, मथा जा रहा रेत का समुद्र

हर जगह पानी की एक कहानी, कविता और संस्कृति

'जल है तो कल है' का नारा हमारे लिए कोई नया नहीं है। लेकिन इसकी परवाह शायद ही किसी ने की हो। पत्रिका समूह के अमृतं जलम् अभियान ने पिछले सालों में हजारों जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम जनसहयोग की बदौलत ही किया है। यही जनसहयोग अमृतं जलम् अभियान के तहत आज से जयपुर के रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के संकल्प में नजर आएगा। पानी का महत्त्व कितना है यह कुलिश जी ने सत्तर के दशक में राजस्थान के दौरे में नजदीक से महसूस किया। उन्होंने लिखा कि विभिन्न इलाकों में पानी की कमी को लेकर अलग-अलग गीत संवाद बने हुए हैं।

कहते है सभ्यता नदी-घाटियों या नदी किनारे पैदा हुई है, लेकिन वह सभ्यता का कौनसा तत्व या लक्षण है जो रेगिस्तान के इस इलाके में नहीं है। यह वह सभ्यता और संस्कृति है जो बिना पानी के ही बालू रेत में पैदा हुई है। देवताओं ने अमृत-कलश निकालने के लिए समुद्र-मंथन किया था, परन्तु राजस्थान के चूरू जिले में पानी की एक-एक बूंद के लिए रेत का समुद्र मथा जा रहा है। जिले के गांव-गांव में पानी की एक कहानी है, पानी की कविता है और पानी की एक संस्कृति है। इसी तरह गांव-गांव में पानी के गीत बने हुए हैं। बूचावास को लेकर एक दोहा इस तरह कहा गया है:-

ऊंचो टीबो, सिर घड़ो, तिरया तेरह मास।
नारी सींचे नर पिये, बालूं बूचावास ॥

अर्थात ऊंचा टीला है, सिर पर पानी से भरा घड़ा है और पेट में तेरह महीने का गर्भ है। स्त्री पानी लाती है और पुरुष पीते हैं, ऐसे गांव को आग लगा दूं। पानी भरने की कठोर यंत्रणा इस तरह से एक महिला के मुंह से निकली है। तेरह मास का गर्भ इसलिए कि प्रसव के लिए समय ही नहीं मिला।

गाजूवास-गडाणसी नाम के युगल गांवों के लिए एक लोकोक्ति है-

गाजूवास गडाणसी, पाणी पीयां जाणसी।
टीबां कानी ताणसी, बैठसी ऊंचाणसी॥

गाजूवास-गडाणसी का खारा पानी पीने से ही मालूम पड़ेगा। पीते ही इसका पता चलेगा। टीबों की तरफ भागना पड़ेगा और...

आलीड़ै में सूखैड़ो, सूखेड़े में कीच।
एक तमासो म्हे देख्यो, रिणी-चुंगाई बीच॥

अर्थात् तारानगर के रिणी और चुंगाई गांव के बीच की मिट्टी ऐसी है कि पानी पड़ने पर गीली मिट्टी तो गाढ़ी हो जाती है और सूखी मिट्टी कीचड़ बन जाती है। इधर थोड़ी बरसात में भी चना पैदा हो जाता है।

भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति में एक गांव है भदीरा, जिसके बारे में यह गीत गाया जाता है:-

कजरा बैंवी भूल गई, भदीरा तेरा पानी।

एक नई बहू कहती है कि, भदीरा के कुओं से पानी खींचते वह काजल-टीकी लगाना भी भूल गई। लोगों ने बताया कि 200 फीट गहरे कुएं थे इसलिए लोग नदबई की तरफ अपनी बेटियां देने का तैयार नहीं होते थे।

आबादी के फैलाव ने गला घोंटा

बीकानेर शहर की रचना इस तरह की है कि आसपास की जमीन ऊंची है। शहर के चारों ओर तालाब थे ताकि बरसात में बाहर का पानी सिमटकर इनमें भर जाए। इससे आबादी को पानी मिल जाता था। सूरसागर, जसोलाई, भाटोलाई, गबोलाई, बिन्नाणियों की तलाई, नरसिंह सागर, बागीनाड़ा आदि इसी तरह के तालाब थे। अब आबादी के फैलाव के साथ तालाबों के अगोरों में मकान बन गए। उनकी उपयोगिता वैसी नहीं रही। एक मुसीबत स्थायी तौर पर बनी रह गई कि बरसात के थोड़े से पानी से भी शहर में ढलान के कारण बाढ़ की सी हालत पैदा हो जाती है। अब तालाब या तो गंदगी के घर बने हुए हैं या मुसीबत की जड़, क्योंकि इन तालाबों से पानी शहर की आबादी में घुस आता है। कुछ तालाब तो आबादी के बीच में आ गए हैं।

*(कुलिश जी के यात्रा वृत्तांत आधारित पुस्तक **'मैं देखता चला गया'** से)*

पाणी पहली चीज़

'सर्वमापोमयंजगत',
पाणी पहली चीज।
अतरी समझ न राज में,
पाणी जग को बीज।।

('सात सैंकड़ा' पुस्तक से)

...गांव का रिश्ता

गांव का रिश्ता मकान, जायदाद का ही रिश्ता नहीं होता। टोंक जिले का सोडा गांव मेरी जन्मभूमि है। यहां मैं पला हूं और बड़ा हुआ हूं। इसकी मिट्टी में खेला हूं। इसके तालाब में रोज नहाता रहा हूं। नहाने का वह मजा किसी बड़े से बड़े होटल के आलीशान स्वीमिंग पूल में भी नहीं आ सकता। अपने गांव की बात ही कुछ और होती है। वह खेलना, वह तैरना, पाठशाला में पढ़ना, खेतों की रखवाली करना, उगती और कटती फसलों को देखना, कुछ और ही मायने रखता है। मुझे अब तक बचपन की सब बातें हूबहू याद हैं।

(कुलिश जी के आत्मकथ्य पर आधारित पुस्तक **'धाराप्रवाह'** से)

(जारी... कुलिश जी का सृजन संसार पढ़ें आगामी गुरुवार को भी)

पर्यावरण दिवस विशेष: इस वर्ष की थीम है- प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें

'प्लास्टिक युग' में फंसी दुनिया, समाधान तभी जब हम अपनी आदतें बदलेंगे

डॉ. पंकज जैन
(लेखक चिकित्सक एवं पर्यावरण विषयों के जानकार हैं)
@patrika.com

प्लास्टिक प्रदूषण की भयावहता को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से प्लास्टिक संकट के लिए एक समग्र अंतरराष्ट्रीय रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

वर्तमान की हमारी जीवनशैली पर अगर गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी प्लास्टिक युग में प्रवेश कर गए हो। सुबह से रात तक प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि इसकी गिरफ्त से बाहर निकलना दिवास्वप्न-सा लगता है। जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के बाद मानव प्रजाति वर्तमान में प्लास्टिक संकट से जूझ रही है, जिसे अगर इसी तर्ज पर प्लास्टिक प्रदूषण से परिभाषित करें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरण के लिए अपितु हमारी एवं आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मनुष्य प्रतिदिन सांस लेने, दूषित भोजन एवं पानी द्वारा निगलने एवं सीधे त्वचा के संपर्क से जहरीली धातुओं, अम्लीय गैसों, कई प्रकार के प्लास्टिक रसायनों और माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आता है।

विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग औसतन हर हफ्ते लगभग पांच ग्राम प्लास्टिक खा रहे है, जो एक क्रेडिट कार्ड के बराबर है। प्लास्टिक पैकेजिंग और उत्पाद कई हानिकारक रसायनों को भोजन व पानी में छोड़ते है, जो मानव शरीर में हार्मोन्स के कार्य में व्यवधान पैदा कर प्रजनन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रतिवर्ष अनुमानित वैश्विक लागत सौ बिलियन के करीब आती है। प्लास्टिक प्रदूषण का सर्वाधिक

जोखिम बच्चों, गर्भस्थ शिशुओं एवं उस आबादी को है, जो प्लास्टिक उत्पादन व निस्तारण संयंत्र के आसपास निवास करती है। प्लास्टिक प्रदूषण के लिए कुछ रसायन जैसे बिसफिनॉल ए, फथलेट्स, एवं स्टाइरीन मोनोमर प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य कारणों में प्लास्टिक का अत्यधिक उत्पादन, गलत निस्तारण और अपघटन की धीमी प्रक्रिया है। प्लास्टिक को नष्ट होने में कई साल लग जाते है और यह सूक्ष्म प्लास्टिक में विभक्त हो जाता है जो अंततः पर्यावरण और जीवों के लिए हानिकारक साबित होता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कई पर्यावरणीय खतरे भी है।

प्लास्टिक प्रदूषण की भयावहता को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से प्लास्टिक संकट के लिए एक समग्र अंतरराष्ट्रीय रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए गए है, जिनमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के तहत एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वाले निर्माताओं को अपने उत्पादों के कचरे को इकट्ठा करने और रीसाइकिल करने की जिम्मेदारी दी है, साथ ही रीसाइक्लिंग केंद्रों की स्थापना एवं रीसाइक्लिंग नीतियां बनाई गई हैं। इन प्रयासों के अतिरिक्त प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए विभिन्न नवीन तकनीकी समाधानों को भी अपनाना होगा जैसे कि प्लास्टिक से ईंधन बनाना, जो भविष्य में ऊर्जा का स्थायी स्रोत हो सकता है। प्लास्टिक कचरे के जरिए सड़क निर्माण होने से इसका बेहतर प्रबंधन तो होता ही है, साथ ही सड़कें पर्यावरण के अनुकूल और अधिक टिकाऊ भी होती हैं। पारंपरिक सड़कों की तुलना में लागत भी कम आती है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अपसाइक्लिंग एक और अभिनव व अनूठा समाधान है, जिसमें प्लास्टिक कचरे को नए, उच्च मूल्य वाले उत्पादों जैसे फर्नीचर, निर्माण सामग्री या फैशन उत्पादों में बदल कर नए आर्थिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसके लिए नए समाधान तो खोजना ही है साथ ही हमें अपनी जीवनशैली में भी बदलाव लाना होगा ताकि प्लास्टिक उपयोग कम से कम हो, जो कि इतना आसान नहीं होगा किंतु सामूहिक साझेदारी से हर स्तर पर छोटे-छोटे बदलाव कर हम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं, जरूरत है तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की।

भारतीय संस्कृति प्रकृति को माना गया है देवतुल्य

प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में जोड़ा गया है प्रकृति से रिश्ता

भारत की संस्कृति में प्रकृति यानी पर्यावरण का बहुत महत्त्व है। संस्कृति और पर्यावरण का संबंध संस्कार की भांति। भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रकृति को देवतुल्य स्थान हासिल है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के हमारे सनातन सिद्धांत ही हमें प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। हमारी सनातन परंपराओं और दर्शन में प्रकृति संरक्षण के सूत्र मौजूद हैं। प्रकृति के प्रति ऐसी पावन भावना भारत को छोड़कर कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारे तमाम संत-महात्माओं, मनीषियों-चिंतकों ने प्रकृति की तमाम शक्तियों को जीवनदायिनी मानते हुए उन्हें देवत्व का स्थान प्रदान किया है।

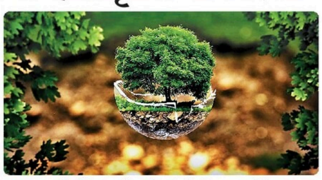

प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि-मुनियों-संत-महात्माओं और वैज्ञानिकों को प्रकृति संरक्षण की अहमियत और मानव के उथले स्वभाव की जानकारी थी। उन्हें ज्ञात था कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए गंभीर भूलें कर सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानवीय संबंध जोड़ते हुए उसे जीवन का हिस्सा बनाया ताकि मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से झिझके। प्रकृति के प्रति इसी मानवीय सोच के चलते हमारे देश में पेड़-पौधों, नदी-नालों, पर्वतों, ग्रह-नक्षत्रों, अग्नि-वायु, जीव-जंतु समेत प्रकृति के नाना विधानों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी समृद्ध संस्कृति, दर्शन और परंपरा के उत्तराधिकारी होने के बावजूद आज के भौतिक युग में हमारी ये प्राचीन परंपराएं-मान्यताएं छीज गई हैं। सुविधाभोगी और तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर हम प्रकृति के साथ बुरी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं।

हमारे पूर्वज प्रकृति को न केवल मनुष्यमात्र के लिए सर्वाधिक फलदायी मानते थे अपितु वन्यजीव-जंतुओं के लिए भी आवश्यक समझते थे। इसीलिए उन्होंने उसकी पूजा-अर्चना की व्यवस्था बनाई थी। हमारे धर्म ग्रथों ने मंत्रोचार को प्रकृति को जोड़कर उसे पवित्रता प्रदान की। धरती को माता, जल, हवा, नदियां, जीव-जंतुओं, पर्वत, वृक्ष और जलाशयों को पूजनीय मानकर उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की व्यवस्था की गई। इन वन्य प्राणियों को पर्यावरण का प्रमुख अंग माना जाता है। इनका सही संतुलन होने से ही पर्यावरण शुद्ध रहता है। इनकी सुरक्षा के लिए वन्यजीवों को पूजने का विधान भी हमारी संस्कृति में हैं। हमारी संस्कृति में दस अवतारों में चार अवतार पशुओं और जीव-जंतुओं से संबद्ध हैं जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कच्छप अवतार तथा नृसिंह अवतार। गाय की महत्ता प्रकट करने के लिए गोपाष्टमी, बछबारस का त्योहार मनाया जाता है। वेदों का भी संदेश है कि मानव शुद्ध वायु में सांस ले, जीव-जंतुओं पर दयाभाव रखे, शुद्ध जलपान करे, शुद्ध अन्न-फल खाए, तभी वह सुख-समृद्धि के साथ दीर्घायु हो सकता है। आज हम इन संस्कारों से न केवल भटक गए हैं बल्कि पिछले कुछ दशकों से हमारे समाज के चिंतन एवं कार्यशैली में बदलाव भी आया है तभी आज प्रकृति अपनी ही प्रवृत्ति से विमुख होने लगी है। इसलिए हम सबका ये युगधर्म है कि हम दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ें ताकि सकुशल जीवन, शुद्ध संतुलित वातावरण स्थापित किया जा सके।

- डॉ. मीना कुमारी

इंफोग्राफिक्स

क्या आप तैयार हैं सच का सामना करने के लिए

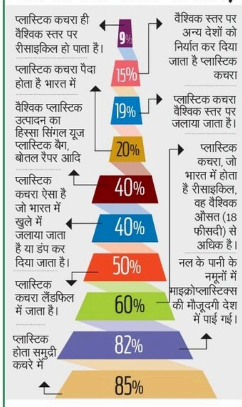

1950 में : दुनिया में केवल 2 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रति वर्ष हो रहा था उत्पादन।

2019 तक: 460 मिलियन टन प्रति वर्ष।

2060 तक: प्लास्टिक कचरा 1.2 बिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगा।

20 किलो: प्लास्टिक का भारत में प्रति व्यक्ति हर साल होता है उपयोग।

स्रोत : ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक : पॉलिसी सिनेरियो 2060

जानने योग्य बातें हमारे ईकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा

प्लास्टिक के जाल से धरती को बचाने का समय

विश्व में हर साल अनुमानित 460 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। पानी और शैम्पू की बोतलें, पॉलिस्टर शर्ट, पीवीसी पाइपिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद गंभीर प्लास्टिक प्रदूषण संकट का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है, लोगों को हानिकारक प्रदूषकों के संपर्क में ला रहा है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है।

Q विश्व में कितना प्लास्टिक मौजूद है?

प्लास्टिक आधुनिक दुनिया का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका कई तरह की चीजों में उपयोग लिया जाता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हमने 9.2 बिलियन टन प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन किया, जिसमें से 7 बिलियन टन कचरा बन गया।

Q सबसे समस्याग्रस्त प्लास्टिक कौन से हैं?

सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पाद, जो पुनः उपयोग नहीं होते इनमें शामिल हैं।

- **पॉलीइथिलीन टेरेफ्थालेट** - पानी की बोतलें, डिस्पेंसिंग कंटेनर, बिस्किट ट्रे।
- **हाई-डेंसिटी पॉलीइथिलीन** - शैम्पू बोतलें, दूध की बोतलें, फ्रीजर बैग, आइसक्रीम कंटेनर।
- **लो-डेंसिटी पॉलीइथिलीन** - बैग, ट्रे, कंटेनर, खाद्य पैकेजिंग फिल्म।
- **पॉलीप्रोपाइलीन** - चिप्स के पैकेट, माइक्रोवेव डिश, आइसक्रीम टब, बोतल के ढक्कन।
- **पॉलीस्टीरिन** - कटलरी, प्लेट, कप।
- **एक्सपैंडेड पॉलीस्टीरिन**- सुरक्षात्मक पैकेजिंग

Q प्लास्टिक प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या क्यों है?

- **पहला: पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव-** छोटे प्लास्टिक कण सूक्ष्म समुद्री शैवाल (फाइटोप्लांक्टन) की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं, जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है। मछलियां गलती से प्लास्टिक खा लेती हैं, जिससे उनका पेट अपचनीय टुकड़ों से भर जाता है और वे भूख से मर जाती हैं।
- **दूसरा: मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव-** प्लास्टिक छोटे-छोटे टुकड़ों माइक्रो और नैनोप्लास्टिक्स में टूट जाता है, जो मानव शरीर में जमा हो सकते हैं।
- **तीसरा: जलवायु परिवर्तन-** प्लास्टिक बनाने में जो ऊर्जा लगती है, उससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। वर्ष 2020 में, ऐसी गैसों का 3 फीसदी से ज्यादा हिस्सा सिर्फ प्लास्टिक उत्पादन से आया था।

Q प्लास्टिक प्रदूषण कहां पाया जाता है?

लगभग हर जगह। यह झीलों, नदियों और समुद्रों में है। यह शहर की सड़कों और खेतों में बिखरा हुआ है। यह डंपसाइट्स में भरा हुआ है। यह रेगिस्तानों में ढेर हो रहा है और समुद्री बर्फ में घुस रहा है। शोधकर्ताओं ने माउंट एवरेस्ट और पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु, मरियाना ट्रेंच में भी प्लास्टिक कचरा पाया है।

Q क्या केवल रीसाइक्लिंग से प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त हो सकता है?

नहीं। केवल 9 फीसदी प्लास्टिक का ही रीसाइक्लिंग होता है। कई प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रीसाइक्लिंग के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं।

Q तो, प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे निपटा जा सकता है?

- सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पादों पर निर्भरता कम करके।
- प्लास्टिक उत्पादों को लंबे समय तक चलने, कम खतरनाक, और पुनः उपयोग व रीसाइक्लिंग योग्य बनाने के लिए पुनः डिजाइन करना होगा।
- कई उत्पादों में प्लास्टिक के विकल्प खोजना जरूरी।

प्रस्तुति : राखी हजेला

संकल्प: हमें समझना होगा कि प्रकृति है तो हमारा जीवन है

एक पेड़ लगाएं, चार लोगों को मिलेगी पूरे साल ऑक्सीजन

बाबूलाल जाजू
पर्यावरणविद्
@patrika.com

पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार या कुछ संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी का कर्तव्य है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान गंभीर चुनौतियां बन चुके हैं। वृक्ष, जिन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, हमारे जीवन के आधार हैं। पेड़ों के बिना, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है।

एक बड़ा वृक्ष एक वर्ष में इतनी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है कि चार व्यक्ति एक वर्ष में उपभोग कर सकें। तापमान को कम करने एवं वर्षा को बढ़ाने में पेड़ों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। भूजल स्तर को बढ़ाने एवं बाढ़ के खतरे को कम करने में भी पेड़ों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही पेड़ हजारों प्रजातियों के पशु-पक्षियों एवं वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। पेड़ों से वातावरण सुहावना होता है, तनाव कम होता है और प्रसन्नता में वृद्धि होती है। एक ओर जहां वृक्ष जीवन और समृद्धि के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर पॉलिथिन एक ऐसा आविष्कार है, जिसने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा किए हैं। पॉलिथीन एक गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करती हैं। इससे वर्षाजल का भूमि में जाना अवरुद्ध होता है। पॉलिथिन नालियों और सीवरों को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

सरकार को सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बने नियमों की सख्ती से पालना करवानी चाहिए। पॉलिथिन का सर्वाधिक कचरा शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जो शहर के सौन्दर्यीकरण को नष्ट कर रहा है। आज हमारा देश प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। इसका मुख्य कारण सरकार की इच्छाशक्ति की कमी एवं प्लास्टिक निपटान की मजबूत व्यवस्था नहीं होना है। हमें यह समझना होगा कि वृक्षों की रक्षा करना और पॉलिथीन का त्याग करना केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे सुखी जीवन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अनिवार्य है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करके एक बड़ा प्रभाव पैदा करना होगा। हमें सभी अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पल्लवित करने का संकल्प लेना चाहिए।

संपादकीय

“पृथ्वी सभी की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को नहीं।” -महात्मा गांधी

बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू (आरसीबी) की आईपीएल जीत का जश्न जिस तरह से एक त्रासदी में बदल गया, वह हृदयविदारक है। प्रशंसकों का उत्साह तो स्वाभाविक था, लेकिन सवाल तो इतने बड़े आयोजन की तैयारियों पर है।

खुशी में मातम

बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू (आरसीबी) की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न जिस तरह से एक त्रासदी में बदल गया, वह स्तब्धकारी होने के साथ हृदयविदारक भी है। उल्लेखनीय है कि हजारों उत्साही प्रशंसक टीम के पहुंचने से घंटों पहले ही स्टेडियम के बाहर जमा होने लगे थे। स्टेडियम भीतर से तो ठसाठस भरा ही हुआ था, उसके बाहर और आसपास की सड़कों पर भी जबर्दस्त जाम की स्थिति थी। आलम यह था कि करीब 5,000 सुरक्षाकर्मी मिलकर भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ ही दिख रहे थे। इसके बाद मची भगदड़ में दस से ज्यादा लोग मारे गए और छह साल की मासूम बच्ची समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ के दौरान के जो दृश्य वायरल हो रहे हैं, वे वाकई दिल दहलाने वाले हैं। यह पूरी घटना दरअसल प्रशासन की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में विफलता को ही उजागर करती है। अठारह संस्करण तक लंबे इंतजार के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी की टीम को लेकर प्रशंसकों का उत्साह कोई अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि स्वाभाविक ही था। बंगलूरू जैसे प्रगतिशील छवि वाले महानगर में इतने बड़े आयोजन के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न हों, तो सवाल तो उठेंगे ही। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भले यह कह रहे हों कि युवा और उत्साही भीड़ पर पूरी तरह से लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन सवाल यह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के वैकल्पिक उपाय, जैसे पर्याप्त बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, आपातकालीन निकासी की व्यवस्था इत्यादि पहले से क्यों नहीं किए गए। भगदड़ के दौरान प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का यों असहाय दिखना वाकई हैरत में डालने वाला था। ऐसी खबरें भी हैं कि आरसीबी ने अपने प्रशंसकों को मुफ्त पास बांटे, जिसकी वजह से भीड़ इतनी बढ़ गई। लिहाजा बीसीसीआई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। यह दुखद ही था कि स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे और अंदर जश्न मनाया जा रहा था। यह त्रासदी हमें उन गहरे सबकों की याद दिलाती है, जिनसे हमें भविष्य के लिए सीख लेने की जरूरत है। बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन एक विज्ञान है, जिसे तकनीक, प्रशिक्षण और योजना के जरिये लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में, सरकार, पुलिस और आयोजकों को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जाए। इस दुखद घटना की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों को सख्त सजा भी मिलने के साथ यह भी जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तय की जाएं, जिनका पालन अनिवार्य हो।

प्लास्टिक मुक्त हों भी, तो कैसे

सरकारें तो केवल नीति और कानून बना सकती हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, तो इससे मुक्त होने के रास्ते भी हमें ही तलाशने होंगे। इस मामले में लापरवाही इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी खोज प्लास्टिक को सबसे बड़ा संकट बना देगी।

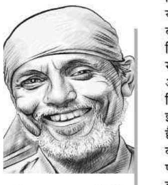

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद

प्लास्टिक की स्थिति इस दुनिया में ठीक वैसी ही है, जैसे एक गरीब व्यक्ति की-जो हमारे कई काम आता है, लेकिन जब उससे कोई गलती हो जाती है, तो उसमें हमें सारी बुराइयां दिखाई देने लगती हैं। यही हाल प्लास्टिक का भी है-पूरी दुनिया में ऐसा कौन है, जिसने पिछले 30 वर्षों में प्लास्टिक का उपयोग न किया हो? कोई गांव, घर, गली, कस्बा या शहर ऐसा नहीं है, जो प्लास्टिक के उपयोग से वंचित हो। किसी न किसी रूप में प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है।

असल में यह एक ऐसी चीज है, जो अब मनुष्य के गले पड़ चुकी है। सीधे शब्दों में कहें, तो आज भी, जब प्लास्टिक विरोधी तमाम नियम और कानून लागू हो चुके हैं, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में बना हुआ है। सब्जी, फल या फिर किराना दुकान में सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा करते हैं, खरीदारी करने के लिए जूट या कपड़े के झोले का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया है। इस तरह प्लास्टिक की थैली का उपयोग करके हम इस प्लास्टिक के प्रसार को और बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

आज के संदर्भ में देखें, तो प्लास्टिक ने हमारे जीवन में इतनी गहराई से अपनी जगह बना ली है कि अब इससे मुक्त होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। घर और बाहर के कामों में तो यह पहले से मौजूद है ही, लेकिन अब खेती-बाड़ी से लेकर उद्योगों में-हर जगह इसका उपयोग होता है। वैसे हम इसके कुप्रभावों को जानते हैं, फिर भी इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। जब भी प्लास्टिक की बात होती है, तो सभी एक सुर में इसका विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया है।

आज भी हालात ये हैं कि न चाहकर भी, कई वजहों से प्लास्टिक हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बना हुआ है। यही कारण है कि बार-बार प्रतिबंध लगने और सरकारी नियम-कानून होने के बावजूद प्लास्टिक का उपयोग सबसे ज्यादा और सर्वोपरि बना हुआ है।

प्लास्टिक को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है-एक तरफ, यह हमारे जीवन में कई रूपों में वरदान है। इसके कारण हम अपनी रोजमर्रा की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ, जब भी प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की बात होती है, तो रोजगार और स्वरोजगार की बात सामने आती है, जिसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते।

सरकारों का मानना है कि इससे मुक्त हुआ जाए। लेकिन जब आम लोग खुद ही इससे मुक्त होना नहीं चाहते, तो सरकारें इसे कैसे खत्म कर पाएंगी? यही हो रहा है-क्योंकि देश और दुनिया में प्लास्टिक उद्योग रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर इस उद्योग को बंद कर दिया जाए, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैज्ञानिक भी प्लास्टिक के नए उपयोग और इसे खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन वे भी कहीं न कहीं बेरोजगारी का सामना कर सकते हैं।

अब सवाल यह है कि हमारे पास क्या विकल्प हैं? एक तरफ इसके आकर्षक और उपयोगी उत्पाद, जो लकड़ी और लोहे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसकी मजबूती और टिकाऊपन हमें अपनी तरफ खींचता है। दूसरी ओर, इसका दुरुपयोग सीमाओं को पार कर चुका है। यह अब सिर्फ गाय-भैंस या अन्य जानवरों के पेट में नहीं पहुंचता, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर चुका है।

हाल के शोध बताते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में 50,000 से अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण पहुंच चुके हैं, जो हमारे दिल, त्वचा और फेफड़ों पर सीधा असर डाल सकते हैं। तो सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी आम लोग और नीति-निर्माता मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं, जिससे प्लास्टिक से छुटकारा पाया जा सके। कुछ नहीं, क्योंकि हम अभी गंभीर ही नहीं हैं। हालांकि, प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त होना संभवतः न तो मुमकिन है और न ही व्यावहारिक। लेकिन एक रास्ता जरूर है-सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग वाली प्लास्टिक) पर नियंत्रण लगाया जाए। इसके लिए सरकार ने कई नियम और कानून बनाए, जुर्माने भी लगाए, लेकिन व्यवहार में कुछ खास असर नहीं पड़ा।

देश में प्लास्टिक के नए-नए प्रयोग और उपयोगों को समर्पित केंद्रीय प्लास्टिक व इंजीनियरिंग संस्थान भी चेन्नई में है, जिसके देश भर में 48 छोटे अनुषांगिक संगठन भी हैं, जो प्लास्टिक पर काम कर रहे हैं। वे मानते हैं कि प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करना न संभव है और न इसका कोई तात्कालिक समाधान। लेकिन वेस्ट प्लास्टिक (अपशिष्ट प्लास्टिक) का सही उपयोग करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो टिकाऊ भी होंगे और तुरंत कचरा भी नहीं बनेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू भी है-जब भी हम प्लास्टिक का उपयोग करें, उसकी प्रवृत्ति यह होनी चाहिए कि वह बार-बार उपयोग में आ सके। इससे प्लास्टिक के उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा और कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा।

अब सवाल है-क्या केवल सरकार को दोष देने से समस्या हल होगी या नागरिक के रूप में कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। सरकारें तो केवल नीति और कानून बना सकती हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक कण प्रवेश कर रहे हैं और जीवन संकट में पड़ रहा है, तो हमें खुद कदम उठाने होंगे।

सरकारें नियम ही बना सकती हैं, लेकिन उनका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर सरकार दबाव बनाएगी, तो फिर दूसरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी तरह अनदेखी करते रहे, तो इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक प्लास्टिक ही हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।

सागर, सगरा और सरोवर

प्रसंगवश

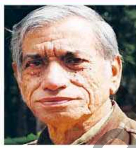

अनुपम मिश्र

जाने-माने गांधीवादी चिंतक एवं जल-संरक्षण के प्रणेता अनुपम मिश्र ने पारंपरिक विधियों से पर्यावरण और जीवन, दोनों को समृद्ध करने की बात की थी। उनकी पुस्तक *आज भी खरे हैं तालाब* के अंश...

जीवन और मृत्यु की लहरों से लहराते इस भवसागर से पार उतरने का लक्ष्य रखने वाले समाज ने तरह-तरह के तालाब बनाए हैं और बहुत रुचि के साथ उनके नामकरण किए हैं। ये नाम तालाबों के गुणों पर, स्वभाव पर, तो कभी किसी विशेष घटना पर रखे जाते थे। इतने नाम, इतने प्रकार कि कहीं नामकरण में भाषा का कोश कम पड़े, तो बोली से उधार लेते थे, तो कहीं ठेठ संस्कृत तक जाते थे। सागर, सरोवर और सर नाम चारों तरफ मिलेंगे। सागर लाड़ प्यार में सगरा भी हो जाता है। सरोवर कहीं सरवर भी है। सर संस्कृत शब्द सरस से बना है और गांव में इसका रस सैकड़ों बरसों से सर के रूप में मिल रहा है। आकार में बड़े और छोटे तालाबों का नामकरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की इन जोड़ियों से जोड़ा जाता रहा है : जोहड़-जोहड़ी, बंध-बंधिया, ताल-तलैया तथा पोखर-पोखरी। ये जोड़ियां मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में जगह-जगह हैं और सीमा पार नेपाल में भी।

पोखर संस्कृत के पुष्कर से मिला है। बंगाल में तो हर घर के पास पोखर हुआ करते थे। वहां तालाब के लिए पुष्करणी शब्द भी चलता रहा है। डिग्गी नाम हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में चलता था। पानी रखने के छोटे हौज से लेकर बड़े तालाब तक डिग्गी नाम मिलता है। कभी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने लाल डिग्गी नामक एक बड़ा तालाब था। डिग्गी शब्द दीघी और दीर्घिका जैसे संस्कृत शब्दों से आया है। हौज का उदाहरण दिल्ली का हौज खास है, जो अब तालाब से अधिक एक मुहल्ले की तरह पहचाना जाता है।

ताल कई जगह हैं, पर इसी से मिलता-जुलता शब्द चाल एक क्षेत्र में सीमित होकर रह गया। यह क्षेत्र है हिमालय का। इन पहाड़ी जिलों में कभी गांव-गांव में चाल थीं। चाल कोई 30 कदम लंबी, इतनी ही चौड़ी और कोई चार-पांच हाथ गहरी होती थी। हिमालय में चाल कहीं खाल है, कहीं तोली है, तो कहीं चौरा भी। ठेठ उत्तर के ये शब्द दक्षिण तक चले जाते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश में चैर और चेरुवू शब्द तालाब के अर्थ में ही पाए जाते हैं।

चौकोर पक्के घाट से घिरे तालाब चोपरा या चौपरा और र का ड़ होकर चौपड़ा भी कहलाते हैं। चौपड़ा उज्जैन जैसे प्राचीन शहर में, झांसी जैसे ऐतिहासिक शहर में तथा चिरगांव जैसे साहित्यिक स्थान में भी हैं। चारों तरफ से अच्छे-पक्के घाटों से घिरा तालाब चौघरा कहलाता है। इसमें एक तरफ संभवतः आगौर की तरफ का भाग कच्चा छोड़ दिया जाता था। कहीं-कहीं तालाबों में स्त्री और पुरुषों के नहाने के लिए भी अलग प्रबंध होता था। छत्तीसगढ़ में डौकी घाट महिलाओं के लिए, तो डौका घाट पुरुषों के लिए बनते थे। बिहार में दो गांव के बीच निर्जन क्षेत्र में गुहिया पोखर मिलते हैं। अपने आप बने ऐसे ही तालाबों का एक और नाम है अमहा ताल। छत्तीसगढ़ी में अमहा का अर्थ है अनायास। अमहा का एक अर्थ आम तो है ही। आम के पेड़ से, बड़ी-बड़ी अमराइयों से घिरे ताल अमहा तरिया, ताल या आमा तरिया कहलाते हैं। इस तरह अमरोहा था। आज यह एक शहर का नाम है, पर एक समय आम के पेड़ों से घिरे तालाब का नाम था। वहीं, लखपेड़ा ताल लाखों पेड़ों से घिरा रहता। कहीं-कहीं ऐसे तालाब को लखरांव भी कहा गया है। लखरांव को भी पीछे छोड़े, ऐसा है भोपाल का ताल।

बड़ों की बात छोड़ें, लौटकर आएं छोटे तालाब पर। उथले, कम गहरे, छोटे आकार के तालाब चिखलिया कहलाते थे। ऐसे तालाबों का एक पुराना नाम डाबर भी था। बाई याबाव भी ऐसे ही छोटे तालाबों का नाम था। बाद में यह नाम तालाब से हटकर बावड़ी में आ लगा। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास राजों की बाव नामक बावड़ी आज इस शब्द की तरह ही पुरानी पड़ चुकी है। कई जगह बहुत पुराने तालाबों के पुराने नाम यदि समाज को याद रखने लायक नहीं लगे, तो वे मिट जाते और उन्हें फिर एक नया नाम मिल जाताः पुरनैहा, यानी काफी पुराना तालाब। आसपास के तालाबों की गिनती में सबसे अंत में बने तालाब नवताल, नौताल, नया ताल कहलाने लगते। वे पुराने भी पड़ जाते, तो भी इसी नाम से जाने जाते।

-प्रस्तुति : सुरेंद्र बांसल

दूसरा पहलू

मस्तिष्क को ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज माना जाता है। वैज्ञानिक दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड करने के प्रयास में लगे हैं।

क्या दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं

डोब्रोमिर राहनेव

विज्ञान ने चांद पर इन्सान को पहुंचाया, डीएनए की खोज की और चेचक जैसी बीमारी को खत्म किया, ये सब कभी असंभव लगते थे।

प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ रही है। चुनौतियों के बावजूद माइंड अपलोडिंग 2045 तक मुमकिन हो सकती है। कुछ का मानना है कि यह सदी के अंत तक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 200 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं।

क्या किसी मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकता है? यह सुनने में रोमांचक तो लगता है, लेकिन थोड़ा डरावना भी है। इसे माइंड अपलोडिंग कहा जाता है। कल्पना करें कि आपका दिमाग, मन व चेतना, सब कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। इस तरह आपको अपने बारे में जानकारी होगी, आप अपनी यादें बनाए रखेंगे और डिजिटल रूप से जी रहे होंगे, लेकिन आपके पास शरीर नहीं होगा। इस नकली दुनिया में आप वे तमाम चीजें कर सकते हैं, जो असली दुनिया में करते हैं, खाना, गाड़ी चलाना, खेल खेलना आदि। विज्ञान के पास सैद्धांतिक संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। विज्ञान ने चांद पर इन्सान को पहुंचाया, डीएनए की खोज की और चेचक जैसी बीमारी को खत्म किया, ये सब कभी असंभव लगते थे। मस्तिष्क को ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज माना जाता है। अपलोड किए गए मस्तिष्क को वही इनपुट चाहिए, जो हमेशा से थे, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, छूना, और शरीर की हर छोटी-बड़ी हरकत। अगर ये अनुभव सही नहीं हुए, तो डिजिटल दिमाग में दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे मानसिक तनाव। अगर इन्सान को उसकी इंद्रियों से दूर रखा जाए, तो उसे मानसिक परेशानी हो सकती है। सफल मस्तिष्क अपलोडिंग के लिए पहला कार्य है, मस्तिष्क की संपूर्ण 3डी संरचना को स्कैन करना और उसका मानचित्रण करना। कुछ दशकों में मानव मस्तिष्क का पूरा नक्शा बनाना संभव हो सकता है। फिर भी, सभी 86 अरब न्यूरॉन्स की पहचान करना, और उनके खरबों कनेक्शन को अपलोड करके भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रत्येक न्यूरॉन लगातार अपने कामकाज को समायोजित करती है, और इसे भी मॉडल करना होगा। यह जानना कि मस्तिष्क किस तरह से चीजों की गणना करता है, शॉर्टकट प्रदान कर सकता है। इससे शोधकर्ता मस्तिष्क के आवश्यक भागों का अनुकरण कर सकेंगे। अगर हमें यह पता चल जाए कि दिमाग कैसे काम करता है, तो शायद हमें हर छोटी चीज की नकल करने की जरूरत न पड़े। एक और तरीका हो सकता है-86 अरब न्यूरॉन्स को एक-एक करके कृत्रिम न्यूरॉन्स में बदलना। इससे दिमाग को अपलोड करना आसान हो जाएगा, लेकिन अभी वैज्ञानिक एक भी असली न्यूरॉन को कृत्रिम न्यूरॉन में नहीं बदल पाए हैं। प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेशक चुनौतियां बड़ी हैं और आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन माइंड अपलोडिंग 2045 तक मुमकिन हो सकती है। कुछ का मानना है कि यह सदी के अंत तक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 200 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। *-द कन्वर्सेशन से*

आंकड़े

इन्सान के हत्यारे

दुनिया में इन्सान समेत कुछ जीव ऐसे हैं, जो प्रतिवर्ष लाखों मनुष्यों की मौत का कारण बनते हैं। इनमें मच्छर सबसे ऊपर हैं।

मच्छर	7,25,000
मनुष्य	4,00,000
सांप	1,38,000
कुत्ते	59,000
हत्यारे बग	10,000

मनुष्य के आंकड़े हत्या करने के हैं, शेष जीवों से बीमारी फैलने के | स्रोत : BBC Science Focus

सूरदास जी कुएं में गिर गए और छह दिन तक उसी में पड़े-पड़े भगवान का नाम जपते रहे। सातवें दिन भगवान श्रीकृष्ण ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए।

अब इन नेत्रों से कुछ और न देखूं

अंतर्यात्रा
संकलित

भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे, बल्कि कुछ उम्र के बाद उनकी दृष्टि चली गई थी। बताया जाता है कि एक बार मुसलमानों से सूरदास जी के पिता का युद्ध हुआ, जिसमें उनके छह भाई मारे गए। सूरदास जी इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन वह कुएं में गिर पड़े और छह दिन तक उसी में पड़े-पड़े भगवान का नाम जपते रहे। सातवें दिन भगवान श्रीकृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि प्रदान कर अपने रूप का दर्शन कराया। सूरदास जी ने वर मांगा कि जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन किया है, उनसे और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं।

सूरदास जी को उद्धव का अवतार बताया जाता है। कहते हैं कि सूरदास जी के साथ उनके मुख से निकलने वाले पदों को लिखने के लिए एक लेखक निरंतर रहता था। कई अवसरों पर तो भगवान श्रीकृष्ण स्वयं लेखक बनकर लिखते थे। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि मेरे मुख से निकलने से पहले ही मेरी बात सिवाय भगवान के और कोई नहीं लिख सकता। उन्होंने तत्काल लेखक की बांह पकड़ ली। भगवान हाथ छुड़ाकर अंतर्धान हो गए। इस पर सूरदास जी ने लिखा, 'बांह छुड़ाए जात हौ, निबल जानिकै मोहि। हिरदै ते जब जाहुगे, मरद बदौंगो तोहि।।' सूरदास जी के पद भक्तों के हृदयों में बारंबार गूंजकर भक्ति की जोत जगा देते हैं।

आज का इतिहास

भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया

इतिहास में हर दिन किसी न किसी अहम घटना से जुड़ा होता है। पांच जून एक ऐसी तारीख है, जिस दिन कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। जून का पहला सप्ताह और उसमें भी पांच जून का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। दरअसल, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश के सबसे खुशहाल राज्य पंजाब को आतंकवाद के दंश से छुटकारा दिलाना चाहती थीं, लिहाजा उन्होंने यह सख्त कदम उठाया और खालिस्तान के प्रबल समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले का खात्मा करने तथा सिखों की आस्था के पवित्रतम स्थल स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया। समूचे सिख समुदाय ने इसे हरमंदिर साहिब की बेअदबी माना और इंदिरा गांधी को अपने इस कदम की कीमत अपने सिख अंगरक्षक के हाथों जान गंवाकर चुकानी पड़ी।

सही को सही कहने की बात

पहलगाम हमले के बाद किसी अन्य विपक्षी की तुलना में थरूर ने सरकार का सबसे ज्यादा समर्थन किया है और इसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है।

सुरेंद्र कुमार, पूर्व राजनयिक | **सियासत**

क्या आप किसी पुरानी राष्ट्रीय पार्टी का नाम बता सकते हैं, जिसके कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का पुतला जलाया हो, और उसे हारते हुए देखने के लिए कड़ी मेहनत भी की हो? क्या आप किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी का नाम बता सकते हैं, जिसके सांसद ने अपने दस मिनट लंबे और बेबाक ऑक्सफोर्ड यूनियन भाषण से शक्तिशाली ब्रिटिश राजनीति, शिक्षा और मीडिया को हिलाकर रख दिया हो, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा व्यवस्थित रूप से किए गए अकथनीय अन्याय व कुकृत्यों और उसकी नीतियों से जन्मे अकालों व आर्थिक दरिद्रता के दुष्चक्र को उजागर किया और सार्वजनिक रूप से माफी और क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे छह घंटे में करीब 70 लाख लोगों ने पसंद किया? उनके इस कार्य की देश के प्रधानमंत्री सहित पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं ने सराहना की, लेकिन खुद उनकी पार्टी इस पर चुप्पी साधे रही!

क्या आप किसी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी का नाम बता सकते हैं, जिसके सांसद ने 26 किताबें लिखी हों, जिनमें से ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्टसेलर रही हों, जिनके साप्ताहिक कॉलम भारत और विदेश में दो दर्जन से अधिक प्रकाशनों में छपते हैं और जिनकी पुस्तक 'एन एरा ऑफ डार्कनेस' ने उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। जिनकी वाद-विवाद और भाषण कला सेंट स्टीफेंस कॉलेज के दिनों से ही ऐसी रही है, जिसके बारे में कहानियां बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है? तिरुवनंतपुरम से चार बार सांसद रहे शशि थरूर लंबे, सुंदर, शालीन, अच्छे कपड़े पहनने वाले, स्टाइलिश और स्पष्टवादी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी धूम है। ट्विटर (अब एक्स) पर भारत में उनके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, जब तक कि शाहरुख खान, बिग बी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पीछे नहीं छोड़ दिया।

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि जब वह छोटे थे, तो काफी बीमार रहते थे। तब टीवी, इंटरनेट, फेसबुक या इंस्टाग्राम न होने के कारण, वह किताबें पढ़ने की तरफ आकर्षित हुए। यह उनके पिता द्वारा प्रोत्साहित की गई एक अच्छी आदत थी। वह 1978 में 22 वर्ष की आयु में फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी ग्रहण करने वाले सबसे कम उम्र के छात्रों में से एक थे। वह संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए और वहां 29 वर्ष बिताए, अवर महासचिव भी बने। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने की सोची और भारत के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन किस्मत और दुनिया की एकमात्र महाशक्ति उनके पक्ष में नहीं थी। हालांकि, उन्हें दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले, दो विदेश मंत्रियों और एक प्रधानमंत्री से ज्यादा।

वह तिरुवनंतपुरम से पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप तौर पर चुनाव लड़े, तो स्थानीय नेता इस बाहरी व्यक्ति से प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने काम से न केवल जनाधार बढ़ाया, बल्कि लगातार चार लोकसभा चुनाव जीते। एक बार भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा था कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन शशि विपक्ष के लिए ऐसा नहीं मानते। वह सरकार से वाजिब सवाल पूछने में नहीं हिचकिचाते, लेकिन जब सरकार कुछ सराहनीय करती है, तो सराहना करने से भी पीछे नहीं हटते। सितंबर 2014 में, वह मोदी को उनके संयुक्त राष्ट्र भाषण खासकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने के लिए बधाई देने वाले पहले लोगों में से एक थे।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 111 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

विचार

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।।

भावार्थः जब मनुष्य का अज्ञान तत्वज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परमतत्व-परमात्मा प्रकट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं।

नहीं सुधरेंगे राहुल

राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार अप्रिय कारणों से चर्चा में हैं। पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद उनके रुख-रवैये से एक बार को लगा था कि वह देश, काल, परिस्थितियों के हिसाब से दलीय स्वार्थों को परे रखकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना भी जान गए हैं, लेकिन वह ऐसा सोचने वालों को गलत साबित करके ही माने। आपरेशन सिंदूर थमने के साथ ही उन्होंने कथित उचित प्रश्न पूछने के बहाने मोदी सरकार पर ऐसे हमले करने शुरू कर दिए कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के लिए भी उनकी हां मे हां मिलाना कठिन हो गया। इससे उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। मोदी सरकार को नीचा दिखाने के साथ सेना के शौर्य की भी अनदेखी करने वाले उनके बयान सामने आते ही रहे। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान उनके बयानों को अपने पक्ष में भुनाने में जुट गया। राहुल गांधी और उनके सहयोगी इससे अवगत भी हुए, लेकिन शायद उन्होंने जिद पकड़ ली है कि उनके जो मन में आएगा, बोलेंगे, भले ही उससे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचे। वह रुके नहीं और उन्होंने अपने करीबी नेताओं के जरिये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल शशि थरूर पर हमले कराने शुरू कर दिए। सलमान खुर्शीद भी उनके करीबियों के निशाने पर आ गए। खुर्शीद का यह पीड़ा भरा प्रश्न वस्तुतः उनके लिए ही था कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है? राहुल ने कोई परवाह नहीं की। वह प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह तक कहने लगे कि ट्रंप ने मोदी को जैसे ही सरेंडर करने को कहा, वैसे ही उन्होंने कर दिया।

राहुल गांधी वहीं पहुंच गए हैं, जहां वह 2019 के लोकसभा चुनाव के समय थे और जब प्रधानमंत्री के प्रति तू-तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। वह भाषा की मर्यादा के साथ देशहित की अनदेखी कर अपना और अपनी पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। राहुल और उनके करीबी कुछ भी सोचें, यह जो छवि बनाई गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें परिपक्व नेता बना दिया है, उसे वह तार-तार करने में लगे हुए हैं। गलतबयानी और अपमानजनक भाषा के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी और उसकी फटकार भी सुननी पड़ी। गत दिवस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें सेना का अपमान करने के लिए फटकार लगाई और यह नसीहत भी दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा है। इस पर राहुल शायद ही ध्यान दें, क्योंकि वह इस नतीजे पर पहुंच गए लगते हैं कि राजनीतिक विरोधियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के प्रति भद्दी भाषा का प्रयोग करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

घुसपैठिये बड़ी समस्या

राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ठिकाना बनना बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। भिलाई में अब तक बांग्लादेशी सात घुसपैठिये पकड़े गए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में ये लोग ठेका श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसी गोपनीय जानकारी सरकार के पास पहुंची है। इतना ही नहीं आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को पता चला है कि राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दौरान करीब पांच हजार घुसपैठियों ने प्रदेश में अपना ठिकाना बनाया है। इन गोपनीय सूचनाओं के आधार पर सरकार ने इनकी पहचान के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया है। इसका काम राज्यभर में घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ कर बिहार, झारखंड होते हुए ये लोग छत्तीसगढ़ आए और यहां चोरी-छिपे रह रहे हैं। झारखंड की सीमा पर स्थित बलरामपुर जिला घुसपैठियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल बन गया है। इनको नागरिकता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका होती है। राज्य में समय-समय पर स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं। इनमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास वार्डवार एक-एक वोट का हिसाब रहता है। ऐसे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इन लोगों के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। वोट बैंक की वजह से जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। यहां तक कि वे एक तरह से इनके सहयोगी ही साबित होते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है कि समाज में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो राष्ट्र विरोधी कार्य करने में तनिक भी संकोच नहीं कर रहे हैं। सरकार की एक सीमा होती है और यह सीमा जहां समाप्त होती है, वहां से समाज और नागरिकों के कर्तव्य प्रारंभ होते हैं। इस समस्या पर तभी अंकुश लग सकता है, जब समाज अपनी जिम्मेदारी पूरी इमानदारी से समझे और उसे निभाये।

> स्थानीय निकाय में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास वार्डवार एक-एक वोट का हिसाब रहता है। ऐसे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि घुसपैठियों के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

नईदुनिया जनमत

कल का परिणाम

कांग्रेस का यह निष्कर्ष सही है कि पीएम मोदी को जी-7 बैठक में न्योता न मिलना बड़ी कूटनीतिक विफलता है?

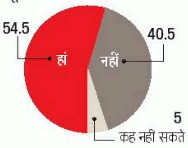

आज का सवाल
क्या पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेंगे?

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भारत को खुद कहनी होगी अपनी कहानी

विकास सारस्वत

एक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को अंतर्मुखी स्वभाव छोड़कर पूरे विश्व को अपना सरोकार बनाना होगा

आपरेशन सिंदूर की समाप्ति के बाद कुहासे के बादल छट गए हैं। देश-विदेश के तमाम रक्षा विशेषज्ञ और उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों से पुष्टि हुई कि यह संघर्ष पूरी तरह एकतरफा था और पाकिस्तान को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। इस सैन्य संघर्ष में दुनिया ने भारत की स्वदेश निर्मित सैन्य उपकरणों की बेजोड़ क्षमताओं का लोहा भी माना। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य शौर्य और रक्षा क्षेत्र की उद्यमशीलता ने आशा से अधिक प्रभावित किया है, परंतु इस कठिन समय में जो एक कमी खली, वह थी सूचना क्षेत्र में भारत की ढिलाई। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आपरेशन सिंदूर की बयानगी को लेकर न सिर्फ भारतीय चिंताओं की अनदेखी हुई, बल्कि पाकिस्तानी दावों को बिना जांचे-परखे आगे बढ़ाया गया। न्यूयार्क टाइम्स, सीएनएन, वालस्ट्रीट जर्नल, निक्केई एशिया, ब्लूमबर्ग आदि में भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव की ज्यादातर रिपोर्टिंग पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा की गई। समाचार एजेंसी रायटर्स ने तो एक ऐसे गुमनाम पाकिस्तानी लेखक सईद शाह के तीन लेख प्रकाशित किए, जो उस दौरान ही कार्यरत रहा। ये पाकिस्तानी पत्रकार केवल पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा ही आगे बढ़ाते रहे। कई पश्चिमी मीडिया माध्यम जाने-अनजाने उनसे प्रभावित भी होते रहे। हालांकि बाद में न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट आदि ने भारतीय दावों की पुष्टि की और इस संघर्ष को भारत की जीत बताया, परंतु युद्ध के दौरान जब मीडिया रिपोर्टिंग देशों के मनोबल और जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, तब पहले चलाए गए झूठे प्रोपेगंडा की बाद में परिशुद्धि संभव नहीं हो पाती।

यह पहली बार नहीं, जब अंतरराष्ट्रीय और खासकर पश्चिमी मीडिया ने भारत के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया हो। भारत दशकों से आतंक की मार झेलता रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया को 'वार आन ग्लोबल टेरर' की याद 9/11 के बाद ही आई। भारत में चल रहे आतंकवाद को वह अब भी कश्मीर विवाद से जोड़कर या फिर भारत में ''बढ़ते उग्र राष्ट्रवाद'' की प्रतिक्रिया के रूप में ही देखता है। भाषा, संप्रदाय की दृष्टि से विविधता भरे देश में इतना सफल जनतंत्र होने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र पर अनर्गल टिप्पणियां होती रहती हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सफलता मिलने पर भारत को उलाहने मिलते हैं और यहां की समस्याओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है। यह कथानक भेद का ही परिणाम है कि ओसामा का मारा जाना सकारात्मक समाचार बनता है, पर आतंकी निज्जर की मौत और पन्नू की जान को कथित खतरे पर भारत सरकार को घेरने का प्रयास होता है। पश्चिमी सरकारों और पाश्चात्य मीडिया में सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता के कारण भारत के प्रति वह संवेदनशीलता नहीं, जो सामान्यतः दिखनी चाहिए। एक उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति होने के कारण भी पश्चिमी दृष्टिकोण में भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव झलकता है। इस सबके बावजूद भारत केवल पश्चिम के असत्य और पूर्वाग्रहों का उल्लेख भर करके चुप नहीं रह सकता। अपने बढ़ते वैश्विक प्रभाव के मध्य भारत को न सिर्फ अपना अपना कथानक, अपनी कहानी स्वयं कहनी-बनानी होगी, बल्कि उसे वैश्विक समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण से दुनिया को भलीभांति परिचित भी कराना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया में स्थान तलाशने के अलावा भारतीयों को स्वतंत्र छवि वाले ऐसे विश्वसनीय मीडिया मंच तैयार करने होंगे, जो भारतीय परिदृश्य में घटनाओं को देखते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी समीक्षा कर सकें। यह दायित्व सरकारी न होकर भारत के ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार-विचारक वर्ग को उठाना होगा, जिसका मानस पश्चिमी या चीनी परतंत्रता से मुक्त हो। इसका वित्तीय प्रबंध उन निवेशकों को करना होगा, जो निवेश पर प्रतिफल के बजाय इस प्रयोजन के महत्व से प्रेरित हों। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक देश के तौर पर हमारी मनःस्थिति में परिवर्तन आए।

अवधेश राजपूत

दीर्घकालिक विदेशी उपनिवेशवाद ने आमजन के साथ-साथ भारत के प्रबुद्ध वर्ग को भी आत्मसंशय और संकोच से भर दिया है और वह न केवल अपने देसी खोल में सिमटकर रह गया है, बल्कि पाश्चात्य विश्वदृष्टि के पराधीन भी हो गया है। एक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को अंतर्मुखी स्वभाव से निकलकर पूरे विश्व को अपना सरोकार बनाना होगा। मीडिया के अलावा इसी प्रत्याशा हेतु थिंक टैंक, शोध संस्थान, पर्यवेक्षी निकाय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भी बनाने होंगे। इनके द्वारा वैश्विक विषयों पर टिप्पणियों के अलावा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सहिष्णुता जैसे मानकों पर पश्चिमी देशों की समीक्षा भी करनी होगी। इसी के साथ सिनेमा, सीरियल और साहित्य जैसी विधाओं को भी अपना दृष्टिकोण वैश्विक करना होगा। कुछ और बिंदुओं पर सरकार को भी ध्यान देना होगा। आपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने भारतीय पक्ष समझाने को विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जो पहल की, वह समय-समय पर करनी होगी। राजनयिकों के अलावा नेताओं और बुद्धिजीवियों के स्तर पर भी आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर भारत का विश्व से संवाद एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए और ऐसे संभाषणों के लिए संस्थागत प्रयास भी होने चाहिए। भारत के विरुद्ध कुप्रचार को हवा मिलने का बड़ा कारण संवाद की कमी और संवाद में देरी भी रहती है।

पुरानी कहावत है कि जब झूठ आधी दुनिया घूम आता है, तब सच अपने जूते पहन रहा होता है। भारतीय सेना के तीन डीजीएमओ ने तो प्रेस कांफ्रेंस में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, परंतु उसके पहले संवादहीनता के कारण ऐसी बातों को बढ़ावा मिला, जिनके जरिये कहा गया कि अमेरिकी और चीनी मध्यस्थता के कारण भारत ने संघर्ष विराम किया। बदलते परिदृश्य में जब भारत को प्रभावित करने वाले मुद्दे रोजाना विमर्श का विषय बनते हैं, तब यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से भी व्हाइट हाउस की तर्ज पर प्रतिदिन प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा जाए। हमें यह समझना होगा कि कथानक को प्रभावित करने की क्षमता के अभाव में पश्चिम अपने एजेंडे के हिसाब से भारत के प्रति खास संदेश देने वाली अपनी कहानियों को आकार देता रहेगा। यानी वही नैरेटिव शेपिंग करता रहेगा।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

हरित भारत के प्रति समर्पित रेलवे

अश्विनी वैष्णव

भारत यह साबित कर रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता एक साथ संभव है

हर बार आप जब परिवहन के अन्य साधनों के बजाय रेलगाड़ी से यात्रा करने का चुनाव करते हैं, तो केवल आराम या सुविधा ही नहीं चुन रहे होते। आप एक स्वच्छ एवं हरित भारत को भी चुन रहे होते हैं। पिछले वर्ष 700 करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा के साधन के रूप में भारतीय रेल को चुना। रेल हमारी जीवन रेखा है और भविष्य के लिए एक हरित वादा भी। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेलवे सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। रेलवे देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए पंचामृत लक्ष्यों-2070 तक शून्य उत्सर्जन को साकार करने में सहायता कर रहा है और एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इसे संभव बना रहा है। यातायात को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित करके और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा स्रोतों के साथ परिचालन को शक्ति प्रदान करके इस दिशा में बढ़ रहा है। ये कदम देश को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को विकार्बनित (डीकार्बोनाइज) करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

यात्रा सेवाओं के साथ ही माल ढुलाई में भी रेलवे की महत्ता समय के साथ बढ़ती जा रही है। 2013-14 में भारतीय रेल ने लगभग 105.5 करोड़ टन माल की ढुलाई की। 2024-25 के दौरान यह ढुलाई बढ़कर 161.7 करोड़ टन हो गई है। इससे भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे बन गया है। विशेषज्ञों द्वारा की गई गणनाओं का उपयोग करते हुए सड़क के बजाय रेल के जरिये माल ढुलाई से संबंधित इस बदलाव ने 14.3 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। यह 121 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। रेल द्वारा माल परिवहन की लागत सड़क मार्ग से होने वाले परिवहन की लागत की लगभग आधी है। इसका अर्थ है कि न केवल व्यवसायों, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बचत। इस बदलाव से पिछले दशक में लाजिस्टिक्स की लागत में 3.2 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। भारतीय रेल स्वच्छ भी है और ट्रकों की तुलना में इससे 90 प्रतिशत कम कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है। परिणामस्वरूप हमारे आसमान में कम धुआं निकलता है और हमें स्वच्छ हवा मिलती है। सड़क से रेल की ओर होने वाले इस बदलाव ने हमें 2,857 करोड़ लीटर डीजल की बचत कराई है, जो ईंधन लागत में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की बचत के बराबर है। चूंकि भारत तेल आयात करता है, इसलिए परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण करना रणनीतिक रूप से एक समझदारी भरा कदम है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। 2014 से पहले के 60 वर्षों में भारतीय रेल ने 21,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया। जबकि पिछले 11 वर्षों के दौरान हमने 47,000 किमी रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया है। आज हमारे ब्राड गेज नेटवर्क का 99 प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत है। भारतीय रेल स्टेशनों, कारखानों और कार्यशालाओं के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग तेजी से कर रहा है। अब यह रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए अधिक हरित ऊर्जा प्राप्त करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह सब भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता देगा। इस गति को आगे बढ़ाते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी) को विद्युतीकृत किया गया है। उच्च क्षमता वाली रेलवे लाइनें भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से माल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। कुल 2,741 किमी परिचालन के साथ डीएफसी ने सड़कों पर भीड़भाड़ कम की है और डीजल की खपत एवं कार्बन उत्सर्जन को भी घटाया है। भारत हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जैसी आधुनिक, शून्य-उत्सर्जन तकनीक भी अपना रहा है। पहली ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और 2,600 यात्रियों को ले जाएगी। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी।

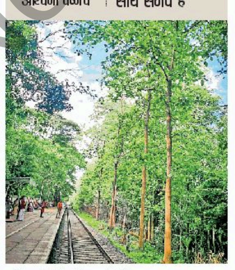

पर्यावरण हितैषी भी है भारतीय रेल ● फाइल

भारत यह साबित कर रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी एक साथ निभाई जा सकती है। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स परफारमेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत अब 139 देशों में 38वें स्थान पर है, जो 2014 की तुलना में 16 स्थान ऊपर है। रेलवे विद्युतीकरण के विस्तार ने लागत और उत्सर्जन को कम किया है। इसने गति और क्षमता भी बढ़ाई है, जिससे भारत को विश्वस्तरीय लाजिस्टिक्स मानकों के निकट पहुंचने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2030 का लक्ष्य तय किया है। विद्युतीकरण और माल को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित करने के कारण भारतीय रेलवे 2025 तक ही नेट जीरो (स्कोप 1) हासिल करने की ओर अग्रसर है। भारतीय रेलवे सतत विकास के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहा है, इसलिए हर विद्युतीकृत ट्रैक, हर सौर पैनल और सड़क से हटा प्रत्येक मालवाहक कंटेनर हमारे लोगों और हमारी धरती के उज्ज्वल भविष्य के प्रति एक शपथ है।

(लेखक केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म के स्तंभ

धर्म भगवत्प्रतिपादित सृष्टि के ऊषा काल से एक सार्वभौम शाश्वत नियम-व्यवस्था है, जिसके सहज अनुपालन से सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे वेद, समृतियां और पुराणादि में जो प्राणिमात्र के कल्याण के सदुपदेश वर्णित और निर्देशित हैं, उनके अनुपालन से व्यक्ति लोक-परलोक में यशस्वी होता है। व्यक्ति को जानबूझकर उपेक्षित और नष्ट किया हुआ धर्म ही मारता है और श्रद्धापूर्वक रक्षित किया हुआ धर्म ही उसको उत्तम जीवन देता है। सत्य ही कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है, तब धर्म ही उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करता है।

धर्मविहीन जीवन अमर्यादित एवं उच्छृंखल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से अनाचार फैलता है। आचार-विचार, आहार-विहार और विश्रामादि समस्त दैनिक कार्यों को धर्मानुसार ही करना चाहिए। धर्मनियंत्रित जीवन ही स्वस्थ-सुंदर समाज का निर्माण करता है। धर्म से विमुख होने के कारण व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में अपनत्व का नितांत अभाव हो रहा है। संप्रति, सहज स्नेह के स्थान पर व्यवहार में शुष्क औपचारिकता मात्र प्रदर्शित है। धर्म ही मनुष्य की विशेषता है। धर्मविहीन होने से समाज में साधुता विलुप्त हो जाती है। स्वार्थ और अभिमानमूलक सोच के दुष्प्रभाव से पाखंडवाद का दानव मानव के सांस्कृतिक मूल्यों को छिन्न-भिन्न कर देता है।

धर्म के मुख्य चार स्तंभ हैं-सत्य, दया-दान तप और पवित्रता। जो व्यक्ति सत्य की उपेक्षा नहीं करता है, वह आध्यात्मिक ताप से प्रभावित नहीं होता। जिसमें दया-दान जैसे दैवीय सद्गुण जागृत रहते हैं, उस पर आधिदैविक ताप का प्रभाव नहीं रहता है। जिसका आचार-विचार पवित्र और जो तपस्वी है, आधिभौतिक उससे बहुत दूर रहता है। तप का तात्पर्य है-अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्मानुशासन को शिरोधार्य किए रहना। धर्म के यही स्तंभ जीवन की आधारशिला हैं।

-आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

letter@naidunia.com

विपक्ष के समझदार नेता

'देश हित पर भारी पड़ते दलगत हित' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने देश के उन विपक्षी नेताओं की नासमझी पर क्षोभ प्रकट किया है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं की आलोचना करने में गुरेज नहीं किया, जो विदेशी धरती पर अपनी राष्ट्रहितैषी बयानबाजी से विपक्ष के समझदार नेता बन गए हैं। देश में विपक्षी नेता के तौर पर भाजपा और मोदी सरकार के आलोचक माने जाने वाले कांग्रेस के शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, डीएमके की कनिमोरी के अलावा एआइएमआइएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश में जाकर जिस समझदारी से देश के मान-सम्मान का खयाल रख 'आपरेशन सिंदूर' पर भारत के पक्ष को रखा, उसकी जितनी सराहना की जाए, कम है। बावजूद इसके कांग्रेस के कुछ नासमझ नेता सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विभिन्न देशों में 'आपरेशन सिंदूर' पर सकारात्मक रूप से भारत का पक्ष रखने वाले सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे समझदार नेताओं की आलोचना करने में व्यस्त हैं। भला इससे भी अधिक लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जयराम रमेश जैसे नेता इस काम को अंजाम देकर अपने आका को खुश करने में लगे हैं।

pandeyvp1960@gmail.com

अब तो बदल जाओ

अग्रलेख 'कांग्रेस का विचित्र रवैया' पढ़कर तो यही लगता है कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कई दशकों में जो नहीं कर पाई थी, वह सत्ताधारी भाजपा ने पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में कर डाला। यही बात कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्व में भारत का चौथे नंबर पर आना भी कांग्रेस को नहीं भा रहा है। कांग्रेस नेताओं की किसी भी क्षेत्र में सत्ताधारी दल की उपलब्धि में मीनमेख निकालना आदत बन गई है। पिछले 11 वर्ष से भाजपा केंद्र सरकार में है और भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनसे भारतीय जनमानस ही नहीं, बाकी दुनिया भी हतप्रभ है। कांग्रेस के नेताओं को अड़ियल रुख छोड़कर सरकार की उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए।

– **नरेश कानूनगो 'शोभना'**, राजाराम नगर, देवास

अच्छी चीज है स्वीकारोक्ति

समाचार : मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 'संगठन सृजन अभियान' की शुरुआत की।

टिप्पणी: कांग्रेस अपनी स्थापना के 140 वर्षों बाद संगठन का सृजन कर रही है। यह स्वीकारोक्ति है कि अब तक कांग्रेस में संगठन नामक कोई चीज थी ही नहीं, यह तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रही है। अभी भी अध्यक्ष तो मुख्य भूमिका में हैं ही कहां?

– **शरद कटारिया,** अन्नपूर्णा रोड, इंदौर

किशोर एवं युवा बनें जागरूक

वर्तमान में बड़े पैमाने में जिस ढंग से अपराधों में तेजी आई है इसमें किशोर एवं युवा की संलिप्तता सामने आई है। एक सर्वे के मुताबिक बड़े अपराधी ऐसे किशोर एवं युवा को फंसते हैं जो बेहद जरूरतमंद के साथ बहुत महत्वकांक्षा पाले हुए रहते हैं। बड़े अपराधी ऐसे लोगों को गुमराह करके उनका उपयोग करते हैं। ऐसे समय में किशोर एवं युवक को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के लिए मोहरा न बनें। बीते दिनों रायपुर और भिलाई में बड़ी संख्या में साइबर अपराध में इस प्रकार की सक्रियता देखने के बाद इसे समझा जा सकता है, कम समय में अधिक पाने की चाह में ये लोग अपराध के दुनिया में कदम रखे बाद में लौटकर जाने की इच्छा के बाद भी नहीं लौट सके और बुराई के दलदल में गले तक फंस गए। पुलिस भी इस बेहतर समझती है परंतु अपराध में संल्पित रहने के कारण वे कार्रवाई करने के लिए विवश है। इस संबंध में साइबर से संबंधित अपराध से बचने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है जिससे वे गलतियों के साथ ही अपराधियों से दूर रह सके। इसी प्रकार की जानकारी प्रदेश भर में सामने आई जब इस आयु वर्ग के लोग बड़ी संख्या में एक ही प्रकार के अपराध में पकड़े गए।

– **केशव प्रसाद,** बिलासपुर

पोस्ट

जीवन में ऐसा कोई काम नहीं, जो पूरा न हो सके, इसलिए किसी का मजाक न बनाएं। आरसीबी ने 18 साल में जितने ताने सुने, उतने शायद ही किसी ने सुने होंगे, लेकिन विराट कोहली ने सबका मुंह बंद कर दिया।
भानु नंद@BhanuNand

एक सामान्य कार्यदिवस वाले दिन भी एक लाख की क्षमता वाले स्टेडियम का भरा रहना और करोड़ों लोगों का उसे स्क्रीन पर देखना दर्शाता है कि भारत में क्रिकेट का कितना जुनून है।
केविन पीटरसन@KP24

जब राहुल गांधी ने उपहास करते हुए कहा था कि ट्रंप ने फोन करके मोदी से सरेंडर करने को बोला... तो क्या उन्हें पता था कि ऐसा करके वह कांग्रेस पार्टी का कितना अहित कर रहे हैं? यह किसी स्कूली बहस का नहीं, बल्कि युद्ध से जुड़ा मसला था, लेकिन लगता है कि उन्हें इसका अंतर नहीं पता।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों को बकरीद पर नमाज या कुर्बानी पर 5 लाख रु. हर्जाना देना होगा। पाकिस्तान निर्माण में इन्हीं अहमदिया ने अहम भूमिका निभाई थी।
कमलेश सिंह@kamleshksingh

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/19457 जागरण प्रकाशन लि.के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस सेक्टर 1, प्लॉट नं 12,13 एवं 14 सिरगिट्टी, बिलासपुर से मुद्रित एवं 2री मंजिल, महिमा ट्रेड सेंटर, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर से प्रकाशित इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com, **संपादक** : सद्गुरु शरण * *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

****

जलवायु परिवर्तन के खतरे

जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनेक अध्ययनों के बीच न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के शोध में बदलाव के बारे में आयी विस्तृत जानकारी हैरान-परेशान करने वाली है, जो विज्ञान पत्रिका 'साइंस' में प्रकाशित हुई है. अध्ययन के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों के कारण ऋतुचक्र तेजी से बदल रहे हैं, जिनका असर सिर्फ मौसम पर नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति और इंसानों की जिंदगी पर पड़ रहा है. गर्मी, सर्दी और बारिश-हर मौसम की अपनी खास भूमिका होती है, लेकिन अब ये समय पर नहीं आ रहे. जलवायु परिवर्तन के कारण वसंत पंद्रह दिन पहले आ रहा है, तो पतझड़ पंद्रह दिन देर से शुरू हो रहा है. इसके कारण पौधों के बढ़ने की अवधि 50 वर्षों में लगभग एक महीना बढ़ी है. गर्मी के दिनों में औसतन पांच-दस दिन की वृद्धि हुई है, तो सर्दी की अवधि घटी है. बर्फबारी कम हो रही है और बर्फ जल्दी पिघलने लगी है. मानसून अनिश्चित हुआ है, यानी कभी बहुत तेज बारिश होती है, तो कभी सूखा पड़ता है. प्रवासी पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों के जीवन चक्र में भी बदलाव आया है. जहां तक मानव स्वास्थ्य का सवाल है, तो गर्मियों की अवधि लंबी और तीव्रता ज्यादा होने से गर्मी से जुड़ी बीमारियों और मृत्युदर में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है. कृषि क्षेत्र में फसलों की बुवाई और कटाई के समय में बदलाव के कारण उपज में गिरावट आयी है, सिंचाई समय पर नहीं हो रही और कीटों के प्रकोप का खतरा बढ़ा है. गर्म ऋतु के लंबे होने से जंगल में आग लगने की घटनाएं और तीव्रता बढ़ी है. जलवायु परिवर्तन से महासागरों के अंदर रोशनी घटी है, जबकि समुद्री खाद्य श्रृंखला तथा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए रोशनी जरूरी है. ऋतु परिवर्तन से जानवरों के प्रजनन का चक्र गड़बड़ाया है और बच्चों के जीवित रहने की दर घटी है. बर्फीले इलाकों में पाया जाने वाला खरगोश- स्नो रैबिट- सर्दी में सफेद और गर्मी में भूरा हो जाता है, ताकि शिकारियों से बच सके. लेकिन समय पर बर्फ न गिरने से वह सफेद ही रह जाता है और दिख जाता है. ऐसे में, उसके शिकार होने का खतरा बढ़ा है. जलवायु परिवर्तन पर दूसरे तरह के अध्ययनों में भी प्रकृति, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर खतरों के बारे में बताया गया है. इससे बचने के लिए जीवन पद्धति में बदलाव के साथ-साथ वैश्विक नीतियों में भी बड़ा बदलाव जरूरी है.

विज्ञान पत्रिका 'साइंस' में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से प्रकृति तथा पशु-पक्षियों के जीवन में तो बदलाव आ ही रहे हैं, गर्मियों की अवधि लंबी और तीव्रता ज्यादा होने से मनुष्य में गर्मियों से जुड़ी बीमारियों और मृत्युदर में वृद्धि हो रही है.

ग्लेशियरों पर मंडराता संकट चिंताजनक

विश्व पर्यावरण दिवस विशेष

पद्मश्री डॉ अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरण कार्यकर्ता
dranilpjoshi@gmail.com

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किये गये एक हालिया अध्ययन के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान में इसी तरह तेज वृद्धि दर्ज होती रही, तो दुनियाभर के सभी ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में पहुंच जायेंगे, जिससे समुद्र का जलस्तर लगभग 113 मिलीमीटर तक बढ़ जायेगा. भारतीय और अन्य देशों के अध्ययनों के आधार पर भी यह पाया गया है कि हिमालय की ऊंचाइयों में अब ग्लेशियर झीलों का रूप ले रहे हैं और इससे भविष्य में विनाशकारी बाढ़ की आशंका बढ़ रही है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किये गये एक हालिया अध्ययन ने दुनियाभर के हिमनदों, यानी ग्लेशियरों से जुड़े चौंकाने वाले और गंभीर तथ्य सामने रखे हैं. अपने अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने दुनियाभर के करीब दो लाख ग्लेशियरों की स्थिति की पड़ताल की. इस अध्ययन में 10 देशों से ताल्लुक रखने वाले लगभग 15 से 21 वैज्ञानिकों ने भाग लिया. इन वैज्ञानिकों ने अब अपने अध्ययन की जानकारी दुनिया के सामने रखी है. इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनियाभर के हिमनदों की स्थिति पर आधारित था और इसमें यह समझने की कोशिश की गयी कि जिस तरह वैश्विक तापमान में तेज वृद्धि दर्ज हो रही है, वह कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारे जल और पेट पर गहरा असर डालेगी. यदि हालात ऐसे ही बने रहे, तो जब दुनिया का औसत तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जायेगा, तब वर्तमान की तुलना में मात्र 24 प्रतिशत ग्लेशियर ही बचे रहेंगे. और यदि हम तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में सक्षम हो भी गये (जैसा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में तय किया गया है), तब भी हमारे पास केवल 54 प्रतिशत ग्लेशियर ही बचे रहेंगे. यह निष्कर्ष उपरोक्त अध्ययन के आधार पर सामने आया है और इसके तथ्य एकदम स्पष्ट हैं, क्योंकि हाल ही में नेपाल का एक विशाल ग्लेशियर पूरी तरह समाप्त हो चुका है. इतना ही नहीं, कुछ समय पहले ही स्विट्जरलैंड में भी एक बड़ा ग्लेशियर अपना अस्तित्व खो चुका है.

यदि वर्तमान हालात ऐसे ही बने रहे, तो दुनियाभर के सभी ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में पहुंच जायेंगे, जिससे समुद्र का जलस्तर लगभग 113 मिलीमीटर तक बढ़ जायेगा. ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि यदि ऐसा हुआ, तो उन सभी देशों का और टापुओं पर जीवन संकट में पड़ जायेगा जो समुद्र तट पर स्थित हैं. इससे बड़ी त्रासदी शायद ही कोई और होगी. अध्ययन में यह भी पाया गया कि सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति कनाडा, अमेरिका, यूरोप, स्कैंडिनेविया और भारत जैसे देशों की है. भारत, जो पहले से ही एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इस बदलाव के सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभावों को झेलेगा. यदि तापमान वृद्धि दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है, तो पूर्वी स्कैंडिनेविया का एक बड़ा हिस्सा अपने ग्लेशियरों को खो देगा और वहां कोई भी हिमखंड शेष नहीं बचेगा. यूरोप में भी केवल 10 से 15 प्रतिशत ग्लेशियर ही बचे रहेंगे. यह स्थिति अत्यंत गंभीर है, पर हम इसे समझने में विफल साबित हो रहे हैं. जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को लेकर दुनियाभर में तमाम बैठकें और चर्चाएं हुई हैं. पर इन तमाम बैठकों और चर्चाओं के बावजूद हम अभी तक किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं और न ही इस बात को समझ पा रहे हैं कि तापमान में थोड़ा सा भी परिवर्तन धरती पर कितनी बड़ी आपदा को जन्म दे सकता है. वैज्ञानिक स्तर पर इस विषय पर बहस अवश्य होती रही है और इस विषय की गंभीरता को माना भी जाता रहा है. पर तापमान वृद्धि किसी एक देश की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है. वर्तमान जीवनशैली ही इस बढ़ते तापमान की प्रमुख वजह है. हमें इस बात को समझना होगा कि तापमान में 0.01 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का प्रभाव कई गुना अधिक होता है. ठीक वैसे ही जैसे भूकंप के रिक्टर स्केल में मामूली वृद्धि भी बड़े नुकसान का संकेत देती है. इसी प्रकार, ग्लोबल वार्मिंग का असर भी सीधा और बहुत बड़ा होता है.

हिमालय के ग्लेशियर विशेष रूप से खतरे में हैं, खासकर हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के, जहां ग्लेशियरों का आकार घटता जा रहा है और वे झीलों में परिवर्तित हो रहे हैं. भारतीय और अन्य देशों के अध्ययनों के आधार पर भी यह पाया गया है कि हिमालय की ऊंचाइयों में अब ग्लेशियर झीलों का रूप ले रहे हैं और इससे भविष्य में विनाशकारी बाढ़ की आशंका भी बढ़ रही है. यदि तापमान वृद्धि की यही गति बनी रही, तो सदी के अंत तक हम केवल 20 से 25 प्रतिशत हिमालयी ग्लेशियर ही देख पायेंगे. यहां प्रश्न यह उठता है कि इन अध्ययनों के आधार पर अब हम कौन से बड़े निर्णय लेंगे? पिछले 30 वर्षों में हमने इन परिवर्तनों को देखा है और आइपीसीसी की रिपोर्टें भी लगातार आती रही हैं. जबकि सरकारें और नीति-निर्माता इन रिपोर्टों से परिचित हैं, फिर भी अब तक हम किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं. यह एक चिंताजनक स्थिति है. आइपीसीसी की रिपोर्टें हर वर्ष आती हैं, लेकिन वे कहीं न कहीं नजरअंदाज हो जाती हैं. इनमें चर्चा होती है कि परिवर्तन के मद्देनजर नियम बनाने चाहिए और सीमाएं तय करनी चाहिए. इन सब चर्चाओं के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी बात करना जरूरी है. जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए दुनियाभर में स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे प्रयोग किये गये हैं, जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, हिमालय में एचइएससीओ नामक संस्था ने एक अनूठा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन प्रयोग किया, जिससे न केवल वनों की पुनः स्थापना हुई, बल्कि सूखी नदी में फिर से पानी भी आ गया, वन्य जीवन को पुनः स्थान मिला और पशु-पक्षियों की वापसी भी हुई. यह प्रयोग ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक सफल उदाहरण है और यह सब स्थानीय लोगों की सहभागिता से संभव हो सका है. इस तरह के अनेक प्रयोग दुनिया में हुए हैं जिन्हें आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया है.

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अब एक नयी पहल की जा रही है. इस पहल के तहत एक संगठन- अलायंस फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट (एजीटी)- की स्थापना की जा रही है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन वैज्ञानिकों और संस्थाओं के प्रयोगों को एक मंच पर लाना है जिन्होंने स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सफल प्रयास किये हैं. इस संगठन की पहली बैठक पांच जून को ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित की जा रही है. आने वाले समय में जब एक ओर हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों से परिचित होंगे, वहीं दूसरी ओर हम यह भी बताने में सक्षम होंगे कि कौन से प्रयोग वर्तमान संकट को संभालने में सहायक हो सकते हैं. यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

गंगा भी बनी थी जेपी आंदोलन की गवाह

अब्दुल बारी सिद्दीकी
पूर्व मंत्री, जेपी आंदोलनकारी
delhi@prabhatkhabr.in

संपूर्ण क्रांति दिवस

वह आंदोलन इतना सफल क्यों हुआ? बहुत साफ है. जनता समझ गयी थी कि जेपी को सत्ता से कोई लेना-देना नहीं है. देश से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म करना ही उनका मकसद है.

पांच जून 1974. पटना के हर रास्ते से भारी भीड़ गांधी मैदान की तरफ जा रही थी. पूरे सूबे से जनता पटना की सड़कों पर थी. सुबह के दस से ग्यारह बजे के बीच पटना जाम हो गया. वक्त बीतने के साथ हुजूम बढ़ता जा रहा था. पूरे राज्य में भीड़ को पटना आने से रोकने की कोशिश होने लगी. जगह-जगह बैरिकेडिंग. सड़क पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया. गंगा किनारे से आ रही भारी भीड़ प्रशासनिक दबिश का शिकार हो गयी. जहां-तहां उन्हें रोक दिया गया. फिर आंदोलनकारियों ने उसकी काट खोजी. केले के तने काटे और उसे नाव का आकार दिया. फिर नाव को गंगा में उतार दिया. खासकर वैशाली व मुजफ्फरपुर से बारी-बारी से नाव से आया जत्था सभास्थल पहुंचने लगा. इसे गुप्त रखा गया. वाहनों के रोके जाने के बाद भी आती भीड़ को देखकर सरकारी अमला हतप्रभ था.

दोपहर के तीन बजे तक गांधी मैदान खचाखच भर गया. लगभग साढ़े तीन बजे जयप्रकाश नारायण के सभास्थल पर आने की घोषणा हुई. मुझे ठीक-ठीक याद है. शाम के लगभग चार बज गये होंगे. जेपी मंच पर थे. सरकार विरोधी नारे से आसमान गूंज रहा था. जेपी के माइक पर आते ही नारों का शोर बढ़ गया. आलम ये था कि जेपी के एक इशारे पर पटना आंदोलनकारियों के कब्जे में आ जाता. मगर सब लोग अपनी जगह पर थे. जेपी का भाषण शुरू हुआ. उम्मीद थी कि वे जोशीला भाषण देंगे. मगर, जेपी तो जेपी ठहरे. भाषण शुरू होते ही शोर एकदम से थम गया. जेपी ने कहा, 'हमें गांधी जी के रास्ते पर चलना है. आंदोलन बिल्कुल अहिंसात्मक होगा और संविधान के दायरे में होगा. कोई गैरकानूनी काम हम नहीं करेंगे'. सब एकाग्रचित्त होकर जेपी को सुन रहे थे. जेपी ने कहा, 'तत्कालीन सरकार विनाश काले, विपरीत बुद्धि की तरह है. यह आंदोलन सिर्फ सरकार गिराने के लिए नहीं है. बल्कि यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए है.' भीड़ बिल्कुल संयमित हो गयी. जेपी ने मंच से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया. फिर वे मंच से उतर गये.

तब तकरीबन पांच से साढ़े पांच बजे का समय होगा. जेपी खुली जीप में सवार हुए. आंदोलनकारी उनके पीछे-पीछे. गांधी मैदान से जुलूस सचिवालय की ओर कूच कर गया. गौर करना होगा. जुलूस के आगे-आगे छात्रों और नौजवानों की फौज थी. इस कारण इस आंदोलन को छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना गया. गांधी मैदान से आयकर गोलंबर, डाक बंगला चौराहा होते हुए सचिवालय जाने का रूट निर्धारित था. छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सब एक ही रंग में रंग गये थे. 'जेपी नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है', ये नारे बार-बार लग रहे थे. नारों में सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा था. एक बात और महत्वपूर्ण है. जेपी का विचार कितना विराट था. तत्कालीन सरकार के खिलाफ उग्र नारे लग रहे थे. जेपी ने तब फौरन कहा : 'हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, पर व्यवस्था में बदलाव लाकर रहेंगे'. छात्र संघर्ष समिति के युवा टोली में सबसे आगे थे. उनका जोश देखकर जेपी के साथ चल रहे बड़े-बड़े समाजवादी नेताओं को आशा की किरणें दिख गयी थीं. सब कुछ ठीक चल रहा था. जुलूस डाक बंगला चौराहा तक पहुंच गया. यहां पुलिस की बैरिकेडिंग थी. तब शाम के लगभग छह बज गये होंगे. जुलूस के बैरिकेडिंग के नजदीक आते ही पुलिस ने बिना किसी सूचना के लाठीचार्ज कर दिया. इसमें जेपी पर भी लाठियां बरसायी गयीं. वे घायल हो गये. उनके साथ शरद यादव, लालू प्रसाद समेत कई नामचीन नेता जख्मी हुए. भीड़ में भगदड़ मच गयी. कई छात्र घायल हुए. जेपी को वहां से सुरक्षित हटाया गया. उनके सिर और पीठ पर चोट आयी थी. तब तक शाम के सात बज गये होंगे. लाठीचार्ज की खबर से बिहार समेत देश में आक्रोश फैल गया. आंदोलन ने नया स्वरूप ले लिया. अखबारों में इस आंदोलन को बड़ा कवरेज मिला. बूढ़े गांधीवादी नेता पर लाठीचार्ज ने जनता की संवेदनाओं को झकझोर दिया. जनता सड़कों पर आ गयी. सरकार का दमन और बढ़ा. गिरफ्तारियां तेज हो गयीं. लड़ाई लंबी चली. फिर क्या हुआ, ये दुनिया जानती है. दमन की हार हुई. लोकतंत्र की जीत हुई.

एक सवाल उस समय भी सबके मन में आया और आज भी होगा ही कि वह आंदोलन इतना सफल क्यों हुआ? बहुत साफ है. जनता समझ गयी थी कि जेपी को सत्ता से कोई लेना-देना नहीं है. देश से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म करना ही उनका मकसद है. एकदम से सुदूर गांव से लेकर बड़े शहरों के लोगों के मन में जेपी को लेकर यही भाव थे. एक बात कहनी जरूरी है. जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा शायद धरातल पर अभी तक नहीं उतरा है. जेपी आंदोलन से उपजी सत्ता ने उनके जीवनकाल में ही उनके आदर्शों और उनकी उपेक्षा की. अगर जेपी कुछ दिन और हमारे बीच रह गये होते, तो लोग उनके खिलाफ भी खड़े हो गये होते, जिनको सत्ता उनकी बदौलत मिली थी. एक वृद्ध का लोकनायक कहा जाना ही जेपी के विराट व्यक्तित्व की संपूर्ण कहानी है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)
(बातचीत पर आधारित)

देश दुनिया

कोर्ट के फैसले के बावजूद शरणार्थियों को लौटायेगा जर्मनी

नयी सरकार के सत्ता संभालने के एक दिन बाद ही जर्मनी की सरकार ने अनियमित आप्रवासन पर रोक लगाने का वादा किया था. हालांकि बर्लिन की प्रशासनिक अदालत ने दो जून को फैसला सुनाया कि जो लोग जर्मनी में शरण लेने की इच्छा जाहिर करते हैं, उन्हें जर्मन सीमा से वापस नहीं भेजा जा सकता. कोर्ट के इस फैसले के कुछ ही घंटे बाद जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर दोबरिंट ने कहा कि 'हम वापस भेजना जारी रखेंगे. हमें लगता है कि हमारे पास इसका कानूनी औचित्य है.' विदित हो कि दो जून को कोर्ट का फैसला तीन सोमाली नागरिकों की अपील पर आया था. पोलैंड की सीमा पर इसी वर्ष नौ मई को एक ट्रेन स्टेशन पर इनका सामना सीमा चौकी अधिकारियों से हुआ था. इन लोगों ने जर्मनी में शरण लेने की इच्छा जतायी थी. हालांकि उन्हें उसी दिन वापस पोलैंड भेज दिया गया. अदालत का कहना है कि उन्हें वापस भेजना गैरकानूनी है और अदालत का फैसला ऐसे लोगों पर भी लागू होता है जिन्हें जर्मनी की सीमाओं से लौटाया जा रहा है. अदालत ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि डब्लिन प्रक्रिया की अवहेलना की जा सकती है अगर यह सार्वजनिक व्यवस्था और घरेलू सुरक्षा को बचाये रखने के लिए जरूरी हो. डब्लिन प्रक्रिया के तहत अनियमित आप्रवासी यूरोपीय संघ में प्रवेश के बाद सबसे पहले जिस देश में प्रवेश करते हैं, उनको वहीं खुद को रजिस्टर कराना होता है. अगर वो संघ के किसी दूसरे देश का रुख करते हैं तो ज्यादातर मामलों में उन्हें उनके पहले ठिकाने पर लौटा दिया जाता है. बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों को जर्मनी की सीमाओं से वापस भेजने की नीति नयी सरकार ने बीते महीने कामकाज संभालने के तुरंत बाद शुरू की. नयी सरकार की इस नीति का असर सीमा पार आवाजाही करने वाले लोगों और सीमांत समुदायों पर भी पड़ने की आशंका है.

-निखिल रंजन

बोधि वृक्ष

दिव्य प्रेम में उदय होना

अपने अंदर की दिव्यता को देखने के लिए स्वयं को जगाओ. पहले आप जड़ता एवं सुस्ती से जागते हैं, फिर आपके अंदर का मनुष्य जागता है, उसके बाद आपके अंदर की दिव्यता स्पष्ट हो जाती है. एक कहानी के अनुसार, मनुष्य को बनाने के बाद भगवान ने कहा कि मैंने एक भूल कर दी. चूंकि भगवान के पास अनेक शिकायतें आ रही थीं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने वैसा क्यों किया? भगवान आश्चर्यचकित थे कि जो भी उन्होंने बनाया था, उसके बावजूद मनुष्य शिकायतों से भरा हुआ है. मनुष्य अधिकतर समय बड़बड़ाता क्यों है? भगवान एक साधु के पास गये और बोले, मैं गहरे संकट में हूं. मनुष्य मुझे न्यायालय तक खींच सकता है. साधु ने भगवान के कान में मनुष्य के हृदय में छिपने के लिए कहा, क्योंकि वहां पर मनुष्य कभी नहीं जाता. भगवान की आंखों में चमक आ गयी. वह मनुष्य के हृदय में चले गये और तब से वहीं पर छिपे हैं. इसलिए अपने अंदर की दिव्यता को पहचानें. भगवान सुंदरता हैं. वे सर्वव्यापी हैं. एक परेशान मन भगवान के निकट नहीं जा सकता. भगवान के बारे में अपनी अवधारणाएं छोड़ दें. अपनी आंखें बंद करके बैठें और अपने अंदर झांकें. जब आप गहराई को अनुभव करेंगे, तब आपको स्वयं ही सत्य का बोध हो जायेगा. आप को उत्तर मिल जायेगा. सबसे अधिक शांत एवं आरामदायक जगह आप में है. अपने अंदर की उस शांत, शीतल, स्थिर, निर्मल गहरे में विश्राम करें जो मूल्यवान है. सब शिकायतें दूर हो जाती हैं जब आप अपने मन की गहराइयों में गोते लगाते हैं. क्या आप ने विष्णु भगवान के नाग पर सोने की पौराणिक तस्वीर देखी है? नाग जागरूकता एवं सतर्कता का प्रतीक है और इस पर प्रभु प्रसन्नता से सो रहे हैं. धन की देवी लक्ष्मी भी वहीं विराजमान हैं. दिव्यता के प्रेम को विकसित करें. यह सहायता करता है, यदि आप उसके साथ हैं जो यह प्रेम खोज चुका है. एक बच्चे की तरह होने के लिए आपको एक बच्चे के साथ होना होगा, प्रसन्न रहने के लिए आपको एक प्रसन्न मनुष्य के साथ रहना होगा. एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो दिव्यता के प्रेम में है, वह आपको भी उसमें लिप्त कर देगा.

-श्री श्री रवि शंकर

कुछ अलग

एंटीबायोटिक प्रदूषण का गंभीर संकट

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

शहरीकरण, औद्योगीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाला है, जिससे जल संसाधनों की स्थिति गंभीर हो गयी है. भारत की संस्कृति नदियों के इर्द-गिर्द विकसित हुई है, पर अब नदियों का अस्तित्व संकट में है. कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, भारत की लगभग 80 प्रतिशत नदियां एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारण खतरे में हैं. इस शोध में 72 देशों के 877 स्थलों पर 21 सामान्य एंटीबायोटिक की उपस्थिति का परीक्षण किया गया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और वियतनाम जैसे देशों की स्थिति अत्यंत गंभीर पायी गयी. अध्ययन के अनुसार देश में लगभग 31.5 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जहां के जल स्रोत इन दवाओं के अवशेषों से प्रदूषित हैं. दिल्ली, लखनऊ, गोवा और चेन्नई जैसे शहरों में नदियों के जल में एंटीबायोटिक की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक पायी गयी है.

एंटीबायोटिक प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औषधि उद्योगों से निकलने वाला अनुपचारित अपशिष्ट जल, मानव और पशु चिकित्सा में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग और कृषि में इसका अत्यधिक उपयोग शामिल है. देश में अक्सर लोग बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाएं खरीद लेते हैं, जिससे दवाओं के अवशेष शरीर से बाहर निकलकर जल स्रोतों में पहुंचते हैं. पशुपालन और कृषि में भी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए इन दवाओं का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा और जल प्रदूषित हो जाते हैं. इस प्रदूषण का प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर रूप से पड़ता है. मानव स्वास्थ्य पर भी इसके दुष्परिणाम स्पष्ट हैं. दूषित जल के सेवन या इससे सिंचित फसलों के माध्यम से इन अवशेषों का शरीर में प्रवेश होता है, जिससे आंतों के संक्रमण, एलर्जी, यकृत और गुर्दे की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. सबसे चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब जीवाणु दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो जाते हैं, जिसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध कहा जाता है. भारत में प्रतिवर्ष लगभग 58,000 नवजात की मृत्यु इसी कारण से हो रही है.

इस संकट के हल के लिए दीर्घकालिक रणनीति आवश्यक है. औषधि उद्योगों को जिम्मेदार बनाते हुए अपशिष्ट जल का उपचार और पुनर्चक्रण अनिवार्य किया जाना चाहिए. जनमानस में भी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति जागरूकता लाना जरूरी है. पशुपालन और कृषि में भी एंटीबायोटिक प्रयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और कठोर निगरानी आवश्यक है. सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे. नहीं तो भविष्य में यह संकट हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है.

आपके पत्र

भारत की ताकत से चिंता में अमेरिका

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की वीर-गाथा से अमेरिका समेत यूरोपीय देशों का भारत प्रेम बनावटी दिखायी दे रहा है. सच यह है कि भारत की बढ़ती ताकत से अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देश चिंतित हैं. उन्हें डर सता रहा है कि 78 साल के सफर में भारत इतना आत्म निर्भर व मजबूत हो गया कि वह बार-बार पाकिस्तान में घुस कर उसकी रीढ़ तोड़ दे रहा है. भारत विकास के क्षेत्रों में भी लंबी छलांग मार रहा है. भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो गयी है. अब भारत यूपरोपियों देश का पिछलग्गू नहीं बनेगा.

युगल किशोर राही, छपरा

पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश

बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो गयी हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहे हैं. तख्तापलट के बाद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का दौर जारी है. हिंदुओं पर अत्याचार में प्रशासन और सरकार की मूक सहमति है. अंतरिम सरकार पर चुनाव कराने का दबाव है, लेकिन सरकार चुनाव को टालना चाहती है. यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते है, जबकि बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार पर हावी हो रही है.

हिमांशु शेखर, गया

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

कल्पमेधा

सच्ची आजादी उसके भाग्य में नहीं, जो अपनी रक्षा खुशामद और सेवा से करता है। अपने आप को गंवा कर ही सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है।

सरदार पूर्णसिंह

साख पर सवाल

लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में शुचिता और पारदर्शिता प्राथमिक शर्त है। मगर राजनीतिक नफे-नुकसान के गणित में सरकारों ने सबसे अधिक कमजोर इन्हीं संस्थाओं को किया है। शायद ही कोई संवैधानिक संस्था बची है, जो भ्रष्टाचार और कदाचार की जकड़बंदी से मुक्त हो। फिर भी जब इन संस्थाओं के भीतर से ही शुचिता लाने के संकल्प उभरते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बेहतरी की उम्मीद बनती है। देश की न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। निचली अदालतों पर तो ऐसे आरोप आम रहे हैं, पर ऊपरी अदालतों में भी पिछले कुछ वर्षों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे न्यायपालिका की साख पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने इस समस्या को साफगोई से स्वीकार किया और इसे दूर करने का संकल्प दोहराया है, तो सकारात्मक नतीजों का भरोसा बना है। ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं से जनता का भरोसा टूटता है। दुख की बात है कि न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं। यह बात उन्होंने दिल्ली में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से बरामद जली नगदी नोटों के संदर्भ में कही।

प्रधान न्यायाधीश ने भारतीय न्यायपालिका के भीतर जड़ें जमा रही या जमा चुकी उन सभी समस्याओं को बड़े साफ शब्दों में स्वीकार किया, जिन्हें लेकर अंगुलियां उठती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के राजनीतिक दबाव में या निजी स्वार्थ साधने के मकसद से फैसले सुनाने को लेकर काफी असंतोष जाहिर किया जाता रहा है। कुछ न्यायाधीशों ने सेवामुक्त होने के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार कर लिया, तो कुछ चुनावी मैदान में उतर गए। इसे किसी भी रूप में नैतिक नहीं माना गया। हालांकि अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे, न इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे। इससे यह उम्मीद तो बनी है कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश सत्ता के किसी दबाव में आकर कोई फैसला सुनाने से बच सकेंगे। राजनीतिक लोभ और दबाव से मुक्त हुए बिना न्यायपालिका सही अर्थों में अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकती। इसलिए प्रधान न्यायाधीश का इस दिशा में प्रयास सराहनीय है।

लोकतंत्र में न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा इसलिए भी बने रहना बहुत जरूरी है कि यही एक स्तंभ है, जिस पर संविधान की रक्षा का दायित्व और राजनीतिक तथा व्यवस्थागत कदाचार पर नकेल कसने का अकूत अधिकार है। यह भी अनुभव जगजाहिर है कि जब भी न्यायपालिका कमजोर दिखती है, तो सत्ता पक्ष की मनमानियां बढ़ती जाती हैं। इसीलिए न्यायाधीशों का व्यक्तिगत आचरण बहुत मायने रखता है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस तकाजे को जैसे भुला दिया गया है। कुछ न्यायाधीशों के सुर्खियां बटोरने के लोभ की वजह से न्यायिक सक्रियता का सवाल भी उठना शुरू हुआ था। कालेजियम प्रणाली और न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात आदि के आरोप भी सुगबुगाते रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर प्रधान न्यायाधीश ने बड़ी बेबाकी से बात की और उन्हें दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया है। निस्संदेह इससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बलवती होंगी। पर देखने की बात होगी कि ये संकल्प जमीन पर कितना उतर पाते हैं।

दोस्ती में दरार

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राहें अब अलग हो गई हैं। इस बार मुद्दा भारी-भरकम खर्च को लेकर है। मस्क लागत में कटौती और दक्षता में सुधार के लिए सरकारी प्रयासों की अगुआई कर रहे थे। उन्होंने सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और खर्च में कटौती की वकालत की। दरअसल, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही मस्क को यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी थी। तब ट्रंप और मस्क की गहरी मित्रता से लगा था कि अमेरिका नए रास्ते पर चल पड़ा है। मगर मार्ग में बाधाएं तब आनी शुरू हुईं, जब मस्क के कई फैसलों का अमेरिका में विरोध होने लगा। वहीं ट्रंप की नीतियों से उनके कारोबारी हित भी टकराने लगे। उनके बीच दोस्ती में पहली दरार तब दिखी, जब ट्रंप ने कृत्रिम मेधा से जुड़ी पांच सौ अरब डालर की योजना कुछ निवेशकों के साथ पेश की। इसके बाद मतभेद बढ़ते चले गए। फिलहाल ताजा टकराव भारी-भरकम सरकारी खर्च पर है। इससे बजट घाटा बढ़ने का खतरा बताते हुए मस्क ने तीखे सवाल उठाए हैं।

मस्क हमेशा विवादों में रहे। उनका कई मंत्रियों से नीतिगत विवाद हआ। वहीं उनके आक्रामक कदम से ट्रंप प्रशासन में भी तनाव दिखा। सरकारी कर्मियों की छंटनी करने का खासा विरोध हुआ। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा। मस्क की नीतियों से चिंतित ट्रंप को कहना पड़ा कि नौकरियों के मामले सरकार की चलेगी, न कि मस्क की। दरअसल, उनके फैसलों पर विवाद बढ़ने से ट्रंप प्रशासन की साख पर असर पड़ने लगा था। मतभेद यहीं तक सीमित नहीं था। आव्रजन नीति को बदलने या इसे खत्म करने के मुद्दे पर मस्क सहमत नहीं थे। उनके दबाव में पहली बार इस मसले पर ट्रंप को झुकना पड़ा था। उन्हें कहना पड़ा कि एच वन बी वीजा उनको पसंद है। कुछ समय पहले शुल्क और व्यापार के मसले पर भी उनके बीच मतभेद गहरा गए थे। ट्रंप के ठेस पहुंचाने वाले बयानों से भी मस्क का मोहभंग हुआ। सवाल है कि क्या अब मस्क के विरोध और सरकारी जिम्मेदारी छोड़ कर अलग हो जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मनमाने फैसले करने और बड़बोलेपन से बचने का प्रयास करेंगे!

प्लास्टिक प्रदूषण से जूझती महिलाएं

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरणीय समस्या, बल्कि यह एक सामाजिक संकट भी बन चुका है। महिलाएं और लड़कियां इससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

विनीता परमार

प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यह सामाजिक और लैंगिक असमानता को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। यह समस्या केवल समुद्र में तैरते प्लास्टिक कचरे तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं और लड़कियों से भी जुड़ी है, जिनके जीवन में प्लास्टिक प्रदूषण ने गहरा असर डाला है। यह एक ऐसी हिंसा है, जो न तो तात्कालिक होती है और न ही स्पष्ट, पर धीरे-धीरे शरीर, समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। इसीलिए इसे 'धीमी हिंसा' कहा जा सकता है।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, यह एक सामाजिक संकट भी बन चुका है। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश अपने प्लास्टिक कचरे का निर्यात विकासशील देशों में करते हैं, उसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से बड़ी मात्रा में 'सिंगल यूज' (एकल उपयोग) प्लास्टिक शामिल होता है, जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आमतौर पर पारंपरिक रूप से घर की सफाई, खाना पकाने और बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभालती हैं। इन सभी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद- जैसे प्लास्टिक पैकिंग में आने वाले खाद्य पदार्थ, सस्ते सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक और घरेलू सफाई उत्पाद आदि में जहरीले रसायन होते हैं, जो सीधे महिलाओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। आज भारत में सौंदर्य प्रसाधनों का उद्योग सालाना लगभग दस हजार करोड़ से अधिक हो चुका है। शोध बताते हैं कि सौंदर्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं, जो हार्मोन के स्राव को बाधित करते हैं। साथ ही, इन उत्पादों में प्रयुक्त रसायन लंबे समय तक त्वचा, रक्त और प्रजनन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इनसे त्वचा रोग, थायराइड संबंधी विकार, हार्मोन असंतुलन, बांझपन और गर्भपात जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

शारीरिक दृष्टि से भी महिलाएं विषाक्त रसायनों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। उनके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है, जो विषैले तत्त्वों को लंबे समय तक संचित रखती है। इसके अलावा, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन इन रसायनों के प्रभाव को और भी गहरा बना देते हैं। गर्भावस्था, मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति जैसे नैसर्गिक चरणों में यह प्रभाव और गंभीर हो जाता है। शोध के मुताबिक, प्लास्टिक में मौजूद बिसफेनाल-ए और फ्थेलेट जैसे रसायन गर्भस्थ शिशु के विकास को बाधित करते हैं, जिससे जन्मजात विकार, मानसिक समस्याएं और हार्मोन से संबंधित विकृतियां पैदा हो सकती हैं।

प्लास्टिक कचरा अक्सर शहरी मलिन बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के नजदीक जमा होता है, जहां बुनियादी सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन सुविधाओं का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित वे समुदाय होते हैं, जो पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक हाशिए पर होने की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। इन समुदायों की महिलाएं, जो पारंपरिक रूप से घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालती हैं, आज वे अपने परिवार की आजीविका के लिए

अनौपचारिक क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा बीनने और जलाने जैसे खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं। ये कार्य बिना किसी सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण या स्वास्थ्य सुविधा के किए जाते हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि देश के कई हिस्सों में महिलाएं कचरा बीनने,

> **प्लास्टिक प्रदूषण लैंगिक रूप से एक पक्षपाती संकट बन चुका है, क्योंकि इसकी नीतियों और समाधान में अक्सर महिलाओं के अनुभवों और आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। पर्यावरण से जुड़ी नीतियों के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम होती है और जो निर्णय लिए जाते हैं, वे प्राय: तकनीकी या आर्थिक दृष्टिकोण से होते हैं, सामाजिक और लैंगिक पहलुओं से नहीं। ऐसे में उन महिलाओं की आवाज दब जाती है, जो इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। परिणामस्वरूप, न तो उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल मिलते हैं और न ही उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो पाती है।**

घरेलू कामगार या कचरा पुनर्चक्रण इकाइयों में असंगठित मजदूर के रूप में काम करती हैं। इन कार्यों में रोजमर्रा का संपर्क प्लास्टिक से होता है- जैसे पालीथीन, बोतलें, प्लास्टिक थैलियां और टूटी घरेलू वस्तुएं, जिनमें अक्सर खतरनाक रसायन मौजूद होते हैं। इनसे त्वचा रोग, सांस की बीमारी, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं और यहां तक कि कैंसर तक का खतरा होता है। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरे का जलाया जाना भी महिलाओं और उनके परिवारों को प्रभावित करता है। जब यह कचरा बस्तियों के पास खुले में जलाया जाता है, तो इससे निकलने वाले डायाक्सिन और अन्य विषैले रसायन हवा और पानी को प्रदूषित करते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होता है।

देश में पर्यावरणीय नीति और कचरा प्रबंधन योजनाएं अक्सर तकनीकी और नगरीय समाधान केंद्रित होती हैं। पर यह जरूरी है कि इन योजनाओं में महिलाओं की भूमिका, उनके श्रम की असंगठित प्रकृति और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संकट का एक अन्य आयाम श्रम और शिक्षा से जुड़ा है। झुग्गी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-सी महिलाएं और लड़कियां प्लास्टिक बीनने और पुनर्चक्रण केंद्रों में काम करती हैं। यह काम न केवल अत्यधिक असुरक्षित होता है, बल्कि अक्सर बिना किसी स्वास्थ्य सुरक्षा के किया जाता है। लड़कियों की शिक्षा भी इससे बाधित होती है, क्योंकि वे कम उम्र में ही अपनी माताओं के साथ इस कार्य में जुड़ जाती हैं। वे स्कूल नहीं जा पातीं, और उनके सामने एकमात्र विकल्प प्लास्टिक से जुड़ा जोखिमपूर्ण श्रम ही रह जाता है। प्लास्टिक उनके जीवन के लिए एक धीमा जहर बन जाता है, जो उनके भविष्य की संभावना को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है।

प्लास्टिक प्रदूषण लैंगिक रूप से एक पक्षपाती संकट बन चुका है, क्योंकि इसकी नीतियों और समाधान में अक्सर महिलाओं के अनुभवों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। पर्यावरण से जुड़ी नीतियों के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम होती है और जो निर्णय लिए जाते हैं, वे प्रायः तकनीकी या आर्थिक दृष्टिकोण से होते हैं, सामाजिक और लैंगिक पहलुओं से नहीं। ऐसे में उन महिलाओं की आवाज दब जाती है, जो इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। परिणामस्वरूप, न तो उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल मिलते हैं और न ही उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो पाती है।

इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले, कार्पोरेट क्षेत्र को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। उन्हें अपने उत्पाद की पैकेजिंग, वितरण और उपभोग की प्रणाली को पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से टिकाऊ बनाना होगा। केवल एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के स्थान पर 'बायोडिग्रेडेबल' उत्पादों के विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए और उनके उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।

दूसरा, सरकार को अपने कचरा प्रबंधन तंत्र को लैंगिक संवेदनशीलता के साथ पुनर्गठित करना होगा। इसमें महिलाओं को सुरक्षित और गरिमामय कार्यस्थल देना, कचरा प्रबंधन में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका देना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। इसके अलावा स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को प्लास्टिक प्रदूषण के जोखिम और उससे निपटने के तरीकों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। साथ ही, हमें शिक्षा और जागरूकता को केंद्र में रखना होगा। जब तक लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी और महिलाएं अपने अधिकारों और स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होंगी, तब तक इस संकट को जड़ से समाप्त करना कठिन होगा। एक शिक्षित महिला न केवल अपने लिए, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए जागरूकता और बदलाव की वाहक बन सकती है।

दुनिया मेरे आगे

उत्सव की तरह जीवन

शिखरचंद जैन

कई लोग अपनी जिंदगी को किसी बोझ की तरह ढोते नजर आते हैं। न मन में कोई उत्साह, न कोई उमंग। ऐसे लोग दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ गपशप और हंसी मजाक भी नहीं करते। जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, कोई जश्न नहीं। पदोन्नति हो या पगार में इजाफा, चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं। ऐसे लोग हमेशा हैरान परेशान नजर आते हैं। वहीं कुछ लोग बीमार पड़े-पड़े भी हंसते-मुस्कुराते रहते हैं। मुसीबत में भी पूरी ऊर्जा से सक्रिय रहते हैं। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ इनकी गपशप चलती रहती है। ऐसे जिंदादिल लोग आए दिन जरा-जरा-सी खुशी पर लड्डू-पेड़े बांटते, केक काटते या लोगों को पार्टी देते नजर आते हैं। असल में जीवन को ऐसे ही लोग जीते हैं। ये जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं।

हमारा जीवन विविधताओं से भरा है। इसमें उतार-चढ़ाव, हर्ष विषाद, सफलता-असफलता, मैत्री-दुश्मनी लगी ही रहेगी। इन सारी चीजों के साथ ही हमें जीवन को जीना है। हमें सपनों को साकार करने के वास्ते लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीना होता है। इस प्रक्रिया को हम जितनी सुगमता, सहजता और सरलता से पूरा करने की तैयारी रखेंगे, उतनी ही सुकूनदेह जिंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, वे ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे चिंताजीवी लोग न खुद को कुछ दे पाते हैं, न अपने परिवार, समाज या देश को। हर समय अवसाद, उदासी और चिढ़ में जीने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जीवन को एक खेल या उत्सव की तरह जीना चाहिए। इसमें हार-जीत का महत्त्व नहीं, कोशिश का महत्त्व है। मस्तिष्क को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रखने के लिए एकाग्रता जरूरी है। इसके लिए सुबह-शाम प्राणायाम, ध्यान और योग जरूरी है।

उत्साह और खुशी हमारे जीवन की गहराइयों में छिपे होते हैं। इन्हें बाहर निकालना चाहिए। नील पसरीचा ने अपनी किताब, 'द हैप्पीनेस इक्वेशन' में कहा है कि मन को हल्का रखने और आराम महसूस करने के लिए रात को फोन बंद कर देना चाहिए, अच्छे पलों को दर्ज करना चाहिए, प्रातःकाल दस-पंद्रह मिनट तक एक रजिस्टर में बीते दिन की अच्छी बातें लिखें। हर हफ्ते कम से कम दो अच्छे काम करें, जैसे किसी की मदद ,किसी की गौशाला या अनाथालय में दान आदि।

एक शोध के मुताबिक, तारीफ में कही गई बातें हमें उतना ही प्रोत्साहित करती हैं जितना हाथ में पैसों का आना। इसलिए अपने गहरे दोस्त या परिवार के किसी सदस्य की तारीफ करनी चाहिए। इस तरह खुशी मिलेगी। रोज सुबह कुछ अच्छा पढ़ने और संगीत सुनने की जरूरत है और पार्क में टहलना।

कठिनाइयों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझना चाहिए। गली के आवारा कुत्ते जब हम पर भौंकते हैं और हम उन्हें देखकर भागने लगते हैं तो वे और भी तेज भौंकते हुए हमारा पीछा करने लगते हैं। वहीं हम जब एक जगह खड़े होकर उन्हें घूरते हैं तो वे शांत होकर पीछा छोड़ देते हैं। यही हाल समस्याओं और कठिनाइयों का है। हम उनसे पलायन करके नहीं बच सकते। उन्हें पहचानने और उनका समाधान धैर्यपूर्वक खोजने की जरूरत है।

जीवन में सफल होने के लिए उन्हीं प्रयासों, ऊर्जा और साधनों पर केंद्रित रहना चाहिए जो किसी न किसी तरह हमारे काम आ सकते हैं। हुनर, धैर्य और मेहनत का साथ हो तो इंसान को आगे बढ़ने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। कठिन समय में जो लोग मदद करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। मशहूर लेखिका रोंडा बर्न अपनी किताब 'द मैजिक' में लिखती हैं कि कृतज्ञता का जादू हमारे समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया।

जीवन को उत्सव की तरह जीना है तो लोगों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि दुनिया बहुत खराब है। यह समझने की जरूरत है कि अगर दुनिया खराब है तो हम भी इसी का एक हिस्सा हैं। हम लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो लोग भी हमसे मुस्कुरा कर मिलेंगे। हम किसी के साथ गेम खेलेंगे तो वे हमें क्यों छोड़ेंगे? विनम्रता, मिलनसारिता, जिंदादिली और हंसमुख स्वभाव बहुत ऊर्जा देते हैं। इससे दूसरे का नहीं, हमारा ही भला होगा। ऊर्जा बनी रहेगी, मिजाज अच्छा रहेगा और काम में मन लगेगा। लोगों से हमेशा किसी स्वार्थ के कारण ही बात नहीं करनी चाहिए, व्यवहार के लिए भी प्रेम के धागे बुनना चाहिए, ताकि बात करके हम अपना मन हल्का रख सकें और किसी के साथ सुझावों का आदान-प्रदान कर सकें।

> **जीवन को उत्सव की तरह जीना है तो लोगों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि दुनिया बहुत खराब है। यह समझने की जरूरत है कि अगर दुनिया खराब है तो हम भी इसी का एक हिस्सा हैं। हम लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो लोग भी हमसे मुस्कुरा कर मिलेंगे।**

जीवन की गति को नियंत्रण में रखना बेहतर होता है। ज्यादातर दुर्घटनाएं अनियंत्रित गति की वजह से होती हैं। कई बार हम जिंदगी को लेकर एक लीक अपना लेते हैं। वक्त चाहे जितना बदले, पर हमारे विचार नहीं बदलते। पूर्वाग्रहों से हमारे मन में जड़ता आ जाती है। समय-समय पर जीवन से फालतू चीजों को हटाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान खुद से कुछ सवाल पूछना चाहिए। मसलन, कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं अपने जीवन से चाहता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं? इन सवालों से जो जवाब मिलें, उनसे पता चल जाएगा कि हम आधी से ज्यादा बेकार चीजों के पीछे भागते रहे हैं और इसीलिए हमारी जिंदगी इतनी उलझी हुई और दुश्वार है। 'द लाइफ आडिट' की लेखिका कैरोलीन राइटन कहती हैं, 'इससे आपको अपनी जीवन यात्रा को समझने और अब तक की गई तरक्की या तरक्की में रुकावट बन रहे कारणों का पता चलता है। आपको यह भी पता चलता है कि आप कहां अटके हुए हैं। आपको अपनी इच्छाओं का भी पता चलता है।'

सही दिशा

भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है, जब हम अपनी युवा शक्ति को सही दिशा में ले जाएं। युवाओं की ऊर्जा देश के भविष्य को सुनहरे दौर की ओर ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगे। यदि यह ऊर्जा गलत दिशा में भटक गई, तो यह देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कई बार युवाओं को धार्मिक कट्टरता और हिंसा की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे उनकी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों की बजाय विनाशकारी गतिविधियों में लग जाती है। यह न केवल उनके भविष्य को अंधकारमय बनाता है, बल्कि समाज में भी विघटन पैदा करता है। इसी तरह, राजनीतिक हथियार बनना भी युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए युवाओं का उपयोग करते हैं। उन्हें प्रदर्शनों, हिंसक गतिविधियों और विभाजनकारी एजंडों में शामिल किया जाता है, जिससे उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का गलत इस्तेमाल होता है। यह न केवल युवाओं के भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी खतरे में डालता है।

– मो. अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

बेलगाम कट्टरपंथी

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो गई हैं। एक ओर वहां अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर वे भारत से दूरियां बढ़ा रहे हैं। तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार का दौर जारी है। कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी का चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतरिम सरकार पर चुनाव कराने का बहुत दबाव है, लेकिन सरकार चुनाव को टालना चाहती है। यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते है। वहीं बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार पर हावी हो रही है। आने वाले वक्त में सेना अपने हाथों में सत्ता ले सकती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा देख कर दुख होता है। बांग्लादेश की आजादी भारतीय सेना के शौर्य के कारण संभव हो पाई थी। बांग्लादेश भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राह पर चल पड़ा है। वहां अमेरिका का भी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है।

– हिमांशु शेखर, गया

मानवीयता की उपेक्षा

संपादकीय 'संवेदनहीनता की हद' (3 जून) में अस्पतालों की बदतर स्थिति और कर्मियों के व्यवहार के बारे में उचित लिखा गया। एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद फिर दरिंदगी की गई। जो लड़की बलात्कार की पीड़ा से गुजर रही थी और जिस पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, उसके लिए घंटों एंबुलेंस में इंतजार करना कितना कष्टदायक रहा होगा? क्या अस्पतालों में वाकई बिस्तर उपलब्ध नहीं होते या गरीब देख उनकी अनदेखी की जाती है? या सरकारी अस्पताल होने की वजह से कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर नहीं होता? अगर समय रहते पीड़िता को इलाज मिल जाता, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। यह अस्पताल द्वारा मरीज की अनदेखी का मामला है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सरकार को पुलिस और अस्पतालों को कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी जरूरतमंद को यथासंभव इलाज और सहायता तुरंत मिले।

– अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

बड़ी उपलब्धि

जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम खून बना लिया है, जिसे हम एंटीबायोटिक के बाद चिकित्सा क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। इस कृत्रिम खून की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी भी 'ब्लड ग्रुप' के मनुष्य को चढ़ाया जा सकता है और साधारण रक्त की तुलना में यह 24 गुना अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। परीक्षण के बाद इस रक्त का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। यह कृत्रिम खून शल्य चिकित्सा, प्रसव और दुर्घटना जनित मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। गरीब देशों के लोगों के लिए भी यह रक्त अपेक्षाकृत कम दाम में उपलब्ध हो सकता है। ऐसे जीवनदायी रक्त का आविष्कार करने वाले चिकित्सा वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि मानवता के लिए महत्त्वपूर्ण और सराहनीय है।

– अनित कुमार राय टिंकू, धनबाद

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

प्रवाह
7 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

पृथ्वी सभी की जरुरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को नहीं। -महात्मा गांधी

बंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु (आरसीबी) की आईपीएल जीत का जश्न जिस तरह से एक त्रासदी में बदल गया, वह हृदयविदारक है। प्रशंसकों का उत्साह तो स्वाभाविक था, लेकिन सवाल तो इतने बड़े आयोजन की तैयारियों पर है।

खुशी में मातम

बंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु (आरसीबी) की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न जिस तरह से एक त्रासदी में बदल गया, वह स्तब्धकारी होने के साथ हृदयविदारक भी है। उल्लेखनीय है कि हजारों उत्साही प्रशंसक टीम के पहुंचने से घंटों पहले ही स्टेडियम के बाहर जमा होने लगे थे। स्टेडियम भीतर से तो ठसाठस भरा ही हुआ था, उसके बाहर और आसपास की सड़कों पर भी जबर्दस्त जाम की स्थिति थी। आलम यह था कि करीब 5,000 सुरक्षाकर्मी मिलकर भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ ही दिख रहे थे। इसके बाद मची भगदड़ में दस से ज्यादा लोग मारे गए और छह साल की मासूम बच्ची समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ के दौरान के जो दृश्य वायरल हो रहे हैं, वे वाकई दिल दहलाने वाले हैं। यह पूरी घटना दरअसल प्रशासन की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में विफलता को ही उजागर करती है। अठारह संस्करण तक लंबे इंतजार के बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी की टीम को लेकर प्रशंसकों का उत्साह कोई अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि स्वाभाविक ही था। बंगलूरु जैसे प्रगतिशील छवि वाले महानगर में इतने बड़े आयोजन के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न हों, तो सवाल तो उठेंगे ही। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भले यह कह रहे हों कि युवा और उत्साही भीड़ पर पूरी तरह से लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन सवाल यह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के वैकल्पिक उपाय, जैसे पर्याप्त बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, आपातकालीन निकासी की व्यवस्था इत्यादि पहले से क्यों नहीं किए गए। भगदड़ के दौरान प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का यों असहाय दिखना वाकई हैरत में डालने वाला था। ऐसी खबरें भी हैं कि आरसीबी ने अपने प्रशंसकों को मुफ्त पास बांटे, जिसकी वजह से भीड़ इतनी बढ़ गई। लिहाजा बीसीसीआई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। यह दुखद ही था

कि स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे और अंदर जश्न मनाया जा रहा था। यह त्रासदी हमें उन गहरे सबकों की याद दिलाती है, जिनसे हमें भविष्य के लिए सीख लेने की जरूरत है। बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन एक विज्ञान है, जिसे तकनीक, प्रशिक्षण और योजना के जरिये लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में, सरकार, पुलिस और आयोजकों को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जाए। इस दुखद घटना की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों को सख्त सजा भी मिलने के साथ यह भी जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तय की जाएं, जिनका पालन अनिवार्य हो।

प्लास्टिक मुक्त हों भी, तो कैसे

सरकारें तो केवल नीति और कानून बना सकती हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, तो इससे मुक्त होने के रास्ते भी हमें ही तलाशने होंगे। इस मामले में लापरवाही इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी खोज प्लास्टिक को सबसे बड़ा संकट बना देगी।

अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद

प्लास्टिक की स्थिति इस दुनिया में ठीक वैसी ही है, जैसे एक गरीब व्यक्ति की-जो हमारे कई काम आता है, लेकिन जब उससे कोई गलती हो जाती है, तो उसमें हमें सारी बुराइयां दिखाई देने लगती हैं। यही हाल प्लास्टिक का भी है-पूरी दुनिया में ऐसा कौन है, जिसने पिछले 30 वर्षों में प्लास्टिक का उपयोग न किया हो? कोई गांव, घर, गली, कस्बा या शहर ऐसा नहीं है, जो प्लास्टिक के उपयोग से वंचित हो। किसी न किसी रूप में प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है।

असल में यह एक ऐसी चीज है, जो अब मनुष्य के गले पड़ चुकी है। सीधे शब्दों में कहें, तो आज भी, जब प्लास्टिक विरोधी तमाम नियम और कानून लागू हो चुके हैं, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में बना हुआ है। सब्जी, फल या फिर किराना दुकान में सामान खरीदते समय हम प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा करते हैं, खरीदारी करने के लिए जूट या कपड़े के झोले का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया है। इस तरह प्लास्टिक की थैली का उपयोग करके हम इस प्लास्टिक के प्रसार को और बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

आज के संदर्भ में देखें, तो प्लास्टिक ने हमारे जीवन में इतनी गहराई से अपनी जगह बना ली है कि अब इससे मुक्त होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। घर और बाहर के कामों में तो यह पहले से मौजूद है ही, लेकिन अब खेती-बाड़ी से लेकर उद्योगों में-हर जगह इसका उपयोग होता है। वैसे हम इसके कुप्रभावों को जानते हैं, फिर भी इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। जब भी प्लास्टिक की बात होती है, तो सभी एक सुर में इसका विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया है।

आज भी हालात ये हैं कि न चाहकर भी, कई वजहों से प्लास्टिक हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बना हुआ है। यही कारण है कि बार-

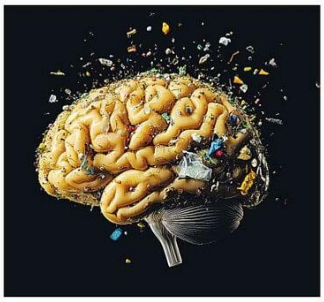

बार प्रतिबंध लगने और सरकारी नियम-कानून होने के बावजूद प्लास्टिक का उपयोग सबसे ज्यादा और सर्वोपरि बना हुआ है।

प्लास्टिक को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है-एक तरफ, यह हमारे जीवन में कई रूपों में वरदान है। इसके कारण हम अपनी रोजमर्रा की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ, जब भी प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की बात होती है, तो रोजगार और स्वरोजगार की बात सामने आती है, जिसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते।

सरकारों का मानना है कि इससे मुक्त हुआ जाए। लेकिन जब आम लोग खुद ही इससे मुक्त होना नहीं चाहते, तो सरकारें इसे कैसे खत्म कर पाएंगी? यही हो रहा है-क्योंकि देश और दुनिया में प्लास्टिक उद्योग रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर इस उद्योग को बंद कर दिया जाए, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैज्ञानिक भी प्लास्टिक के नए उपयोग और इसे खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन वे भी कहीं न कहीं बेरोजगारी का सामना कर सकते हैं।

अब सवाल यह है कि हमारे पास क्या विकल्प हैं? एक तरफ इसके आकर्षक और उपयोगी उत्पाद, जो लकड़ी और लोहे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसकी मजबूती और टिकाऊपन हमें अपनी तरफ खींचता है। दूसरी ओर, इसका दुरुपयोग सीमाओं को पार कर चुका है। यह अब सिर्फ गाय-भैंस या अन्य जानवरों के पेट में नहीं पहुंचता, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर चुका है।

हाल के शोध बताते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में 50,000 से अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण पहुंच चुके हैं, जो हमारे दिल, त्वचा और फेफड़ों पर सीधा असर डाल सकते हैं। तो सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी आम लोग और नीति-निर्माता मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं, जिससे प्लास्टिक से छुटकारा पाया जा सके। कुछ नहीं, क्योंकि हम अभी गंभीर ही नहीं हैं। हालांकि, प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त होना संभवतः न तो मुमकिन है और न ही व्यावहारिक। लेकिन एक रास्ता जरूर है-सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग वाली प्लास्टिक) पर नियंत्रण लगाया जाए। इसके लिए सरकार ने कई नियम और कानून बनाए, जुर्माने भी लगाए, लेकिन व्यवहार में कुछ खास असर नहीं पड़ा।

देश में प्लास्टिक के नए-नए प्रयोग और उपयोगों को समर्पित केंद्रीय प्लास्टिक व इंजीनियरिंग संस्थान भी चेन्नई में है, जिसके देश भर में 48 छोटे अनुषांगिक संगठन भी हैं, जो प्लास्टिक पर काम कर रहे हैं। वे मानते हैं कि प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करना न संभव है और न इसका कोई तात्कालिक समाधान। लेकिन वेस्ट प्लास्टिक (अपशिष्ट प्लास्टिक) का सही उपयोग करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो टिकाऊ भी होंगे और तुरंत कचरा भी नहीं बनेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू भी है-जब भी हम प्लास्टिक का उपयोग करें, उसकी प्रवृत्ति यह होनी चाहिए कि वह बार-बार उपयोग में आ सके। इससे प्लास्टिक के उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा और कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा।

अब सवाल है-क्या केवल सरकार को दोष देने से समस्या हल होगी या नागरिक के रूप में कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। सरकारें तो केवल नीति और कानून बना सकती हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक कण प्रवेश कर रहे हैं और जीवन संकट में पड़ रहा है, तो हमें खुद कदम उठाने होंगे।

सरकारें नियम ही बना सकती हैं, लेकिन उनका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर सरकार दबाव बनाएगी, तो फिर दूसरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी तरह अनदेखी करते रहे, तो इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक प्लास्टिक ही हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।

edit@amarujala.com

सागर, सगरा और सरोवर

जीवन और मृत्यु की लहरों से लहराते इस भवसागर से पार उतरने का लक्ष्य रखने वाले समाज ने तरह-तरह के तालाब बनाए हैं और बहुत रुचि के साथ उनके नामकरण किए हैं। ये नाम तालाबों के गुणों पर, स्वभाव पर, तो कभी किसी विशेष घटना पर रखे जाते थे। इतने नाम, इतने प्रकार कि कहीं नामकरण में भाषा का कोश कम पड़े, तो बोली से उधार लेते थे, तो कहीं ठेठ संस्कृत तक जाते थे। सागर, सरोवर और सर नाम चारों तरफ मिलेंगे। सागर लाड़ प्यार में सगरा भी हो जाता है। सरोवर कहीं सरवर भी है। सर संस्कृत शब्द सरस से बना है और गांव में इसका रस सैकड़ों बरसों से सर के रूप में मिल रहा है। आकार में बड़े और छोटे तालाबों का नामकरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की इन जोड़ियों से जोड़ा जाता रहा है : जोहड़-जोहड़ी, बंध-बंधिया, ताल-तलैया तथा पोखर-पोखरी। ये जोड़ियां मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में जगह-जगह हैं और सीमा पार नेपाल में भी।

प्रसंगवश

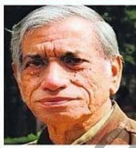

अनुपम मिश्र

जाने-माने गांधीवादी चिंतक एवं जल-संरक्षण के प्रणेता अनुपम मिश्र ने पारंपरिक विधियों से पर्यावरण और जीवन, दोनों को समृद्ध करने की बात की थी। उनकी पुस्तक *आज भी खरे हैं तालाब* के अंश...

पोखर संस्कृत के पुष्कर से मिला है। बंगाल में तो हर घर के पास पोखर हुआ करते थे। वहां तालाब के लिए पुष्करणी शब्द भी चलता रहा है। डिग्गी नाम हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में चलता था। पानी रखने के छोटे हौज से लेकर बड़े तालाब तक डिग्गी नाम मिलता है। कभी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने लाल डिग्गी नामक एक बड़ा तालाब था। डिग्गी शब्द दीघी और दीर्घिका जैसे संस्कृत शब्दों से आया है। हौज का उदाहरण दिल्ली का हौज खास है, जो अब तालाब से अधिक एक मुहल्ले की तरह पहचाना जाता है।

ताल कई जगह हैं, पर इसी से मिलता-जुलता शब्द चाल एक क्षेत्र में सीमित होकर रह गया। यह क्षेत्र है हिमालय का। इन पहाड़ी जिलों में कभी गांव-गांव में चाल थीं। चाल कोई 30 कदम लंबी, इतनी ही चौड़ी और कोई चार-पांच हाथ गहरी होती थी। हिमालय में चाल कहीं खाल है, कहीं तोली है, तो कहीं चौरा भी। ठेठ उत्तर के ये शब्द दक्षिण तक चले जाते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश में चैर और चेरुवू शब्द तालाब के अर्थ में ही पाए जाते हैं।

चौकोर पक्के घाट से घिरे तालाब चोपरा या चौपरा और र का ड़ होकर चौपड़ा भी कहलाते हैं। चौपड़ा उज्जैन जैसे प्राचीन शहर में, झांसी जैसे ऐतिहासिक शहर में तथा चिरगांव जैसे साहित्यिक स्थान में भी हैं। चारों तरफ से अच्छे-पक्के घाटों से घिरा तालाब चौघरा कहलाता है। इसमें एक तरफ संभवतः आगौर की तरफ का भाग कच्चा छोड़ दिया जाता था। कहीं-कहीं तालाबों में स्त्री और पुरुषों के नहाने के लिए भी अलग प्रबंध होता था। छत्तीसगढ़ में डौकी घाट महिलाओं के लिए, तो डौका घाट पुरुषों के लिए बनते थे। बिहार में दो गांव के बीच निर्जन क्षेत्र में गुहिया पोखर मिलते हैं। अपने आप बने ऐसे ही तालाबों का एक और नाम है अमहा ताल। छत्तीसगढ़ी में अमहा का अर्थ है अनायास। अमहा का एक अर्थ आम तो है ही। आम के पेड़ से, बड़ी-बड़ी अमराइयों से घिरे ताल अमहा तरिया, ताल या आमा तरिया कहलाते हैं। इस तरह अमरोहा था। आज यह एक शहर का नाम है, पर एक समय आम के पेड़ों से घिरे तालाब का नाम था। वहीं, लखपेड़ा ताल लाखों पेड़ों से घिरा रहता। कहीं-कहीं ऐसे तालाब को लखरांव भी कहा गया है। लखरांव को भी पीछे छोड़े, ऐसा है भोपाल का ताल।

बड़ों की बात छोड़ें, लौटकर आएं छोटे तालाब पर। उथले, कम गहरे, छोटे आकार के तालाब चिखलिया कहलाते थे। ऐसे तालाबों का एक पुराना नाम डाबर भी था। बाई याबाव भी ऐसे ही छोटे तालाबों का नाम था। बाद में यह नाम तालाब से हटकर बावड़ी में आ लगा। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास राजों की बाव नामक बावड़ी आज इस शब्द की तरह ही पुरानी पड़ चुकी है। कई जगह बहुत पुराने तालाबों के पुराने नाम यदि समाज को याद रखने लायक नहीं लगे, तो वे मिट जाते और उन्हें फिर एक नया नाम मिल जाताः पुरनैहा, यानी काफी पुराना तालाब। आसपास के तालाबों की गिनती में सबसे अंत में बने तालाब नवताल, नौताल, नया ताल कहलाने लगते। वे पुराने भी पड़ जाते, तो भी इसी नाम से जाने जाते।

-प्रस्तुति : सुरेंद्र बांसल

दूसरा पहलू

मस्तिष्क को ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज माना जाता है। वैज्ञानिक दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड करने के प्रयास में लगे हैं।

क्या दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं

क्या किसी मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकता है? यह सुनने में रोमांचक तो लगता है, लेकिन थोड़ा डरावना भी है। इसे माइंड अपलोडिंग कहा जाता है। कल्पना करें कि आपका दिमाग, मन व चेतना, सब कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। इस तरह आपको अपने बारे में जानकारी होगी, आप अपनी यादें बनाए रखेंगे और डिजिटल रूप से जी रहे होंगे, लेकिन आपके पास शरीर नहीं होगा। इस नकली दुनिया में आप वे तमाम चीजें कर सकते हैं, जो असली दुनिया में करते हैं, खाना, गाड़ी चलाना, खेल खेलना आदि।

डोब्रोमिर राहनेव

विज्ञान ने चांद पर इन्सान को पहुंचाया, डीएनए की खोज की और चेचक जैसी बीमारी को खत्म किया, ये सब कभी असंभव लगते थे।

प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ रही हैं। चुनौतियों के बावजूद माइंड अपलोडिंग 2045 तक मुमकिन हो सकती है। कुछ का मानना है कि यह सदी के अंत तक हो सकता हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 200 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं।

विज्ञान के पास सैद्धांतिक संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। विज्ञान ने चांद पर इन्सान को पहुंचाया, डीएनए की खोज की और चेचक जैसी बीमारी को खत्म किया, ये सब कभी असंभव लगते थे। मस्तिष्क को ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज माना जाता है। अपलोड किए गए मस्तिष्क को वही इनपुट चाहिए, जो हमेशा से थे, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, छूना, और शरीर की हर छोटी-बड़ी हरकत। अगर ये अनुभव सही नहीं हुए, तो डिजिटल दिमाग में दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे मानसिक तनाव। अगर इन्सान को उसकी इंद्रियों से दूर रखा जाए, तो उसे मानसिक परेशानी हो सकती है। सफल मस्तिष्क अपलोडिंग के लिए पहला कार्य है, मस्तिष्क की संपूर्ण 3डी संरचना को स्कैन करना और उसका मानचित्रण करना। कुछ दशकों में मानव मस्तिष्क का पूरा नक्शा बनाना संभव हो सकता है। फिर भी, सभी 86 अरब न्यूरॉन्स की पहचान करना, और उनके खरबों कनेक्शन को अपलोड करके भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रत्येक न्यूरॉन लगातार अपने कामकाज को समायोजित करती है, और इसे भी मॉडल करना होगा। यह जानना कि मस्तिष्क किस तरह से चीजों की गणना करता है, शॉर्टकट प्रदान कर सकता है। इससे शोधकर्ता मस्तिष्क के आवश्यक भागों का अनुकरण कर सकेंगे। अगर हमें यह पता चल जाए कि दिमाग कैसे काम करता है, तो शायद हमें हर छोटी चीज की नकल करने की जरूरत न पड़े। एक और तरीका हो सकता है-86 अरब न्यूरॉन्स को एक-एक करके कृत्रिम न्यूरॉन्स में बदलना। इससे दिमाग को अपलोड करना आसान हो जाएगा, लेकिन अभी वैज्ञानिक एक भी असली न्यूरॉन को कृत्रिम न्यूरॉन में नहीं बदल पाए हैं। प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेशक चुनौतियां बड़ी हैं और आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन माइंड अपलोडिंग 2045 तक मुमकिन हो सकती है। कुछ का मानना है कि यह सदी के अंत तक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 200 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। *-द कन्वर्सेशन से*

आंकड़े

इन्सान के हत्यारे

दुनिया में इन्सान समेत कुछ जीव ऐसे हैं, जो प्रतिवर्ष लाखों मनुष्यों की मौत का कारण बनते हैं। इनमें मच्छर सबसे ऊपर हैं।

मच्छर	7,25,000
मनुष्य	4,00,000
सांप	1,38,000
कुत्ते	59,000
हत्यारे बग	10,000

मनुष्य के आंकड़े हत्या करने के हैं, शेष जीवों से बीमारी फैलने के | स्रोत : BBC Science Focus

सूरदास जी कुएं में गिर गए और छह दिन तक उसी में पड़े-पड़े भगवान का नाम जपते रहे। सातवें दिन भगवान श्रीकृष्ण ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए।

अब इन नेत्रों से कुछ और न देखूं

भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे, बल्कि कुछ उम्र के बाद उनकी दृष्टि चली गई थी। बताया जाता है कि एक बार मुसलमानों से सूरदास जी के पिता का युद्ध हुआ, जिसमें उनके छह भाई मारे गए। सूरदास जी इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन वह कुएं में गिर पड़े और छह दिन तक उसी में पड़े-पड़े भगवान का नाम जपते रहे। सातवें दिन भगवान श्रीकृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि प्रदान कर अपने रूप का दर्शन कराया। सूरदास जी ने वर मांगा कि जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन किया है, उनसे और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं।

सूरदास जी को उद्धव का अवतार बताया जाता है। कहते हैं कि सूरदास जी के साथ उनके मुख से निकलने वाले पदों को लिखने के लिए एक लेखक निरंतर रहता था। कई अवसरों पर तो भगवान श्रीकृष्ण स्वयं लेखक बनकर लिखते थे। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि मेरे मुख से निकलने से पहले ही मेरी बात सिवाय भगवान के और कोई नहीं लिख सकता। उन्होंने तत्काल लेखक की बांह पकड़ ली। भगवान हाथ छुड़ाकर अंतर्धान हो गए। इस पर सूरदास जी ने लिखा, 'बांह छुड़ाए जात हौ, निबल जानिकै मोहि। हिरदै ते जब जाहुगे, मरद बदौंगो तोहि।।' सूरदास जी के पद भक्तों के हृदयों में बारंबार गूंजकर भक्ति की जोत जगा देते हैं।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 12 जून, 1953

अमेरिका शक्तिशाली देश, पर अकेला कुछ नहीं कर सकता

अमरीका सबसे अधिक शक्ति शाली

अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि उनका देश सबसे अधिक शक्तिशाली होते हुए भी यह तय नहीं कर सकता कि उसे कब लड़ना चाहिए और कब नहीं। इसलिए मित्र देशों के बीच एकता बहुत जरूरी है।

सही को सही कहने की बात

पहलगाम हमले के बाद किसी अन्य विपक्षी की तुलना में थरूर ने सरकार का सबसे ज्यादा समर्थन किया है और इसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है।

सुरेंद्र कुमार, पूर्व राजनयिक | **सियासत**

क्या आप किसी पुरानी राष्ट्रीय पार्टी का नाम बता सकते हैं, जिसके कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का पुतला जलाया हो, और उसे हारते हुए देखने के लिए कड़ी मेहनत भी की हो? क्या आप किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी का नाम बता सकते हैं, जिसके सांसद ने अपने दस मिनट लंबे और बेबाक ऑक्सफोर्ड यूनियन भाषण से शक्तिशाली ब्रिटिश राजनीति, शिक्षा और मीडिया को हिलाकर रख दिया हो, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा व्यवस्थित रूप से किए गए अकथनीय अन्याय व कुकृत्यों और उसकी नीतियों से जन्मे अकालों व आर्थिक दरिद्रता के दुष्चक्र को उजागर किया और सार्वजनिक रूप से माफी और क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे छह घंटे में करीब 70 लाख लोगों ने पसंद किया? उनके इस कार्य की देश के प्रधानमंत्री सहित पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं ने सराहना की, लेकिन खुद उनकी पार्टी इस पर चुप्पी साधे रही!

क्या आप किसी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी का नाम बता सकते हैं, जिसके सांसद ने 26 किताबें लिखी हों, जिनमें से ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्टसेलर रही हों, जिनके साप्ताहिक कॉलम भारत और विदेश में दो दर्जन से अधिक प्रकाशनों में छपते हैं और जिनकी पुस्तक 'एन एरा ऑफ डार्कनेस' ने उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। जिनकी वाद-विवाद और भाषण कला सेंट स्टीफेंस कॉलेज के दिनों से ही ऐसी रही है, जिसके बारे में कहानियां बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है? तिरुवनंतपुरम से चार बार सांसद रहे शशि थरूर लंबे, सुंदर, शालीन, अच्छे कपड़े पहनने वाले, स्टाइलिश और स्पष्टवादी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी धूम है। ट्विटर (अब एक्स) पर भारत में उनके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, जब तक कि शाहरुख खान, बिग बी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पीछे नहीं छोड़ दिया।

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि जब वह छोटे थे, तो काफी बीमार रहते थे। तब टीवी, इंटरनेट, फेसबुक या इंस्टाग्राम न होने के कारण, वह किताबें पढ़ने की तरफ आकर्षित हुए। यह उनके पिता द्वारा प्रोत्साहित की गई एक अच्छी आदत थी। वह 1978 में 22 वर्ष की आयु में फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी ग्रहण करने वाले सबसे कम उम्र के छात्रों में से एक थे। वह संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए और वहां 29 वर्ष बिताए, अवर महासचिव भी बने। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने की सोची और भारत के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। लेकिन किस्मत और दुनिया की एकमात्र महाशक्ति उनके पक्ष में नहीं थी। हालांकि, उन्हें दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले, दो विदेश मंत्रियों और एक प्रधानमंत्री से ज्यादा।

वह तिरुवनंतपुरम से पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप तौर पर चुनाव लड़े, तो स्थानीय नेता इस बाहरी व्यक्ति से प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने काम से न केवल जनाधार बढ़ाया, बल्कि लगातार चार लोकसभा चुनाव जीते।

एक बार भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा था कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन शशि विपक्ष के लिए ऐसा नहीं मानते। वह सरकार से वाजिब सवाल पूछने में नहीं हिचकिचाते, लेकिन जब सरकार कुछ सराहनीय करती है, तो सराहना करने से भी पीछे नहीं हटते। सितंबर 2014 में, वह मोदी को उनके संयुक्त राष्ट्र भाषण खासकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने के लिए बधाई देने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने मोदी के कई फैसलों खासकर 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की प्रशंसा की है। तभी से कई लोग कह रहे हैं कि वह नाव छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। पिछले महीने उन्होंने यह कहकर अफवाहों को हवा दे दी थी कि अगर पार्टी उनकी सेवाओं की कद्र नहीं करती, तो उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से, वह किसी भी अन्य विपक्षी नेता की तुलना में टीवी/अखबार साक्षात्कारों, पॉडकास्ट और बैठकों में अधिक दिखाई दिए हैं, जिसमें उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की है, सरकार का समर्थन किया है और इसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य तक बताया है। अब, जब वह अमेरिका, ब्राजील और कोलंबिया में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और सरकार की तरफ से प्रशंसा पा रहे हैं, तो वह कांग्रेस की आंख की किरकिरी बनते जा रहे हैं। उनके जैसी क्षमता और सकारात्मक व रचनात्मक सोच वाला नेता किसी भी पार्टी के लिए एक संपत्ति होगा। कांग्रेस अगर उन्हें खोती है, तो नुकसान उसका ही है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 05-06-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH14 User: dilip.lal Time: 06-04-2025 20:55 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 5 जून 2025

शर्मनाक वाकया

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शख्स के साथ पुलिस का क्रूरता भरा बर्ताव सीधे-सीधे नस्लभेदी हिंसा है। स्थानीय पुलिस अपने इस कृत्य का चाहे जितना बचाव करे, लेकिन उससे यह सच नहीं छिपेगा कि वहां के एक तबके में नस्लवादी सोच बसी हुई है और ये लोग इस आधार पर भेदभाव करते हैं। चूंकि भारतीय कम्युनिटी वहां तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए उसे इसका ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत को डिप्लोमैटिक स्तर पर यह मामला जरूर उठाना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया में रंगभेद

गले पर पैर रखा । एडिलेड में रहने वाले गौरव कुंडी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की बर्बरता के कारण अस्पताल में जीवन-मौत से जूझ रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ऑफिसर ने उनकी गर्दन पर पैर रखकर दबा दिया था। उनके दिमाग और गले की नसों को गंभीर क्षति पहुंची है और नहीं पता कि वह दोबारा कभी खड़े हो भी पाएंगे या नहीं। कहा जा रहा है कि गौरव और उनकी पत्नी के बीच सड़क पर बहस हो रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को लगा कि वह घरेलू हिंसा कर रहे हैं।

ब्लैक लाइव्स मैटर । यह मामला मई 2020 में अमेरिका में हुए जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस की याद दिलाता है। जॉर्ज की गिरफ्तारी के दौरान भी पुलिस ने इसी तरह की क्रूरता की थी और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे अमेरिका में 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी गूंज दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई पड़ी। तब अश्वेतों के हक में दूसरे समुदायों ने भी आवाज बुलंद की थी।

कूटनीतिक संकट । ऑस्ट्रेलिया के केस में देखें, तो भारतीयों के खिलाफ हिंसा के यहां कई मामले सामने आ चुके हैं - और इनमें से कई के पीछे वजह नस्ल और त्वचा का रंग होता है। 2010 का नितिन गर्ग हत्याकांड तो इतना गंभीर था कि इसकी वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया था। ग्रैजुएट स्टूडेंट नितिन की हत्या एक नाबालिग ने की थी।

छात्रों में डर । 2009-10 के दौरान हालात इतने खराब हो गए थे कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय छात्रों की तादाद 46% तक कम हो गई थी। 2017 में कैब ड्राइवर प्रदीप शर्मा को भारतीय होने के कारण निशाना बनाया गया, 2022 में शुभम गर्ग नाम के स्टूडेंट की इसी वजह से हत्या कर दी गई।

भरोसा डिगेगा । 2021 की जनगणना के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 9.76 लाख है। चीन के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भारत से पहुंचते हैं। 2024 में उनकी तादाद 1.39 लाख रही। ऑस्ट्रेलिया के विकास और उसकी आय में भारतीयों का बड़ा योगदान है। ऐसे में एडिलेड जैसी घटनाएं नागरिकों के स्तर पर ही नहीं, देशों के स्तर पर भी भरोसे को कमजोर करती हैं।

साड्डी दिल्ली

जब वाल्मीक रोए

विवेक शुक्ला

वह साल था 1963। चीन के साथ हुई जंग के बाद देश में छाए हताशा के बादल छंट नहीं रहे थे। फिर उस युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी चेतन आनंद की फिल्म 'हकीकत' आई। उसे देखने के लिए मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड के कुछ विद्यार्थी कनॉट प्लेस के ओडियन पिक्चर हॉल पहुंचे। 'हकीकत' के शुरू होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। दर्शक पूरे मन से फिल्म देख रहे थे। जैसे ही फिल्म का अमर गीत 'होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा...' पर्दे पर दिखाया जाने लगा, मॉडर्न स्कूल का एक छात्र भावुक होकर रोने लगा। उसका नाम था वाल्मीक थापर, जो आगे चलकर बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। थापर का हाल ही में निधन हुआ।

वाल्मीक थापर अपने कुछ स्कूली दोस्तों के साथ 'हकीकत' इसलिए भी देखने गए थे, क्योंकि उसमें उनकी रिश्ते की मौसी प्रिया राजवंश मुख्य भूमिका में थीं। उनके साथ उनकी बहन मालविका सिंह, तेजबीर सिंह जुगनू, राजीव नारायण सिंह वगैरह थे। मालविका सिंह ने आगे चलकर तेजबीर सिंह से शादी कर ली। तेजबीर सिंह नई दिल्ली के प्रमुख बिल्डर सोबा सिंह के पौत्र हैं। इस नाते वे खुशवंत सिंह के भतीजे होते हैं। सोबा सिंह परिवार की बहू बनने के बाद मालविका सिंह ने नई दिल्ली के बनने की कहानी को अपनी कई किताबों में तफसील से लिखा।

इस बीच, वाल्मीक परिंदों और पशुओं के हक के लिए स्कूल में अपने दोस्तों के साथ अखंड चर्चाएं करने लगे थे। यह चर्चा स्कूल से लेकर बंगाली मार्केट और वाल्मीक के कौटिल्य मार्ग स्थित घर तक में चलती रहती। वाल्मीक को कहीं कोई घायल चिड़िया, तोता, कौआ या कोई और परिंदा मिलता तो वह उसे अपने घर में ले आते। उसका इलाज करते। उसे सेहतमंद करने के बाद खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देते। मॉडर्न स्कूल के बाद वाल्मीक ने हिंदू कॉलेज और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में दाखिला लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए वाल्मीक एक तरह से बाघों को अपना मित्र बना चुके थे। तब उन्होंने तेजबीर सिंह के साथ बाघों का गहराई से अध्ययन करने के लिए रणथंभौर के जंगलों की खाक छानना शुरू कर दिया। लुटियंस दिल्ली की सुविधाओं को छोड़कर जंगलों में रहना उन्हें सुकून देने लगा। जब वाल्मीक दिल्ली में होते तो पत्नी संजना कपूर, पुत्र हमीर और किताबों से ही घिरे रहते।

एकदा

बाघिन की बेबसी

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक बाघिन नरभक्षी बन कई ग्रामीणों की जान ले चुकी थी। सरकारी प्रयासों के बावजूद वह हर बार बच निकलती और अधिक घातक होती जाती। तब ग्रामीणों को याद आया एक नाम - जिम कॉर्बेट। वह कोई साधारण शिकारी नहीं थे। उनके

Subrata Dhar
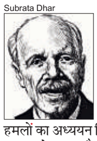

भीतर मानवता, समझ और जानवरों के प्रति सहानुभूति भी थी। उन्होंने यह कार्य न इनाम के लिए किया, न प्रसिद्धि के लिए, बल्कि मासूमों को बचाने और यह सच्चाई जानने के लिए कि आखिर वह बाघिन नरभक्षी कैसे बन गई। तब तक उसने 436 लोगों की जान ले ली थी। जिम ने बाघिन की गतिविधियों और हमलों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि वह बाघिन गोली के एक पुराने जख्म और टूटे दांतों की पीड़ा झेल रही थी। इसके कारण उसके लिए जानवरों का शिकार करना मुश्किल हो गया था। बाघिन को मारने के बाद भी जिम को खुशी नहीं हुई। वह उसकी मृत देह के पास घुटनों के बल बैठ गए। अपनी पुस्तक 'Man-Eaters of Kumaon' में उन्होंने लिखा है - हर प्राणी के व्यवहार के पीछे एक कारण होता है। जो खतरा दिखता है, वह अक्सर बेबसी होती है। सच्ची बहादुरी मारने में नहीं, उसे समझने में है।

संकलन : दिलीप लाल

इलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति के टैक्स बिल को शर्मनाक बताया, विश्वविद्यालयों में भी नाराज़गी

US में ट्रंप को क्यों कहा जा रहा TACO

मनीष गुप्ता, न्यू यॉर्क से

अमेरिका में 'TACO' आम बोलचाल में शामिल शब्द है। यह एक तरह का मेक्सिकन खाना है, लेकिन कभी-कभी मेक्सिकन्स को नीचा दिखाने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को 'TACO' कहा जा रहा है। ट्रंप को चिढ़ाने वाले TACO का मतलब बता रहे - Trump Always Chickens Out यानी ट्रंप हमेशा डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किल यह है कि उन्हें अब वह भी चिढ़ा रहे हैं, जो कभी उनके 'राइट हैंड मैन' कहे जा रहे थे, यानी इलॉन मस्क।

मस्क की नाराजगी । टेस्ला के सीईओ ने ट्रंप के महत्वाकांक्षी 'वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट' (OBBB) को घिनौना और शर्मनाक कहा है। पिछले महीने ही उन्होंने सरकार का साथ छोड़ा था और तब कहा गया कि दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। मस्क का ताजा ट्वीट उनकी नाराजगी जाहिर करता है, जिसमें उन्होंने टैक्स बिल को बेहूदगी से भरा हुआ और फिजूलखर्ची वाला बताया है। बिल में टैक्स कम करने की बात कही गई है, जिससे सरकार की कमाई कम होगी और खर्च बढ़ेगा। अमेरिका पर पहले ही 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है और महंगाई बढ़ी हुई है।

यूटर्न या रणनीति । TACO से टेस्ला सीईओ तक, ट्रंप की इमेज कैसे प्रभावित हुई? जवाब उनके फैसलों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति को TACO की उपमा मिली उनकी टैरिफ नीति के चलते। पहले वह आक्रामक टैक्स की धमकी देते हैं, जिससे घबराकर वहां का शेयर बाजार गिरता है। फिर कुछ दिनों में वही ट्रंप शांति दूत बनकर टैरिफ स्थगित कर देते हैं - बाजार फिर उछलता है। वॉल स्ट्रीट अब इस पैटर्न को समझ गया है।

गरम, फिर नरम । बाजार में 2 अप्रैल के बाद गिरावट आई थी, मीडिया में बड़ा हंगामा था, लेकिन आज मार्केट रिकवर कर चुका है। ट्रंप फिर भी बीच-बीच में शिगूफा छोड़ते रहते हैं। जैसे उन्होंने ऐपल पर टैरिफ लगाने की बात की, चीन में आईफोन बनने की प्रक्रिया को सीधे निशाने पर ले लिया। फिर सैमसंग को भी लपेटा, ताकि कोई यह न कहे कि सिर्फ चीन विरोधी चाल है। कुछ ही दिनों में ट्रंप नरम पड़े और कहा, 'हम बात कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं।' इस टैरिफ तमाशे में यूरोप भी उलझा पड़ा है। लेकिन ट्रंप की राजनीति सिर्फ टैक्स लगाने की नहीं, तार छेड़ने की है, और वह भी तब तक, जब तक अगला बयान पलटी न खा ले।

ट्रंप की डराओ और बचाओ रणनीति
- टैरिफ को हथियार बनाकर व्यापारिक सौदेबाजी कर रहे
- विश्वविद्यालयों में खास विचारधारा आगे बढ़ाने की कोशिश
- हर नीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मुखौटा पहना रहे

विचारधारा की लड़ाई । यह कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं है। दूसरा मोर्चा है विचारों का, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का सामना हो रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। पिछले दिनों ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की फेडरल फंडिंग रोक दी। कारण? ट्रंप का आरोप है कि हार्वर्ड अब एजुकेशन की जगह रेडिकल Woke विचारधारा का अड्डा बन चुका है। जब से गाजा-इस्राइल विवाद शुरू हुआ, हार्वर्ड कैंपस में कुछ छात्रों ने हमास के पक्ष में नारे लगाए, जिसे ट्रंप ने अमेरिका के मूल्यों के खिलाफ बताया।

निशाने पर संस्थान । यह बात नई नहीं है। ट्रंप पहले भी Ivy League यूनिवर्सिटीज को वामपंथियों का मैदान कह चुके हैं। उनका तर्क है कि यहां अब शिक्षा कम और वैचारिक ब्रेनवॉश ज्यादा होता है। हार्वर्ड, येल, कोलंबिया जैसे संस्थान उनके निशाने पर इसलिए हैं, क्योंकि यहां की राजनीति अब कैंपस से निकल कर कैपिटल हिल तक पहुंचने लगी है।

हार्वर्ड से टकराव । ट्रंप का मानना है कि राजनीतिक शुद्धता के नाम पर अमेरिका की नई पीढ़ी को अपराध बोध, शर्म और पहचान की उलझनों में धकेला जा रहा है और हार्वर्ड इस 'cancel culture' का किला बन गया है। यह लड़ाई सिर्फ एक विश्वविद्यालय की नहीं, अमेरिकी चेतना की है। ट्रेड वॉर में ट्रंप 'मेड इन अमेरिका' की बात करते हैं, तो थॉट वॉर में 'थिंक फॉर अमेरिका' की। उनका कहना है कि छात्रों को अमेरिका के इतिहास से प्यार करने की सीख दी जाए, न कि उससे शर्मिंदा होने की।

भारत के लिए मौका । अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के बीच भारत को दोनों तरफ से ऑफर मिल रहे हैं। कंपनियां अब चीन से हटकर नए मैन्युफैक्चरिंग ठिकानों की तलाश में हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति ने इस प्रक्रिया को तेज किया है। यदि भारत प्रशासनिक जटिलताओं और लॉजिस्टिक बाधाओं को कम करे, तो वह चीन का विकल्प नहीं, अपना खुद का ब्रैंड बन सकता है। उदाहरण के लिए, ऐपल पहले ही कुछ आईफोन मॉडल भारत में असेंबल कर रही है और Foxconn जैसी कंपनियां दक्षिण भारत में बड़े निवेश कर रही हैं।

ट्रंप का सिद्धांत । अब सवाल है कि डॉनल्ड ट्रंप कौन हैं - नेता या रणनीतिकार? ट्रंप केवल राष्ट्रपति ही नहीं हैं, वह एक राजनीतिक सिद्धांत बन चुके हैं। टैक्स और टैरिफ से लेकर थॉट और थिंकिंग तक- वह हर स्तर पर लड़ाई छेड़ते हैं। कभी बाजार को हिलाते हैं, कभी विश्वविद्यालय को। उनका नया नाम TACO एक नई तरह की राजनीति का परिचायक है - खौफ से शुरू, सौदेबाजी पर खत्म।

(लेखक फिल्मकार, कॉलमनिस्ट और राइटर हैं)

कितनी खस्ताहाल है बिहार की स्वास्थ्य सेवा

शैलेंद्र पांडेय

पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी PMCH अपनी स्थापना के 100 बरस पूरे कर चुका है। इस बात का ऐलान करता है 22 फुट ऊंचा वह स्ट्रक्चर, जिसका उद्घाटन इस साल मई की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश सरकार PMCH को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहती है, जिसमें 5,462 बेड होंगे। दावा है कि इसके बाद बिहार के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मौत से सवाल । मार्च 2027 में इसके पूरा होने की तारीख है और उसके बाद ही पता चलेगा कि हकीकत में साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और 6 साल की मेहनत का हासिल क्या रहा। लेकिन बिहार का गौरव बनने से पहले फिलहाल PMCH चर्चा में है 10 साल की रेप पीड़िता की मौत के लिए। आरोप है कि इलाज में देरी उसकी जान पर भारी पड़ी।

लापरवाही और असंवेदनशीलता । इस घटना के दो पहलू हैं - बिहार में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और जो संसाधन हैं भी, उनका संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल न करना। रेप पीड़िता को पहले मुजफ्फरपुर में एडमिट किया गया था, पर यहां सांस की नली की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की सुविधा नहीं थी। इस पर उसे राजधानी रेफर कर दिया गया, लेकिन पटना AIIMS के ENT विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर छुट्टी पर थे। बच्ची को फिर PMCH लाया गया। यहां के ENT में ICU नहीं था और बच्ची को लेकर परिजन एक से दूसरे विभाग में घूमते रहे। PMCH का कहना है कि उन्हें मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल की तरफ से सूचना ही नहीं मिली थी।

बदहाल व्यवस्था । स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। साल दर साल आने वाले सर्वे, रिपोर्ट और ऑडिट बताते हैं कि नई इमारतें भले बन रही हों, लेकिन मैनपावर और इक्विपमेंट में बदहाली बनी हुई है। साल 2018 के नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में स्वास्थ्य मानकों पर देश के 50 सबसे पिछड़े जिलों में से 15 बिहार के थे। आज भी कमोबेश हालात वही हैं।

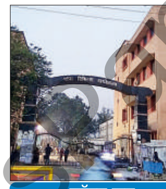
कॉमन रूम

डॉक्टरों की कमी । पिछले साल नवंबर में आई कैग की रिपोर्ट बताती है कि बिहार के 15 मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल में 1,436 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन केवल 691 थे। इसी तरह 1,001 मेडिकल ऑफिसर की जगह महज 338 की तैनाती हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज में ही 247 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का काम 129 से कराया जा रहा था। पटना में 11,500 लोगों पर एक डॉक्टर की तैनाती है। अररिया जैसे भी जिले हैं, जहां एक डॉक्टर के भरोसे 56 हजार लोग हैं। पूर्वी चंपारण की 50 लाख की आबादी स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 10% मेडिकल प्रफेशनल्स के भरोसे चल रही है।

सुविधाओं का अकाल । बिहार के सभी बड़े अस्पतालों पर हद से ज्यादा दबाव है और इसकी वजह है प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं की कमी। ऑडिट टीम ने जिन हेल्थकेयर फैसिलिटीज को चेक किया, वहां पानी, पंखे, कुर्सी और महिलाओं-पुरुषों के लिए अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। दवाओं और स्टाफ की कमी से जूझ रहे ये स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को आगे रेफर करने पर ज्यादा जोर देते हैं।

पलायन की मार । बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1645 MBBS सीटें हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को जोड़कर यह आंकड़ा ढाई हजार तक पहुंच जाता है। लेकिन, सवाल है कि इनमें से कितने मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद राज्य में रुक रहे हैं।

आज़ादी के आंदोलन में राजा का रोल

अरुणांश बी. गोस्वामी

आज यानी 5 जून 2025 को एक दूरदर्शी भारतीय शासक की 100वीं पुण्यतिथि है, जिन्हें भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने 'राजकुमारों का अगुआ' कहा था। यहां बात ग्वालियर के महाराजा माधो राव सिंधिया की हो रही है। उनके बारे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय ने लिखा था, 'उन्होंने लोगों के कल्याण में पिता के समान चिंता दिखाई है।' 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान, सिंधिया ने महात्मा गांधी को न केवल मौखिक संदेश भेजा बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए बड़ी मात्रा में धन भी दान के रूप में भेजा।

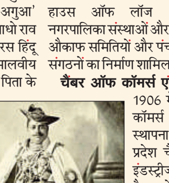

स्थायी स्मारक । ग्वालियर उनका ही क्रिएशन है। महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर, जयारोग्य अस्पताल, होटल डी ग्वालियर जो अब NCC ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के रूप में कार्य करता है, द सिंधिया स्कूल, दिल्ली परिवहन निगम और शिवपुरी शहर सभी महाराजा माधो राव सिंधिया के बनवाए स्थायी स्मारक हैं।

टाइम मशीन

विकास बोर्ड का निर्माण । सिंधिया राज्य की आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली एक और पहल सिंचाई परियोजनाओं में लगभग 2.5 करोड़ रुपये का निवेश था। माधो के शासनकाल के 31 वर्षों के दौरान कई अन्य कार्यक्रम शुरू किए गए और 1920 तक, वे आर्थिक संसाधनों के विकास के लिए एक बोर्ड के निर्माण के लिए पर्याप्त रूप से विस्तारित हो गए।

प्रमुख सुधार । महाराजा माधो राव सिंधिया के प्रमुख सुधारों में न्यायपालिका को कार्यकारी शाखाओं से अलग करना, कानूनों का संहिताकरण और हाउस ऑफ कॉमन्स (मजलिस-ए-आम), हाउस ऑफ लॉज (मजलिस-ए-कानून), नगरपालिका संस्थाओं और जिला और परगना बोर्ड, औकाफ समितियों और पंचायत बोर्ड जैसे स्थानीय संगठनों का निर्माण शामिल था।

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज । उन्होंने 1906 में ग्वालियर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जिसे अब मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ग्वालियर और नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की भी स्थापना की, जिसे अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के रूप में जाना जाता है। सिंधिया ने अपने राजसी निवेश से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना में मदद की।

अनगिनत सम्मान । माधो महाराज को ऑक्सफर्ड, कैंब्रिज और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अप्रैल 1925 में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इस वजह से उन्हें पेरिस में रुकना पड़ा, जहां 5 जून को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद 'द डेली टेलीग्राफ' ने लिखा था, 'किसी भी भारतीय राजकुमार के नाम पर अपने राज्य के सुदृढ़ प्रशासन का और विज्ञान और राजनीतिक विचार दोनों में आधुनिक तरीकों को अपनाने का इतना बड़ा रेकॉर्ड नहीं था, जितना कि ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के नाम पर था।'

(लेखक सिंधिया रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं)

अदृश्य ज़ंजीरें

प्रणव प्रियदर्शी

इसमें दो राय नहीं कि लड़कियों को जहां, जिस फील्ड में मौका मिल रहा है, वे खुद को साबित कर रही हैं। कई मामलों में तो वे हालात से अपने लिए मौका छीन कर खुद को साबित कर रही हैं। मिसाल के तौर पर, सेना में लड़कियों को आज भी आधिकारिक रूप से फ्रंटलाइन कॉम्बैट की भूमिका नहीं मिली है। मगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अखनूर में इंटरनैशनल बॉर्डर पर तैनात आधा दर्जन महिला बीएसएफ कर्मियों ने पाया कि उन पर अग्रिम चौकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आन पड़ी है। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी के नेतृत्व में इन बहादुर लड़कियों ने तीन दिन, तीन रात पाकिस्तानी गोलीबारी का मुकाबला किया और दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर करके ही मानीं। ऐसी मिसालें हर फील्ड में और देश के हर हिस्से में मिल जाएंगी। फिर भी ज्यादातर क्षेत्रों में महिलाओं की मौजूदगी आज भी प्रतीकात्मक ही है। देश के कई शहर ऐसे हैं जहां महिला कैबी की बात की जाए तो लोग आश्चर्य से आपकी ओर देखने लगते हैं। कुछ अन्य शहरों में वे हैं भी तो अपवाद रूप में नजर आती हैं। आंकड़े भी इस स्थिति की पुष्टि करते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय के नए टाइम यूज सर्वे के मुताबिक, खाना बनाने के कार्य में महिलाओं की भागीदारी 76% है जबकि पुरुषों की मात्र 6%। ऐसे में महिला साक्षरता दर आजादी के समय के 9% से बढ़कर 77% हो जाने के बावजूद अगर लड़कियां घरेलू कामकाज में बंधी नजर आती हैं तो क्या आश्चर्य! हालात की यह हकीकत अन्य आंकड़ों में भी झलकती है। अपने देश में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी आज भी 37% ही है जबकि यह जापान में 55%, चीन में 60% और वियतनाम में 63% है। लड़कियों और महिलाओं के पैरों में यह ऐसी अदृश्य बेड़ी है, जिससे मुक्ति के लिए कानून बदलना काफी नहीं है। व्यक्ति, परिवार और समाज की सोच बदलनी होगी।

नेहा भंडारी

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

इलाज की सुविधा

3 जून का लेख 'गांवों के इस मर्ज का इलाज होना चाहिए' पढ़ा। भारत की ज्यादातर आबादी गांवों और छोटे कस्बों में रहती है। निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए न तो उसके पास पैसे हैं, न ही आसानी से शहरों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों तक पहुंच है। कुल मिलाकर उन लोगों को झोलाछाप डॉक्टरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी देश की 95 करोड़ आबादी सरकार से मिलने वाले स्वास्थ्य बजट से दूर है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बिना देश के विकास की बात करना बेमानी है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो ताकि समय पर अपना इलाज करा सकें। शहर हो या गांव, वहां रहने वालों के लिए शिक्षा के साथ-साथ चिकित्सा सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

मीना धानिया, दिल्ली

विराट का संन्यास

कुछ दिन पहले जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, तब शायद ही किसी को ज्यादा हैरानी हुई होगी। लेकिन पांच दिन बाद जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तो दुनिया भर के प्रशंसक चौंक उठे। किसी को दूर-दूर तक ये अंदेशा नहीं था कि विराट इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट से विदा ले लेंगे। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टेस्ट क्रिकेट में उनका खराब प्रदर्शन है। उन्हें लगातार दबाव और आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल, भारत का आगामी इंग्लैंड दौरा बहुत ही कठिन रहने वाला है। विराट उसके बाद संन्यास लेते तो बेहतर होता।

विजय कुमार किराड़, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

पाक में भूकंप का फायदा उठा जेल से 216 कैदी फरार - एक खबर
- तो भूकंप ने जेल अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी!

प्रीति सिंह

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

किसानों का मान रखें तो वह अन्न बन जाएगा प्रसाद

ब्रह्मा कुमारी शिवानी

पर्यावरण हमें दो सत्यता का बोध कराता है - अच्छी भावनाएं स्वस्थ वातावरण बनाती हैं और हमारे स्वास्थ्य पर पर्यावरण का गहरा प्रभाव है। हमारी भावनाओं की ऊर्जा भौतिक तत्वों को प्रभावित करती है। अगर मन शांत, स्थिर और स्नेह से भरा हो, तो हम प्रकृति की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। जब मन तनाव और नकारात्मकता से भरा होता है, तब हम अनजाने में ही प्रकृति का नुकसान करते हैं। असल में यह एक आध्यात्मिक समस्या भी है। 'संकल्प से सृष्टि' का सिद्धांत कहता है कि जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही आसपास का माहौल बनता है।

देखा जाए तो मनुष्य का चिड़चिड़ापन, कटु बोल, गुस्सा, घबराहट अथवा असुरक्षा भाव उसके घर, दफ्तर और आसपास के वातावरण को बिगाड़ता है, क्योंकि हर स्थान का एक वाइब या वाइब्रेशन होता है। तभी पूजा स्थलों में शांति, परिवार के लोगों के बीच सुख और हॉस्पिटल में बेचैनी का अनुभव होता है। हमारी भावनाओं का वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलता है, जो सबके मन बुद्धि को प्रभावित करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमेशा शांति का संकल्प चलाएं, अच्छे शब्द बोलें और अपने अंदर दया का भाव भरकर कर्म करें, ताकि हमसे औरों को राहत देने वाला वातावरण बने।

हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पेड़-पौधे, वृक्ष-लता और खेती-फसल आदि हैं, वे पूरी मानवता का दुख, दर्द, तनाव और तड़प वाली जहरीली ऊर्जा को झेल रहे हैं - ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी वनस्पतियों से बना भोजन हमारा सही पोषण नहीं कर पाता। इसके चलते आज अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। इसका निदान जैविक खेती के साथ यौगिक खेती में है। वनस्पतियों को फलने-फूलने के लिए इंसानों का स्नेह, सम्मान, आदर और मेडिटेशन की शक्ति चाहिए। इसके साथ ही हमें किसानों का भी ध्यान रखना है, उनका सम्मान करना है, उन्हें उनकी मेहनत और लागत का उचित मूल्य चुकाना भी है। किसानों की फसल में उनके मन की खुशी और संतुष्टि भी सम्मिलित हो जाती है, जिससे उनकी ऊपज स्वस्थ व पौष्टिक बनती है।

प्रकृति और समाज को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपनी मानसिक ऊर्जा को पवित्र और सकारात्मक बनाना होगा। इसके लिए भय, हिंसा और दर्द भरे विकारी कंटेंट से दूर रहना है। सुबह प्रभु की मधुर याद में होनी चाहिए। उस वक्त दुनियावी बातों का ध्यान नहीं करना। खाना बनाते और खाते समय ईश्वर के ध्यान में रहना है। इससे वह प्रसाद बन जाएगा और तन-मन को स्वस्थ व संतुलित रखेगा। आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्म ध्यान, आंतरिक सशक्तिकरण वाली सात्विक सामग्री व स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना है। तभी हम जड़ और जीव जगत को हरा-भरा व खुशहाल बना सकते हैं।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन: 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु. संपादक (दिल्ली मार्केट): आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 5 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जहां अकारण अत्यंत सत्कार हो, वहां परिणाम में दुख की आशंका करनी चाहिए।
-कुमार संभव

पर्यावरण बचा तो बचेगी मानवता

पर्यावरण दिवस

राजेश मणि

प्रत्येक वर्ष जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था और आज 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना दिलाना है। वर्ष 2025 की थीम है 'पृथ्वी के साथ शांति बनाएं' (मेक पीस विद नेचर), जो बताती है कि अब प्रकृति के साथ संतुलन बनाना विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनिवार्यता है।

आज दुनिया और भारत एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं। तेजी से होते शहरीकरण, औद्योगीकरण और अत्यधिक उपभोग ने पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। जलवायु परिवर्तन अब केवल भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। वर्ष 2024 में भारत में रिकॉर्ड 294 हीटवेव की घटनाएं दर्ज की गईं। राजस्थान के फालोदी में तापमान 51 डिग्री पहुंच गया जो अब तक का सबसे अधिक है। महाराष्ट्र, बिहार और मध्य भारत के कई हिस्सों में बाढ़ और सूखा एक साथ देखने को मिला। यह जलवायु असंतुलन का स्पष्ट संकेत है। वायु प्रदूषण भी एक विकराल समस्या है। IQAir की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। दिल्ली, कानपुर और गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर 300 से ऊपर रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में हर साल 12 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं।

जल संकट भी गहराता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 21 बड़े शहरों में 2030 तक भूजल समाप्त हो सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में गर्मियों के दौरान टैंकरों के भरोसे पानी की आपूर्ति हो रही है। लगभग 60 करोड़ भारतीय मध्यम से गंभीर जल संकट झेल रहे हैं। वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। एफएओ के मुताबिक, 2010-2024 के बीच दुनिया भर में औसतन हर साल 1.1 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हुई। भारत में विकास परियोजनाओं, खनन और अवैध कटाई के कारण अरावली, झारखंड और पश्चिमी घाट के जंगलों में वृक्षों की संख्या तेजी से घटी है। इससे न केवल कार्बन अवशोषण घटता है, बल्कि वन्य जीवन भी संकट में आ गया है। हालांकि इन समस्याओं के बीच कुछ प्रेरक प्रयास भी हुए हैं। इंदौर, जिसने लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है, अब पूरी तरह जीरो वेस्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। वहां 100% कचरे का पृथक्करण होता है, और वेस्ट-टू-

एनर्जी प्लांट से प्रति दिन 20 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इससे 50,000 घरों को बिजली मिल रही है। केरल का कोच्चि शहर, जहां 'हरित कोच्चि' अभियान के अंतर्गत 1.5 लाख पौधे लगाए गए, अब तापमान में औसतन 1.8 डिग्री की कमी और जैव विविधता में 22% वृद्धि देख रहा है। यह परियोजना पूरी तरह से नागरिकों की भागीदारी से चलाई गई, जिससे सामुदायिक चेतना भी बढ़ी।

उत्तराखंड के फुलवारी गांव की कहानी भी प्रेरक है। वहां के किसानों ने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाया। रासायनिक उर्वरकों से दूरी बना कर उन्होंने परंपरागत बीज और गोबर खाद का उपयोग शुरू किया। इससे फसल की गुणवत्ता सुधरी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ी और किसानों की आय में 22% की वृद्धि हुई। दिल्ली सरकार ने 2023 में ट्री ट्रांसप्लांटेशन नीति लागू की जिसके अंतर्गत सड़क या परियोजना के कारण हटाए गए पेड़ों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। इनमें से 70% से अधिक पेड़ जीवित रहे, जो उल्लेखनीय सफलता है। सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से भी कई पहलें की जा रही है। मिशन LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरन्मेंट) के तहत लोगों को पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जैसे साइकिल चलाना, बिजली-पानी की बचत, और दोबारा उपयोग।

राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारत ने 2025 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें भारत अग्रणी देशों में शामिल है। नमामि गंगे योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और हरित भारत मिशन जैसे अभियान भी निरंतर चल रहे हैं। फिर भी, प्लास्टिक प्रदूषण जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत हर साल लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से 60% का ही पुनर्चक्रण होता है। यह कचरा नदियों, समुद्र और खेतों को प्रदूषित कर रहा है। कई क्षेत्रीय कानूनों के बावजूद प्लास्टिक बैग और थर्मोकोल का खुलेआम उपयोग भी जारी है।

विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक रस्म नहीं, बल्कि वैश्विक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमने अभी से कदम नहीं उठाए तो अगली पीढ़ियों को शुद्ध हवा, पानी और हरियाली केवल चित्रों और किताबों में ही मिलेंगी। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या स्वयसेवी संथाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समुदाय को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें अपने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव लाने होंगे। जैसे पेड़ लगाना, ऊर्जा की बचत करना, कचरे का पृथक्करण और टिकाऊ उत्पादों का उपयोग। यही छोटे कदम मिल कर पृथ्वी को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऋतु प्रभावित हुई हैं। मानसून का आकलन कठिन हो जा रहा है। आपदाएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। आंधी, तूफान, बाढ़ बारिश बेढंगे हुए जा रहे हैं।

भूकंप पहले कभी-कभी सुना जाता था। आज अक्सर धरती हिल जाती है, हिट वेव और तापमान बढ़ना अपने आप में चौंकाने वाला है। एक तरफ अपार्टमेंट और सड़कों का जाल तो दिखता है लेकिन इसके पीछे ताल, पोखरे, पेड़ सब सूने होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आर्गेनिक फार्मिंग, अमृत योजना के तहत ताल, पोखरों के संरक्षण को अभियान बनाना होगा। युवाओं और बच्चों को विशेष रूप से इनसे जोड़ना होगा। पंचायतों और नगर निकायों की जवाबदेही तय करनी होगी। शिक्षण संस्थाओं को भी आगे आना होगा। हम अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक नहीं निभा पाए तो समझिए अगली पीढ़ी के साथ पर्यावरण को लेकर के न्याय नहीं कर रहे हैं। 'अगर पृथ्वी हरी रहेगी, तो भविष्य हमारी मुट्ठी में होगा। पर्यावरण की रक्षा, मानवता की रक्षा है।'

(लेख में विचार निजी हैं)

भूकंप पहले कभी-कभी सुना जाता था। आज अक्सर धरती हिल जाती है, हिट वेव, तापमान बढ़ना अपने आप में चौंकाने वाला है। अपार्टमेंट और सड़कों का जाल तो दिखता है लेकिन इसके पीछे ताल, पोखरे, पेड़ सब सूने होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आर्गेनिक फार्मिंग, अमृत योजना के तहत ताल, पोखरों के संरक्षण को अभियान बनाना होगा। युवाओं, बच्चों को विशेष रूप से इनसे जोड़ना होगा। पंचायतों, नगर निकायों की जवाबदेही तय करनी होगी

'पारी' से जीत का मंतव्य

भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत का जिक्र करने के लिए क्रिकेट की एक आकर्षक उपमा का इस्तेमाल किया। कहा कि भारत ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 'पारी से हरा' दिया। जनरल चौहान सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित 'भविष्य के युद्ध और संघर्ष' पर अपना भाषण पूरा करने के उपरांत सीडीएस वहां मौजूद विद्वानों के सवालों का जवाब दे रहे थे। क्रिकेट की उपमा देने से पहले जनरल चौहान ने फुटबॉल मैच का जिक्र किया था। कहा था, 'मान लीजिए आप एक फुटबॉल मैच में जाते हैं, और 4-2 से जीत जाते हैं, प्रतिद्वंद्वी ने दो गोल किए और आपने चार गोल किए। तो यह

बराबरी का मैच रहा। इसके तुरंत बाद उन्होंने रूपक के जरिए शत्रुता के परिणाम के बारे में स्पष्ट रूप से अंतर समझाने के लिए क्रिकेट का सहारा लिया। इस प्रकार भारत के शीर्ष कमांडर ने प्रकारांतर से भारत को हुए नुकसान की बात भी कही जब कहा कि पेशेवर सेनाएं अस्थायी नुकसान से प्रभावित नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि नुकसान महत्त्वपूर्ण नहीं होता, परिणाम महत्त्वपूर्ण होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को भारत हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने की नीति पर चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी है। दरअसल, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के नजरिए अब स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से कुछ रोज पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने भारत को लहुलुहान करते रहने की कुत्सित मंशा जतलाई थी। उसके कुछ रोज बाद ही पहलगाम की बैसरान घाटी में सैलानियों पर हमला करके पाकिस्तान ने अपने कुत्सित मंसूबे को पूरा करने का प्रयास तो किया लेकिन भारत ने पूरी सख्ती से जवाब देते हुए उसकी जमीन पर चल रहे आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करके मुकम्मल जवाब दे दिया। अब सीडीएस का यह कहना कि भारत अपने प्रतिद्वंद्वी को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने की नीति पर चल पड़ा है, तो यह पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी है कि नहीं संभला तो अपना खासा नुकसान कर बैठेगा। और किसी अन्य देश से मदद लेना भी उसके काम नहीं आने वाला। दरअसल, राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता ने भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ा दिया है।

कोहली का सपना पूरा

विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शुमार रखते हैं। वह आईसीसी वनडे विश्व कप, टी-20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीमों में शामिल रहे हैं। पर एक ही खिताब था, जो उनकी कैबिनेट में नहीं होने का उन्हें मलाल था और यह खिताब है आईपीएल का। वह पिछले 18 सालों से इसे पाने के लिए अपना सब कुछ दे चुके थे पर इसकी उनसे दूरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जाकर उनका यह सपना साकार हो गया है। इस सपने के साकार होने पर विराट बच्चे की तरह भावविह्वल नजर आए। वह मैदान में ही दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक कर जमीन पर सिर रखे दिखे। इस ट्रॉफी का उनके और उनकी टीम के लिए क्या मायने हैं, बताने के लिए काफी है। विराट ने पिछले दिनों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और टी-20 से संन्यास पहले ही ले चुके हैं। इसलिए बहुत संभव है कि वह भविष्य में आईपीएल में खेलते नजर नहीं आएं। इसलिए वह आगे नहीं खेलने का

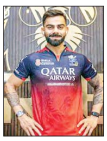

फैसला करते भी हैं तो उन्हें इस बात की खुशी रहेगी कि यह खिताब भी उनकी कैबिनेट में है। आईपीएल में अब परिपक्वता साफ दिखने लगी है। अब फ्रेंचाइजी नीलामी में अच्छा होमवर्क करके आती हैं। यही वजह है कि अब प्रतिभागी टीमों में अंतर बहुत कम हो गया है। इसलिए प्लेऑफ की टीमों के लिए आखिरी लीग मुकाबले तक इंतजार करना पड़ा। सही मायनों में यह टी-20 लीग दुनिया की सबसे लुभावनी लीग बन चुकी है, इस कारण हर खिलाड़ी किसी न किसी तरह इसका हिस्सा बनना चाहता है। इस बार इस लीग के पूरा करने को लेकर खतरा जरूर मंडराया था पर आयोजक किसी तरह इसे पूरा करने में सफल रहे। इस लीग से भारतीय क्रिकेट को फायदा हुआ है। इसमें यंग ब्रिगेड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने से उनके ग्रेजुएशन में सहूलियत होने लगी है। इसका ही परिणाम है कि भारत आज एक साथ दो टीमें खिलाने का माद्दा रखता है। इस लीग से अन्य देशों की क्रिकेट को भी फायदा हुआ है। उनके भी कई युवा यहां खेल कर तैयर हो रहे हैं। इस सत्र में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जैसा प्रदर्शन किया, उसे वर्षों याद रखा जाएगा। वहीं वेवाल्ड ब्रेविस युवा भी सुर्खियां बटोरने वाले रहे। यह लीग क्रिकेटरों को ही करोड़पति नहीं बना रही है, बल्कि इसके माध्यम से लाखों घरों का गुजारा भी हो रहा है।

कटाक्ष/ सहीराम

लहू में क्या-क्या है

जब से मोदी जी ने घोषणा की है कि उनके खून में गर्म सिंदूर दौड़ता है, सारी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक सेमिनार में एक डॉक्टर अपना दर्द बयान कर रहा था-मैंने एक मरीज की रिपोर्ट देख कर कहा कि तुम्हारे खून में शुगर बढ़ गया है। यह सुन कर मरीज बोला-देखिए, मैं देशभक्त हूं। इस वक्त मेरे खून में सिंदूर बढ़ना चाहिए। शुगर नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई खून में सिंदूर नहीं होता। इस पर वह नाराज हो गया-खून में शुगर हो सकती है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है तो सिंदूर क्यों नहीं हो सकता।

मैंने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और भड़क गया-तुम क्या मोदी जी को झूठा साबित करना चाहते हो। एक देश-जिसका नाम बताना यहां उचित नहीं है-की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बोलते हुए एक सदस्य ने जोश में कहा कि मेरा खून खौल रहा है, तो किसी ने कहा-उसमें थोड़ा सिंदूर मिला लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। सदस्य नाराज हो गया-मेरा मजाक बना रहे हो? इस पर दूसरे सदस्य ने कहा-नहीं, अब जोश की नई रैसिपी यही है। इस पर सभी ने मेजें थपथपा कर इसका अनुमोदन किया। एक हिन्दूवादी संगठन के जुलूस में एक स्वयंसेवक ने संगठन का पुराना नारा दोहरा दिया-जिस हिन्दू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जुलूस में शामिल लोगों ने उसे कूट दिया। पता चला कि उसे सौ बार समझाया गया था कि नया नारा लगवाना है-जिसके खून में गर्म सिंदूर न दौड़े, खून नहीं, पानी है। एक देशभक्त एक पैथ लैब में खून की जांच कराने पंहुच गया। लैबकर्मी ने खून शीशी में डाला तो उसने कहा-जरा दिखाना। पैथकर्मी को कुछ समझ नहीं आया। इस पर उसने जबर्दस्ती शीशी हाथ में उठा ली-देखूं जरा कितना गर्म है। उसे बड़ी निराशा हुई और रिपोर्ट देख कर तो वह बिल्कुल ही भड़क गया और अपने साथियों के साथ मिल कर लैब में तोड़फोड़ करने लगा। लोगों ने नाराजगी का कारण पूछा तो बोला-रिपोर्ट के मुताबिक मेरे खून में सिंदूर तो है ही नहीं। यह देशद्रोहियों की लैब है। एक देशभक्त ने अपनी मां से कहा-मां मुझे तुमने क्या सिंदूरयुक्त दूध पिलाया था। मां ने कहा-नहीं बेटा सिंदूर मेरी मांग में लगा था-तभी तो तू पैदा हुआ। इस पर उसने मां को उलाहना दिया-जरा सा सिंदूर मिला कर दूध पिलाती तो तेरा बेटा प्रधानमंत्री बन सकता था।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के सी-फूड निर्यात में उछाल

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष में 16.85 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया, जो 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है
- मूल्य के संदर्भ में, निर्यात वित्त वर्ष 2015 के 5.4 बिलियन डॉलर से बढ़ कर 7.2 बिलियन डॉलर हो गया। भारत 130 देशों को समुद्री खाद्य निर्यात करता है, जो 2014-15 में 105 देशों से अधिक है
- फ्रोजन झींगा सबसे ज्यादा निर्यातित समुद्री उत्पाद है, जो कुल मात्रा का 40 प्रतिशत और कुल निर्यात मूल्य का 66.12 प्रतिशत योगदान देता है, जिसमें अमेरिका और चीन सबसे बड़े बाजार हैं

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

सेनानिवृत्त सैन्य अधिकारी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) नियुक्त किया जाना अप्रत्याशित कदम था। माना जा रहा था कि सेना के इस शीर्ष नेतृत्वकारी पद को लेकर राजनीति का खेल शुरू हो सकता है। सिंगापुर में सीडीएस के हालिया इंटयव्यू के बाद फिर से यह बहस शुरू हो सकती है। इंटरव्यू में सीडीएस ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को चीन के समर्थन की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

आरसीबी का विराट नाम दर्ज

आईपीएल | **मनोज चतुर्वेदी**

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता जरूर पर इसे विराट कोहली के सपने के साकार होने के तौर पर ही लिया गया। इस कारण फाइनल मैच का परिणाम आने पर अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम पर बने माहौल ने 2011 में वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी वनडे विश्व कप जीतने पर बने माहौल की यादें ताजा कर दीं। उस वक्त सारी टीम सचिन तेंदुलकर के विश्व कप जीतने के सपने के साकार होने पर उन्हें कंधे पर उठा कर घुमा रही थी। वजह यह थी कि विराट 2008 से इस टीम को खिताब जिताने के लिए प्रयास करते रहे थे पर खिताब से दूरी खत्म होकर नहीं दे रही थी।

इस खिताब का विराट को किस बेसब्री से इंतजार था, इसे उनकी भावनाओं से समझा जा सकता है। जॉश हेजलवुड के आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों पर छक्का लगते ही आरसीबी का खिताब जीतना पक्का हो गया था। खिताब तय होते ही विराट की आंखें खुशी से नम हो गईं और खेल खत्म होते ही वह मैदान पर सिर झुका कर अपनी भावनाएं बयां करते रहे। जिस काम को अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी और खुद विराट कप्तान रहते नहीं कर पाए थे, उसे रजत पाटीदार ने कर दिखाया। इस तरह अब मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, डेक्कन चार्जर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के साथ आरसीबी का भी नाम आईपीएल खिताब जीतने वाली टीमों में शामिल हो गया है। आरसीबी का यह फाइनल खेलने का चौथा मौका था जिसमें से 2009 और 2016 में तो वह बहुत ही मामूली अंतर से पिछड़ कर खिताब जीतने से रह गई थी। 2009 के फाइनल में उसे छह रनों से और 2016 में आठ रनों से हार का सामना करना पड़ा था। हां, वह 2011 के फाइनल में जरूर बुरी तरह से हार गई थी। पर इन सबकी कमी उसने पंजाब किंग्स को छह रनों से हरा कर पूरी कर दी।

आरसीबी का खिताबी सपना तो पूरा हो गया पर पंजाब किंग्स का सपना अधूरा बना हुआ है। अय्यर जिस तरह से कोच रिकी पोंटिंग के साथ मिल कर टीम को तस्वीर बदलने में सफल हुए हैं और उन्होंने दूसरे क्वालिफायर में जिस तरह से मुंबई इंडियंस की चुनौती तोड़ी, उससे वह भी खिताबी मजबूत दावेदार मानी जा रही थी पर शायद किस्मत

में चैंपियन बनना लिखा नहीं था। इस आईपीएल खिताब का आरसीबी और विराट को इंतजार था, उसी तरह लग रहा था कि नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी चाहते थे कि विराट की पिछले 17 सालों से चली आ रही दूरी खत्म हो। पूरा स्टेडियम आरसीबी की जर्सी पहने पटा पड़ा था। आरसीबी के पक्ष में चौका या छक्का लगने या फिर विकेट मिलने पर स्टेडियम शोर से गूंज उठता था। आरसीबी टीम ने विराट और उनके चहेते दर्शकों को निराश नहीं किया। खिताब जीतने पर भावनाओं से भरे विराट ने कहा, 'यह जीत जितनी टीम के लिए है, उतनी ही प्रशंसकों के लिए भी है। यह पूरे 18 सालों का इंतजार था। मैंने इस टीम को अपना युवा समय, अपना सर्वश्रेष्ठ दौर और अपना अनुभव सब कुछ दिया। हर सीजन इसे जीतने की कोशिश की और अपनी सारी ताकत लगा दी। अब जाकर इसे हासिल करना अविश्वसनीय अहसास है। कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। मैं आखिरी गेंद के बाद भावनाओं में बह गया। अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी और अब जो महसूस हो रहा, वो बयां करना मुश्किल है। वाकई कमाल का अहसास है।'

आरसीबी के विजेता बनने पर एक और तस्वीर देखने को मिली। आरसीबी की सफलताओं में अहम भूमिका निभाने वाले एबी डिविलियर्स टीम के विजेता बनते ही मैदान में दौड़कर आए और विराट को गले लगा लिए। क्रिस गेल भी वहां पहुंच कर विराट को गले लगाकर बधाई देते नजर आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरसीबी के महान खिलाड़ियों की सूची में विराट का नाम सबसे ऊपर है। पर डिविलियर्स और गेल का नाम विराट के बाद होने में शायद ही किसी को शक हो। विराट ने कहा, 'इन दोनों ने फ्रेंचाइजी के लिए जो किया है, वह जबर्दस्त है। इसलिए यह जीत जितनी मेरी है, उतनी ही इन दोनों की भी है। इसलिए ट्रॉफी को हम एक साथ उठाएंगे।' अय्यर भले ही पंजाब किंग्स को खिताब नहीं दिला सके पर वह तीन टीमों को फाइनल में पहुंचाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। पिछले साल केकेआर को विजेता बना चुके हैं और इससे पहले दिल्ली केपिटल्स उनकी अगुआई में फाइनल में पहुंची थी। आरसीबी को विजेता बनने पर 20 करोड़ और पंजाब किंग्स को उपविजेता रहने पर 13.5 करोड़ का इनाम मिला। मुंबई को 7 करोड़ और गुजरात टाइटंस को 6.5 करोड़ रुपये का इनाम मिला। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 759 रन बना कर ऑरेंज कैप और प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लेकर ऑरेंज कैप मिली। इस सत्र के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को एक पारी में सबसे ज्यादा 11 छक्के लगाने और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट का इनाम मिला।

आत्मशक्ति | **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

मान लीजिए कि आपके पास एक सुंदर और महंगी कार है-उसमें पावरफुल इंजन है, चमकदार बॉडी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आरामदायक सीटें हैं। उसके पास सभी कुछ है, पर यदि उसका ड्राइवर ही गाड़ी में बैठा न हो, तो वह कार एक इंच भी नहीं बढ़ सकती। इसी तरह, हमारे शरीररूपी वाहन में इंद्रियां (आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा) हैं जो बाहर की दुनिया को अनुभव करती हैं, मन है जो भावनाओं को महसूस करता है, बुद्धि है जो सोचती है-ये सभी अपनी-अपनी जगह पर कार्यरत हैं, अच्छी बात है, पर अगर आत्मा नहीं है, तो यह सब व्यर्थ है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी आंखें होती हैं, हृदय होता है, मन होता है,बुद्धि होती है,-लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। आत्मा वह चेतना है, जीवनशक्ति है जो इन सबको चलाती है। जैसे बिजली चली जाए तो कितना भी महंगा पंखा हो, वह नहीं घूमेगा; वैसे ही आत्मा के बिना शरीर और इंद्रियां निर्जीव हो जाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण इंद्रिय, मन, बुद्धि को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बता कर आत्मा को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। एक गांव में एक वृद्ध हाथी लेकर आया। चार अंधे व्यक्ति, जो हाथी को देखने में असमर्थ थे, उसे छूकर उसकी कल्पना करने लगे। एक ने उसकी सूंड छुई और कहा, 'हाथी तो रस्सी जैसा है। दूसरे ने पैर छुआ और कहा, 'नहीं, खंभे जैसा है। तीसरे ने कान छूकर उसे पंखे जैसा बताया। चौथे ने पूंछ छूकर उसे झाड़ू जैसा समझा। चूंकि सभी अंधे थे, उन्होंने हाथी का अपूर्ण और विकृत अनुभव प्राप्त किया। इसी प्रकार, यदि मनुष्य आत्मा को केवल इंद्रियों, मन या बुद्धि के आधार पर समझने का प्रयास करे, तो वह भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का आंशिक ही अनुभव कर पाएगा क्योंकि देह और आत्मा पूर्णतया भिन्न हैं। महंत स्वामी महाराज समझाते हैं कि जब मनुष्य आत्म-शक्ति को पहचान लेता है, तब बाह्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। जैसे सूर्य को केवल बादल ढंक सकते हैं, उसका तेज कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही हमारी आत्म-शक्ति भीतर सदैव विद्यमान रहती है, बस उसे जानने और जाग्रत करने की आवश्यकता होती है।

रीडर्स मेल

हल्के में न लें कोविड को

2021 के बाद से बीच-बीच में कोरोना थोड़ा-बहुत असर दिखाता रहा है, लेकिन इस बार इसका फैलाव और इससे होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पुराने अनुभवों, जानकारी, जागरूकता, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, सफल टीकाकरण आदि के कारण कोविड से लड़ना आसान रहेगा; फिर भी इस महामारी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। नये वायरस की पहचान और उपचार के तरीकों पर युद्ध स्तर पर काम हो क्योंकि कोविड के म्यूटेट होते वायरस के हर रूप का असर और उपचार अलग-अलग रहा है। कोविड से संबंधित दवाओं, जांच किट, ऑक्सीजन आदि की अनुपलब्धता और कालाबाजारी रोकने के लिए इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस बार कोरोना प्रबंधन कुछ इस तरह से हो कि घबराहट, डर का माहौल और पूर्ण लॉकडाउन जैसे हालात न बनें। फेक न्यूज, पोस्ट या अन्य भ्रामक सूचनाओं पर भी सख्ती से लगाम लगे।

बृजेश माथुर, गाजियाबाद

पर्यावरण की महत्ता समझें

जलवायु परिवर्तन से सभी जीव-जंतु प्रभावित हो रहे हैं। इससे जल-थल-नभ सभी शामिल हैं। प्रदूषण के बढ़ते खतरे की वजह से आज सभी देश पर्यावरण की महत्ता को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति दुनिया में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन से आज आंधी, तूफान, आग, बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात जैसी समस्याओं से दुनिया को जूझना पड़ रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से भूमि प्रदूषित हो रही है। कार्बन उत्सर्जन एवं वृक्षों के कटाव से तापमान और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण की समस्या वैश्विक समस्या का रूप ले चुकी है, इसके समाधान के लिए सरकार के साथ हर व्यक्ति को भी अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

आरसीबी ने जीत ही लिया खिताब

आखिरकार, 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत ही लिया। एक सपना जो हर साल टूटता रहा हकीकत बन ही गया। विराट कोहली ने अपने आईपीएल कॅरिअर में पहली बार ट्रॉफी उठाई। जो मैदान पर हो रहा था, वह सिर्फ मैच नहीं था। यह सालों की उम्मीदों, टूटे दिलों और हर बार अगली बार कह कर खुद को समझाने वालों की जीत थी। जब विराट ने ट्रॉफी उठाई तो वो सिर्फ एक जीत भर नहीं थी, वो हर चोट का जवाब था, हर मजाक का पलटवार था। विराट को हर बार ट्रोल किया गया पर विराट ने हार नहीं मानी। विराट के आंखों से छलकते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। वो 18 सालों की तड़प, न जाने कितनी बार विराट की आंखें छलकीं। दुनिया ने देखी विराट की वफादारी। चाहता तो कभी भी जर्सी बदल सकता था पर उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं। दुनिया मजाक उड़ाती रही पर वो सिर झुकाए खड़ा रहा। विराट ने साबित कर दिया वो खिलाड़ी ही नहीं हैं, हमारी उम्मीदों, संघर्षों और सपनों के प्रतीक हैं।

नवनीत कुमार, बिहार

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 289
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

कुर्बानी के दायरे

ईद-उल-अजहा से पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम का यह अनुरोध बहुत विचारणीय है कि पशुओं की कुर्बानी किसी खुले स्थान पर न की जाए। सार्वजनिक रूप से कुर्बानी के खिलाफ इन दिनों समाज में काफी चर्चा चल भी रही है। कई जगह विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। ऐसे में, नायब शाही इमाम मौलाना सैयद शबान बुखारी की गुजारिश गौर फरमाने लायक है। उनका मानना है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या खुली जगहों पर कुर्बानी न हो, कुर्बानी की रस्म घर में ही निभाई जाए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी गुजारिश की है कि कुर्बानी का वीडियो इत्यादि बनाकर प्रसारित-प्रचारित न किया जाए। इधर के वर्षों में फोटो खींचने या वीडियो उतारने के उपकरणों की बहुलता की वजह से भी लोगों के बीच कुर्बानी के फोटो-वीडियो साझा करने का चलन बहुत बढ़ गया है। ऐसे में, खुलेआम कुर्बानियों से आहत होने वालों की संख्या स्वयं अल्पसंख्यक समाज में बढ़ रही है। कुर्बानी व्यक्तिगत धार्मिक मामला है, उसका प्रदर्शन जब सार्वजनिक रूप से होने लगता है, तो शिकायत करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। इस शिकायत या चिंता के साथ ही शाही नायब इमाम की गुजारिश को जोड़कर देखना चाहिए।

शाही नायब इमाम का यह कहना काबिल-ए-तारीफ है कि इस्लाम शांति और सौहार्द का धर्म है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यवहार से इसे साबित करें, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यह बात हर धर्म को मानने वालों पर लागू होती है। धर्म का काम है कि दूसरों को यथोचित मान-सम्मान दिया जाए और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचा जाए। कुर्बानी ही नहीं, कोई भी ऐसा कृत्य अगर कानून और मर्यादा के दायरे में रहकर किया जाए, तो इससे न केवल सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ता है, बल्कि समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य को भी बल मिलता है। हिंदुओं के विभिन्न समुदायों में बलि प्रथा रही है, किंतु इसकी समय-समय पर निंदा भी बहुत हुई है और सुधार का क्रम भी जारी है। जो समाज संवेदनशील हुए हैं, वहां कई जगह देवी पूजन में सांकेतिक बलि ही अब शेष रह गई है, ठीक ऐसी ही मांग कुर्बानी के साथ भी हो रही है। यह मांग अनुरोध ही रहे, इसके लिए किसी को बाध्य न किया जाए। किसी भी समाज में सुधार की इच्छा को समय देना चाहिए और यह इच्छा नायब शाही इमाम की गुजारिश में साफ झलकती है।

कुर्बानी ही नहीं, कोई भी ऐसा कृत्य अगर कानून और मर्यादा के दायरे में रहकर किया जाए, तो इससे सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता व स्वास्थ्य को बल मिलता है।

दुनिया में अनेक मुस्लिम देश हैं, जहां बहुत शालीनता के साथ त्योहार मनाए जाते हैं, पूरे समाज का ध्यान रखा जाता है। वैसे भी, बलि हो या कुर्बानी, ऐसी चीजों के महिमामंडन से समाज को सार्वजनिक रूप से बचना चाहिए। ध्यान रहे, अनेक पाबंदियां या बाध्यताएं ऐसी होती हैं, जो हम खुद पर लादते हैं। धर्म या मजहब के दायरे में इतनी उदारता है कि परंपराओं को समय और परिवेश के हिसाब से ढाला जा सकता है। मिसाल के लिए, 99 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले अफ्रीकी देश मोरक्को में ईद-उल-अजहा या बकरीद से पहले ही पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोरक्को में विगत छह वर्षों से सूखे की स्थिति है, जिससे वहां पशुधन की संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसे में, वहां के बादशाह मोहम्मद ने पशुधन बाजार भी बंद करवा दिए हैं। यही नहीं, वहां जो लोग अपने घरों में बकरीद के मकसद से पशुधन पाल रहे हैं, उनसे भी पशुधन छीने जा रहे हैं। हमें व्यापक लोकहित में समय और जरूरत के हिसाब से खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 05 जून, 1950

एकता और अनुशासन

भारत के प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने हिन्देशिया के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपना कुछ समय त्रावणकोर कोचीन संघ में बिताया। यह प्रदेश भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है और उसकी अपनी विशेष परिस्थितियां और समस्यायें हो सकती हैं; किंतु वह देश के शेष भाग के साथ अविभेद्य रूप में जुड़ा हुआ है और इसलिए बुनियादी तौर पर उसका भविष्य सारे देश के भविष्य से अलग नहीं हो सकता। कुछ ही समय पहले भारत के उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने इस प्रदेश की यात्रा की थी और उसके तुरन्त बाद उसे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने और उनके सुलझे हुए विचारों को सुनने का अवसर मिला। भारतीय नेताओं को दक्षिण भारतीयों के बीच में जाने का अधिक अवसर नहीं मिलता। किंतु ऐसे अवसर जितने निकाले जा सकें, उतने ही लाभदायी सिद्ध होंगे। यह सम्पर्क लोगों को अखिल भारतीय समस्याओं का संतुलित और आवश्यक ज्ञान सुलभ करेगा और एकदेशीय भावना को मजबूत बनायेगा। जब नेहरूजी कन्याकुमारी में थे, तो उन्हें भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित काश्मीर और लद्दाख की याद हो आई और उन्होंने महसूस किया कि रहन-सहन, रीति-रिवाज और आचार-विचार के समस्त भेदों के बावजूद काश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक भारत एक देश है। भौगोलिक कारणों से भारत के लोगों में विविधता का होना अनिवार्य है; किंतु इस कारण हमारी एकदेशीय भावना निर्बल नहीं पड़नी चाहिए।

नेहरूजी की इस यात्रा ने प्रकट कर दिया कि दक्षिण भारतीय उनके प्रति श्रद्धा और स्नेह प्रकट करने में किसी से पीछे नहीं हैं। नेहरूजी को वह उतना ही अपना मानते हैं, जितना कि उत्तर भारतीय नेहरूजी का संदेश सुनने को। उनकी उत्सुकता विशेष होनी स्वाभाविक थी, क्योंकि इस प्रकार का अवसर उन्हें वंचित ही मिलता है। नेहरूजी के दो विस्तृत भाषणों की रिपोर्ट हमें मिली है, जो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विशाल जनसमूह के सामने दिये। इनमें उन्होंने उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनको वह बहुधा इस देश के लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। उन्होंने त्रावणकोर कोचीन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह बताया कि आज एकता और अनुशासन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि स्वतन्त्रता मिलने से पहले थी।

आईपीएल से नई दीवानगी का आगाज

मदन लाल | विश्वकप विजेता क्रिकेटर

यहां स्कैन करें

फटाफट क्रिकेट लगातार नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। एक शानदार सत्र बीता है और उसकी तमाम खासियत के साथ ही भीड़ को संभालने की जरूरत भी बढ़ गई है।

यह क्रिकेट के प्रति बढ़ती दीवानगी का ही नतीजा है कि बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर इतनी भीड़ उमड़ी कि संभालना मुश्किल हो गया। भगदड़ से इतर मंगलवार को अहमदाबाद में हुआ मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास के रोमांचकारी फाइनल में एक था। दूसरी पारी में करीब-करीब आधे मुकाबले तक यही लग रहा था कि पंजाब किंग्स की टीम आसानी से मैच जीत लेगी। मगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपना धैर्य नहीं खोया। नतीजतन, मैच के आखिरी ओवरों तक पहुंचते-पहुंचते पंजाब किंग्स जूझने लगी और छह रन से खिताबी जीत से चूक गई।

ट्वंटी-20 में किसी टीम की जीत के कयास नहीं लगाए जा सकते। इसके हर मैच उतार-चढ़ाव लिए होते हैं। इसीलिए, जो उस दिन बाजी मार ले जाए, वही विजेता बनता है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी की बल्लेबाजी बीच में धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन जीतेश शर्मा ने आकर कुछ बड़े शॉट लगाए। नतीजतन, पहली पारी 190 तक पहुंच सकी। ऐसे मुकाबलों में विकेट गिरने पर खेल कुछ धीमा पड़ जाता है, क्योंकि नए खिलाड़ी को जमने में वक्त लगता है। फिर, ओवर भी इसमें कम होते हैं। लिहाजा, इन तनावों के बीच संतुलन बनाकर रखने की जरूरत होती है।

यही कारण है कि फाइनल के लिहाज से 190 रन को 'फाइटिंग' जरूर माना गया, मगर 'सेफ' नहीं था। इस टूर्नामेंट में ही कुल 74 मुकाबलों में से 34 बार स्कोर बोर्ड पर 200 या इससे अधिक रंग टंगे। इतना ही नहीं, नौ मुकाबले तो ऐसे थे, जिनमें विपक्षी टीम ने 200 से ज्यादा रनों का पीछा करते हुए जीत हासिल की। मगर फाइनल में पंजाब किंग्स के साथ दिक्कत यह हुई कि कुणाल पांड्या ने जब उसके दो विकेट चटकाए, तो शशांक सिंह के बाद कोई अन्य बल्लेबाज टिक नहीं पाया। मुझे लगता है, कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट गिरना मैच का टर्निंग प्वॉइंट बन गया।

ऐसे वक्त में गेम को कंट्रोल करना काफी अहम होता है। इसमें तनाव काफी ज्यादा रहता है। आप हर बॉल पर बड़े शॉट नहीं लगा सकते। पंजाब ने इसी तरह की गलतियां कीं। उधर, आरसीबी ने कभी भी मैच को नहीं छोड़ा। उसको पता था कि हर गिरते विकेट के साथ मैच पर उसकी पकड़ बनती चली जाएगी। रही-सही कसर उसकी कसी फिल्डिंग ने पूरी कर दी। देखा जाए, तो एक टीम के तौर पर पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। किसे शीर्ष क्रम में और किसे मध्य क्रम में खेलने भेजना है, किससे कितनी गेंदबाजी करानी है और किस लाइन-लेंथ की गेंद डलवानी है- मानो सब रणनीति उसने सोच-समझकर बनाए थे।

किसी भी ट्वंटी-20 मैच में आखिरी के तीन-चार ओवर 'विनिंग ओवर' माने जाते हैं। फाइनल में इन्हीं ओवरों में जीतेश की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आरसीबी के रन तेजी से आगे बढ़ गए। फिर, गेंदबाजी में यश दयाल, कुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी किफायती गेंदबाज साबित हुए। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी टीम की अच्छी बॉलिंग लाइन-अप है, तो उसके जीतने की संभावना दूसरों के मुकाबले बढ़ जाती है।

यहां विराट कोहली की चर्चा लाजिमी है। हर कोई चाहता था कि वह इस बार खिताब जीतें। यह आईपीएल का 18वां सीजन था और विराट शुरू से ही आरसीबी से जुड़े रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी इतना लंबा वक्त किसी एक टीम को देता है, तो उसकी कोशिश खिताब जीतने की होती है। निस्संदेह, मंगलवार विराट कोहली के लिए बड़ा दिन था। उनके आंसू बता रहे थे कि यह जीत उनके लिए कितना मायने रखती है। आज भी जिस ऊर्जा के साथ वह मैदान में उतरते हैं, विकेटों के बीच जैसी तेज दौड़ लगाते हैं या फिर क्षेत्ररक्षण में चपलता दिखाते हैं, वह सीखने लायक है। दूसरे खिलाड़ियों से वह कहीं अधिक फिट हैं, जिसकी तस्दीक उनके आंकड़े करते हैं। इस आईपीएल में कुल 15 मैचों में उन्होंने 54.47 की औसत से 657 रन बनाए। उनसे अधिक रन सिर्फ दो खिलाड़ी- साईं सुदर्शन (759) और सूर्यकुमार यादव (717) ही बना सके।

इस आईपीएल ने कई ऐसे खिलाड़ियों से हमारा परिचय कराया, जो आने वाले दिनों में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। साईं सुदर्शन, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, आशुतोष शर्मा, नमन धीर, साई किशोर, यश दयाल जैसे न जाने कितनी प्रतिभाएं इस टूर्नामेंट में निखरकर सामने आईं। अब यह इन पर निर्भर करता है कि वे कितना खेलना चाहते हैं। यह सही है कि आईपीएल आने के बाद पारंपरिक क्रिकेट का स्वरूप बदल गया है। यहां तक कि टेस्ट मैच भी आक्रामक हो गए हैं और तीन से चार दिनों में नतीजा निकलने लगा है। मगर जैसा कि विराट कोहली ने कहा भी कि टेस्ट क्रिकेट से ही खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है। उन्होंने नए खिलाड़ियों से उचित आग्रह किया कि वे टेस्ट क्रिकेट का सम्मान करें। आईपीएल का एक बड़ा लाभ यह है कि प्रतिभाओं की एक लंबी श्रृंखला अब भारत के पास है। हम उनका क्रिकेट-हित में उपयोग कर सकेंगे।

बहरहाल, आईपीएल फॉर्मेट ने कई खिलाड़ियों की आर्थिकी भी बदल दी है। आईपीएल-2025 के बारे में कहा जाता है कि विज्ञापनों से इसे 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई है, जो पिछले संस्करण के मुकाबले 50 फीसदी अधिक है। अगर फ्रेंचाइजी, स्पॉन्सर आदि सब मिला दें, तो अरबों-खरबों रुपये का यह कारोबार है, जिसका एक बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों को भी मिलता है। इसकी जरूरत भारतीय क्रिकेट को थी भी। किसी भी खेल को चलाने के लिए पैसे की दरकार होती है। 'स्ट्रैटेजिक टाइम-आउट' की संकल्पना भी कुछ हद तक इसी से जुड़ी है। इस मध्यांतर का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। हालांकि, इस ढाई मिनट में कोच अपनी योजना भी टीम के साथ साझा करते हैं और हांफते-भागते खिलाड़ियों को कुछ क्षण सुस्ताने के लिए भी मिल जाते हैं।

कुल मिलाकर, आईपीएल क्रिकेट का एक ऐसा पैकेज है, जिसमें मनोरंजन भी है, व्यावसायिक गुणा-भाग भी और फटाफट खेल भी। इसमें चौकों-छक्कों की मानो बरसात होती है, जो दर्शकों को खूब लुभाती है। कामकाजी दिन होने के बावजूद मंगलवार को जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था, वह बताता है कि लोग इसे कितना पसंद करते हैं। लेकिन अब इस खुशी का इजहार करने के लिए उमड़ने वाली भीड़ का बेहतर प्रबंधन भी जरूरी हो गया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक से बनाएं दूरी

अनिता भटनागर जैन | पूर्व आईएएस अधिकारी

यहां स्कैन करें

वह क्या है, जो जल में, थल में, हम सब में एक ही समय में सभी जगह विद्यमान है? कदाचित हममें से अधिकांश पहले इसका उत्तर देते- दैवीय शक्ति। परंतु आज इसका उत्तर है प्लास्टिक! प्लास्टिक के नैनो कण समुद्रों की अधिकतम गहराई तक, नदियों में, आकाश में 9,500 फीट की ऊंचाई तक, भूमि में, यहां तक कि हमारे नमक, शरीर, मां के दूध, शुक्राणु, किडनी, फेफड़ों, दिमाग तक में पाए जाने लगे हैं। विभिन्न आकार-प्रकार में प्लास्टिक अब सब तरफ ऐसे है कि इसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता।

सन् 1972 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए स्वीडन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का विषय है- 'वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का अंत।' हमारे जीवन के अनेक पहलुओं में प्लास्टिक जरूरी है और उसका कोई विकल्प भी अभी नहीं है। मगर इसके कारण 'डिस्पोजेबल कंज्यूमर कल्चर' पैदा हुआ। महज एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक के कारण 'थ्रो अवे पीढ़ी' का जन्म हुआ। इससे सबका नुकसान हो रहा है। असहाय पशु-पक्षी भी मनुष्य की गतिविधियों का परिणाम भुगत रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा बताया गया था कि विश्व भर में एक मिनट के भीतर 10 लाख प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग होता है। यानी एक दिन में 144 करोड़! है न भयावह? हम पृथ्वी पर प्लास्टिक कचरे की कैसी विरासत छोड़ रहे हैं? शहरों में जल जमाव की समस्या का मुख्य कारण ये प्लास्टिक कचरे ही हैं। आंकड़ों से वास्तविकता अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। वैश्विक प्लास्टिक कचरे में भारत का योगदान 18 प्रतिशत है। हमारे यहां हर दिन करीब 26,000 मीट्रिक टन और देश के 60 मुख्य शहरों में 4,000 से अधिक मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सृजन होता है। इनमें से ज्यादातर कचरा खुली जगहों और गड्ढों में पड़ा रहता है।

वैश्विक प्लास्टिक कचरे में भारत का योगदान 18 प्रतिशत है। हमारे यहां रोज करीब 26,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है।

गौर कीजिए, 99 प्रतिशत प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से तैयार होता है, जो जैविक रूप से कभी नष्ट नहीं होता, यानी प्लास्टिक अमर है। लोगों में यह भ्रांति है कि समस्त प्लास्टिक और अन्य कचरों का पुनः उपयोग हो जाता है। लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन सीएसई का कहना है, देश में मात्र 12 प्रतिशत प्लास्टिक का ही पुनः उपयोग हो रहा है और 20 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा जलाया जा रहा है। इस दहन से घातक गैस पैदा होती है, जिससे अनेक जानलेवा बीमारियां बढ़ रही हैं। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों में इजाफा हो रहा है और इस सब के फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस कुचक्र का कोई अंत है?

आखिर इस अजर-अमर दिखते दानव का वध कैसे संभव है? पर्यावरण सुरक्षा दिवस मनाने से कुछ जागरूकता बढ़ी है, लेकिन वास्तविक उपाय निकालने में पता नहीं कितने दशक लग जाएं? आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग समाधान का हिस्सा बनें। देश में प्लास्टिक के 30,000 से अधिक उत्पादक उद्यम हैं। इन पर भी इसके विकल्पों के उपयोग करने और प्लास्टिक को एकत्र कर उसे रीसाइकिल करने का दायित्व होना चाहिए। वैसे, जिम्मेदारी तो उद्योग, समाज, नागरिक सभी की है। लेकिन, यदि नागरिक को कर्तव्य समझ में आ जाए, तो बहुत आसानी से स्थिति में व्यापक सुधार लाया जा सकता है। क्या हम विभिन्न आयोजनों में प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग बंद कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम हवन या पूजा-सामग्री प्लास्टिक की थैली में बांधकर नदियों में न फेंके? क्या हम अपने कूड़े को गीले, कागज, प्लास्टिक आदि श्रेणियों में अलग कर सकते हैं? क्या हम फल, सब्जियां और अन्य सामान कपड़े के थैलों में नहीं ला सकते? जब हम अपना मोबाइल कहीं ले जाना नहीं भूलते, तो अपनी पानी की बोतल और कपड़े का थैला भी साथ रख सकते हैं?

हम सब अपने और अपने परिजनों के लिए स्वस्थ जीवन चाहते हैं। तो क्या इसी स्वार्थवश अपनी आदतों में हमें बदलाव नहीं लाना चाहिए? बदलाव कठिन हो सकता है, मगर असंभव नहीं। आइए, हम अपने ही दायरे से पर्यावरण बिगाड़ने वाली इस बिल्ली के गले में घंटी बांधकर शुरुआत करें।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद

यह कौन-सा धर्म है, जिसे हम सनातन या शाश्वत कहकर पुकारते हैं? इसे हिंदू धर्म इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसे हिंदू राष्ट्र ने सुरक्षित रखा, क्योंकि सागर और हिमालय के एकांत में, इस प्रायद्वीप में इसका विकास हुआ, क्योंकि इस पुनीत और पुरातन भूमि में इसका भार आर्य जाति को उसे युग-युगांतर तक सुरक्षित रखने के लिए सौंपा गया था। किंतु वह किसी एक देश की सीमाओं से परिसीमित नहीं है; वह विश्व के किसी सीमित भाग की विशिष्ट और निरंतर संपत्ति नहीं है।

जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि यह सार्वभौम धर्म है, जो अन्य सभी को अपने में समाहित कर लेता है। यदि कोई धर्म सार्वभौम नहीं है, तो वह सनातन नहीं हो सकता। एक संकीर्ण धर्म, एक सांप्रदायिक धर्म सीमित समय और सीमित उद्देश्य के लिए ही जीवित रह सकता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जो विज्ञान के आविष्कारों, दर्शन के चिंतनों का पूर्वानुमान और उन्हें आत्मसात करके भौतिकवाद के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। यह अकेला ऐसा धर्म है, जो हमारे प्रति ईश्वर की निकटता पर बल देकर मानवता को बताता है। वह अपने में उन सभी संभव साधनों को संजोए हुए है, जिनके द्वारा मनुष्य ईश्वर के समीप जा सकता है।

यही एक ऐसा धर्म है, जो सभी धर्मों द्वारा स्वीकृत इस सत्य पर प्रतिक्षण जोर देता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों और चराचर वस्तुओं में विद्यमान है और उसी में हम चलते, फिरते और वास करते हैं। केवल यही धर्म हमें इस सत्य को समझने, उस पर विश्वास करने में न केवल सहायता करता है, बल्कि अपने अस्तित्व के हरेक भाग से उसका एहसास कराता है।

यही एक धर्म विश्व को बताता है कि यह संसार है क्या; कि यह वासुदेव की ही एक लीला है। यही धर्म है, जो हमें बताता है कि उस लीला में, उसके सूक्ष्मतम विधानों में, उसके उत्कृष्टतम नियमों में हम अच्छी से अच्छी तरह अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं! यही एक धर्म है, जो छोटे से छोटे ब्योरे में भी जीवन को धर्म से अलग नहीं करता, जो यह जानता है कि अमरत्व क्या है और जिसने हमसे मृत्यु की विभीषिका को बिल्कुल दूर हटा दिया है...।

यही वह धर्म है, जो हमें बताता है कि संसार वासुदेव की लीला है। उस लीला में, उसके सूक्ष्मतम विधानों में, उसके उत्कृष्टतम नियमों में हम अच्छी से अच्छी भूमिका कैसे निभा सकते हैं!

मैंने पहले कहा था कि राष्ट्रवाद राजनीति नहीं, बल्कि एक धर्म है, एक सिद्धांत है, एक विश्वास है। मैं फिर आज उसे दोहराता हूं, लेकिन उसे दूसरी तरह से प्रस्तुत करता हूं। मैं अब यह नहीं कहता कि राष्ट्रवाद एक सिद्धांत है, धर्म है, विश्वास है : आज मैं कहता हूं, यह सनातन धर्म है, जो हमारे लिए राष्ट्रवाद है।... सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। यही वह संदेश है, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं।

श्री अरविंद

निर्मला सीतारमण | केंद्रीय वित्त मंत्री

हमें अधिक जागरूकता और कार्रवाई योग्य खुफिया सूचनाओं की आवश्यकता है। एजेंसियों के लिए यह समझना अधिक अहम है कि डाटा के ढेर से कौन सी जानकारी कार्रवाई के योग्य है और किस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

अनुलोम-विलोम

पर्यावरण दिवस

अब भी नहीं संभले तो देर हो जाएगी

प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों में और सार्वजनिक स्थानों पर पर्यावरण के बारे में पोस्टर लगाए जाते हैं, नारे लिखे जाते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ एक दिन यह सब करके पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे? अगर सचमुच पर्यावरण बचाना है, तो उसके लिए हर दिन प्रयासरत रहना होगा। आज हर घर व दफ्तर में एसी लगे हैं और लोग आराम से अंदर रहते हैं। मगर इससे पर्यावरण को कितना अधिक नुकसान पहुंच रहा है। इससे हम आंखें नहीं मूंद सकते। सभी जानते हैं कि पेड़-पौधे से ही हमारी जिंदगी संभव है, फिर भी लोग जागरूक नहीं हैं। पढ़े-लिखे लोग भी अपनी आरामतलबी के लिए पर्यावरण को जाने-अनजाने नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में, बहुत जरूरी है कि सभी वर्गों के लोग पर्यावरण को बचाने में आगे आएं। कहीं ऐसा न हो कि हम अपने आराम के लिए पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दे कि उसकी भरपायी ही न हो सके। पर्यावरण को बचाने के लिए अगर अब भी हम तत्पर नहीं हुए, तो काफी देर हो सकती है। शायद ऐसी देर, जिसको बदल पाना हमारे लिए नामुमकिन हो।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना रखा गया है। मगर सच यही है कि प्लास्टिक और पॉलिथीन जीवन के हर क्षेत्र में गहरे प्रवेश कर चुका है। दूसरी ओर, ई-कचरे से लेकर रेडियो एक्टिव विकिरणों तक, पॉलीएथिलीन से लेकर विषाक्त रसायनों तक, वातावरण में छोड़ते जहरीली गैसों से लेकर पाताल लोक तक भेजते विषैले जल तक, सिंगल यूज प्लास्टिक से लेकर केमिकल निर्मित वस्तुओं तक पर्यावरण को दूषित करने मनुष्य स्वयं व अपनी संतति के जीवन को नारकीय बना रहा है। 30 वर्ष पूर्व सभी की साइकिलों में आगे टोकरी होती थी, दोपहियों में साइड में डिक्की होती थी। बाजार जाने की पहचान लोगों के हाथ में थैले से होती थी। आज की पीढ़ी इनको हीन भाव से देखती है। आज हर काम में प्लास्टिक और पॉलिथीन की अहम भूमिका हो चुकी है। पॉलिथीन ने पर्यावरण के साथ-साथ सामाजिकता के नाश में भी योगदान दिया है। वास्तव में पॉलीथिन 'कलयुगी दानव' है, जो बहुत कुछ नष्ट कर रहा है। मनुष्य इसे प्रयोग में लाकर अपने अस्तित्व को ही चुनौती दे रहा है। मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो उसे अपनी मानसिकता व जीवन-शैली में बदलाव लाना होगा और प्लास्टिक- पॉलिथीन के विकल्पों को मजबूती से अपनाना होगा।

मनोज कुमार शर्मा, टिप्पणीकार

आबोहवा बचाने को गंभीर हुई दुनिया

आज पर्यावरण के सवाल को लेकर समाज व सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार हो रहा है और इसको बचाने को लेकर कई तरह के प्रयास भी हो रहे हैं। आम लोग भी अब खाली जगहों पर बड़ी संख्या में पेड़ लगा रहे हैं। इस काम में सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो कई संगठन भी सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। पेड़ जीवन को बनाए रखते हैं और एक मां की तरह ही मनुष्य को पोषण, सुरक्षा और भविष्य प्रदान करते हैं। सरकार की ओर से चलाया गया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर्यावरण के प्रति, जागरूक भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यावरण संरक्षण के आह्वान और माताओं के प्रति सम्मान की भावना के साथ यह पहल धरती को हरित ग्रह बनाने में अपना योगदान देने की ओर अग्रसर है। पर्यावरण बचाने के लिए चलाए गए अभियान को मां जैसे संवेदनशील शब्द के साथ जोड़ने से इसकी सफलता की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इस अभियान के तहत देश में मार्च 2025 तक 140 करोड़ से अधिक पौधों को लगाया जा चुका है। इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति एक पेड़ लगाकर अपनी माता को श्रद्धांजलि और स्थायी स्मृति भेंट कर सकता है, इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता भी पूरी की जा सकती है। जरूरत ऐसे अभियान को आगे भी जारी रखने की है, ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच बनी रहे और वे हरियाली बढ़ाने का काम करें।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

एक तरफ देश में माफिया हैं, जो हरीतिमा के दुश्मन बनकर जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, ऐसे जज्बे वाले कर्मयोगी और वृक्ष प्रेमी भी हैं, जिन्होंने पानी की कमी के बावजूद हजारों एकड़ में जंगल लगा दिया। कर्नाटक के दावनगेरे, शिमोगा और हनोली जिलों के 12 गांवों में सूखे की मार पड़ी, तो इन गांवों के 4,500 लोगों ने बंजर पहाड़ियों पर एक करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाकर इस पूरे इलाके को ही जंगल में तब्दील कर दिया। इस अभियान के मुख्य प्रेरणास्त्रोत गुडादमदापुरम गांव के किसान करीबसवप्पा कानिनेले रहे हैं। ऐसे कर्मयोगियों से जंगल उजाड़ने वालों को सीख लेनी चाहिए। अगर वे पेड़ नहीं लगा सकते, तो कम से कम जंगलों को तो न काटें। एक दिन ऐसा आएगा कि जंगलों की कमी से हम सभी रोएंगे (रो तो रहे हैं)। कर्नाटक के 12 गांवों के लोगों के इस जज्बे को सलाम, जो दूसरों को अपने जंगल प्रेम से प्रेरणा दे रहे हैं। कनार्टक के अलावा देश के कई अन्य प्रदेशों में काफी सारे लोग धरती की हरियाली बढ़ाने में जुटे हुए हैं।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

संपादकीय जागरण

(10) गुरुवार, 5 जून, 2025 : ज्येष्ठ शुक्ल - 10 वि. 2082

मौन अंतरात्मा का उपवास है

नहीं सुधरेंगे राहुल

राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार अप्रिय कारणों से चर्चा में हैं। पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद उनके रुख-रवैये से एक बार को ऐसा लगा था कि वह देश, काल, परिस्थितियों के हिसाब से दलीय स्वार्थों को परे रखकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना भी जान गए हैं, लेकिन वह ऐसा सोचने वालों को गलत साबित करके ही माने। आपरेशन सिंदूर थमने के साथ ही उन्होंने कथित उचित प्रश्न पूछने के बहाने मोदी सरकार पर ऐसे हमले करने शुरू कर दिए कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के लिए भी उनकी हां में हां मिलाना कठिन हो गया। इससे उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। मोदी सरकार को नीचा दिखाने के साथ सेना के शौर्य की भी अनदेखी करने वाले उनके बयान सामने आते ही रहे। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान उनके बयानों को अपने पक्ष में भुनाने में जुट गया। राहुल गांधी और उनके सहयोगी इससे अवगत भी हुए, लेकिन शायद उन्होंने जिद पकड़ ली है कि उनके जो मन में आएगा, बोलेंगे, भले ही उससे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचे। वह रुके नहीं और उन्होंने अपने करीबी नेताओं के जरिये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल शशि थरूर पर हमले कराने शुरू कर दिए। सलमान खुर्शीद भी उनके करीबियों के निशाने पर आ गए। खुर्शीद का यह पीड़ा भरा प्रश्न वस्तुतः उनके लिए ही था कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है? राहुल ने कोई परवाह नहीं की। वह प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह तक कहने लगे कि ट्रंप ने मोदी को जैसे ही सरेंडर करने को कहा, वैसे ही उन्होंने कर दिया। राहुल गांधी वहीं पहुंच गए हैं, जहां वह 2019 के लोकसभा चुनाव के समय थे और जब प्रधानमंत्री के प्रति तू-तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। वह भाषा की मर्यादा के साथ देशहित की अनदेखी कर अपना और अपनी पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके करीबी उन्हें यही समझाते हैं कि वह जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी और उनके निकट के लोग कुछ भी सोचें, यह जो छवि बनाई गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें परिपक्व नेता बना दिया है, उसे वह तार-तार करने में लगे हुए हैं। वह शायद ही अपना व्यवहार बदलें, क्योंकि गलतबयानी और अपमानजनक भाषा के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी और उसकी फटकार भी सुननी पड़ी। गत दिवस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें सेना का अपमान करने के लिए फटकार लगाई और यह नसीहत भी दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा है। इस पर राहुल शायद ही ध्यान दें, क्योंकि वह इस नतीजे पर पहुंच गए लगते हैं कि राजनीतिक विरोधियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के प्रति भद्दी भाषा का प्रयोग करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

रेफर पर लगे लगाम

राज्य सरकार अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने व सुविधाएं बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। सरकारी मेडिकल कालेजों की संख्या भी बढ़ी है। इसके बाद भी मरीजों को इसका लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों और डाक्टरों की लापरवाही सामने आती है। अधिकतर सरकारी अस्पतालों में जिम्मेदार अपनी बला टालने के लिए मरीजों को रेफर कर देते हैं। इस कारण सदर अस्पताल और मेडिकल कालेजों में भीड़ बढ़ने के साथ मरीजों की जान पर बन आती है। मुजफ्फरपुर की दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मौत में ऐसी ही लापरवाही सामने आई है। उसे मुजफ्फरपुर से जिस तरह रेफर किया गया और पटना मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, उससे साफ है कि इसमें किस हद तक सिस्टम ने संवेदनहीनता बरती। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इसपर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय जांच टीम गठित कर बता दिया कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी ऐसी ही बात कही है। लेकिन, सिर्फ कार्रवाई व जांच टीम गठित करने से ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसके लिए रेफर संस्कृति पर रोक जरूरी है। गंभीर स्थिति में रेफर करने पर एंबुलेंस में सुविधा के साथ उच्च अस्पताल में भर्ती करने में देरी न की जाए। साथ ही सरकारी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ मरीजों को मिले, इसकी सख्त मानीटरिंग होनी चाहिए।

सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का समुचित लाभ मरीजों को मिले, इसकी सख्त मानीटरिंग की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

कांग्रेस का यह निष्कर्ष सही है कि पीएम मोदी को जी-7 बैठक में न्योता न मिलना बड़ी कूटनीतिक विफलता है?

आज का सवाल

क्या पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेंगे?

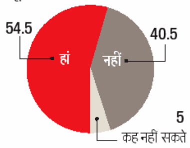

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भारत को खुद कहनी होगी अपनी कहानी

विकास सारस्वत

एक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को अंतर्मुखी स्वभाव छोड़कर पूरे विश्व को अपना सरोकार बनाना होगा

आपरेशन सिंदूर की समाप्ति के बाद कुहासे के बादल छट गए हैं। देश-विदेश के तमाम रक्षा विशेषज्ञ और उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों से पुष्टि हुई कि यह संघर्ष पूरी तरह एकतरफा था और पाकिस्तान को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। इस सैन्य संघर्ष में दुनिया ने भारत की स्वदेश निर्मित सैन्य उपकरणों की बेजोड़ क्षमताओं का लोहा भी माना। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य शौर्य और रक्षा क्षेत्र की उद्यमशीलता ने आशा से अधिक प्रभावित किया है, परंतु इस कठिन समय में जो एक कमी खली, वह थी सूचना क्षेत्र में भारत की ढिलाई। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आपरेशन सिंदूर की बयानगी को लेकर न सिर्फ भारतीय चिंताओं की अनदेखी हुई, बल्कि पाकिस्तानी दावों को बिना जांचे-परखे आगे बढ़ाया गया। न्यूयार्क टाइम्स, सीएनएन, वालस्ट्रीट जर्नल, निक्केई एशिया, ब्लूमबर्ग आदि में भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव की ज्यादातर रिपोर्टिंग पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा की गई। समाचार एजेंसी रायटर्स ने तो एक ऐसे गुमनाम पाकिस्तानी लेखक सईद शाह के तीन लेख प्रकाशित किए, जो उस दौरान ही कार्यरत रहा। ये पाकिस्तानी पत्रकार केवल पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा ही आगे बढ़ाते रहे। कई पश्चिमी मीडिया माध्यम जाने-अनजाने उनसे प्रभावित भी होते रहे। हालांकि बाद में न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट आदि ने भारतीय दावों की पुष्टि की और इस संघर्ष को भारत की जीत बताया, परंतु युद्ध के दौरान जब मीडिया रिपोर्टिंग देशों के मनोबल और जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, तब पहले चलाए गए झूठे प्रोपेगेंडा की बाद में परिशुद्धि संभव नहीं हो पाती।

यह पहली बार नहीं, जब अंतरराष्ट्रीय और खासकर पश्चिमी मीडिया ने भारत के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया हो। भारत दशकों से आतंक की मार झेलता रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया को 'वार आन ग्लोबल टेरर' की याद 9/11 के बाद ही आई। भारत में चल रहे आतंकवाद को वह अब भी कश्मीर विवाद से जोड़कर या फिर भारत में "बढ़ते उग्र राष्ट्रवाद" की प्रतिक्रिया के रूप में ही देखता है। भाषा, संप्रदाय की दृष्टि से विविधता भरे देश में इतना सफल जनतंत्र होने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र पर अनर्गल टिप्पणियां होती रहती हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सफलता मिलने पर भारत को उलाहने मिलते हैं और यहां की समस्याओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है। यह कथानक भेद का ही परिणाम है कि ओसामा का मारा जाना सकारात्मक समाचार बनता है, पर आतंकी निज्जर की मौत और पन्नू की जान को कथित खतरे पर भारत सरकार को घेरने का प्रयास होता है। पश्चिमी सरकारों और पाश्चात्य मीडिया में सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता के कारण भारत के प्रति वह संवेदनशीलता नहीं, जो सामान्यतः दिखनी चाहिए। एक उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति होने के कारण भी पश्चिमी दृष्टिकोण में भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव झलकता है। इस सबके बावजूद भारत केवल पश्चिम के असत्य और पूर्वाग्रहों का उल्लेख भर करके चुप नहीं रह सकता। अपने बढ़ते वैश्विक प्रभाव के मध्य भारत को न सिर्फ अपना अपना कथानक, अपनी कहानी स्वयं कहनी-बनानी होगी, बल्कि उसे वैश्विक समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण से दुनिया को भलीभांति परिचित भी कराना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया में स्थान तलाशने के अलावा भारतीयों को स्वतंत्र छवि वाले ऐसे विश्वसनीय मीडिया मंच तैयार करने होंगे, जो भारतीय परिदृश्य में घटनाओं को देखते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी समीक्षा कर सकें। यह दायित्व सरकारी न होकर भारत के ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार-विचारक वर्ग को उठाना होगा, जिसका मानस पश्चिमी या चीनी परतंत्रता से मुक्त हो। इसका वित्तीय प्रबंध उन निवेशकों को करना होगा, जो निवेश पर प्रतिफल के बजाय इस प्रयोजन के महत्व से प्रेरित हों। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक देश के तौर पर हमारी मनःस्थिति में परिवर्तन आए।

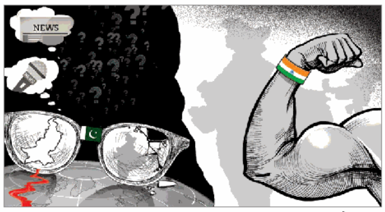

अवधेश राजपूत

दीर्घकालिक विदेशी उपनिवेशवाद ने आमजन के साथ-साथ भारत के प्रबुद्ध वर्ग को भी आत्मसंशय और संकोच से भर दिया है और वह न केवल अपने देसी खोल में सिमटकर रह गया है, बल्कि पाश्चात्य विश्वदृष्टि के पराधीन भी हो गया है। एक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को अंतर्मुखी स्वभाव से निकलकर पूरे विश्व को अपना सरोकार बनाना होगा। मीडिया के अलावा इसी प्रत्याशा हेतु थिंक टैंक, शोध संस्थान, पर्यवेक्षी निकाय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भी बनाने होंगे। इनके द्वारा वैश्विक विषयों पर टिप्पणियों के अलावा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सहिष्णुता जैसे मानकों पर पश्चिमी देशों की समीक्षा भी करनी होगी। इसी के साथ सिनेमा, सीरियल और साहित्य जैसी विधाओं को भी अपना दृष्टिकोण वैश्विक करना होगा। कुछ और बिंदुओं पर सरकार को भी ध्यान देना होगा। आपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने भारतीय पक्ष समझाने को विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जो पहल की, वह समय-समय पर करनी होगी। राजनयिकों के अलावा नेताओं और बुद्धिजीवियों के स्तर पर भी आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर भारत का विश्व से संवाद एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए और ऐसे संभाषणों के लिए संस्थागत प्रयास भी होने चाहिए। भारत के विरुद्ध कुप्रचार को हवा मिलने का बड़ा कारण संवाद की कमी और संवाद में देरी भी रहती है।

पुरानी कहावत है कि जब झूठ आधी दुनिया घूम आता है, तब सच अपने जूते पहन रहा होता है। भारतीय सेना के तीन डीजीएमओ ने तो प्रेस कांफ्रेंस में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, परंतु उसके पहले संवादहीनता के कारण ऐसी बातों को बढ़ावा मिला, जिनके जरिये कहा गया कि अमेरिकी और चीनी मध्यस्थता के कारण भारत ने संघर्ष विराम किया। बदलते परिदृश्य में जब भारत को प्रभावित करने वाले मुद्दे रोजाना विमर्श का विषय बनते हैं, तब यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से भी व्हाइट हाउस की तर्ज पर प्रतिदिन प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा जाए। हमें यह समझना होगा कि कथानक को प्रभावित करने की क्षमता के अभाव में पश्चिम अपने एजेंडे के हिसाब से भारत के प्रति खास संदेश देने वाली अपनी कहानियों को आकार देता रहेगा। यानी वही नैरेटिव शेपिंग करता रहेगा।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

हरित भारत के प्रति समर्पित रेलवे

अश्विनी वैष्णव

भारत यह साबित कर रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता एक साथ संभव है

हर बार आप जब परिवहन के अन्य साधनों के बजाय रेलगाड़ी से यात्रा करने का चुनाव करते हैं, तो केवल आराम या सुविधा ही नहीं चुन रहे होते। आप एक स्वच्छ एवं हरित भारत को भी चुन रहे होते हैं। पिछले वर्ष 700 करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा के साधन के रूप में भारतीय रेल को चुना। रेल हमारी जीवन रेखा है और भविष्य के लिए एक हरित वादा भी। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेलवे सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। रेलवे देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए पंचामृत लक्ष्यों-2070 तक शून्य उत्सर्जन को साकार करने में सहायता कर रहा है और एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इसे संभव बना रहा है। यातायात को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित करके और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा स्रोतों के साथ परिचालन को शक्ति प्रदान करके इस दिशा में बढ़ रहा है। ये कदम देश को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को विकार्बनित (डीकार्बोनाइज) करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

यात्रा सेवाओं के साथ ही माल ढुलाई में भी रेलवे की महत्ता समय के साथ बढ़ती जा रही है। 2013-14 में भारतीय रेल ने लगभग 105.5 करोड़ टन माल की ढुलाई की। 2024-25 के दौरान यह ढुलाई बढ़कर 161.7 करोड़ टन हो गई है। इससे भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे बन गया है। विशेषज्ञों द्वारा की गई गणनाओं का उपयोग करते हुए सड़क के बजाय रेल के जरिये माल ढुलाई से संबंधित इस बदलाव ने 14.3 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। यह 121 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। रेल द्वारा माल परिवहन की लागत सड़क मार्ग से होने वाले परिवहन की लागत की लगभग आधी है। इसका अर्थ है कि न केवल व्यवसायों, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बचत। इस बदलाव से पिछले दशक में लाजिस्टिक्स की लागत में 3.2 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। भारतीय रेल स्वच्छ भी है और ट्रकों की तुलना में इससे 90 प्रतिशत कम कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है। परिणामस्वरूप हमारे आसमान में कम धुआं निकलता है और हमें स्वच्छ हवा मिलती है। सड़क से रेल की ओर होने वाले इस बदलाव ने हमें 2,857 करोड़ लीटर डीजल की बचत कराई है, जो ईंधन लागत में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की बचत के बराबर है।

पर्यावरण हितैषी भी है भारतीय रेल ● फाइल

चूंकि भारत तेल आयात करता है, इसलिए परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण करना रणनीतिक रूप से एक समझदारी भरा कदम है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। 2014 से पहले के 60 वर्षों में भारतीय रेल ने 21,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया। जबकि पिछले 11 वर्षों के दौरान हमने 47,000 किमी रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया है। आज हमारे ब्राड गेज नेटवर्क का 99 प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत है। भारतीय रेल स्टेशनों, कारखानों और कार्यशालाओं के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग तेजी से कर रहा है। अब यह रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए अधिक हरित ऊर्जा प्राप्त करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह सब भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता देगा। इस गति को आगे बढ़ाते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी) को विद्युतीकृत किया गया है। उच्च क्षमता वाली रेलवे लाइनें भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से माल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। कुल 2,741 किमी परिचालन के साथ डीएफसी ने सड़कों पर भीड़भाड़ कम की है और डीजल की खपत एवं कार्बन उत्सर्जन को भी घटाया है। भारत हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जैसी आधुनिक, शून्य-उत्सर्जन तकनीक भी अपना रहा है। पहली ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और 2,600 यात्रियों को ले जाएगी। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी।

भारत यह साबित कर रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी एक साथ निभाई जा सकती है और ऐसा होना भी चाहिए। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स परफारमेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत अब 139 देशों में 38वें स्थान पर है, जो 2014 की तुलना में 16 स्थान ऊपर है।

रेलवे विद्युतीकरण के विस्तार ने लागत और उत्सर्जन को कम किया है। इसने गति और क्षमता भी बढ़ाई है, जिससे भारत को विश्वस्तरीय लाजिस्टिक्स मानकों के निकट पहुंचने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2030 का लक्ष्य तय किया है। तेजी से हो रहे विद्युतीकरण और बड़े पैमाने पर माल को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित करने के कारण भारतीय रेलवे 2025 तक ही नेट जीरो (स्कोप 1) हासिल करने की ओर अग्रसर है। चूंकि भारतीय रेलवे सतत विकास के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहा है, इसलिए हर विद्युतीकृत ट्रैक, हर सौर पैनल और सड़क से हटा प्रत्येक मालवाहक कंटेनर हमारे लोगों और हमारी धरती के उज्जवल भविष्य के प्रति एक शपथ है।

(लेखक केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म के स्तंभ

धर्म भगवत्प्रतिपादित सृष्टि के ऊषा काल से एक सार्वभौम शाश्वत नियम-व्यवस्था है, जिसके सहज अनुपालन से सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे वेद, समृतियां और पुराणादि में जो प्राणिमात्र के कल्याण के सदुपेदश वर्णित और निर्देशित हैं, उनके अनुपालन से व्यक्ति लोक-परलोक में यशस्वी होता है। व्यक्ति को जानबूझकर उपेक्षित और नष्ट किया हुआ धर्म ही मारता है और श्रद्धापूर्वक रक्षित किया हुआ धर्म ही उसको उत्तम जीवन देता है। सत्य ही कहा गया है कि जो धर्म की रक्षा करता है, तब धर्म ही उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करता है।

धर्मविहीन जीवन अमर्यादित एवं उच्छृंखल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से अनाचार फैलता है। आचार-विचार, आहार-विहार और विश्रामादि समस्त दैनिक कार्यों को धर्मानुसार ही करना चाहिए। धर्मनियंत्रित जीवन ही स्वस्थ-सुंदर समाज का निर्माण करता है। आज मानव बड़े-बड़े कार्य कर समृद्धिशाली हो रहा है, किंतु धर्म से विमुख होने के कारण उसके पारस्परिक संबंधों में अपनत्व का नितांत अभाव हो रहा है। संप्रति, सहज स्नेह के स्थान पर व्यवहार में शुष्क औपचारिकता मात्र प्रदर्शित है। धर्म ही मनुष्य की विशेषता है। धर्मविहीन होने से समाज में साधुता विलुप्त हो जाती है। स्वार्थ और अभिमानमूलक सोच के दुष्प्रभाव से पाखंडवाद का दानव मानव के सांस्कृतिक मूल्यों को छिन्न-भिन्न कर देता है।

धर्म के मुख्य चार स्तंभ हैं-सत्य, दया-दान तप और पवित्रता। जो व्यक्ति सत्य की उपेक्षा नहीं करता है, वह आध्यात्मिक ताप से प्रभावित नहीं होता। जिसमें दया-दान जैसे दैवीय सद्गुण जागृत रहते हैं, उस पर आधिदैविक ताप का प्रभाव नहीं रहता है। जिसका आचार-विचार पवित्र और जो तपस्वी है, आधिभौतिक उससे बहुत दूर रहता है। तप का तात्पर्य है-अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्मानुशासन को शिरोधार्य किए रहना। धर्म के यही स्तंभ जीवन की आधारशिला हैं।

आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

विपक्ष के समझदार नेता

'देश हित पर भारी पड़ते दलगत हित' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने देश के उन विपक्षी नेताओं की नासमझी पर क्षोभ प्रकट किया है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं की आलोचना करने में गुरेज नहीं किया जो विदेशी धरती पर अपनी राष्ट्रहितैषी बयानबाजी से विपक्ष के समझदार नेता बन गए हैं। देश में विपक्षी नेता के तौर पर भाजपा और मोदी सरकार के आलोचक माने जाने वाले कांग्रेस के शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, डीएमके की कनिमोरी और के अलावा एआइएमआइएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश में जाकर जिस समझदारी से देश के मान-सम्मान का खयाल रखते हुए 'आपरेशन सिंदूर' पर भारत के पक्ष को रखा उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बावजूद इसके कांग्रेस के कुछ नासमझ नेता सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विभिन्न देशों में 'आपरेशन सिंदूर' पर सकारात्मक रूप से भारत का पक्ष रखने वाले सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे समझदार नेताओं की आलोचना करने में व्यस्त हैं। भला इससे भी अधिक लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जयराम रमेश जैसे नेता इस काम को अंजाम देकर अपने आका को खुश करने में लगे हुए हैं। इस विद्रूपता को आज पूरा देश देख रहा है। मोदी सरकार चाहती तो भाजपा के कद्दावर नेताओं के नेतृत्व में दो-चार प्रतिनिधि मंडल बनाकर विदेशों में भेज सकती थी, लेकिन उसने भारत की एकता प्रदर्शित करने के लिए विपक्षी दल के ओवैसी जैसे अपने कटु आलोचकों को भी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंप कर, उन्हें भारत के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वाह करने का अवसर प्रदान किया। निःसंदेह मोदी सरकार द्वारा चुने गए सभी विपक्षी नेता देश की उम्मीद पर खरे उतरे हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए शुभ संकेत है।

pandeyvp1960@gmail.com

बढ़ेगा स्वदेशी रक्षा उपकरण की मांग

अजय कुमार द्वारा लिखित आलेख मिसाल बनेंगी रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां पढ़ा। आपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमता को प्रमाणित किया है। 2018 से भारतीय रक्षा उत्पादन में तेजी आई है, लेकिन आज भी भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस, फ्रांस, इजरायल और अमेरिका पर निर्भर हैं। दूसरे देशों से तकनीक के आदान-प्रदान में मुश्किलें आती है एवं रक्षा सामग्रियां भी समय पर नहीं मिल पाती है। वायुसेना अध्यक्ष ने रक्षा सामग्रियों में देरी का मामला उठाया है। रूस-यूक्रेन युद्ध रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहा है। अभी तक रक्षा उत्पादन में सरकारी कंपनियां कार्य कर रही हैं। निजी कंपनियों की बदौलत भारत साफ्टवेयर क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश है। निजी कंपनियों की मदद से अमेरिका रक्षा सामग्रियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। आपरेशन सिंदूर की सफलता के उपरांत भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग में तेजी आई है।

हिमांशु शेखर, केसपा, गया।

पर्यावरण दिवस की प्रासंगिकता

आज देश में पर्यावरण संरक्षण की बात हर ओर हो रही है। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमारा जीवन पारिस्थितिक असंतुलन के कारण प्रभावित हो रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पांच जून को सारे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में इसकी शुरुआत की थी। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण आज पर्यावरण में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में पर्यावरण दिवस की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। आज मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहा है। पहाड़ों को काटकर होटल और घर बनाए जा रहे हैं। गाड़ी, एसी आदि का उपयोग कर रहा है।

डा. हरि गोविंद प्रसाद, बेगूसराय

भूल सुधार

बुधवार, 4 जून को प्रकाशित 'मिसाल बनेंगी रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां' शीर्षक वाले लेख के तीसरे पैरे में रक्षा निर्यात संबंधी आंकड़े त्रुटिपूर्ण छप गए थे। सही आंकड़े इस प्रकार हैं-2017-18 में निजी क्षेत्र का जो रक्षा निर्यात 1,400 करोड़ रुपये का था, वह 2024-25 में बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये हो गया। इस भूल और पाठकों की असुविधा के लिए खेद है।

-संपादक

पोस्ट

जीवन में ऐसा कोई काम नहीं, जो पूरा न हो सके, इसलिए किसी का मजाक न बनाएं। आरसीबी ने 18 साल में जितने ताने सुने, उतने शायद ही किसी ने सुने होंगे, लेकिन विराट कोहली ने सबका मुंह बंद कर दिया। भानु नंद@BhanuNand

एक सामान्य कार्यदिवस वाले दिन भी एक लाख की क्षमता वाले स्टेडियम का भरा रहना और करोड़ों लोगों का उसे स्क्रीन पर देखना दर्शाता है कि भारत में क्रिकेट का कितना जुनून है। केविन पीटरसन@KP24

जब राहुल गांधी ने उपहास करते हुए कहा था कि ट्रंप ने फोन करके मोदी से सरेंडर करने को बोला... तो क्या उन्हें पता था कि ऐसा करके वह कांग्रेस पार्टी का कितना अहित कर रहे हैं? यह किसी स्कूली बहस का नहीं, बल्कि युद्ध से जुड़ा मसला था, लेकिन लगता है कि उन्हें इसका अंतर नहीं पता। तवलीन सिंह@tavleen_singh

पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों को बकरीद पर नमाज या कुर्बानी पर 5 लाख रु. हर्जाना देना होगा। पाकिस्तान निर्माण में इन्हीं अहमदिया ने अहम भूमिका निभाई थी। कमलेश सिंह@kamleshksingh

जनपथ

दुश्मन भारतवर्ष के हैं अब साढ़े तीन,
'आधा' वाला आजकल है निंदा में लीन।
है निंदा में लीन कह रहा हुआ सरेंडर,
इसका कौन इलाज करेंगे भला नरेंदर!
बीस बार खुद हार कर रहा है हल्का मन,
खड़ा पाक के साथ दिख रहा 'आधा' दुश्मन!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 54

****

{ संपादकीय }

रायपुर, गुरुवार 5 जून 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

विदेश नीति में नाकामी के कुछ और उदाहरण

प्रधानमंत्री मोदी भारत की विदेश नीति और विदेशों में भारत की साख को बचाने में किस कदर नाकाम हो चुके हैं, इसके कुछ और उदाहरण सामने आए हैं। एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने पाकिस्तान के लिए 668 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। पाकिस्तान को ये रुपये राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एडीबी की डायरेक्टर एम्मा फैन ने कहा कि पाकिस्तान ने मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियों में सुधार के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एडीबी का यह फैसला तब आया है जब दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा से अपने आधिकारिक निवास पर मुलाकात की थी और इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा था कि- मसातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई, जिसमें हमने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पिछले दशक में भारत के तेजी से हुए परिवर्तन ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इस यात्रा में और गति लाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं मसातो कांडा ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साहसिक बताते हुए लिखा था कि हम अगले पांच वर्षों में नगर निगम के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने और शहर की सेवाओं के आधुनिकीकरण में थर्ड पार्टी कैपिटल सहित 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे।

दो दिन पहले ऐसी खबरें देख कर भ्रम हो सकता था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारी बात नहीं सुनी, कम से कम एशियाई विकास बैंक भारत के साथ खड़ा रहेगा और पाकिस्तान को वित्तीय मदद नहीं देगा। लेकिन यहां फिर भारत की कूटनीति बुरी तरह नाकाम दिखी। श्री मोदी से मिलकर भले ही भारत में निवेश की बातें हुई हों, लेकिन इसके फौरन बाद पाकिस्तान को भी बड़ी मदद देकर एडीबी ने बता दिया कि उसका रवैया भी वही है जो पश्चिमी देशों और संस्थाओं का है। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एडीबी अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाकात कर अपील की थी कि पाकिस्तान की मदद न की जाए, क्योंकि वह आतंकवाद का पोषण करता है। इसके अलावा भारत कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान का नाम ग्रे सूची में डलवाया जाए, इसके लिए यूरोपीय देशों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें भारत कामयाब होता है या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पहले आईएमएफ और अब एडीबी के फैसलों ने भारत की कोशिश को झटका तो दे ही दिया है।

वहीं पाकिस्तान अब अमेरिका, रूस, चीन तमाम बड़ी शक्तियों का करीबी बनने की कोशिश में लगा है। अमेरिका और चीन तो पहले ही भारत के ऊपर पाकिस्तान को तवज्जो दे सकते हैं, अगर रूस में पाकिस्तान अपने लिए जगह बना लेता है, तब भारत की साख पर जो बट्टा लग सकता है, उसका अंदाज सरकार को कर लेना चाहिए। हालांकि मौजूदा रवैया देखकर लगता नहीं कि सरकार को कूटनीति या विदेश नीति की कोई परवाह है। पाठक जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दोहरा रहे हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध विराम करवाया है। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सीधे कोई खंडन नहीं किया है।

अपना पक्ष रखने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की यात्रा पर भेजे गए थे, उनके नतीजे भी कुछ खास नजर नहीं आ रहे। क्योंकि इसमें सरकार की मंशा ही साफ नहीं थी कि आखिर वह प्रतिनिधिमंडलों के जरिए क्या हासिल करना चाहती थी। अगर मकसद विदेशों से समर्थन हासिल करना था, तो फिर इन मंडलों के सदस्यों की मुलाकात हरेक देश में नीति निर्माताओं से होनी चाहिए थी, जहां उन्हें आश्वासन मिलता कि वे पाकिस्तान की जमीन से संचालित आतंकी गतिविधियों का विरोध करेंगे, लेकिन एकाध देश छोड़कर अधिकतर देशों में प्रतिनिधिमंडल में गए सदस्यों ने कहीं थिंक टैंक के लोगों से मुलाकात की या फिर पूर्व मंत्री, पूर्व राजनयिक, पूर्व अधिकारी के साथ बैठकें कीं। इसमें भी एक वीडियो सामने आया जब एक प्रतिनिधिमंडल की सदस्या रेखा शर्मा खाने की मेज़ पर गीत गाते दिखीं और बाकी लोग तालियां बजा रहे थे। इस पर सवाल भी उठे कि एक बड़े आतंकी हमले के बाद वैश्विक समर्थन हासिल करने यह दल गए हैं या जनता के पैसों पर विदेशों में पिकनिक मनाने। इन्हीं रेखा शर्मा ने देश लौटकर एक समाचार चैनल से कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि जिन देशों में कांग्रेस कभी पहुंच नहीं पाई और जिन देशों में कांग्रेस का कभी स्वागत नहीं होता था, वो देश अब भारत की लीडरशिप की तरफ नेतृत्व के लिए देख रहे हैं। इस मूर्खतापूर्ण और सिरे से गलत बयान पर हंसा जाए या दुख मनाया जाए कि देश की संसद में ऐसे लोग पहुंच गए हैं, जिन्हें मोदीभक्ति तो खूब आती है, लेकिन राजनैतिक इतिहास का ज्ञान शून्य है। जिस प्रतिनिधिमंडल की सदस्या रेखा शर्मा थीं, वह सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर गया था। और पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह खुद इनमें से सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की यात्रा कर चुके हैं।

अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने प्रतिनिधिमंडल इसलिए भेजे थे ताकि वापस लौटकर ये नरेन्द्र मोदी का गुणगान करें और कांग्रेस को कोसें। वैसे वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार को प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसी खबरों से क्या विदेशों में भारत की छवि सुधरेगी, ये सोचने वाली बात है। इधर विदेश नीति के मोर्चे पर एक बड़ा झटका और लगा है। कनाडा में हो रही जी-7 की बैठक में मोदी सरकार को न्यौता नहीं मिला। 2023 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने फौरन ही खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में जो खटास बढ़ी तो अब तक उसका असर दिखाई दे रहा है। जबकि इस बीच कनाडा में नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पद संभाल लिया है और भारतीय मूल की अनीता आनंद विदेश मंत्री बनीं तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें बधाई दी थी। यह भारत-कनाडा के बीच पहला आधिकारिक राजनीतिक संवाद था, लेकिन अब जी-7 के लिए भारत को आमंत्रित न कर कनाडा ने जाहिर कर दिया कि उसकी तरफ से तनाव जारी रहेगा। 2019 के बाद यह पहला मौका है जब भारत जी-7 की बैठक में शामिल नहीं होगा।

दालमोठ बनाम बिस्कुट, मामला गंभीर है

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

> **अगर खबर सच्ची है तब तो मामला संगीन है कि क्या जज को जानबूझकर पुरानी दालमोठ पेश करने का कोई षड्यंत्र रचा गया और अगर खबर काल्पनिक है, तब भी गंभीर चिंता का विषय है कि क्या दालमोठ और बिस्कुट को चर्चा में लाने की यह कोई चाल है। क्योंकि आमतौर पर तो सरकारी बैठकों में चाय के साथ समोसे, ढोकले, कलाकंद आदि परोसे जाते हैं। लेकिन सिविल जज और सत्र न्यायाधीश जब साथ बैठे हों और बात केवल बिस्किट और दालमोठ में निपट जाए, क्या यह नाइंसाफी नहीं है।**

सोशल मीडिया पर खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के गोण्डा में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने अर्दली को चाय और बिस्कुट ठीक से न मिलने पर नोटिस थमा दिया। नोटिस में अर्दली राकेश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि सिविल जज के आने पर चाय/बिस्कुट लाने के लिए कहने पर ऐसी दालमोठ क्यों लाई गई, जिससे गंध आ रही थी। इस खबर में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर जो नोटिस वायरल हो रहा है, उसमें जज की तरफ से लिखा गया है- 'आज दिनांक 30 मई को लंच समय में मेरे विश्राम कक्ष में सिविल जज (जू.डि.) / एफटीसी नवीन, गोंडा सुश्री शर्मिष्ठा साहू मिलने आई थीं जिस पर मेरे द्वारा आपको चाय/बिस्कुट लाने हेतु कहा गया, जबकि आपके द्वारा केवल दो चाय लाई गई। मेरे द्वारा पुन: बिस्कुट लाने के लिए कहा गया, किंतु आपके द्वारा बिस्कुट न लाकर पुरानी खराब स्थिति में जिसमें से गंदी गंध आ रही थी, दालमोठ रखी गई। आलमारी में दो डिब्बे में अच्छी स्थिति में बिस्कुट रखे हुए थे। बावजूद आपके द्वारा जानबूझकर खराब पुरानी दालमोठ रखी गई, जो कि फेंकने की स्थिति में थी। इस सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31 मई को समय 10.30 बजे प्रस्तुत करें कि इस प्रकार की जानबूझकर घोर त्रुटि आपके द्वारा क्यों की गई।'

अगर खबर सच्ची है तब तो मामला संगीन है कि क्या जज को जानबूझकर पुरानी दालमोठ पेश करने का कोई षड्यंत्र रचा गया और अगर खबर काल्पनिक है, तब भी गंभीर चिंता का विषय है कि क्या दालमोठ और बिस्कुट को चर्चा में लाने की यह कोई चाल है। क्योंकि आमतौर पर तो सरकारी बैठकों में चाय के साथ समोसे, ढोकले, कलाकंद आदि परोसे जाते हैं। लेकिन सिविल जज और सत्र न्यायाधीश जब साथ बैठे हों और बात केवल बिस्किट और दालमोठ में निपट जाए, क्या यह नाइंसाफी नहीं है।

राहुल गांधी को देखना चाहिए कि नेहरूजी ने कैसा भारत बनाकर छोड़ा है, जहां किसी को रोजाना मखाने खाने मिलते हैं और किसी को पुरानी दालमोठ परोसी जाती है। नेहरूजी के बाद शास्त्रीजी, इंदिराजी, राजीवजी सबने शासन कर लिया, किसी का ध्यान इस विसंगति पर नहीं गया। सब पता नहीं क्या-क्या करते रहे। कोई जय जवान, जय किसान कहता रहा, किसी ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए, कोई पंचायतों को मजबूत करने में लगा रहा और साथ में देश में कम्प्यूटर लेकर भी आ गया। ये सब करने से क्या भारत का भला हो गया। आईआईटी, आईआईएम, एम्स न भी बनते तब भी भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए रोजाना शाखाएं कार्यरत थी हीं, वहीं से निकले लोग आज राडार से बचने के नुस्खे हमारे लड़ाकू विमानों को देते हैं। और राहुल गांधी की हिमाकत देखिए, उन्हीं से सवाल करते हैं कि हमारे कितने विमान पाकिस्तान ने गिराए हैं। राहुल गांधी भारतीय परंपरा में पढ़े-लिखे होते तो जानते कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले। लेकिन नहीं, वो तो वही अटके हैं कि ट्रंप ने फोन कब किया, क्या कहा और उसके बाद यहां प्रधानमंत्री ने क्या किया। अब जो किया सो किया, लेकिन क्या उससे जो कुछ घटा है, वो बदल जाएगा, नहीं न। तो फिर वही-वही सवाल दोहराने का क्या मतलब।

2004 से राहुल गांधी सांसद चुने जा रहे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने, अब नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन राजनीति के तकाजे समझ ही नहीं रहे हैं। ये समय बड़े-बड़े सवालों पर चिंतन करने का है, जिससे देश में सब कुछ कुशलमंगल रहे। कहां अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, चीन के सवालों पर उलझे हुए हैं। देखिए मोदीजी को वो इन सबमें नहीं उलझते, मन की बात करते हैं। जिसमें देश के लोगों से जुड़े जरूरी सवाल रहते हैं।

जैसे जून के आखिरी में मोदीजी जब मन की बात करेंगे तो शायद गोंडा के दालमोठ प्रकरण पर कुछ उच्चकोटि के विचार देश के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा कि यह खबर सोशल मीडिया पर आई कैसे। खबर में सच्चाई है तो यह नोटिस किसी सोशल मीडिया यूजर के हाथ कैसे लगा। अगर खबर गलत है तो भी इसके पीछे मंशा क्या है। फिर कुछ जरूरी सवालों पर मोदीजी की राय सामने आएगी, जैसे जज महोदय के आदेश के बावजूद अर्दली ने बिस्किट की जगह पुरानी दालमोठ पेश कर जो नाफरमानी की है, उसके पीछे कारण क्या है। क्या अर्दली ने अपने से ऊंचे ओहदे पर बैठे इंसान को इसके जरिए चुनौती पेश की है। क्या अर्दली अर्बन नक्सल गैंग से प्रेरित है। बस्तर से तो नक्सलियों का सफाया मोदी-शाह की युति कर चुकी है, लेकिन अर्बन नक्सलियों से निपटने के लिए अभी रणनीति तैयार हो रही है, इसके लिए अपने 140 करोड़ भाई-बहनों से मोदीजी सहयोग मांगेंगे।

अर्दली राकेश कुमार के नाम से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे किस जाति और वर्ग के हैं। इससे मामला और भी पेचीदा हो जाता है। क्योंकि यहां फिर राहुल गांधी गड़बड़ कर चुके हैं। समाज का एक्सरे करने की बात कर पूरे समाज को यह एहसास करा दिया कि कोई गंभीर बीमारी का शिकार समाज हो गया है। जबकि इससे पहले सब आराम से चल रहा था। किसी को उसकी कमजोरी के बारे में खुलकर कहना अशिष्टता होती है, इसलिए शिष्टाचार के नाते समाज में पसरी बीमारी का जिक्र सरकार नहीं करती थी, ताकि किसी को बुरा न लगे। लेकिन राहुल गांधी को तो शिष्टाचार निभाना आता ही नहीं, इसलिए वो खुलकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कह देते हैं कि आपके हाथ में शक्ति है ही नहीं, जहां से फैसले लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, वहां आप हैं ही नहीं। इसलिए वो एक्सरे की बात पूरे देश में करते फिर रहे हैं। जिसके बाद सरकार को जाति जनगणना कराने का ऐलान करना पड़ा। तो देखने वाली बात ये है कि क्या अर्दली राकेश कुमार भी जाति जनगणना का पक्षधर है या उसे वर्ण व्यवस्था के तहत बने खांचों में जीना मंजूर है। क्या बिस्कुट की जगह दालमोठ परोस कर उसने जाति जनगणना का कोई संकेत तो नहीं दिया।

बिस्कुट की जगह दालमोठ परोसने के पीछे क्या कोई कारोबारी या अंतरराज्यीय विवाद है, यह भी देखा जाएगा। दालमोठ तो आगरे की ही मशहूर है, लेकिन बिस्कुट कौन सी कंपनी का था, कहां बना था और कहां से खरीदा गया था। दालमोठ को पुरानी पड़ने तक बची क्यों रहने दिया गया। क्यों उसे न खाकर सरकारी धन की बर्बादी की गई। क्या इसमें योगी प्रशासन ने कोई चूक की, यह देखना होगा। इस पूरे प्रकरण में विचारणीय पहलू यह भी है कि जज महोदय ने अलमारी में बिस्कुट के दो पैकेट अच्छी स्थिति में रखे होने का जिक्र किया है, अर्थात वे उच्च कोटि के ईमानदार जज हैं। क्योंकि वे चाहते तो बिस्कुट के दो पैकेट अपनी हिफाजत में अपनी दराज़ में रख सकते थे। लेकिन उन्होंने सरकारी संपत्ति पर अनायास कब्जा करने की कोई चेष्टा नहीं जताई। यह उन तमाम सांसदों के लिए मिसाल है जो मंत्री या सांसद न रहने पर भी सरकारी बंगले में टिके रहते हैं। गोंडा के अपर सत्र न्यायाधीश ने उन सरकारी अफसरों के लिए भी मिसाल पेश की है जो तिजोरी भरने के बाद दीवारों में नोट चुनवा कर रखते हैं। इनकी वजह से इनकमटैक्स और ईडी पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ता है।

दालमोठ बनाम बिस्कुट प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि जब अर्दली ने केवल चाय की दो प्यालियां पेश कीं और फिर बिस्कुट लाने का आदेश हुआ, लेकिन फिर भी पुरानी दालमोठ पेश की गई, इस सबमें जो वक्त बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा। दालमोठ में एक से ज्यादा नमकीनों का मिश्रण होता है, कुछ-कुछ इंडिया गठबंधन की तरह, कुछ सख्त, कुछ चटपटे, कुछ तीखे तत्व होते हैं। तो क्या अर्दली ने इस बात से प्रेरित होकर दालमोठ परोसी, इसे भी परखना चाहिए। यह सीधे सरकारी कर्मचारी की राजनैतिक पक्षधरता को दिखाता है। साथ ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दालमोठ लाने जे जाने के बीच चाय गर्म बनी रही या ठंडी हो गई। क्योंकि कुछ भी हो जाए चाय की शान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी तो शायद कॉफी पीते हैं, वो क्या जानें कि चाय बेचने और चाय पीने का सुख क्या होता है।

बहरहाल अभी जस्टिस फॉर बिस्कुट या बायकॉट पुरानी दालमोठ हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर नया अभियान खड़ा करने की जरूरत है। हमारे कितने विमान गिरे, किसने सरेण्डर किया, सीज़फायर का आदेश कहां से हुआ, ऐसे फालतू सवालों में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि बड़े सवालों पर देश मन की बात करे।

गाजा और पश्चिमी तट पर कब्ज़ा करने के लिए इजरायल पूरी तरह तैयार

■ नन्तू बनर्जी

> **युद्ध के अंत, जो अंतिम चरण में पहुंच गया है, तक मृत्यु और विस्थापन के कारण फिलिस्तीनी आबादी में काफी कमी आने की उम्मीद है। गाजा की लगभग 70 प्रतिशत फिलिस्तीनी आबादी शरणार्थी हैं, जो अपनी दैनिक आजीविका के लिए ज़्यादातर मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। भूमि, वायु और समुद्र के माध्यम से परिवहन की आवाजाही पर सुरक्षा से जुड़ी इजरायली नाकाबंदी ने गाजा की अच्छी-खासी आबादी को क्षेत्र से भागने या भूख से मरने के लिए मजबूर किया है। एक तरह से, गाजा की शरणार्थी आबादी लंबे समय से संकीर्ण पट्टी में शो चलाने वाले हमास आतंकवादियों द्वारा बंदी बना ली गयी है।**

गाजा के हमास उग्रवादियों को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायल लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही, इजरायल फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन और यहां तक कि तेल अवीव में अपने ही लोगों के एक वर्ग के विरोध को नजरअंदाज करते हुए पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से (क्षेत्र सी) पर कब्ज़ा करने के लिए कमर कसता हुआ दिखायी दे रहा है।

पिछले सप्ताह, इजरायल ने कहा कि वह कब्जे वाले पश्चिमी तट पर 22 अतिरिक्त यहूदी बस्तियाँ स्थापित करेगा। ईरान और ईरान समर्थक हौथियों को छोड़कर अरब दुनिया में हमास के कुछ ही सच्चे समर्थक हैं। 7 अक्तूबर 2023 से इजरायल-हमास युद्ध के दौरान हुई मौतों और विस्थापन के कारण फिलिस्तीनी आबादी में भारी कमी के साथ गाजा जल्द ही इजरायल के विस्तारित क्षेत्र का हिस्सा बन सकता है।

वर्तमान गाजा युद्ध अतीत में कई अनसुलझे इजरायली-फिलिस्तीनी संघर्षों के बाद हुआ है, जिनमें 2008, 2009, 2012, 2014 और 2021 के संघर्ष शामिल हैं। विडंबना यह है कि इजरायल ने 2005 में दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली बस्तियों में से एक गाजा पट्टी का नियंत्रण छोड़ दिया था। वह गाजा पट्टी से हट गया था और उसने वहां से अपनी सभी बस्तियों को खत्म कर दिया था। इजरायल फिलाडेल्फी मार्ग से भी वापस हो गया था, जो मिस्र के साथ सीमा से सटे भूमि की एक संकरी पट्टी थी, जब मिस्र ने राफा समझौते के तहत अपने क्षेत्र की सीमा को सुरक्षित रखने पर रजामंदी व्यक्त की थी। इजरायल चाहता तो 1967 में छह दिवसीय युद्ध के बाद गाजा को अपने नियंत्रण में ले सकता था। उसने पश्चिमी बैंक और पूर्वी येरूशलम पर भी कब्जा कर लिया था। उस समय गाजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबी थी और उसकी आबादी 13लाख थी। गाजा में जन्म दर दुनिया में सबसे अधिक है। हालांकि, वहां बिना किसी तनाव के शासन करने के लिए उचित यहूदी बस्ती के लिए बहुत कम जगह थी।

युद्ध के अंत, जो अंतिम चरण में पहुंच गया है, तक मृत्यु और विस्थापन के कारण फिलिस्तीनी आबादी में काफी कमी आने की उम्मीद है। गाजा की लगभग 70 प्रतिशत फिलिस्तीनी आबादी शरणार्थी हैं, जो अपनी दैनिक आजीविका के लिए ज़्यादातर मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। भूमि, वायु और समुद्र के माध्यम से परिवहन की आवाजाही पर सुरक्षा से जुड़ी इजरायली नाकाबंदी ने गाजा की अच्छी-खासी आबादी को क्षेत्र से भागने या भूख से मरने के लिए मजबूर किया है। एक तरह से, गाजा की शरणार्थी आबादी लंबे समय से संकीर्ण पट्टी में शो चलाने वाले हमास आतंकवादियों द्वारा बंदी बना ली गयी है।

एक बार फिर से उस क्षेत्र को हासिल करने के बाद, इजरायल वहां यहूदी आबादी की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित करेगा ताकि इसका सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित हो सके और पट्टी को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। एक बार जब गाजा पट्टी पर विजय प्राप्त कर ली जायेगी है और पश्चिमी तट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इजरायल के नियंत्रण में आ जायेगा है, तो उम्मीद है कि देश दुनिया की शीर्ष आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरने के अपने लंबे समय से संजोये गये सपने को साकार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

वर्तमान में, इजरायल पश्चिम एशिया का सबसे विकसित और उन्नत देश है, जिसके पास दुनिया में 17वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। अरब प्रायद्वीप के साथ-साथ तुर्की, मिस्र और ईरान सहित 18 सदस्यीय पश्चिम एशियाई क्षेत्र में प्रति वयस्क औसत संपत्ति सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में इजरायल दुनिया भर में 10वें स्थान पर है। उल्लेखनीय रूप से, आठ अरब देश अब खुले तौर पर और बेशर्मी से इजरायल के साथ व्यवहार करते हैं। वे हैं-सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन, ओमान, मोरक्को, बहरीन और सूडान।

यह मानते हुए कि गाजा और लेबनान में इजरायल की लड़ाई जल्द ही कम हो जायेगी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने पूर्वानुमान लगाया है कि देश की अर्थव्यवस्था 2025 में 3.4 प्रतिशत और 2026 में 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो कि ओईसीडी के वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2025 में 3.1प्रतिशत और 2026 में तीन प्रतिशत के औसत विकास पूर्वानुमान से अधिक है। चालू वर्ष के लिए ओईसीडी का विकास पूर्वानुमान बैंक ऑफ इजरायल के चार प्रतिशत और इजरायल वित्त मंत्रालय के 4.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। हालांकि, ओईसीडी को उम्मीद है कि इस साल इजरायल की अर्थव्यवस्था में सुधार आयेगा, हालांकि यह विकास की गति के बारे में निराशावादी है, क्योंकि युद्ध से संबंधित खर्च के जोखिम का हवाला देतेहुए इसने कहा कि देश के वित्त पर इसका असर पड़ रहा है।

2023 यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने इजरायल को दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों में स्थान दिया। इसने पाया कि इजरायल की सेना दुनिया भर में चौथी सबसे मजबूत है, जो केवल अमेरिका, चीन और रूस से पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल दुनिया की छठी सबसे अधिक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली शक्ति भी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अग्रणी वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति बनने के लिए इजरायल की बोली बहुआयामी है। इनमें देश के उच्च तकनीक क्षेत्र को मजबूत करना, रक्षा प्रौद्योगिकी में निरंतर नवाचार और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है। कई बहुराष्ट्रीय निगम देश में अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित कर रहे हैं। इसमें एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। इजरायल के पास एक अच्छी तरह से स्थापित और अत्यधिक अभिनव रक्षा विनिर्माण उद्योग है, और वह उन्नत हथियार और प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है। वह रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है।

इज़राइल देश के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गाजा युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। वर्ष की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खायी कि वर्तमान युद्ध के अंत तक, पूरा गाजा पट्टी इज़रायली सुरक्षा नियंत्रण में होगा। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिणी गाजा क्षेत्र में फ़िलिस्तीनी हाल ही में हमास के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। गाजा स्थित फ़िलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये वीडियो में युद्ध को समाप्त करने और गाजा से सशस्त्र समूह को हटाने का आह्वान करते हुए देखा गया। उन्होंने नारे लगाये 'बाहर! बाहर! बाहर! पूरा हमास, बाहर!' पिछले हफ़्ते इज़रायली हमले में हमास के सशस्त्र विंग के प्रमुख मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद, गाजा युद्ध के लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है।

ललित सुरजन की कलम से

पत्थरगड़ी, पेसा और स्वायत्त शासन

'यदि सरकारी तंत्र में विकेन्द्रीकरण के बजाय केन्द्रीकरण पर जोर होगा तो कभी भी सुचारु शासन संभव नहीं हो सकता। हमारे सामने तमाम दुनिया के उदाहरण हैं। ग्रेट ब्रिटेन स्पष्ट तौर पर चार हिस्सों में विभाजित है और उनमें से हरेक को पर्याप्त स्वायत्तता हासिल है। हमारा सत्ताधारी वर्ग जिस अमेरिका को अपना चरम आदर्श मानता है वहां भी पचास में से हर राज्य संघीय गणराज्य का सदस्य तो है, लेकिन हर बात के लिए संघ पर निर्भर नहीं है। ऐसा ही कनाडा में है। फिनलैंड जैसे छोटे देश में दो भाषाएं आधिकारिक हैं और सिंगापुर में चीनी व मलय के साथ तमिल को बराबरी की भाषा का दर्जा हासिल है। भारत की संकल्पना भी संघीय गणराज्य के रूप में की गई है, लेकिन इस अवधारणा के पीछे जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनका पालन करने में सत्ताधारी वर्ग की रुचि कुछ कम ही दिखाई देती है। भारत में दर्जनों क्षेत्रीय दलों का उभरना इस केन्द्रीकृत मानसिकता के विरोध का उदाहरण है।'

(देशबन्धु में 03 मई 2018 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2018/05/blog-post.html

पावन प्रसंग

गृहस्थ जीवन में माधुर्य

गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए शिक्षा, संपन्नता और योग्यता ही पर्याप्त नहीं है। गृहस्थ जीवन का आधार है-पति-पत्नी के जीवन में सामंजस्य तथा संबंधों में मधुरता। घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर यदि दिन-रात चिक-चिक होती रहती है तो पति-पत्नी कितने ही योग्य सुशिक्षित क्यों न हों। घर का वातावरण कलह तथा तनाव से ही भरा रहेगा। बिना पढ़े गंवार पति-पत्नी भी प्यार से रहते देखे गए हैं। पत्नी बचपन से मिले संस्कारों के कारण सब कुछ सहजता से सहती है, परंतु अपनी प्रतिक्रिया अन्य रूपों में प्रकट करती है।

आधुनिक शिक्षित परिवारों में जहां पत्नी भी अपना दर्जा पुरुष के बराबर मानती है, वहां सीधी टकराहट होती है, परिणाम होता है-पति-पत्नी से असंतुष्ट और पत्नी, पति से असंतुष्ट, दोनों एकदूसरे के प्रति शिकायतों से भरे हुए और दोनों ही एकदूसरे से भीतर-ही-भीतर ऊबे हुए, इन कारणों से परिवार हर घड़ी टूटन के कगार पर खड़े रहते हैं। यदि पति-पत्नी एकदूसरे से सामंजस्य स्थापित कर सकें और वैसा ही स्नेह, सद्भाव बरतते रहें जैसा कि दांपत्य जीवन में प्रवेश करते समय नवदंपती के रूप में बरतते थे तो परिवार का वातावरण सुख और आनंद से परिपूरित हो जाए।

इस तथ्य को सभी स्वीकारते हैं कि पति-पत्नी एकदूसरे के प्रति सामंजस्य बनाए रहने पर ही गृहस्थी को सुख-शांतिपूर्ण स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, परंतु जानते हुए भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता। इसके कारण हैं- पहला तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं। पति-पत्नी विवाह से पूर्व अपने जीवनसाथी की एक आदर्श छवि अपने मन में बनाए रहते हैं। विवाह होने पर नए-नए साथी के प्रति भावुकता भरा आकर्षण उन त्रुटियों को नजरअंदाज करा देता है, परंतु जैसे-जैसे परिचय पुराना होता जाता है, वैसे-वैसे पूर्व से संजोई गई वह छवि धूमिल पड़ने लगती है और एकदूसरे की कमियां अखरने लगती हैं।

आवश्यक है कि मनुष्य होने के नाते अपने जीवनसाथी की कमियों, त्रुटियों और कमजोरियों के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसका यह अर्थ नहीं कि त्रुटियों को सहन करने से जीवनसाथी के व्यक्तित्व और चरित्र को वैसा ही रहने देना है। विवाह ही इसलिए किया जाता है कि पति-पत्नी एक प्रगाढ़ आत्मीय साथी के रूप में एकदूसरे का विकास करें, लेकिन जीवनसाथी की त्रुटियों को पुलिस अधिकारी की तरह देखने और उसे अपराधी समझने की जो प्रवृत्ति है, वह दांपत्य जीवन की सरसता को तोड़ती ही है।

यहीं से एकदूसरे के प्रति शिकायत रखने और असंतोष व्यक्त करने की शुरुआत होती है। वस्तुत: शिकायत इसलिए नहीं होती कि पति या पत्नी में कोई अवगुण है, बल्कि शिकायत इसलिए रहती है कि उस अवगुण के कारण स्वयं अपने को असुविधा हो रही है।

इसी प्रकार पत्नी पड़ोस के लोगों से, घर के अन्य सदस्यों से चाहे जितना लड़-झगड़ ले कोई गंभीर बात नहीं है। बात गंभीर तो तब बनती है, जब पत्नी पतिदेव की सेवा-टहल में कोई कमी कर देती है या उसको इच्छित सुविधाएं नहीं दे सकती है। कहने का अर्थ यह कि पति-पत्नी को एकदूसरे के अवगुणों से उतनी घृणा नहीं होती, जितनी कि उनके कारण स्वयं को होने वाली असुविधा से। इसी मनोवृत्ति के कारण पति-पत्नी एक-दूसरे के विकास में सहायक होने के स्थान पर एकदूसरे को परेशान करने वाले शत्रु की तरह बरताव करने लगते हैं।

अवगुणों का परिष्कार या व्यक्तित्व का परिमार्जन ही यदि उद्देश्य रहे तो उससे पति-पत्नी एकदूसरे के प्रति इतना भयंकर रुख नहीं अपनाते, जितना कि आमतौर पर अपना लेते हैं। अवगुण या व्यक्तित्व की दुर्बलताएं तो बीमारियों की तरह हैं, जिन्हें उपचार से ठीक किया जाना चाहिए। बीमार और कमजोर आदमी को कोई बैर अथवा प्रताड़ना की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति ही रखता है। उद्देश्य यदि वस्तुत: अपने जीवनसाथी के व्यक्तित्व का परिमार्जन ही है।

-युग निर्माण योजना

आपके पत्र

पाकिस्तानपरस्त आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कूटनीतिक अभियान

पाकिस्तानपरस्त आतंकवाद का विदेशी धरती पर अभियान तेज हो गया है। भारत से गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के खिलाफ पुरजोर विरोध किया। भारत के सर्वदलीय नेताओ में ओवैसी, शशि थरूर, कनिमोझी और सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गज नेताओं ने पाकिस्तान की साजिश की पोल खोलकर रख दी है। इन नेताओं का जज्बा और जोश देशप्रेम से सराबोर नजर आ रहा है। ओवैसी मोदी के बड़े आलोचक रहे हैं हर समय मोदी को मंच से घेरने वाले नेता ने आतंकवादी को संरक्षण देने वाले देश पाकिस्तान पर खूब बरसे। उनका देशप्रेम साफ झलक रहा है। ओवैसी ने विदेश में पाकिस्तानी आतंतियों द्वारा पहलगाम में किए हमले की पुरजोर निंदा की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लेकर फटकार लगाई है। देशभक्ति की पराकाष्ठा में लीन ये नेता आतंकवाद पर खुल कर बोल रहे है कनिमोझी को अपनी भाषा के लिए पूछे जाने पर उनके जवाब पर भारत ही नहीं, देशभक्तों ने भूरि भूरि प्रशंसा की है। सलमान खुर्शीद भारत में भाजपा पर प्रहार करते नजर आते हैं लेकिन उनका देशप्रेम किसी से छुपा नही है। सलमान खुर्शीद ने देशहित की मुखर पैरोकारो को राजनीति से जोड़े जाने की पीड़ा व्यक्त की। पाकिस्तान को आतंकवाद पर बेनकाब करने में कोई कसर नही छोड़ी। इंडोनेशिया में सलमान खुर्शीद ने धारा 370 हटाये जाने पर पुरजोर समर्थन किया। देश में लोग राजनैतिक निष्ठा की बात भले ही करे, लेकिन सर्वदलीय नेताओं की देशप्रेम और आतंकवाद पर उनकी निष्ठा साफ झलकती दिखाई दे रही है। शशि थरूर ने भारत का पक्ष मजबूत रखने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आतंकवादियो को प्रशिक्षण देने वाले पाकिस्तान का नकाब चीरता दिखाई दिया। मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। खुर्शीद को मोदी सरकार के नए पैरोकार होने का तंज कसा है। लेकिन उनको कोई गिले शिकवे नहीं है। देश के पक्ष में बोलने की जरूरत है और वो हम कर रहे है जिस तरह से खुर्शीद शशि थरूर सांसद कनिमोझी और ओवैसी के सर्वदलीय दल ने विदेश में भारत के आतंकवादी गतिविधियों पर फोकस कर उसको बेनकाब किया है, वह सच्चा देशप्रेम है। वो अंदर पार्टियों पर कुछ भी बोलें, लेकिन देश की बात हो वहां एकजुटता रखने की इस देशभक्ति एवं एकजुट होने पर सभी को गर्व है।

-कांतिलाल मांडोत, सूरत

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

गरीब कैदियों को वित्तीय मदद में तेजी लाएं राज्य

देश के जेलों में बंद गरीब कैदियों को जमानत के लिए कानूनी सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय जेलों में हजारों विचाराधीन कैदी हैं, जिन्हें अपने लिए इंसाफ का इंतजार है। भारतीय अदालतों में मुकदमों की इतनी भीड़ है और न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त है कि जेलों में बंद आरोपी गरीब कैदियों की न्याय की आस ही पथरा जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों की जमानत में मदद के लिए राज्यों से केंद्रीय कोष का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे केंद्रीय कोष से उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करें, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना अदा न कर पाने से जमानत या जेल से रिहाई पाने में असमर्थ हैं। सरकार के इस फैसले से गरीब कैदियों को जमानत में और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी। सरकार की पहल पात्र कैदियों को लाभ पहुंचाने की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सीएनए के रूप में नामित है। मोदी सरकार ने वर्ष 2023 के मई में गरीब कैदियों को सहायता योजना शुरू की थी। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मदद करती है और राज्य इस फंड का इस्तेमाल गरीब कैदियों की कानूनी मदद में करते हैं। दिक्कत यह है कि राज्य व केंद्र शासित सरकारें गरीब कैदियों की मदद के लिए इस योजना के क्रियान्वयन में उदासीन रहती हैं। इससे केंद्र को बार-बार राज्यों को याद दिलाना पड़ता है, यह स्थिति चिंताजनक है। देश की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। राज्यों को अपने यहां की जेलों का ऑडिट करना चाहिए, पात्र कैदियों की पहचान कर उन्हें केंद्रीय मदद का लाभ पहुंचाना चाहिए। इसके लिए राज्यों के जेलमंत्री को अपने स्तर पर पहल कर आधिकारी को लगाना चाहिए। जिन राज्यों ने सीमित मात्रा में गरीब कैदियों की मदद की केंद्रीय योजना का उपयोग भी किया है, उनका भी समग्र कार्यान्वयन उत्साहजनक नहीं है। गृहमंत्रालय की ओर से पूर्व में ही योजना के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय कर दी गई है, जिसमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में एक 'अधिकार प्राप्त समिति' और राज्य मुख्यालय स्तर पर एक 'निगरानी समिति' गठित की जानी चाहिए। इन समितियों को ही पात्र गरीब कैदियों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का अधिकार है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये समितियां मानवीयता व जिम्मेदारी के भाव से अपना काम नहीं कर रही हैं। इससे योजना का लाभ गरीब कैदियों को नहीं मिल रहा है। हाल ही में जारी 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025' के अनुसार, जेलों में कैदियों की राष्ट्रीय औसत कुल क्षमता का 131 प्रतिशत से अधिक है। वहीं कुल कैदियों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 76 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2030 तक कारागारों में कैदियों की संख्या 6.8 लाख तक पहुंच जाएगी, जबकि इनकी क्षमता केवल 5.15 लाख तक होगी। देश में एक बड़े जेल सुधार की आवश्यकता है। इसी के साथ पुलिस के काम करने के तरीके में भी सुधार की आवश्यकता है। जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ते रहने के पीछे पुलिस का ही दोषपूर्ण व गैरजिम्मेदाराना कामकाज है। हजारों विचाराधीन कैदी अपने ऊपर लगे आरोप में होने वाली सजा की अवधि से अधिक वक्त तक केस खुलने के इंतजार में जेल में बंद हैं। राज्यों को जेल की दशा में सुधार व गरीब कैदियों की मदद के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए।

दिवस विशेष

राजकुमार सिन्हा

प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रभावी प्रतिबंध लगाना आवश्यक

विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय दिवस है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला यह दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों को हमारे ग्रह की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साझा मिशन के साथ आता है। यह दिन सरकारों, व्यवसायियों और लोगों के लिए प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ़ कार्रवाई करने और स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करने का एक अवसर है। इस बार 5 जून, 2025 को कोरिया गणराज्य विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। प्लास्टिक प्रदूषण एक व्यापक पर्यावरणीय समस्या है जो दुनियाभर में पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। साल 1950 में दुनिया में प्लास्टिक उत्पादन 2 मिलियन टन था, जो साल 2021 में बढ़कर 390 मिलियन टन हो गया है। एक अध्ययन के मुताबिक 2.2 करोड़ टन प्लास्टिक पर्यावरण में मिल गया है जिसमें से 60 लाख टन नदियों, तालाबों और सागरों में गया है। 'डाउन टू अर्थ' पत्रिका में रोहिणी कृष्णमूर्ति की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है। यहां सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता है जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग पांचवां हिस्सा है। प्लास्टिक के बेहद महीन कण, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आज पूरी दुनिया में हावी हो चुके हैं। पृथ्वी पर मौजूद पानी का केवल कुछ हिस्सा लगभग 0.3 प्रतिशत ही पीने लायक है। भारत में जल प्रदूषण पहले से ही एक चिंता का विषय है, प्लास्टिक और कचरे के लीक होने से दुनिया का पानी खतरे में है। भूजल और जलाशय का पानी विषाक्त पदार्थों के रिसाव के कारण अतिसंवेदनशील है। यह न केवल पर्यावरण बल्कि इंसानी स्वास्थ्य और जैवविविधता के लिए बड़ा संकट है। समुद्री जीवन, मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने के अलावा प्लास्टिक कचरा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 3 से 4 प्रतिशत का योगदान देता है। प्लास्टिक प्रदूषण अब नए चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। 'टॉक्सिओलॉजिकल साइंसेज' में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण अब माता के गर्भाशय तक पहुंच गए हैं। यह अध्ययन अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको हेल्थ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने किया है। साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध के प्रमुख लेखक सैमुअल पोटींगर के अनुसार यदि विश्व में प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो 2050 तक प्लास्टिक प्रणाली से होने वाले वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 37 फीसदी की वृद्धि होगी। एक नए वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि 2018 में दुनियाभर में दिल की बीमारी से हुई 3,56,000 से ज्यादा मौतों का संबंध प्लास्टिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले एक विशेष रसायन 'डाइ-2-एथाइलहेक्सिल फ्थेलेट (डीईएचपी)' से था। यह रसायन प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। चिंता की बात यह है कि इस मामले में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, जहां हृदय रोग से होने वाली 1,03,587 मौतों के लिए कहीं न कहीं यह केमिकल भी जिम्मेवार था। भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 देश में पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। नियम शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक कचरे के संग्रह सहित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन करने का आदेश देता है। नियमों के तहत, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि प्लास्टिक कचरे को खुले में न जलाया जाए। विश्व के लगभग 90 फीसदी समुद्री मछली भंडार का पूर्णतः दोहन हो चुका है, या उनका अत्यधिक दोहन हो चुका है। भारत के ऋषि - मुनि जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है- 'वृक्षाद् वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न सम्भवः ' अर्थात वृक्ष जल है, जल अन्न है, अन्न जीवन है। भारत में पेड़-पौधों, नदी-पर्वत, ग्रह-नक्षत्र, अग्नि-वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को मां स्वरूप माना गया है। परन्तु हमने इस सीख को भुलाकर विनाश का रास्ता पकड़ लिया है।

(लेखक होम्योपैथिक चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

विश्व पर्यावरण दिवस

डा.ए.के. अरुण

पर्यावरण की अनदेखी पड़ रही भारी

> पहाड़ों में प्लास्टिक प्रदूषण को मानव जीवन एवं हिमालय पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड एवं अन्य पर्वतीय प्रदेशों में प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से पर्यावरण की दुर्गति की बात करें तो विगत वर्षों के आंकड़े डरावने लगते हैं। उत्तराखंड में प्रदूषण फैलाने वाले तत्व में मल्टी लेयर प्लास्टिक प्रमुख हैं, जिसमें स्नैक्स के पैकेट, पानी की बोतलें आदि शामिल हैं। विडंबना यह है कि उत्तराखंड में वर्ष 2018 से प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर पहाड़ और वहां के पर्यावरण को बचाने की पहल तेज नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं, जब धरती पर वन्य जीव और मानव नहीं, केवल कंक्रीट के घर और प्लास्टिक ही रह जाएंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के बहाने हम इस बार उत्तराखंड सहित देश के लगभग सभी पर्वतीय प्रदेशों में पर्यावरण की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में यह दिवस पर्यावरण के प्रति जागरुकता फैलाने का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। वर्ष 2025 विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह के आयोजन की मेज़बानी इस वर्ष कोरिया गणराज्य कर रहा है। इसका थीम है "वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना।" पृथ्वी को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपभोग को कम करना, पहाड़, समुद्र और महासागरों की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी तंत्र की मरम्मत और जैव विविधता को बनाए रखना शामिल है। उत्तराखंड एवं अन्य पर्वतीय प्रदेशों में प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से पर्यावरण की दुर्गति की बात करें तो विगत वर्षों के आंकड़े डरावने लगते हैं। उत्तराखंड में प्रदूषण फैलाने वाले तत्व में मल्टी लेयर प्लास्टिक प्रमुख हैं, जिसमें स्नैक्स के पैकेट, पानी की बोतलें आदि शामिल हैं।

कोरोना महामारी के दौरान के वर्षों में जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब वर्ष 2021-22 में उत्तराखण्ड में लगभग 25 हजार टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ था। वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 45 हजार टन को पार कर चुका था। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक प्रदूषण में यह वृद्धि पर्यावरणविदों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पहाड़ों में प्लास्टिक प्रदूषण को मानव जीवन एवं हिमालय पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। विडंबना यह है कि उत्तराखंड में वर्ष 2018 से प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। राज्यभर में प्लास्टिक की थैलियों में सामान लेने देने वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन इस प्रतिबंध का कोई ख़ास असर तो दिखाई नही दिया। लोग पूछते हैं कि प्लास्टिक का विकल्प क्या है? क्या प्लास्टिक प्रदूषण के लिए सिर्फ़ दुकानों पर बिकने वाली प्लास्टिक थैलियां ही ज़िम्मेवार हैं।प्‌लास्टिक पैकेजिंग करने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां क्या अपने प्लास्टिक कचरे का ईमानदारी से निस्तारण करती हैं? हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थान पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। इन जगहों पर प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति बहुत चिंताजनक पाई गई है। प्लास्टिक को पर्वतीय परिपेक्ष्य में भी देखने की ज़रूरत है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट-2016 की "एक्सटेंडेड प्रोडूसर रिस्पांसिबिलिटी" नियम के तहत कंपनियों पर ज़िम्मेदारी होती है कि वे अपने द्वारा पैदा किए गए कचरे का निस्तारण करें लेकिन उत्तराखंड सहित किसी भी पर्वतीय प्रदेश में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों के मुताबिक़ यदि हम प्लास्टिक का ऐसे ही अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहे तो अगले 20 वर्षों में प्लास्टिक कचरा बढ़कर दोगुना हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे के मामले में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर हरिद्वार आता है। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर जो चिंता जतायी जा रही है उसके मद्देनज़र पहाड़ों और उसके आस पास के इलाकों को प्लास्टिक मुक्त करने की सख़्त ज़रूरत है। भले ही प्लास्टिक ने हमारी

ज़िंदगी आसान कर दी हो लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्लास्टिक से होते नुक़सान के रूप में दुनिया को इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ रही है। अभी हाल के एक वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक में उपयोग होने वाले कुछ केमिकल मनुष्य और जीव जन्तुओं की सेहत पर भारी पड़ रहे हैं।

अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया भर में दिल की बीमारी से हुई 3,56,000 से ज़्यादा मौतों का संबंध प्लास्टिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले एक विशेष रसायन "डाई-2ऐथाइलहेक्सिल फ़्थेलेट"(डीईएचपी) से था। यह रसायन प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह तो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा है। चिंता की बात यह है कि इस मामले में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहां हृदय रोग से होने वाली 1,03,587 मौतों के लिए कहीं न कहीं यह केमिकल ज़िम्मेवार है। इस अध्ययन का नेतृत्व न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगोन हेल्थ के वैज्ञानिकों ने किया है। इस अध्ययन के नतीजे एक विश्व प्रसिद्ध जर्नल "लैंसेट ई बायोमेडिसिन" में प्रकाशित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक में उपयोग होने वाले इन केमिकल्स को फ़ेथेलेट्स कहा जाता है। ये प्लास्टिक के डब्बों, कॉस्मेटिक उत्पादों, डिटर्जेंट सालवेंट, कीटनाशकों, पाइपों और मेडिकल उपकरणों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल सूक्ष्म कणों में बदल कर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शोधकर्ताओं के मुताबिक़ ये मोटापा, डायबिटीज, कैंसर तथा प्रजनन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा देते हैं। वर्ष 2022 के दौरान दुनियाभर में जितना प्लास्टिक तैयार हुआ उसमें 10 फ़ीसद से भी कम रीसाइकल मैटीरियल से बनाया गया था। आंकड़ों पर नज़र डालें तो सन् 2022 में चालीस करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ लेकिन उसमें से महज़ 3.8 करोड़ टन यानी 9.5 फ़ीसद ही रीसाइकल करके बनाया गया, जबकि बाक़ी 36.2 करोड़ टन प्लास्टिक में से 98 फ़ीसद का उत्पादन जीवाश्म ईंधन (मुख्य रूप से कोयला और तेल) से किया गया। यह जानकारी प्लास्टिक के जीवन चक्र पर किए गए पहले व्यापक वैश्विक अध्ययन से सामने आई है। भारत के पारिस्थितिकी संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण का संकट दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। नाज़ुक और संवेदी पहाड़ों पर 80 फ़ीसद से अधिक प्लास्टिक कचरा सिंगल यूज खाद्य और पेय पैकिंग से उत्पन्न हो रहा है। चिंताजनक यह है कि इस कचरे में 70 फीसद तो वह प्लास्टिक है जिसे न तो रीसाइकल किया जा सकता है और न ही इसका कोई बाज़ार मूल्य है। कुल कचरे में पीईटी जैसे रीसाइकल योग्य प्लास्टिक की मात्रा मात्र 18.5 फ़ीसद है। द हिमालयन क्लीनअप (टीएचसी) 2024 रिपोर्ट ने 2018 से जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश का व्यापक प्लास्टिक कचरा और ब्रांड ऑडिट के दौरान यह निष्कर्ष दिया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि अधिकांश प्रदूषण फैलाने वाले ब्रांड्स जैसे इंस्टेंट नूडल्स और ऊर्जा पेय पदार्थों की पैकिंग कचरे में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज समाज में पर्यावरण संरक्षण की समझ पैदा करने की आवश्यकता है। यह प्लास्टिक मानव जीवन के लिए ख़तरा बन गया है। संवेदनशील पहाड़ों में प्लास्टिक के जमा होते ढेर जानलेवा हैं। यह वन्य जीवों और वनस्पति तथा पर्यावरण के लिए ख़तरा हैं।

इस ख़तरे के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करना होगा। ईको सिस्टम को जानने और इसके संरक्षण के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना तथा इससे आम नागरिकों को भी जोड़ना होगा। अगर पहाड़ और वहां के पर्यावरण को बचाने की पहल तेज नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं, जब धरती पर वन्य जीव और मानव नहीं, केवल कंक्रीट के घर और प्लास्टिक ही रह जाएंगे।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

शिवत्व की साधना

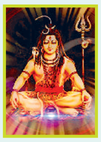

संकलित

दर्शन

हर कर्म का आरंभ संकल्प से होता है। बातों को बनाने, बिगाड़ने व संभालने का आधार भी हमारा सोच रूपी कर्म है। अच्छे या बुरे सोच के कारण हमारे कर्म और कर्मफल सुखदायी व दुखदायी होते हैं। इसलिए कहते हैं, परमात्मा शिव अपनी शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों से सोच को परिष्कृत कर दुनिया को परिवर्तित कर देते हैं। उनका प्रत्येक संकल्प मानवता का कल्याण व सद्ज्ञान है, जिसकी वर्षा से प्रकृति में शांति, संतुलन, सद्भावना व प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है। मानव जीवन व संसार से विकार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुख, कष्ट व हिंसा के ताप समाप्त होते हैं। परमात्मा के इस सृष्टि परिवर्तन या उद्धार कार्य से कृतज्ञ होकर हम श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत-उपवास करते हैं। शिव की महिमा स्मरण, गायन, पूजन व श्रवण से श्रावण मास शिवमय हो जाता है। कहते हैं, चातुर्मास के आरंभ में भगवान विष्णु जब शयन में चले जाते हैं, तब परमात्मा शिव संसार की बागडोर संभालते हैं। शिव निराकार ज्योति स्वरूप हैं। वे शिव ज्ञान व योग सिखाकर मनुष्यों में सतयुगी दिव्य गुण व दैवी संस्कारों को पुनः विकसित करते हैं। जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, तब सृष्टि को बचाने एवं भक्तों की शुद्ध भावनाओं और कामनाओं का फल देने हेतु शिव अदृश्य रूप में संसार का कार्यभार संभालते हैं। ज्ञान सूर्य ज्योति स्वरूप शिव अपने ईश्वरीय ज्ञान व शिक्षा के प्रकाश द्वारा मनुष्यों के आसुरी अवगुणों को सद्गुण, दैवी चरित्र व दैवी संस्कारों में बदलते हैं।

दो पैसे के काम के लिए तीस साल की बलि

संकलित

प्रेरणा

स्वामी विवेकानंद एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी तो वे वहीं रुक गए क्योंकि नदी पार कराने वाली नाव कहीं गई हुई थी। स्वामीजी बैठकर राह देखने लगे कि उधर से नाव लौटे तो नदी पार की जाए। एका-एक वहां एक महात्मा भी आ पहुंचे। स्वामीजी ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय लिया। बातों ही बातों में महात्माजी को पता चला की स्वामीजी नदी किनारे नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा जी बोले, अगर ऐसी छोटी-मोटी बाधाओं को देखकर रुक जाओगे तो दुनिया में कैसे चलोगे? तुम तो स्वामी हो, बड़े आधात्यात्मिक गुरु और दार्शनिक माने जाते हो। जरा सी नदी नहीं पार कर सकते? देखो, नदी ऐसे पार की जाती है। महात्मा जी खड़े हुए और पानी की सतह पर तैरते हुए लंबा चक्कर लगाकर वापस स्वामी जी के पास आ खड़े हुए। स्वामीजी ने आश्चर्य चकित होते हुए पूछा, महात्माजी, यह सिद्धि आपने कहां और कैसे पाई? महात्मा जी मुस्कुराए और बड़े गर्व से बोले, यह सिद्धि ऐसे ही नहीं मिल गई। इसके लिए मुझे हिमालय की गुफाओं में तीस साल तपस्या करनी पड़ी। महात्मा की इन बातों को सुनकर स्वामी जी मुस्करा कर बोले, आपके इस चमत्कार से मैं आश्चर्यचकित तो हूं लेकिन नदी पार करने जैसे काम जो दो पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने अपनी जिंदगी के तीस साल बर्बाद कर दिए। यानी दो पैसे के काम के लिए तीस साल की बलि! ये तीस साल अगर आप मानव कल्याण के किसी कार्य में लगाते या कोई दवा खोजने में लगाते, जिससे रोग से मुक्ति मिलती तो आपका जीवन सचमुच सार्थक हो जाता।

अंतर्मन

आज की पाती

फास्ट फूड के सेवन से पनपती स्वास्थ्य समस्याएं

भारत की खाद्य संस्कृति वैश्वीकरण, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के परिणामस्वरूप बदल रही है, जो प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का कारण बन रही है। भारत में युवा पीढ़ी तेजी से फास्ट फूड का सेवन कर रही है, जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे मोटापा, टाइप-2 मधुमेह और हृदय संबंधी विकार। फास्ट फूड में अक्सर बड़ी मात्रा में कैलोरी, चीनी, सोडियम और खराब वसा होती है, जो खराब खाने की आदतों और पोषण संबंधी कमियों को जन्म दे सकती है। इसका परिणाम एक गतिहीन जीवन शैली भी हो सकता है, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ाएगा। इस प्रवृत्ति में समय के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर दबाव डालने और पीढ़ियों के जीवन की सामान्य गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता है।

- महेश साहू, बसना

ट्रेंड

रक्षा साझेदारी की समीक्षा

ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की समीक्षा की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने में उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमारी रणनीतिक साझेदारी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है।

-राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षामंत्री

अग्निवीरों का सम्मान

चार वर्ष की सेवा के उपरांत अग्निवीरों के ससम्मान समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने एवं आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

सुरक्षित आश्रय बनाए

दिल्ली में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चौक-चौराहों पर कैमरा नेटवर्क को दुरुस्त किया जा रहा है। 'सखी निवास' जैसे सुरक्षित आश्रय बनाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर महिलाएं वहां ठहर सकें।

-रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

बिहार कब बदलेगा

जिला मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म व उसके इलाज में देरी/लापरवाही से हुई मौत की ताजा घटना राज्य की भी बदहाल कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता-जागता प्रमाण, जो अति-निन्दनीय एवं चिन्तनीय। बिहार कब बदलेगा?

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

करंट अफेयर

पोलैंड की पीएम 11जून को करेगी विश्वासमत साबित

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि उनकी सरकार संसद में 11 जून को विश्वास मत साबित करेगी। बीते सप्ताहांत में राष्ट्रपति चुनाव में उनके राजनीतिक सहयोगी और उदारवादी नेता के वारसॉ के मेयर करोल नवरोकी से हारने के बाद टस्क ने विश्वास मत का आह्वान किया। पोलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में अधिकांश शक्ति संसद द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के पास होती है। यह राष्ट्रपति पद से अलग है, लेकिन राष्ट्रपति के पास कानूनों को वीटो करने की शक्ति है और नवरोकी की जीत से टस्क के लिए अपने यूरोपीय समर्थक एजेंडे को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। टस्क ने वारसॉ में कैबिनेट बैठक की शुरुआत में विश्वास मत साबित करने की तारीख की घोषणा की। टस्क ने कहा, 'नए राजनीतिक परिदृश्य में हम सत्र शुरू करने जा रहे हैं। नई राजनीतिक सच्चाई है। हमारे पास एक नए राष्ट्रपति हैं। लेकिन संविधान, हमारे दायित्व और नागरिकों की अपेक्षाएं नहीं बदली हैं। पोलैंड में, सरकार शासन करती है जो एक बड़ा दायित्व और सम्मान है।' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित नवरोकी को बेहद करीबी मुकाबले में 50 .89 फीसदी मत हासिल हुए जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी वारसॉ के मेयर रफाल त्राज्स्कोव्स्की को 49 .11 प्रतिशत वोट मिले।

ऑफ बीट

क्या कॉफी वाकई कैफीन मुक्त होती है

डिकैफ़िनेटेड या 'कैफीन मुक्त' कॉफ़ी व्यापक रूप से उपलब्ध है, और इसकी खपत में वृद्धि होने की सूचना है। यहां आपको कैफीन मुक्त कॉफ़ी के बारे में जानने की आवश्यकता है : यह कैसे बनाई जाती है, स्वाद, लाभ - और क्या यह वास्तव में कैफीन मुक्त है। डिकैफ़ कैसे बनता है? कॉफ़ी बीन की सुगंध और स्वाद को बरकरार रखते हुए कैफीन को हटाना कोई आसान काम नहीं है। डिकैफ़ कॉफ़ी हरे, बिना भुने कॉफ़ी बीन्स से उनकी कैफीन सामग्री को हटाकर बनाई जाती है और इस तथ्य पर निर्भर करती है कि कैफीन पानी में घुल जाता है। कैफीन को हटाने के लिए तीन मुख्य तरीकों का उपयोग किया जाता है : रासायनिक सॉल्वैंट्स, तरल कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2), या विशेष फिल्टर वाला सादा पानी। इन सभी प्रसंस्करण विधियों में आवश्यक अतिरिक्त कदमों के कारण डिकैफ़ कॉफ़ी अक्सर अधिक महंगी होती है। अधिकांश डिकैफ़ कॉफी विलायक-आधारित तरीकों का उपयोग करके बनाई जाती है क्योंकि यह सबसे सस्ती प्रक्रिया है। यह विधि दो और प्रकारों में विभाजित है : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में कॉफी बीन्स को भाप में पकाना और फिर उन्हें बार-बार एक रासायनिक विलायक (आमतौर पर मेथिलीन क्लोराइड या एथिल एसीटेट) में भिगोना शामिल है जो कैफीन से बंध जाता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
मौन अंतरात्मा का उपवास है

नहीं सुधरेंगे राहुल

राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार अप्रिय कारणों से चर्चा में हैं। पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद उनके रुख-रवैये से एक बार को ऐसा लगा था कि वह देश, काल, परिस्थितियों के हिसाब से दलीय स्वार्थों को परे रखकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना भी जान गए हैं, लेकिन वह ऐसा सोचने वालों को गलत साबित करके ही माने। आपरेशन सिंदूर थमने के साथ ही उन्होंने कथित उचित प्रश्न पूछने के बहाने मोदी सरकार पर ऐसे हमले करने शुरू कर दिए कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के लिए भी उनकी हां मे हां मिलाना कठिन हो गया। इससे उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। मोदी सरकार को नीचा दिखाने के साथ सेना के शौर्य की भी अनदेखी करने वाले उनके बयान सामने आते ही रहे। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान उनके बयानों को अपने पक्ष में भुनाने में जुट गया। राहुल गांधी और उनके सहयोगी इससे अवगत भी हुए, लेकिन शायद उन्होंने जिद पकड़ ली है कि उनके जो मन में आएगा, बोलेंगे, भले ही उससे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचे। वह रुके नहीं और उन्होंने अपने करीबी नेताओं के जरिये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल शशि थरूर पर हमले कराने शुरू कर दिए। सलमान खुर्शीद भी उनके करीबियों के निशाने पर आ गए। खुर्शीद का यह पीड़ा भरा प्रश्न वस्तुतः उनके लिए ही था कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है? राहुल ने कोई परवाह नहीं की। वह प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह तक कहने लगे कि ट्रंप ने मोदी को जैसे ही सरेंडर करने को कहा, वैसे ही उन्होंने कर दिया।

राहुल गांधी वहीं पहुंच गए हैं, जहां वह 2019 के लोकसभा चुनाव के समय थे और जब प्रधानमंत्री के प्रति तू-तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। वह भाषा की मर्यादा के साथ देशहित की अनदेखी कर अपना और अपनी पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके करीबी उन्हें यही समझाते हैं कि वह जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी और उनके निकट के लोग कुछ भी सोचें, यह जो छवि बनाई गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें परिपक्व नेता बना दिया है, उसे वह तार-तार करने में लगे हुए हैं। वह शायद ही अपना व्यवहार बदलें, क्योंकि गलतबयानी और अपमानजनक भाषा के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी और उसकी फटकार भी सुननी पड़ी। गत दिवस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें सेना का अपमान करने के लिए फटकार लगाई और यह नसीहत भी दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा है। इस पर राहुल शायद ही ध्यान दें, क्योंकि वह इस नतीजे पर पहुंच गए लगते हैं कि राजनीतिक विरोधियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के प्रति भद्दी भाषा का प्रयोग करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार

हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में जिलाधिकारी, एसडीएम एवं नगर आयुक्त समेत सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित कर उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। हरिद्वार में जिस 33 बीघा भूमि को 15 करोड़ रुपये में खरीदा जाना था, उसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते 54 करोड़ रुपये में खरीदा गया। यह सब गड़बड़झाला तब हुआ, जब नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार जिलाधिकारी के पास था। नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने भूमि खरीद में नियमों को ताक पर रखने का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में जिलाधिकारी की भूमिका सवालों के घेरे में रही। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने में विलंब नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि भूस्वामियों को खरीद की एवज में दिए गए धन की रिकवरी भी सुनिश्चत की जा रही है। भष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तंत्र के भीतर एवं बाहर दोनों स्तर पर अभियान छेड़े हुए है। आम जनता भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत करने में संकोच नहीं करे, इसके लिए टोल फ्री नंबर है। इस पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई भी हो रही है। दरअसल भ्रष्टाचार सामाजिक बुराई की तरह पनप गई है। इससे निजात पाने के लिए सरकार के साथ ही आम जन को इसके विरुद्ध लड़ने का साहस दिखाना होगा, तभी इस पर शिकंजा कसा जा सकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुकाबले को हर स्तर पर लड़ना होगा।

भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम आवश्यक है। सरकार ने कड़ी कार्रवाई से अच्छा संदेश दिया है

भारत को खुद कहनी होगी अपनी कहानी

विकास सारस्वत

एक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को अंतर्मुखी स्वभाव छोड़कर पूरे विश्व को अपना सरोकार बनाना होगा

आपरेशन सिंदूर की समाप्ति के बाद कुहासे के बादल छट गए हैं। देश-विदेश के तमाम रक्षा विशेषज्ञ और उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों से पुष्टि हुई कि यह संघर्ष पूरी तरह एकतरफा था और पाकिस्तान को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। इस सैन्य संघर्ष में दुनिया ने भारत के स्वदेश निर्मित सैन्य उपकरणों की बेजोड़ क्षमताओं का लोहा भी माना। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य शौर्य और रक्षा क्षेत्र की उद्यमशीलता ने आशा से अधिक प्रभावित किया है, परंतु इस कठिन समय में जो एक कमी खली, वह थी सूचना क्षेत्र में भारत की ढिलाई। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आपरेशन सिंदूर की बयानगी को लेकर न सिर्फ भारतीय चिंताओं की अनदेखी हुई, बल्कि पाकिस्तानी दावों को बिना जांचे-परखे आगे बढ़ाया गया। न्यूयार्क टाइम्स, सीएनएन, वालस्ट्रीट जर्नल, निक्केई एशिया, ब्लूमबर्ग आदि में भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव की ज्यादातर रिपोर्टिंग पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा की गई। समाचार एजेंसी रायटर्स ने तो एक ऐसे गुमनाम पाकिस्तानी लेखक सईद शाह के तीन लेख प्रकाशित किए, जो उस दौरान ही कार्यरत रहा। ये पाकिस्तानी पत्रकार केवल पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगंडा ही आगे बढ़ाते रहे। कई पश्चिमी मीडिया माध्यम जाने-अनजाने उनसे प्रभावित भी होते रहे। हालांकि बाद में न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट आदि ने भारतीय दावों की पुष्टि की और इस संघर्ष को भारत की जीत बताया, परंतु युद्ध के दौरान जब मीडिया रिपोर्टिंग देशों के मनोबल और जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, तब पहले चलाए गए झूठे प्रोपेगंडा की बाद में परिशुद्धि संभव नहीं हो पाती।

यह पहली बार नहीं, जब अंतरराष्ट्रीय और खासकर पश्चिमी मीडिया ने भारत के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया हो। भारत दशकों से आतंक की मार झेलता रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया को 'वार आन ग्लोबल टेरर' की याद 9/11 के बाद ही आई। भारत में चल रहे आतंकवाद को वह अब भी कश्मीर विवाद से जोड़कर या फिर भारत में ''बढ़ते उग्र राष्ट्रवाद'' की प्रतिक्रिया के रूप में ही देखता है। भाषा, संप्रदाय की दृष्टि से विविधता भरे देश में इतना सफल जनतंत्र होने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र पर अनर्गल टिप्पणियां होती रहती हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सफलता मिलने पर भारत को उलाहने मिलते हैं और यहां की समस्याओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है। यह कथानक भेद का ही परिणाम है कि ओसामा का मारा जाना सकारात्मक समाचार बनता है, पर आतंकी निज्जर की मौत और पन्नू की जान को कथित खतरे पर भारत सरकार को घेरने का प्रयास होता है। पश्चिमी सरकारों और पाश्चात्य मीडिया में सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता के कारण भारत के प्रति वह संवेदनशीलता नहीं, जो सामान्यतः दिखनी चाहिए। एक उभरती आर्थिक और सैन्य शक्ति होने के कारण भी पश्चिमी दृष्टिकोण में भारत के प्रति ईर्ष्या का भाव झलकता है। इस सबके बावजूद भारत केवल पश्चिम के असत्य और पूर्वाग्रहों का उल्लेख भर करके चुप नहीं रह सकता। अपने बढ़ते वैश्विक प्रभाव के मध्य भारत को न सिर्फ अपना अपना कथानक, अपनी कहानी स्वयं कहनी-बनानी होगी, बल्कि उसे वैश्विक समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण से दुनिया को भलीभांति परिचित भी कराना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया में स्थान तलाशने के अलावा भारतीयों को स्वतंत्र छवि वाले ऐसे विश्वसनीय मीडिया मंच तैयार करने होंगे, जो भारतीय परिदृश्य में घटनाओं को देखते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी समीक्षा कर सकें। यह दायित्व सरकारी न होकर भारत के ऐसे प्रबुद्ध पत्रकार-विचारक वर्ग को उठाना होगा, जिसका मानस पश्चिमी या चीनी परतंत्रता से मुक्त हो।

दीर्घकालिक विदेशी उपनिवेशवाद ने आमजन के साथ-साथ भारत के प्रबुद्ध वर्ग को भी आत्मसंशय और संकोच से भर दिया है और वह न केवल अपने देसी खोल में सिमटकर रह गया है, बल्कि पाश्चात्य विश्वदृष्टि के पराधीन भी हो गया है। एक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को अंतर्मुखी स्वभाव से निकलकर पूरे विश्व को अपना सरोकार बनाना होगा। मीडिया के अलावा इसी प्रत्याशा हेतु थिंक टैंक, शोध संस्थान, पर्यवेक्षी निकाय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भी बनाने होंगे। इनके द्वारा वैश्विक विषयों पर टिप्पणियों के अलावा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सहिष्णुता जैसे मानकों पर पश्चिमी देशों की समीक्षा भी करनी होगी। इसी के साथ सिनेमा, सीरियल और साहित्य जैसी विधाओं को भी अपना दृष्टिकोण वैश्विक करना होगा। कुछ और बिंदुओं पर सरकार को भी ध्यान देना होगा। आपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने भारतीय पक्ष समझाने को विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जो पहल की, वह समय-समय पर करनी होगी। राजनयिकों के अलावा नेताओं और बुद्धिजीवियों के स्तर पर भी आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर भारत का विश्व से संवाद एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए और ऐसे संभाषणों के लिए संस्थागत प्रयास भी होने चाहिए। भारत के विरुद्ध कुप्रचार को हवा मिलने का बड़ा कारण संवाद की कमी और संवाद में देरी भी रहती है।

पुरानी कहावत है कि जब झूठ आधी दुनिया घूम आता है, तब सच अपने जूते पहन रहा होता है। भारतीय सेना के तीन डीजीएमओ ने तो प्रेस कांफ्रेंस में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, परंतु उसके पहले संवादहीनता के कारण ऐसी बातों को बढ़ावा मिला, जिनके जरिये कहा गया कि अमेरिकी और चीनी मध्यस्थता के कारण भारत ने संघर्ष विराम किया। बदलते परिदृश्य में जब भारत को प्रभावित करने वाले मुद्दे रोजाना विमर्श का विषय बनते हैं, तब यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से भी व्हाइट हाउस की तर्ज पर प्रतिदिन प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा जाए। हमें यह समझना होगा कि कथानक को प्रभावित करने की क्षमता के अभाव में पश्चिम अपने एजेंडे के हिसाब से भारत के प्रति खास संदेश देने वाली अपनी कहानियों को आकार देता रहेगा। यानी वही नैरेटिव शेपिंग करता रहेगा।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

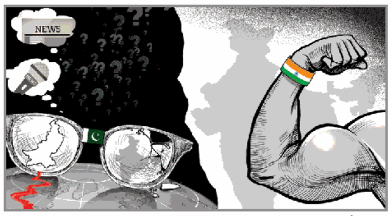

अवधेश राजपूत

हरित भारत के प्रति समर्पित रेलवे

अश्विनी वैष्णव

भारत यह साबित कर रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता एक साथ संभव है

हर बार आप जब परिवहन के अन्य साधनों के बजाय रेलगाड़ी से यात्रा करने का चुनाव करते हैं, तो केवल आराम या सुविधा ही नहीं चुन रहे होते। आप एक स्वच्छ एवं हरित भारत को भी चुन रहे होते हैं। पिछले वर्ष 700 करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा के साधन के रूप में भारतीय रेल को चुना। रेल हमारी जीवन रेखा है और भविष्य के लिए एक हरित वादा भी। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेलवे सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। रेलवे देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए पंचामृत लक्ष्यों-2070 तक शून्य उत्सर्जन को साकार करने में सहायता कर रहा है और एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से इसे संभव बना रहा है। यातायात को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित करके और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा स्रोतों के साथ परिचालन को शक्ति प्रदान करके इस दिशा में बढ़ रहा है। ये कदम देश को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को विकार्बनित (डीकार्बोनाइज) करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

यात्रा सेवाओं के साथ ही माल ढुलाई में भी रेलवे की महत्ता समय के साथ बढ़ती जा रही है। 2013-14 में भारतीय रेल ने लगभग 105.5 करोड़ टन माल की ढुलाई की। 2024-25 के दौरान यह ढुलाई बढ़कर 161.7 करोड़ टन हो गई है। इससे भारतीय रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे बन गया है। विशेषज्ञों द्वारा की गई गणनाओं का उपयोग करते हुए सड़क के बजाय रेल के जरिये माल ढुलाई से संबंधित इस बदलाव ने 14.3 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। यह 121 करोड़ पेड़ लगाने जैसा है। रेल द्वारा माल परिवहन की लागत सड़क मार्ग से होने वाले परिवहन की लागत की लगभग आधी है। इसका अर्थ है कि न केवल व्यवसायों, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बचत। इस बदलाव से पिछले दशक में लाजिस्टिक्स की लागत में 3.2 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। भारतीय रेल स्वच्छ भी है और ट्रकों की तुलना में इससे 90 प्रतिशत कम कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है। परिणामस्वरूप हमारे आसमान में कम धुआं निकलता है और हमें स्वच्छ हवा मिलती है। सड़क से रेल की ओर होने वाले इस बदलाव ने हमें 2,857 करोड़ लीटर डीजल की बचत कराई है, जो ईंधन लागत में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की बचत के बराबर है।

पर्यावरण हितैषी भी है भारतीय रेल। फाइल

चूंकि भारत तेल आयात करता है, इसलिए परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण करना रणनीतिक रूप से एक समझदारी भरा कदम है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। 2014 से पहले के 60 वर्षों में भारतीय रेल ने 21,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया। जबकि पिछले 11 वर्षों के दौरान हमने 47,000 किमी रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया है। आज हमारे ब्राड गेज नेटवर्क का 99 प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकृत है। भारतीय रेल स्टेशनों, कारखानों और कार्यशालाओं के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग तेजी से कर रहा है। अब यह रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए अधिक हरित ऊर्जा प्राप्त करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह सब भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता देगा। इस गति को आगे बढ़ाते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी) को विद्युतीकृत किया गया है। उच्च क्षमता वाली रेलवे लाइनें भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से माल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। कुल 2,741 किमी परिचालन के साथ डीएफसी ने सड़कों पर भीड़भाड़ कम की है और डीजल की खपत एवं कार्बन उत्सर्जन को भी घटाया है। भारत हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जैसी आधुनिक, शून्य-उत्सर्जन तकनीक भी अपना रहा है। पहली ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और 2,600 यात्रियों को ले जाएगी। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी।

भारत यह साबित कर रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी एक साथ निभाई जा सकती है और ऐसा होना भी चाहिए। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स परफारमेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत अब 139 देशों में 38वें स्थान पर है, जो 2014 की तुलना में 16 स्थान ऊपर है।

रेलवे विद्युतीकरण के विस्तार ने लागत और उत्सर्जन को कम किया है। इसने गति और क्षमता भी बढ़ाई है, जिससे भारत को विश्वस्तरीय लाजिस्टिक्स मानकों के निकट पहुंचने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2030 का लक्ष्य तय किया है। तेजी से हो रहे विद्युतीकरण और बड़े पैमाने पर माल को सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित करने के कारण भारतीय रेलवे 2025 तक ही नेट जीरो (स्कोप 1) हासिल करने की ओर अग्रसर है। चूंकि भारतीय रेलवे सतत विकास के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहा है, इसलिए हर विद्युतीकृत ट्रैक, हर सौर पैनल और सड़क से हटा प्रत्येक मालवाहक कंटेनर हमारे लोगों और हमारी धरती के उज्ज्वल भविष्य के प्रति एक शपथ है।

(लेखक केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म के स्तंभ

धर्म भगवत्प्रतिपादित सृष्टि के ऊषा काल से एक सार्वभौम शाश्वत नियम-व्यवस्था है, जिसके सहज अनुपालन से सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे वेद, समृतियां और पुराणादि में जो प्राणिमात्र के कल्याण के सदुपेदश वर्णित और निर्देशित हैं, उनके अनुपालन से व्यक्ति लोक-परलोक में यशस्वी होता है। व्यक्ति को जानबूझकर उपेक्षित और नष्ट किया हुआ धर्म ही मारता है और श्रद्धापूर्वक रक्षित किया हुआ धर्म ही उसको उत्तम जीवन देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, तब धर्म ही उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करता है।

धर्मविहीन जीवन अमर्यादित एवं उच्छृंखल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से अनाचार फैलता है। आचार-विचार, आहार-विहार और विश्रामादि समस्त दैनिक कार्यों को धर्मानुसार ही करना चाहिए। धर्मनियंत्रित जीवन ही स्वस्थ-सुंदर समाज का निर्माण करता है। आज मानव बड़े-बड़े कार्य कर समृद्धिशाली हो रहा है, किंतु धर्म से विमुख होने के कारण उसके पारस्परिक संबंधों में अपनत्व का नितांत अभाव हो रहा है। संप्रति, सहज स्नेह के स्थान पर व्यवहार में शुष्क औपचारिकता मात्र प्रदर्शित है। धर्म ही मनुष्य की विशेषता है। धर्मविहीन होने से समाज में साधुता विलुप्त हो जाती है। स्वार्थ और अभिमानमूलक सोच के दुष्प्रभाव से पाखंडवाद का दानव मानव के सांस्कृतिक मूल्यों को छिन्न-भिन्न कर देता है। धर्म के मुख्य चार स्तंभ हैं-सत्य, दया-दान तप और पवित्रता। जो व्यक्ति सत्य की उपेक्षा नहीं करता है, वह आध्यात्मिक ताप से प्रभावित नहीं होता। जिसमें दया-दान जैसे दैवीय सद्गुण जागृत रहते हैं, उस पर आधिदैविक ताप का प्रभाव नहीं रहता है। जिसका आचार-विवार पवित्र और जो तपस्वी है, आधिभौतिक उससे बहुत दूर रहता है। तप का तात्पर्य है-अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्मानुशासन को शिरोधार्य किए रहना। धर्म के यही स्तंभ जीवन की आधारशिला हैं।

आचार्य नारायण दास

दूर हो ई-वाहनों की चार्जिंग की समस्या

सुनीता मिश्रा

इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि भविष्य की जरूरत हैं। ये पर्यावरण और आर्थिक रूप से फायदेमंद हैं

सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) एक डिजिटल एप विकसित करने जा रही है, जिसकी मदद से देशभर में स्थित इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशन की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस एप से इलेक्ट्रिक वाहनों के यूजर्स अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए स्लाट बुक करा सकेंगे, भुगतान कर सकेंगे और चार्जर की उपलब्धता की स्थिति भी जान सकेंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत मार्च 2026 तक सार्वजनिक स्थानों पर 72 हजार चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्वीकार्यता बेहतर भविष्य की नींव मजबूत कर रही है। वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 49 फीसद की सालाना बढ़ोतरी देखी गई। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023 में 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिके। वहीं ईवी इंडस्ट्री ने वर्ष 2022 में कुल 10,25,063 वाहन बेचे थे।

पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन कार्बन डाईआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। इनसे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन से हानिकारक गैसें नहीं निकलतीं और वायु प्रदूषण भी कम होता है। इलेक्ट्रिक वाहन बहुत शांत होते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना पेट्रोल-डीजल की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। इसके रखरखाव में भी कम व्यय करना पड़ता है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। वर्ष 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। सितंबर 2024 में पीएम-ई ड्राइव योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक, आटो और दोपहिया वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी की घोषणा की गई। इस योजना के तहत अगले वर्ष मार्च तक 14,028 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि भविष्य की जरूरत हैं। ये न केवल पर्यावरण, आर्थिक रूप से फायदेमंद हैं, बल्कि देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य देने का माध्यम भी हैं। लोगों को अक्सर इसकी चार्जिंग, पावर और स्पीड को लेकर शिकायत रहती है। फरवरी 2024 तक भारत में केवल 12,146 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन थे। ऐसे में सरकार द्वारा मार्च 2026 तक 72 हजार चार्जिंग स्टेशन लगाने और एक एप के जरिए सभी स्टेशनों की जानकारी देने का फैसला लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विपक्ष के समझदार नेता

'देश हित पर भारी पड़ते दलगत हित' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने देश के उन विपक्षी नेताओं की नासमझी पर क्षोभ प्रकट किया है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं की आलोचना करने में गुरेज नहीं किया जो विदेशी धरती पर अपनी राष्ट्रहितैषी बयानबाजी से विपक्ष के समझदार नेता बन गए हैं। देश में विपक्षी नेता के तौर पर भाजपा और मोदी सरकार के आलोचक माने जाने वाले कांग्रेस के शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, डीएमके की कनिमोरी के अलावा एआइएमआइएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश में जाकर जिस समझदारी से देश के मान-सम्मान का खयाल रखते हुए 'आपरेशन सिंदूर' पर भारत के पक्ष को रखा उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बावजूद इसके कांग्रेस के कुछ नासमझ नेता सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विभिन्न देशों में 'आपरेशन सिंदूर' पर सकारात्मक रूप से भारत का पक्ष रखने वाले सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे समझदार नेताओं की आलोचना करने में व्यस्त हैं। भला इससे भी अधिक लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जयराम रमेश जैसे नेता इस काम को अंजाम देकर अपने आका को खुश करने में लगे हुए हैं। इस विद्रूपता को आज पूरा देश देख रहा है। मोदी सरकार चाहती तो भाजपा के कद्दावर नेताओं के नेतृत्व में दो-चार प्रतिनिधि मंडल बनाकर विदेशों में भेज सकती थी, लेकिन उसने भारत की एकता प्रदर्शित करने के लिए विपक्षी दल के ओवैसी जैसे अपने कटु आलोचकों को भी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंप कर, उन्हें भारत के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वाह करने का अवसर प्रदान किया। निःसंदेह मोदी सरकार द्वारा चुने गए सभी विपक्षी नेता देश की उम्मीद पर खरे उतरे हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए शुभ संकेत है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

रक्षा क्षमता मजबूत होना जरूरी

निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन का जिम्मा सौंपा जाए। इससे देश की रक्षा क्षमता मजबूत हो सकती है। हालांकि, यह भी आवश्यक है कि निजी कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण अधिकतम हो, ताकि देश की सुरक्षा को खतरे में न डाला जा सके। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत आधुनिक तकनीक में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी कारण, देश ने अपनी रक्षा प्रणाली और युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह विमान पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा, जिसकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह लगभग 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद वर्ष 2034 तक है। इससे देश का धन अन्य देशों में जाने से बचेगा, क्योंकि यदि यह विमान विदेश से खरीदा जाता, तो हमारे संसाधन विदेशों में चले जाते। यदि मोदी सरकार ने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई होती, तो शायद सिंदूर मिशन सफल नहीं होता। सच है कि भारत सदियों से युद्ध पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब पाकिस्तान जैसे पड़ोसी प्यार की भाषा नहीं समझते, तो उनके खिलाफ हथियार उठाना आवश्यक हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने पड़ोसियों को कमजोर न समझें। चीन के पास भी आधुनिक तकनीक है और वह भी ऐसे विमानों का निर्माण कर सकता है। भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है, लेकिन साथ ही हमें अपने पड़ोसियों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

भूल सुधार

बुधवार, 4 जून को प्रकाशित 'मिसाल बनेंगी रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां' शीर्षक वाले लेख के तीसरे पैरे में रक्षा निर्यात संबंधी आंकड़े त्रुटिपूर्ण छप गए थे। सही आंकड़े इस प्रकार हैं-2017-18 में निजी क्षेत्र का जो रक्षा निर्यात 1,400 करोड़ रुपये का था, वह 2024-25 में बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये हो गया। इस भूल और पाठकों की असुविधा के लिए खेद है। -संपादक

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://t.me/AllNewsPaperPaid